



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 656]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 17, 2008/अग्रहायण 26, 1930

No. 656]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 17, 2008/AGRAHAYANA 26, 1930

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 15 दिसम्बर, 2008

सा.का.नि. 861(अ).—संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति, एतद्वारा, इसके साथ संलग्न निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों को असम रायफल्स नियम, 2008 कहा जाए।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- (3) ये नियम असम रायफल्स अधिनियम, 2006 के अध्यक्षीन सभी व्यक्तियों पर लागू होंगे।

{फा. सं. एल-11011/1/2007/पर्स-III}

वी. एन. गोड़, संयुक्त सचिव

असम राइफल्स नियम, 2008

केन्द्रीय सरकार असम राइफल्स नियम, 1985 को अधिक्रान्त करते हुए और असम राइफल्स अधिनियम, 2006 (2006 का 47) की धारा 165 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

अध्याय - 1प्रारम्भिक1. संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ और लागू होना -

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम असम राइफल्स नियम, 2008 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।
- (3) ये नियम इस अधिनियम के अधीन समस्त व्यक्तियों पर लागू होंगे।

2. परिभाषाएं - इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

- (क) "अधिनियम" से असम राइफल्स अधिनियम, 2006 से अभिप्रेत है।
- (ख) "परिशिष्ट" से इन नियमों में उपाबद्ध परिशिष्ट अभिप्रेत से है ;
- (ग) "नियुक्ति" से बल में किसी व्यक्ति की नियुक्ति अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत अभ्यावेशन भी है।
- (घ) "न्यायालय" से बल न्यायालय अभिप्रेत है।
- (ङ) "टुकड़ी" में अपेक्षित बल की किसी इकाई का कोई भाग, या मुख्यालय से दूर कर्तव्य पर जाने के आदेश भी है।
- (च) "बल प्राधिकारी" का प्रयोग जब किसी शक्ति, कार्य, या विषय (मामले) के कर्तव्य संबंध में प्रयोग किया जाता है, तो ऐसा बल प्राधिकार से अभिप्रेत है, जो इन नियमों के अनुसरण में, उस शक्ति का प्रयोग करती है, या ड्यूटी का निर्वहन करती है या उस मामले से संबंधित होती है।
- (छ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।
- (ज) इन नियमों में प्रयुक्त सभी अन्य शब्द और पद जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु इस अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में हैं।

3. रिपोर्ट और आवेदन :- इन नियमों के अधीन किसी उच्च प्राधिकारी या बल प्राधिकारी को यदि कोई रिपोर्ट या आवेदन देना अपेक्षित हो तो इसे उचित माध्यम द्वारा लिखित रूप में देना होगा जब तक कि उक्त प्राधिकारी सेवा की आत्यावश्यकता या अन्यथा के मद्दे लिखित रूप में देन से छूट न दे दे।4. उपाबद्ध में प्ररूप :- (1) उपाबद्ध में दिए प्ररूप इसे प्रत्येक मामले की परिस्थिति की ऐसी भिन्नताओं के अनुसार उसमें उल्लिखित प्ररूपों क्रमशः प्रयोजन के लिए उपयोग किए जा सकें और यदि इनका प्रयोग किया जाना पर्याप्त होगा, परन्तु इन प्ररूपों से कोई विचलन, केवल इस कारण से किसी आरोप, वारंट, आदेश, कार्यवाहियों अथवा इन नियमों से संबंधित किसी अन्य दस्तावेज को अविधिमाम्य नहीं होगा।

(2) किसी ऐसे प्ररूप में कोई लोप से केवल ऐसी किसी लोप के कारण किसी कार्य या विषय को अविधिमाम्य नहीं माना जाएगा।

(3) टिप्पणों में दिए गए निदेशों, और प्ररूपों (फार्म) में दिए गए अनुदेशों का, उन सभी मामलों में, जिनसे वे संबंधित होते हैं, अनुपालन किया जाएगा, किंतु टिप्पणों में दिए गए ऐसे किसी भी निदेशों या अनुदेशों के अनुपालन में किसी लोप से, केवल लोप होने के कारण से, किसी कार्य या विषय (मामले) को अविधिमाम्य करार नहीं दिया जाएगा।

5. बल में किसी पद धारक पर को निहित शक्तियों का प्रयोग :- इस बल में किसी पद के धारक किसी व्यक्ति को, इन नियमों के प्रयोज के लिए कोई कार्य यात को करने के लिए या इससे पहले, उसे दी गई किसी शक्ति या अधिकारिता का प्रयोग, ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जो तत्समय, इस बल के नियम और पद्धति के अनुसार उस कार्यालय में कार्य को कर रहा होगा, किया जा सकेगा।6. अप्रस्तुत मामले :- ऐसे किसी मामलों के संबंध में, जो विशेष रूप से इन नियमों में विनिर्दिष्ट नहीं हैं, तो सक्षम प्राधिकारी के लिए यह विधिपूर्ण होगा कि वह ऐसी बातों के बारे में या ऐसी कार्यवाही करे जो मामले की अत्यावश्यकता और परिस्थितियों के अनुसार ठीक समझे।अध्याय - 2संगठन7. बल का गठन - असम राइफल्स निम्नलिखित होंगे :-

- (1) असम राइफल्स में नियुक्ति के लिए आफिसर, अधीनस्थ आफिसर तथा अभ्यावेशित व्यक्ति या अभ्यावेशित उनके भर्ती प्ररूप, नियुक्ति पत्र या इस निमित्त बनाए गए नियमों उल्लिखित निबंधन या अभ्यावेशित में निरंतर सेवा के दायी होंगे।

(2) असम राइफल्स में नियुक्त प्रतिनियुक्ति आफिसर तथा अन्य कार्मिक अपनी नियुक्ति पत्र में उल्लिखित निबंधन के अनुसार सेवा करेंगे।

8. बल के कार्य और कमान तथा उस पर नियंत्रण :- (1) धारा 4 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, बल निम्नलिखित कार्य करेगा -

- (i) भारत की सीमाओं की सुरक्षा को सुरक्षित रखना और सीमावर्ती क्षेत्रों में निवास करने वाली जनता में सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना;
- (ii) भारत के राज्य क्षेत्र में अंतर सीमा अपराध, तस्करी, अप्राधिकृत प्रवेश या निकास तथा कोई अन्य अवैध क्रिया कलापों को रोकना;
- (iii) संवेदनशील संस्थापनों, बैंको, सुरक्षा जोखिम व्यक्तियों की सुरक्षा का उपबन्ध करना;
- (iv) किसी क्षेत्र में उपद्रव होने की दशा में वहां व्यवस्था पुनर्स्थापित करना और उसे बनाए रखना।

(2) उपनियम (1) के अधीन कृत्यों के निर्वहन में कमान, अनुशासन, प्रशासन, नैतिकता तथा प्रशिक्षण के लिए उत्तरदायित्व होगा-

(क) अपर महानिदेशक की दशा में, उनके अधीन सभी बटालियनों, यूनिटों के मुख्यालय, स्थापना और बल के कार्मिकों पर विस्तार करना तथा क्षेत्र के भीतर जो उन्हें समनुदेशित किए जा सकते हैं;

(ख) महानिरीक्षक की दशा में, उनके अधीन सभी बटालियनों, यूनिट मुख्यालय, स्थापनाएं और कार्मिक बल पर विस्तार करना तथा क्षेत्र के भीतर जो उन्हें समनुदेशित किए जा सकते हैं;

(ग) उपमहानिरीक्षक और अपर महानिरीक्षक की दशा में उनके अधीन बटालियनों, यूनिटों और अन्य कार्मिकों का विस्तार करना तथा क्षेत्र के भीतर उन्हें समनुदेशित किए जा सकते हैं।

(घ) कमाण्डेंट की दशा में उनके अधीन बटालियन या यूनिट पर विस्तार करना तथा क्षेत्र के अधीन जो उन्हें समनुदेशित किए जा सकते हैं।

(3) संघर्ष के दौरान महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक, अपर महानिरीक्षक और कमाण्डेंट ऐसे कृत्यों का निर्वहन करेंगे जो उन्हें उनके क्रमशः वरिष्ठों द्वारा समनुदेशित किए जाएं।

(4) बटालियन, यूनिटों तथा स्थापनों की कमान, अनुशासन, प्रशासन, नैतिकता तथा प्रशिक्षण जो किसी अपर उपमहानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक या महानिरीक्षक के अधीन न हो कर ऐसे आफिसरों द्वारा और ऐसी रीति में किया जाएगा जो समय-समय पर, महानिदेशक द्वारा अधिकथित किए जाएं।

(5) बल के किसी सदस्य को नियम 8 (1) में उल्लिखित प्रशासन, अनुशासन, प्रशिक्षण तथा बल कल्याण और ऐसे अन्य कृत्यों के लिए तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन निर्वहन को कहा जा सकेगा तो वह बल संबंधी काम में किसी भी कृत्यों को निर्वहन करने का उत्तरदायी होगा। इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी वरिष्ठ आफिसर द्वारा इस निमित्त जारी कोई आदेश विधिपूर्ण होगा।

9. कमान - (1) कमान के लिए नियुक्त कोई आफिसर, उनके अधीनस्थ समस्त कमान आफिसर तथा व्यक्तियों, जेष्ठता का विचार किए बिना उसके कमान के अधीन होंगे।

(2) (क) किसी आकस्मिकता में कोई आफिसर समादेश का प्रयोग करने में असमर्थ रहने पर, जिसके लिए वह नियुक्त किया गया हो, द्वितीय कमान अफसर को कमान न्यायगत हो जाएगी यदि वह इस प्रकार नियुक्त किया गया हो।

(ख) यदि कोई द्वितीय कमान अफसर इस प्रकार नियुक्त न किया गया हो तो यह उस आफिसर को न्यायगत की जाएगी जिसे समादेश का प्रयोग असमर्थ आफिसर करने में के तत्काल वरिष्ठ अधिकारी द्वारा स्थानापन्न करने के लिए नियुक्त किया हो।

(ग) यदि ऐसा आफिसर नियुक्त न किया गया हो तो यह उपस्थित सबसे वरिष्ठ आफिसर को न्यायगत जाएगी।

(घ) कमान का प्रयोग करने में कोई आफिसर की असमर्थता और इस उपबंध के अंतर्गत किसी दूसरे आफिसर द्वारा ग्रहण करने पर तुरंत अपने से ठीक ऊपर प्राधिकारी को उस आफिसर द्वारा रिपोर्ट दी जाएगी जिसने ऐसी कमान ग्रहण की हो।

(3) यदि विभिन्न यूनिटों से संबंधित व्यक्ति एक साथ काम कर रहे हैं:-

(क) उस विनिर्दिष्ट कार्य के संबंध में जिसमें वह लगे हुए हैं, तो कमान के लिए नियुक्त आफिसर व अनुपस्थिति में उपस्थित ठीक वरिष्ठ आफिसर ऐसे समस्त व्यक्तियों पर कमान का प्रयोग करेगा।

(ख) अन्य सभी मामलों में, संबंधित प्रत्येक यूनिट का वरिष्ठ आफिसर अपनी यूनिट के समस्त व्यक्तियों पर कमान का प्रयोग करेगा।

(4) जब बल से संबंधित आफिसरों तथा अन्य व्यक्तियों को किसी शत्रु द्वारा बंदी बना लिया जाता है वरिष्ठ और अधीनस्थ का विद्यमान संबंध और कर्तव्य आज्ञापालन अपरिवर्तित रहेगा तथा इस निमित्त अनुशासनहीनता या अनधीनता का कोई दोषी व्यक्ति अपनी रिहाई के बाद दण्ड का दायी होगा।

(5) अधिनियम के उपबंधों के अधीन, अनुशासनिक शक्तियां अधिनियम के अधीन आफिसर द्वारा जो कमांडेंट रैंक के नीचे का न हो या यूनिट जिसका ऐसा कोई व्यक्ति है कि या आफिसर जिसे उपनियम (2) के अनुसरण में कमान न्यागत की गई हो द्वारा कार्यवाई की जाएगी।

(6) जहां ऐसा कोई व्यक्ति विलग्नता ड्यूटी कर रहा है जिसके अंतर्गत कोई अनुदेश पाठ्यक्रम में उपस्थिति भी है तो ऐसा आफिसर जो यूनिट केन्द्र या स्थापन के कमांडेंट रैंक के नीचे का न हो, उसे कमांडेंट की समस्त अनुशासनिक शक्तियां प्राप्त होंगी जो ऐसी ड्यूटी कर रहा हो।

(7) महानिदेशक, अपर महानिदेशक, महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक तथा अपर उप महानिरीक्षक कर्मचारिवृंद एक या ज्यादा आफिसरों को अपने मुख्यालय में विलग्नता ड्यूटी कर रहे संबंधित व्यक्तियों को विनिर्दिष्ट कर सकते हैं जो क्रमशः कमांडेंट की शक्तियों का प्रयोग कर सकेंगे।

(8) महानिदेशक ऐसे किसी आफिसरों को जो अपने मुख्यालय से संबंधित व्यक्तियों के या विलग्नता ड्यूटी कर रहे व्यक्तियों के संबंध में क्रमशः महानिरीक्षक और उपमहानिरीक्षक या अपर महानिरीक्षक की अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

(9) महानिरीक्षक ऐसी किसी आफिसर को जो अपने मुख्यालय से संबंधित व्यक्तियों का विलग्नता ड्यूटी कर रहे व्यक्तियों के संबंध में हैं जो क्रमशः उपमहानिरीक्षक या अपर महानिरीक्षक की अनुशासनिक शक्तियों का प्रयोग करने के लिए विनिर्दिष्ट कर सकेगा।

स्पष्टीकरण - उपनियम (1), (2) और (3) उपबंधों में "आफिसर" शब्द के अंतर्गत अधीनस्थ आफिसर तथा अधीन आफिसर भी सम्मिलित है।

अध्याय - 3

भर्ती

10. अपात्रता:-

(1) कोई व्यक्ति, जिसकी एक से अधिक जीवित पत्नी हैं या जिसने किसी दशा में, अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी दशा में विवाहित पत्नी या पति के होते हुए जिसमें ऐसी विवाहित पत्नी या पति के जीवित रहते हुए किन्ही कारण घटना होने पर विवाह करता है जिससे ऐसा विवाह शून्य होगा वह बल में नियुक्ति, भर्ती तथा रोजगार के लिए पात्र होगा।

(2) अधिनियम के अधीन यदि कोई व्यक्ति अपने पहले पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह विवाह या करता है तो स्वयं को सेवा में रखने के अयोग्य बना देगा और अनुपयुक्तता के आधार पर सेवा से पदच्युत, हटा दिया, निष्काषित या निवृत्त किया जा सकेगा।

परंतु केन्द्रीय सरकार का यदि समाधान हो जाता है कि ऐसा करने के समुचित आधार हैं तो इस नियम के कार्यान्वयन से किसी व्यक्ति को छूट दे सकेगी।

11. **अन्यदेशीय की अपात्रता :** कोई व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है, केन्द्रीय सरकार की लिखित रूप में संज्ञापित सम्मति के सिवाए बल में नियोजन, नियुक्ति या अभ्यावेशन नहीं किया जाएगा।

परंतु इस नियम में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, बल में नेपाल या भूटान की प्रजा को नियुक्ति, अभ्यावेशन या नियोजन को वर्जित नहीं करेगी।

12. **आफिसरों की नियुक्ति:** केन्द्रीय सरकार निम्नलिखित रीति में बल में ऐसे व्यक्तियों को जिसे आफिसरों के रूप में उभययुक्त समझे नियुक्ति कर सकेगी और उनकी सेवा शर्तें इस प्रकार होंगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा इसे विभिन्न बनाए गए नियमों में उपबंधित कि जाए:-

(क) सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) रक्षा बलों, संघ की कोई अन्य सशस्त्र बल या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी अन्य विभाग से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा;

(ग) समय-समय पर यथा विहित पदोन्नति द्वारा;

(घ) स्थानांतरण द्वारा;

(ङ) पुनर्नियोजन द्वारा।

13. अधीनस्थ आफिसरों और अभ्यावेशित व्यक्तियों की नियुक्ति — सूबेदार मेजरों या सूबेदारों के पदों की नियुक्ति महानिरीक्षक द्वारा और नायब सूबेदार या अधीन आफिसरों को उपमहानिरीक्षक या अपर महानिरीक्षक द्वारा तथा अभ्यावेशित व्यक्तियों को कमांडेंट या बल के अन्य किसी आफिसर द्वारा जिसे निम्नलिखित रीति में महानिदेशक द्वारा क्रमशः नियुक्ति किया जा सकेगा और उनकी सेवा की शर्तें इस प्रकार हो सकेंगी जो इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा इन नियमों में उपबोधित की जाए—

(क) सीधी भर्ती द्वारा;

(ख) संघ के रक्षा बलों और अन्य सशस्त्र बलों केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अन्य किसी विभाग से प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा;

(ग) समय-समय पर यथा विहित प्रोन्नति द्वारा;

(घ) स्थानांतरण द्वारा;

(ङ) पुनर्नियोजन द्वारा।

14. परिवीक्षा

(1) किसी अधीनस्थ आफिसर या अभ्यावेशित व्यक्ति के रूप में सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त कोई व्यक्ति, दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेगा।

(2) आफिसरों की दशा में केन्द्रीय सरकार और अधीनस्थ आफिसरों तथा अभ्यावेशित व्यक्तियों की दशा में नियम 13 में विहित प्राधिकारी, कारणों को लेखबद्ध करते हुए ऐसी और अवधि के लिए या दो वर्ष से अनधिक अवधि के लिए या परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकेंगी या परिवीक्षा के दौरान बिना कारण बताए उसकी सेवाएं समाप्त कर सकेंगी।

(3) उपनियम (1) और उपनियम (2) के उपबंध किसी व्यक्ति पर उसकी एक आफिसर के रूप में उसकी प्रारम्भिक पदोन्नति पर भी लागू होंगे। वे व्यक्ति जो अपनी परिवीक्षा की अवधि संतोषजनक पूर्ण नहीं करते हैं तो वे अपने पूर्व रैंक में प्रतिवर्तित होने के दायी होंगे।

15. अभ्यावेशन की प्रक्रिया, अभ्यावेशन की रीति और इससे संबंधित अन्य विषय—

(1) कोई व्यक्ति जो बल में एक सदस्य के रूप में अभ्यावेशित होने के पहले, यूनिट का कमांडेंट या अन्य कोई आफिसर जिसे महानिदेशक द्वारा अभ्यावेशन आफिसर के रूप में नियुक्त किया हो, उसे सेवा की वे शर्तें जिन पर उसे अभ्यावेशित किया जाना है, उसे पढ़कर सुनाएगा और उसे समझाएगा या अपनी उपस्थिति में पढ़वाकर सुनवाएगा और उसे समझवाएगा तथा अभ्यावेशन के प्ररूप परिशिष्ट-1 में अभिकथित के रूप में अभ्यावेशन प्ररूप में समाविष्ट प्रश्न उससे पूछेगा और उसे इस बात से सावधान करने के पश्चात् कि यदि वह ऐसे किसी प्रश्न का मिथ्या उत्तर देगा तो वह इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय होगा, ऐसे हर प्रश्न का उसका उत्तर अभिलिखित करेगा या अभिलिखित कराएगा।

(2) यदि उपनियम (1) के उपबंधों के अनुपालन के पश्चात् और समय-समय पर महानिदेशक द्वारा इस निमित्त जारी ऐसे अन्य निदेशों के पश्चात् अभ्यावेशन आफिसर का समाधान हो जाता है, भर्ती का इच्छुक व्यक्ति उससे पूछे गए प्रश्नों को पूर्णतया समझता है और सेवा की शर्तों के बारे में अपनी सहमति देता है और यदि ऐसे अधिकारी को कोई अडचन जान नहीं पड़ती तो वह अभ्यावेशन पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और उस व्यक्ति से भी कराएगा और तदुपरांत वह व्यक्ति अभ्यावेशित हो गया समझा जाएगा।

(3) (क) उपनियम (2) के अधीन बल के सदस्य के रूप में अभ्यावेशित प्रत्येक व्यक्ति को परिशिष्ट-1 में दिए गए प्ररूप में शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा।

(ख) जहां तक संभव हो, शपथ या प्रतिज्ञान ऐसे किसी आफिसर द्वारा जो कमांडेंट रैंक के नीचे का नहीं होगा या इस निमित्त प्राधिकृत ऐसे आफिसर द्वारा लिखित में प्राधिकृत ऐसे आफिसर द्वारा दिलाई जाएगी।

(ग) अनुप्रमाणन के लिए व्यक्ति को शपथ या अभिज्ञान उस समय कराया जाएगा जब उसने अपना प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया हो तथा सभी प्रकार से योग्य हो।

16. सेवा के दायित्व

(1) केन्द्रीय सरकार द्वारा निदेश पर सभी आफिसर संघ के किसी अन्य सशस्त्र बल के साथ सेवा के लिए दायी होंगे। ऐसी सेवा के लिए आफिसरों के चयन में सभी स्वयंसेवकों को प्राथमिकता दी जा सकेगी लेकिन यदि योग्य स्वयंसेवकों की अपेक्षित संख्या उपलब्ध नहीं है तो आफिसरों को प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण या अन्यथा केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझें कर सकती है।

(2) इस नियम के उपबंध, अधीनस्थ आफिसरों तथा अभ्यावेशित व्यक्तियों के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार बल के किसी आफिसर के संबंध में और पर लागू होते हैं तथा केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग महानिदेशक उपनियम (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करेगा।

अध्याय - 4

सेवा समाप्ति

17. सेवा समाप्ति - नीचे दी गई सारणी के स्तंभ उसे 6 शीर्षों में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी इस अध्याय में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार, स्तंभ-2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में कथित आधार पर स्तंभों में विनिर्दिष्ट बल के किसी सदस्य को बर्खास्त, निष्कासित, सेवामुक्त, सेवानिवृत्त या निर्गुक्त करने के लिए सक्षम होंगे। उससे उच्चतर कोई अन्य प्राधिकारी किसी भी उपर्युक्त प्राधिकारियों पर इस नियम या इस अध्याय के किसी भी उपबंधों द्वारा प्रदत्त किसी भी शक्ति का प्रयोग कर सकेगा।

परंतु इस अध्याय के उपबंध बल में प्रतिनियुक्त हुए व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे।

सारणी

क्र०सं०	जिस आधार पर सेवा पर्यावसन किया जा सकेगा	केन्द्रीय सरकार	महानिरीक्षक	उपमहानिरीक्षक / अपर उपमहानिरीक्षक	कमांडेंट
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i)	कदाचार	आफिसर	सूबेदार मेजर और सूबेदार	नायब सूबेदार	अभ्यावेशित व्यक्ति
(ii)	अनुपयुक्तता	आफिसर	सूबेदार मेजर और सूबेदार	नायब सूबेदार	अभ्यावेशित व्यक्ति
(iii)	प्रशिक्षण में असंतोषजनक प्रगति	आफिसर	सूबेदार मेजर और सूबेदार	नायब सूबेदार	अभ्यावेशित व्यक्ति
(iv)	नियुक्ति/अभ्यावेशन के समय मिथ्या/ गलत सूचना देना	आफिसर	सूबेदार मेजर और सूबेदार	नायब सूबेदार	अभ्यावेशित व्यक्ति
(v)	शारीरिक अयोग्यता	आफिसर	सूबेदार मेजर और सूबेदार	नायब सूबेदार	अभ्यावेशित व्यक्ति
(vi)	स्वयं के अनुरोध पर	आफिसर	सूबेदार मेजर और सूबेदार	नायब सूबेदार	अभ्यावेशित व्यक्ति

18. केन्द्रीय सरकार द्वारा कदाचार के कारण आफिसरों की सेवा की समाप्ति -

(1) जब धारा 10 के अधीन किसी आफिसर की सेवा को कदाचार के कारण समाप्त करने का प्रस्ताव किए जाने पर उसे किसी कार्रवाई के विरुद्ध उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति में कारण बताने का अवसर दिया जाएगा।

परंतु यह उपनियम निम्नलिखित को लागू नहीं होगा :-

(क) जहां उसकी सेवा उस आचरण के आधार पर समाप्त की जाती है, जिस आचरण पर दण्ड न्यायालय या बल न्यायालय ने उसे दोषासिद्ध ठहराया है; या

(ख) जहां केन्द्रीय सरकार का समाधान हो गया है कि आफिसर को कारण बताने का अवसर देना समीचीन या युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है, के लिए ऐसे कारण को लेखबद्ध किया जाएगा।

(2) जब किसी आफिसर के कदाचार की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात्, केन्द्रीय सरकार या महानिदेशक का समाधान हो जाता है कि बल न्यायालय द्वारा आफिसर का विचारण असमीचीन या अव्यवहार्य है, किन्तु उसकी यह राय है कि उक्त आफिसर को सेवा में आगे प्रतिधारण करना अवांछनीय है तो महानिदेशक, आफिसर को अधिकथनों की विशिष्टियों तथा अन्वेषण की रिपोर्ट के साथ जिसके अंतर्गत साक्षियों का कथन, यदि कोई हो, उसके विरुद्ध उपयोग करने के आशय से लेखबद्ध किए गए हों या दस्तावेजों की प्रतियां भी हैं उन मामलों में जहां अभिकथनों का अन्वेषण किया गया हो, सूचित करेगा और उससे लिखित में अपना स्पष्टीकरण और प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।

परंतु महानिदेशक की अपनी राय में, यदि किसी ऐसी रिपोर्ट या उसके भाग का प्रकटीकरण राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है तो वह उसे प्रकट नहीं करेगा।

(3) महानिदेशक द्वारा यदि आफिसर का स्पष्टीकरण, असमाधानप्रद होने की दशा में, या जब केन्द्रीय सरकार द्वारा ऐसा निदेश दिया जाए, तब मामले, को आफिसर की प्रतिरक्षा और महानिदेशक की आफिसर की सेवा की समाप्ति के बारे में सिफारिश सहित उपनियम (4) से विनिर्दिष्ट रीति से, केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा।

(4) जब कोई मामला उपनियम (2) या उपनियम (3) के उपबंधों के अधीन केन्द्रीय सरकार को भेजा जाता है महानिदेशक अपनी सिफारिश में कारण देगा कि क्या आफिसर की सेवा समाप्ति की जानी चाहिए या नहीं यदि हाँ तो क्या आफिसर:-

(क) आफिसर को सेवा से पदच्युत किया जाना चाहिए; या

(ख) आफिसर को सेवा से हटाया जाना चाहिए; या

(ग) आफिसर को सेवा से अनिवार्य सेवा निवृत्त किया जाना चाहिए; या

(घ) आफिसर से पद त्याग की अपेक्षा की जानी चाहिए।

5. केन्द्रीय सरकार, रिपोर्टों और आफिसर की प्रतिरक्षा, यदि कोई हो, या यथास्थिति दंड न्यायालय का निर्णय या बल न्यायालय की और महानिदेशक की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात्, आफिसर से सेवा निवृत्त होने या पद त्याग करने की अपेक्षा कर सकेगी और उसके ऐसे इंकार करने पर उसे अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त या सेवा से हटाया जा सकेगा।

19. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुपयुक्तता के आधार पर आफिसरों की सेवा की समाप्ति —

(1) जब महानिदेशक का समाधान हो जाता है कि सेवा में बने रहने के अनुपयुक्त है, तो आफिसर—

(क) आफिसर को यह जानकारी दी जाएगी;

(ख) आफिसर को उसके प्रतिकूल सभी मामलों की विशिष्टियाँ दी जाएंगी; और

(ग) आफिसर से यह अपेक्षा की जाएगी कि सेवा में उसे रखे जाने के पक्ष में जो भी कारण बताना चाहता है, उन्हें भेजे।

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि उनके उपबन्धों का अनुपालन करने के लिए ऐसे कारणों के, जो लेखबद्ध किए जाएंगे समीचीन युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं हैं तो खण्ड (क), खंड (ख) और (ग) लागू नहीं होंगे।

परन्तु यह और कि यह महानिदेशक, आफिसर को उसके प्रतिकूल कोई सामग्री देने से इंकार कर सकेगा यदि उसकी राय में सामग्री देना राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है।

(2) यदि महानिदेशक द्वारा स्पष्टीकरण पर विचार करने पर असमाधानप्रद होने की दशा में, तो आफिसर के स्पष्टीकरण और महानिदेशक की इस सिफारिश के साथ कि क्या आफिसर से सेवा निवृत्त होने की अपेक्षा की जानी चाहिए या ऐसे पदत्याग की अपेक्षा की जानी चाहिए, मामला केन्द्रीय सरकार को भेजा जाएगा।

(3) केन्द्रीय सरकार रिपोर्टों, आफिसर के स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, और महानिदेशक की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात्, आफिसर से सेवानिवृत्त होने या पदत्याग करने की अपेक्षा कर सकेगी और उसके ऐसा करने से इंकार करने पर आफिसर का अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया जा सकेगा या सेवा से हटाया जा सकेगा।

20. कदाचार के आधार पर आफिसरों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों की सेवा से समाप्ति —

(1) अधिनियम के अधीन किसी आफिसर से भिन्न किसी व्यक्ति की सेवा समाप्त करने का प्रस्ताव किए जाने पर उसे ऐसी कार्यवाई करने के विरुद्ध उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट रीति में कारण बताने का अवसर दिया जाएगा:

परन्तु यह उपनियम निम्नलिखित को लागू नहीं होगा :—

(क) जहां सेवा उस आचरण के आधार पर समाप्त की जाती है, जिस आधार पर दण्ड न्यायालय या बल न्यायालय ने उसे सिद्धदोष ठहराया है; या

(ख) जहां नियम 17 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसे कारण जो लेखबद्ध किए जाएंगे, व्यक्ति को कारण दर्शित करने का अवसर देना समीचीन या युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है।

(2) जब संबंधित व्यक्ति की कदाचार की रिपोर्टों पर विचार करने के पश्चात्, नियम 17 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि बल न्यायालय द्वारा ऐसे किसी व्यक्ति का विचारण असमीचीन या अव्यवहार्य है, किन्तु उसकी यह राय है कि उक्त व्यक्ति का सेवा में आगे प्रतिधारण अवांछनीय है, तो यह उसे उसकी समस्त प्रतिकूल रिपोर्टों के साथ सूचित करेगा और उससे लिखित रूप में अपना स्पष्टीकरण और प्रतिरक्षा प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाएगी।

परन्तु नियम 17 में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की राय में यदि किसी ऐसी रिपोर्ट या उसके भाग का प्रकटीकरण राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है तो वह उसका प्रकटन से रोक देगा।

(3) नियम 17 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी उसके स्पष्टीकरण और प्रतिरक्षा, यदि कोई हो, या यथास्थिति, दंडिक न्यायालय का निर्णय या बल न्यायालय की कार्यवाही विचार करने के पश्चात् उसे सेवा से बर्खास्त या सेवा से हटा सकेगा।

(4) इस नियम के अधीन, बर्खास्तगी या निष्कासन के सभी मामले महानिदेशक को रिपोर्ट किए जाएंगे।

21. प्रशिक्षण में असंतोषजनक प्रगति के आधार पर सेवा से सेवामुक्ति करना —

(1) अधिनियम के अधीन जब किसी व्यक्ति को प्रशिक्षण में असंतोषजनक प्रगति के कारण सेवामुक्त करने का प्रस्ताव किया जाता है, प्रशिक्षण स्थापन का कमांडेंट, जहां पर व्यक्ति प्रशिक्षण कर रहा है, उस संबंधित यूनिट या बटालियन के कमांडेंट से उपयुक्त कार्यवाई के लिए सिफारिश करेगा जिससे ऐसा व्यक्ति है उसे सेवामुक्त किया जाएगा।

(2) प्रशिक्षण स्थापन कमांडेंट किसी व्यक्ति की सेवामुक्त की सिफारिश के सभी मामलों में, तथ्य स्पष्ट प्रमाणित करेगा कि उक्त व्यक्ति को प्रगति दिखाने के लिए उपयुक्त चेतावनी तथा पर्याप्त समय दिया गया है, इस संबंध में दस्तावेजी साक्ष्य सिफारिश के साथ होगी।

(3) उपनियम (1) के अधीन सिफारिश के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या नियम 17 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी संबंधित व्यक्ति को सेवा से सेवान्मुक्त या निर्मुक्त कर सकता है।

22. नियुक्ति या अभ्यावेशन के समय मिथ्या या गलत सूचना देने के आधार पर सेवा की समाप्ति— यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या नियम 17 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, किसी व्यक्ति को जिसने सेवा में आने के लिए नियुक्ति या अभ्यावेशन के समय गलत या मिथ्या सूचना देने के आधार पर इस अधिनियम के अधीन सेवा से हटाया जा सकेगा।

परन्तु इस नियम के अधीन कोई कार्यवाई सक्षम प्राधिकारी द्वारा, संबद्ध व्यक्ति को कारण बताओ नोटिस देने के एक मास के समय में अपनी प्रतिरक्षा में, यदि कोई हो, आधार बताने के लिए दिए बिना और उसे असमाधान प्रद पाए जाने पर, की जाएगी।

23. शारीरिक अस्वस्थता के आधार पर आफिसरों की निर्मुक्ति या सेवान्मुक्ति या सेवानिवृत्ति—

(1) जहां उपमहानिरीक्षक से निम्न रैंक का कोई आफिसर यह समझता है कि बल का कोई आफिसर अपनी शारीरिक दशा के कारण अपने कर्तव्यों का निर्वहन में अनुपयुक्त है तो आफिसर को किसी चिकित्सा बोर्ड के सामने प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) चिकित्सा बोर्ड ऐसे आफिसरों से मिलकर बनेगा तथा ऐसी रीति से गठन किया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा समय-समय पर अभिकथित की जाए।

(3) जहां चिकित्सा बोर्ड द्वारा किसी आफिसर को आगे सेवा करने में अनुपयुक्त पाया जाता है वहां केन्द्रीय सरकार यदि चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्ष से यदि सहमत हो तो बोर्ड के चिकित्सीय निष्कर्ष से उक्त आफिसर को संसूचित करेगी और तत्पश्चात् ऐसी संरचना के तीस दिन की अवधि के भीतर, चिकित्सा बोर्ड द्वारा मत में दिए गए गलत निर्णय के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के समर्थन से केन्द्रीय सरकार को इसके विरुद्ध प्रतिवेदन दे सकेगा। ऐसा कोई साक्ष्य सिविल सर्जन की हैसियत से अन्तून सरकारी चिकित्सक होना चाहिए कि उसे अपना मत प्रस्तुत करने से पूर्व चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्षों पर विचार किया गया है।

(4) केन्द्रीय सरकार, उस आफिसर से प्राप्त होने वाले प्रतिवेदन के पश्चात् मामले को इस प्रयोजन के लिए गठित नए चिकित्सा बोर्ड पुनर्विलोकन करवाने के लिए निर्दिष्ट कर सकेगी और यदि नया चिकित्सा बोर्ड का निर्णय उसके विपरीत है तो उक्त आफिसर की सेवानिवृत्ति या सेवान्मुक्ति या निर्मुक्ति का आदेश दे सकती है।

(5) जहां उपनियम (3) के अधीन चिकित्सा बोर्ड के विनिश्चय के विरुद्ध कोई प्रतिवेदन नहीं दिया जाता है यदि केन्द्रीय सरकार, चिकित्सीय बोर्ड के निष्कर्ष से सहमत हो जाती है तो उक्त आफिसर की सेवानिवृत्ति या सेवान्मुक्ति या निर्मुक्ति का आदेश दे सकती है।

24. अनुपयुक्तता के आधार पर नियम 17 में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा अधीनस्थ आफिसरों के सेवा समाप्ति —

(1) जहां कोई आफिसर जो कमांडेंट रैंक से अन्यून हो, का यह समाधान हो जाता है कि कोई अधीनस्थ आफिसर सेवा में बने रहने में अनुपयुक्त है तो अधीनस्थ आफिसर;

(क) अधीनस्थ आफिसर को इस बात की सूचना दी जाएगी

(ख) अधीनस्थ आफिसर के विरुद्ध सभी मामलों की विशिष्टियों सहित उसे दिया जाएगा; और

(ग) अधीनस्थ आफिसर से यह अपेक्षा की जाएगी कि सेवा में उसे रखे रहने के पक्ष में जो भी कारण बताना चाहता है, उन्हें दें;

परन्तु यदि नियम 17 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी का समाधान हो जाता है कि ऐसे कारण से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, खंड (क), खंड (ख) और खंड (ग) संबंध का अनुपालन करना समीचीन या अनुचितमुक्त व्यवहार्य नहीं है तो लागू नहीं होंगे।

परन्तु यह और कि ऐसा सक्षम प्राधिकारी को उसके प्रतिकूल कोई सामग्री को अधीनस्थ आफिसर को देने से इंकार कर सकेगा यदि, उसकी राय में सामग्री देना राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है।

(2) यदि कमांडेंट रैंक से अन्यून रैंक का आफिसर द्वारा स्पष्टीकरण को असमाधानप्रद होने की दशा में अधीनस्थ आफिसर के स्पष्टीकरण तथा ऐसे आफिसर की इस सिफारिश सहित मामला को नियम 17 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को भेजा जाएगा।

(3) नियम 17 में यथाविहित प्राधिकारी रिपोर्टों और अधीनस्थ आफिसर के स्पष्टीकरण यदि कोई हो, और कमांडेंट रैंक से अन्यून आफिसर की सिफारिश पर विचार करने के पश्चात् अधीनस्थ आफिसर से सेवानिवृत्त होना या पद त्याग करने की अपेक्षा कर सकेगा और उसके ऐसा करने से इंकार करने पर अधीनस्थ आफिसर को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया जा सकेगा या सेवा से निर्मुक्त किया जा सकेगा।

25. अभ्यावेशित व्यक्ति की अनुपयुक्तता के आधार पर सेवा समाप्ति :

(1) जहां किसी कमांडेंट का समाधान हो जाता है कि भर्ती किए गए व्यक्ति को सेवा में रखे रहना अनुपयुक्त है तो —

(क) अभ्यावेशित व्यक्ति को यह सूचना दी जाएगी;

(ख) अभ्यावेशित व्यक्ति के विरुद्ध सभी मामलों की विशिष्टियों सहित उसे दिया जाएगा; और

(ग) अभ्यावेशित व्यक्ति से यह अपेक्षा की जाएगी कि सेवा में उसे रखे रहने के पक्ष में जो भी कारण बताना चाहता है, उन्हें दें :

परंतु यदि कमांडेंट का समाधान हो जाता है कि खण्ड (क), खंड (ख) एवं खंड के उपबंधों का अनुपालन करना समीचीन या युक्तियुक्त रूप से व्यवहार्य नहीं है, ऐसे कारणों से जो लेखबद्ध किए जाएंगे, लागू नहीं होंगे।

परंतु यह और कि कमांडेंट, व्यक्ति को उसके प्रतिकूल कोई सामग्री देने से इंकार कर सकेगा है, यदि उसकी राय में सामग्री देना राज्य की सुरक्षा के हित में नहीं है।

(2) कमांडेंट, अभ्यावेशित व्यक्ति के स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् अभ्यावेशित व्यक्ति से सेवा निवृत्त होने या पद त्याग करने की अपेक्षा कर सकेगा और उसके ऐसा करने के लिए इंकार करने पर उसे अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकेगा या सेवा से निर्युक्त किया जा सकेगा।

26. अधीनस्थ आफिसरों का अभ्यावेशित व्यक्तियों की शारीरिक अस्वस्थता के आधारपर सेवानिवृत्ति या सेवानुक्ति -

(1) जहां किसी कमांडेंट का समाधान हो जाता है कि अधीनस्थ आफिसर या अभ्यावेशित व्यक्ति अपनी शारीरिक असमर्थता के कारण अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में असक्षम है तो वह निदेश दे सकता है कि यथास्थिति, उक्त अधीनस्थ आफिसर या अभ्यावेशित व्यक्ति को किसी चिकित्सा बोर्ड सम्मुख प्रस्तुत किया जाए।

(2) चिकित्सा बोर्ड ऐसे आफिसरों से मिल कर बनेगा तथा ऐसी रीति से गठित किया जाएगा जो महानिदेशक द्वारा समय-समय पर अधिकथित की जाए।

(3) जहां चिकित्सा बोर्ड द्वारा यथास्थिति उक्त अधीनस्थ आफिसर का अभ्यावेशित व्यक्ति को बल में आगे की सेवा करने में अनुपयुक्त पाया जाता है, तो नियम 17 में यथा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी यदि चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्ष से सहमत हो जाता है तो वह उक्त व्यक्ति को चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्ष को संसूचित करेगा और तत्पश्चात् ऐसी संसूचना के तीस दिनों की अवधि के भीतर व्यक्ति चिकित्सा बोर्ड द्वारा इस मत में दिए गए गलत निर्णय के प्रथम दृष्टया साक्ष्य के समर्थन से सक्षम प्राधिकारी को इसके विरुद्ध प्रतिवेदन दे सकेगा। ऐसा कोई साक्ष्य, सिविल सर्जन की हैसियत से अन्यून किसी सरकारी चिकित्सक से होना चाहिए और विशेष उल्लेख होना चाहिए कि उसके अपना राय देने से पहले चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्षों पर विचार किया गया है।

(4) जहां, व्यक्ति को आगे सेवा के लिए अनुपयुक्त घोषित कर दिया गया हो तो वह उपनियम (3) के अधीन प्रतिवेदन करता है और उसे ठीक वरिष्ठ आफिसर को देगा। यदि नए चिकित्सा बोर्ड का निर्णय उसके प्रतिकूल है तो वरिष्ठ आफिसर इस उद्देश्य के लिए गठित नए चिकित्सा बोर्ड द्वारा मामले की समीक्षा करवाएगा और उक्त व्यक्ति को सेवानिवृत्ति या सेवानुक्ति का आदेश दे सकता है।

(5) यथास्थिति जहां उपनियम (3) के अधीन चिकित्सा बोर्ड के विनिश्चय विरुद्ध कोई प्रतिवेदन नहीं दिया जाता है तो नियम 17 में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी (यदि वह चिकित्सा बोर्ड के निष्कर्ष से सहमत हो) यथास्थिति संबंधित व्यक्ति को सेवानिवृत्ति या सेवानुक्ति का आदेश दे सकेगा।

27. त्यागपत्र -

(1) केन्द्रीय सरकार, किसी मामले की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, बल के किसी आफिसर को वचनबंध की शर्तों के अनुपालन से पहले बल से पद त्याग की अनुज्ञा दे सकती है।

परंतु केन्द्रीय सरकार ऐसी अनुज्ञा प्रदान करने से पहले आफिसर से उसके द्वारा आहरित तीन मास के वेतन और भत्ते इसमें से जो अधिक हो सरकार को वापस करने की अपेक्षा कर सकेगी या उसके प्रशिक्षण में व्यय को वापस करने की अपेक्षा कर सकेगी,।

(2) केन्द्रीय सरकार, उपनियम (1) के अधीन ऐसी तारीख से प्रभावी त्यागपत्र स्वीकार कर सकेगी जिसे वह समीचीन समझे।

(3) केन्द्रीय सरकार, ऐसे किसी आफिसर को उस स्थिति में त्यागपत्र देने की अनुज्ञा देने से इन्कार कर सकेगी :-

(क) यदि आन्तरिक उपद्रव या वाहय आक्रमण के कारण देश में आपात काल की घोषणा कर दी गई हो; या

(ख) यदि बल में अनुशासन के हित में ऐसा किया जाना असमीचीन समझा जाए; या

(ग) यदि आफिसर ने उस विनिर्दिष्ट निश्चित अवधि के लिए सेवा करने का विशेष रूप से वचनबंध दिया हो और वह अवधि समाप्त न हुई हो।

(4) इस नियम के उपबंध उन अधीनस्थ आफिसर और अभ्यावेशित व्यक्तियों पर उसी प्रकार लागू होंगे, जिस तरह से ये इस बल के किसी आफिसर पर लागू होते हैं और उप-नियम (1) और उपनियम (2) के अधीन केन्द्रीय सरकार में निहित शक्तियों का प्रयोग, किसी सूबेदार मेजर और सूबेदार के मामले में महानिरीक्षक द्वारा, किसी नायब सूबेदार के मामले में ऐसे किसी आफिसर द्वारा, जो अपर उप महानिरीक्षक के रैंक से कम का न हो, और अभ्यावेशित व्यक्तियों के मामले में कमांडेंट द्वारा किया जाएगा।

28. पदच्युति, निष्कासन या अनिवार्य सेवा निवृत्ति के आदेश के विरुद्ध अपील :-

(1) इस अधिनियम के अधीन, किसी आफिसर से भिन्न, कोई व्यक्ति, जिसे सेवा से पदच्युत किया जाता है, निष्कासित किया जाता है या वह अनिवार्य रूप से सेवा से निवृत्त होता है, उसे किसी प्राधिकारी, जो उस आफिसर से उच्च है, जिसने सेवा समाप्ति आदेश परित किया हो, के समक्ष अपनी सेवा समाप्ति के विरुद्ध सेवा समाप्ति के नब्बे दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार होगा।

(2) आफिसरों के मामले में अपील केन्द्रीय सरकार को की जाएगी और ऐसी अपील सेवा समाप्ति के नब्बे दिन के भीतर फाइल की जाएगी।

(3) जहां अपील प्राधिकारी इस नियम के अधीन पदच्युति, निष्कासन या अनिवार्य सेवानिवृत्ति के आदेश को रद्द कर देता है तो ऐसा प्राधिकारी उस व्यक्ति, जिसकी पदच्युति, निष्कासित या अनिवार्य सेवा निवृत्ति को अपास्त (रद्द) कर दिया गया हो, की इयूटी से अनुपस्थित रहने की अवधि के बारे में ऐसा आदेश, जिसे वह जरूरी समझे, पारित कर सकेगा।

29. पदच्युत, निलम्बन, निर्मुक्ति या सेवानिवृत्ति की तारीख:-

(1) पदच्युत, निलम्बन या सेवा निवृत्ति की प्रभावी तारीख निम्न होगी:-

(क) पदच्युत या निलम्बन या निर्मुक्ति या सेवा-निवृत्ति के आदेश में उल्लिखित तारीख; या

(ख) यदि ऐसी किसी तारीख का उल्लेख न हो तो संबंधित व्यक्ति को इयूटी से कार्यमुक्त करने की तारीख।

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति की पदच्युति, निष्कासन निर्मुक्ति या सेवा निवृत्ति भूतलक्षी प्रभाव से लागू नहीं होगी।

अध्याय - 5

नौलिक अधिकारों पर निर्बंधन

30. अप्राधिकृत संगठन :- इस अधिनियम के अधीन, कोई व्यक्ति केन्द्रीय सरकार की स्पष्ट मंजूरी के बिना किसी सोसाइटी, संस्था या संगठन, जो संघ के शास्त्र बलों के भाग के रूप में मान्यता प्राप्त न हो, में तब तक शासकीय संज्ञान नहीं लेगा या सहायता नहीं करेगा या उसमें सक्रिय हिस्सेदारी नहीं लेगा, जब तक कि वह आनन्द-प्रमोद या धार्मिक प्रकृति का न हो, जिसमें वरिष्ठ आफिसर की लिखित रूप में स्वीकृति प्राप्त करनी जरूरी हो।

31. राजनैतिक किया-कलाप:-

(1) इस अधिनियम के अधीन, कोई व्यक्ति किसी दल या राजनैतिक प्रयोजनों के लिए आयोजित किसी अधिवेशन या प्रदर्शन में उपस्थित नहीं होगा या उसे संबोधित नहीं करेगा या उसमें भाग नहीं लेगा या किसी राजनैतिक संगम या आन्दोलन का सदस्य नहीं होगा या उसमें सम्मिलित नहीं होगा या उसकी सहायता चंदा नहीं देगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन, कोई व्यक्ति निर्वाचकों को संबोधित नहीं करेगा या किसी अन्य रीति से संसद, किसी राज्य के विधान मण्डल, या किसी स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य स्थानीय निकाय के निर्वाचन के लिए स्वयं को अभ्यर्थी या भावी अभ्यर्थी के रूप में सार्वजनिक रूप से घोषित नहीं करेगा या किसी अभ्यर्थी के हितों का किसी भी तरह से सक्रिय रूप से अभिवृद्धि नहीं करेगा।

32. प्रेस को सूचनाएं, व्याख्यान आदि-इस अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति -

(क) ऐसी कोई सामग्री, जो किसी राजनीतिक प्रश्न या सेवा से विषय से संबंधित हो या जिसमें किसी सेवा से संबंधित कोई सूचना निहित हो, किसी भी रूप में, प्रकाशित नहीं करेगा अथवा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रेस को सूचित नहीं करेगा, अथवा ऐसे विषय या मामले से संबंधित किसी पुस्तक या पत्र या लेख या कोई अन्य दस्तावेज या इससे संबंधित कोई सूचना केन्द्रीय सरकार, या इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी अन्य आफिसर की पूर्व मंजूरी के बिना प्रकाशित नहीं करेगा या प्रकाशित नहीं करवाएगा।

(ख) राजनीतिक प्रश्न से संबंधित किसी मामले या सेवा से संबंधित किसी विषय या किसी सूचना से संबंधित मामले पर केन्द्रीय सरकार, या इस निमित्त केन्द्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किसी आफिसर की पूर्व मंजूरी के बिना कोई व्याख्यान नहीं देगा या बतार सूचना नहीं भेजेगा या सेवा से संबंधित किसी विषय पर अपने विचार नहीं देगा।

स्पष्टीकरण:- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, "सेवा सूचना" और "सेवा विषय" पद में इस बल, रक्षा अथवा संघ के विदेशी संबंधों से संबंधित यथास्थिति, सूचना या विषय, सम्मिलित होंगे।

अध्याय - 6

गिरफ्तारी और निलंबन

33. गिरफ्तारी के प्रारूप :-

(1) गिरफ्तारी या तो खुली गिरफ्तारी या बंद गिरफ्तारी हो सकेगी।

(2) कोई गिरफ्तारी जब तक अन्यथा विनिर्दिष्ट न हों, से खुली गिरफ्तारी अभिप्रेत होगी।

(3) गिरफ्तारी अधिरोपित करने का आदेश गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को मौखिक या लिखित रूप से संसूचित किया जा सकेगा।

34. गिरफ्तारी का आदेश देने का प्राधिकार:-

(1) इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को वरिष्ठ आफिसर, जिसे उस व्यक्ति पर अधिनियम के अधीन कमान करने की शक्ति है, के आदेशों के अधीन और उनके आदेशों के अनुसार के सिवाय किसी आरोप के आधार पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।

(2) उप नियम (1) में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को किसी वरिष्ठ आफिसर द्वारा निम्नलिखित स्थितियों में गिरफ्तार किया जा सकेगा:-

(क) यदि वह ऐसे वरिष्ठ आफिसर के विरुद्ध अपराध करता है; या

(ख) यदि वह ऐसे वरिष्ठ आफिसर की राय में अपराध करता है; या

(ग) यदि वह विच्छिन्न रीति में व्यवहार कर रहा हो और उक्त वरिष्ठ आफिसर ऐसे व्यक्ति को, उसके ऐसे विच्छिन्न व्यवहार को रोकने के लिए, गिरफ्तारी करना आवश्यक समझता हो।

(3) उप नियम (2) के अधीन गिरफ्तारी करने वाला वरिष्ठ आफिसर यथासंभव और किसी भी स्थिति में गिरफ्तारी के चौबीस घंटे के भीतर उस बटालियन या यूनिट, कमाण्डेंट को ऐसी रिपोर्ट भेजेगा, जिसका कि गिरफ्तार किया जाने वाला व्यक्ति सदस्य है और किसी ऐसे आफिसर जो कमाण्डेंट से ऊपर के रैंक का आफिसर हो, की गिरफ्तारी की रिपोर्ट उसके तत्काल ऊपर के वरिष्ठ आफिसर को दी जाएगी।

35. गिरफ्तारी, कैसे की जाए -

(अ) बंद गिरफ्तारी:- (1) (क) भर्ती किए गए अभ्यावेशित के मामले में बंद गिरफ्तारी, गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को सूचना देकर की जाएगी और उसे परिरोध वाले स्थान पर जाने के लिए आदेश दिया जाएगा, जिसके साथ उसी समान के रैंक वाला व्यक्ति या वरिष्ठ रैंक का अनुरक्षक लगाया जाएगा।

(ख) जब ऐसा कोई अनुरक्षक उपलब्ध न हो, तो गिरफ्तार व्यक्ति को यह आदेश दिया जाएगा कि वह क्वार्टर गार्ड या परिरोध वाले, अन्य स्थान पर तत्काल स्वयं रिपोर्ट करें।

(2) (क) आफिसर, अधीनस्थ आफिसरों या अवर आफिसरों के मामले में बंद गिरफ्तारी, ऐसे आफिसर, अधीनस्थ आफिसर या अवर आफिसर को रखकर या उसके समतुल्य रैंक या वरिष्ठ रैंक के दूसरे व्यक्ति, की अभिरक्षा में की जाएगी और जब भी जरूरी समझा जाए, ऐसे आफिसर, अधीनस्थ आफिसर या अवर आफिसर को गार्ड लगाकर परिरोध में रखा जाएगा।

(ख) गिरफ्तारी के अधीन व्यक्ति परिरोध के स्थान को कमाण्डेंट या कमाण्डेंट द्वारा पदाविहित किसी वरिष्ठ आफिसर की अनुज्ञा के बिना नहीं छोड़ेगा।

(आ) खुली गिरफ्तारी:- (3) (क) गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति को सूचना देकर की जाएगी कि वह खुली गिरफ्तारी में है और वह ऐसी सीमाओं, जो ऐसी गिरफ्तारी करने वाले संबंधित वरिष्ठ आफिसर द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाए, सीमाओं के भीतर रहेगा।

(ख) कमाण्डेंट, उपर्युक्त खण्ड (क) में निर्विष्ट सीमाओं में, समय-समय पर, फेर-फार कर सकेगा।

36. अन्वेषण के दौरान गिरफ्तारी से निर्मुक्ति:- (1) नियम 34 के अधीन, गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को किसी आफिसर के आदेश के अधीन गिरफ्तारी से निर्मुक्ति किया जा सकेगा।

परंतु किसी आफिसर द्वारा गिरफ्तार किए जाने वाले किसी व्यक्ति के मामले में, ऐसे व्यक्ति को उसके कमाण्डेंट या उस कमाण्डेंट से वरिष्ठ किसी आफिसर के आदेश के अधीन निर्मुक्त किया जाएगा।

37. पुनः गिरफ्तारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना के बिना निर्मुक्ति - अन्वेषण या किसी न्यायालय के गठन लम्बित होने पर, गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को उसके कमाण्डेंट या कमाण्डेंट से वरिष्ठ किसी आफिसर द्वारा पुनः गिरफ्तारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निर्मुक्त किया जा सकेगा।

38. गिरफ्तारी कब की जाए - (1) किसी भी व्यक्ति पर निम्नलिखित आरोप होने पर गिरफ्तार किया जा सकेगा -

(i) धारा 21, खण्ड (क) या खण्ड (ख) या धारा 23 या धारा 24 या धारा 27 या धारा 28 की उपधारा (1) के अधीन कोई अपराध होने पर।

(ii) सिविल अपराध, जो मृत्यु दण्ड या आजीवन कारावास की सजा से दंडनीय होने पर।

(iii) इस अधिनियम के तहत निम्नलिखित कोई अन्य अपराध होने पर -

(क) यदि अनुशासन को बनाए रखने के लिए ऐसा आपेक्षित हो, या

(ख) यदि संबंधित व्यक्ति जानबूझकर अनुशासन भंग करता है, या

(ग) यदि संबंधित व्यक्ति उग्र प्रवृत्ति का है, या

(घ) यदि विचारण से बचने के लिए संबंधित व्यक्ति के अनुपस्थित होने की संभावना हो; या

(ङ) यदि संबंधित व्यक्ति के साक्षियों के साथ हस्तक्षेप की संभावना हो या साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ की आशंका हो, तो उसे गिरफ्तारी में रखा जाएगा।

(2) जब गिरफ्तार किए गए व्यक्ति में बीमारी के लक्षण दिखाई दें, तो ऐसे व्यक्ति को चिकित्सा सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

39. मृत व्यक्ति की गिरफ्तारी के मामले में विशेष उपबंध— (1) जहाँ किसी मृत व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो उसे यथा संभव पृथक् रखा जाएगा और उसके ड्यूटी आफिसर या ड्यूटी अधीनस्थ आफिसर या ड्यूटी अवर आफिसर या गार्ड के प्रभारी अवर आफिसर द्वारा प्रत्येक दो घंटों में उसका एक बार निरीक्षण किया जाएगा।

(2) मृत व्यक्ति को अन्वेषण के लिए वरिष्ठ आफिसर के समक्ष उसके शांत न हो जाने तक नहीं ले जाया जाएगा।

40. जिस व्यक्ति के विचारण का आदेश दिया जा चुका हो, उसकी गिरफ्तारी—(1) जब तक संयोजक प्राधिकारी ने अन्यथा निर्देश न दिया हो, न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के खिलाफ विचारण शुरू हो जाने पर, उक्त व्यक्ति को उसके कमाण्डेंट द्वारा गिरफ्तारी के अधीन रखा जाएगा और विचारण के दौरान वह गिरफ्तारी में रहेगा।

(2) जब किसी न्यायालय द्वारा कारावास से कम का दंडादेश दिया गया हो, तो गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को, न्यायालय के निर्णय और दण्डादेश के पुष्टिकरण को लंबित रखते हुए, उसके कमाण्डेंट द्वारा उसकी निर्मुक्ति की जा सकेगी—

परन्तु संयोजक प्राधिकारी, उप नियम (1) या उपनियम (2) के अधीन किसी कमाण्डेंट द्वारा पारित आदेश को विखंडित, परिवर्तित या उपातरित कर सकेगा और जहाँ कमाण्डेंट द्वारा ऐसा आदेश पारित न किया गया हो, तो संयोजक प्राधिकारी ऐसा आदेश पारित कर सकेगा जो वह उचित समझे—

परन्तु यह और कि किसी व्यक्ति को जिसे पदच्युत किए जाने का दण्डादेश हो चुका हो, उसे व्यक्ति को सक्रिय ड्यूटी के सिवाय, किसी ड्यूटी पर नहीं रखा जाएगा।

41. विलम्ब रिपोर्ट— (1) (क) धारा 81 के अधीन यथाअपेक्षित विलम्ब होने के कारण रिपोर्ट परिशिष्ट-2 में दिए गए प्ररूप में होगी और इसे कमाण्डेंट द्वारा उप महानिरीक्षक या अपर उप महानिरीक्षक, जिसके अधीन अभियुक्त कार्यरत होगा, को भेजा जाएगा।

(ख) आठवीं विलंब रिपोर्ट की एक प्रति और रिपोर्ट की प्रतियाँ संबंधित प्रत्येक पश्चावर्ती महानिरीक्षक जिसके अधीन अभियुक्त कार्यरत होगा, और मुख्य विधि अधिकारी को भेजी जायेगी।

(2) जहाँ उसके विचारण के लिए किसी बल न्यायालय के संयोजन के आदेश के बिना, अभियुक्त को तीन मास से अधिक अवधि तक गिरफ्तारी में रखा जाता है, इस संबंध में की गई कार्यवाई तथा विलंब के कारण की एक विशेष रिपोर्ट कमाण्डेंट द्वारा महानिदेशक को भेजी जायेगी, जिससे प्रत्येक की एक प्रति उप महानिरीक्षक या अपर उप महानिरीक्षक और संबंधित महानिरीक्षक को भेजी जाएगी।

42. गिरफ्तारी के अधीन किसी व्यक्ति के अधिकार—

(1) (क) गिरफ्तारी के अधीन रखे गए किसी व्यक्ति को, उसे गिरफ्तार करते समय, गिरफ्तारी करने वाले आफिसर द्वारा उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों की विशिष्टियाँ लिखित रूप में दी जाएगी।

(ख) खंड (क) में किसी बात के होते हुए भी, जहाँ अन्वेषण के दौरान अभियुक्त द्वारा किए गए अन्य अपराधों का पता चल जाए, उन अपराधों के बारे में उस व्यक्ति पर आरोप लगाए जाना विधि पूर्ण होगा।

(2) (क) ड्यूटी आफिसर या ड्यूटी अधीनस्थ आफिसर गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का प्रत्येक दिन निरीक्षण करेगा और वह गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अनुरोध या दिए गए अभ्यावेदन पर कमाण्डर से आदेश लेगा।

(ख) गिरफ्तार किए गए व्यक्ति द्वारा किए गए अनुरोध या दिए गए अभ्यावेदन को परिशिष्ट-3 में दिए गए प्ररूप में प्रविष्ट किया जायेगा।

43. निलंबन— (1) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, अनुशासनिक या नियुक्ति प्राधिकारी, जो जनरल या पेटी बल न्यायालय के संयोजन में सक्षम है, अपने अधीन सेवारत व्यक्ति को अपने विवेक पर निम्नलिखित स्थितियों में निलंबन में रख सकेगा—

(i) जहाँ अधिनियम के अधीन, उस व्यक्ति के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाई अनुद्ध्यत है या लम्बित है; या

(ii) जहाँ उपर्युक्त प्राधिकारी की राय में, उसने स्वयं को ऐसी गतिविधियों में लिप्त कर लिया है जो कि राज्य की सुरक्षा के हित के प्रतिकूल हैं; या

(iii) जब उस व्यक्ति के खिलाफ सिविल अपराध से संबंधित किसी मामले का अन्वेषण, अन्वेषण या विचारण चल रहा हो।

(2) अधिनियम के अधीन, किसी व्यक्ति को नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा निम्नलिखित स्थितियों में निलंबित समझा जाएगा—

(i) सिविल पुलिस द्वारा किसी आपराधिक आरोप के आधार पर या इससे अन्यथा उस व्यक्ति को निरोध में लेने की तारीख से 48 घंटे से अधिक की अवधि तक निरोध में रखने पर; या

(ii) किसी अपराधिक आरोप पर किसी दण्ड न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति को दोष सिद्ध होने की तारीख से, यदि अड़तालिस घंटे से अधिक की अवधि तक कारावास का दंडादेश दिया जाता है।

(3) इस नियम के अधीन किए या किया गया समझे जाने वाला निलंबन आदेश, तब तक निरन्तर प्रवृत्त रहेगा, जब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसे संशोधित या प्रतिसंहारित नहीं किया जाता है।

(4) इस नियम के अधीन किए गए या किया गया समझे जाने वाले निलंबन का आदेश, किसी भी समय, निलंबन आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा या ऐसे किसी प्राधिकारी जिससे वह अधीनस्थ है, द्वारा संशोधित या निरस्त किया जा सकेगा।

(5) किसी व्यक्ति के निलंबन की अवधि के दौरान, उसमें निहित शक्तियाँ स्थगित रहेंगी, किंतु वह समान उत्तरदायित्वों, अनुशासन, शांति और सेवा के अन्य सभी शर्तों जिसके अधीन वह है जैसे कि वह ड्यूटी पर था और वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा घोषित मुख्यालय को पूर्व अनुमति के बिना नहीं छोड़ेगा।

(6) जब कोई व्यक्ति 90 दिन से अधिक की अवधि तक निलंबन पर रहता है, तो उसके मामले के निपटारे में हुए विलम्ब के कारण देते हुए एक रिपोर्ट अभियुक्त के कमाण्डेंट द्वारा महानिदेशक को भेजी जाएगी और उसके पश्चात् उक्त मामले के समाप्त होने तक या निलंबन आदेश प्रतिसंहारित होने तक, इसमें से जो भी पहले हो, प्रत्येक माह उत्तरवर्ती रिपोर्टें प्रस्तुत की जाएंगी।

अध्याय - 7

बल न्यायालय और दण्ड न्यायालय की अधिकारिता का चयन

44. बल न्यायालय या दण्ड न्यायालय द्वारा मामलों का विचारण -

(1) जब किसी अपराध को दोनों न्यायालयों में से किसी दण्ड न्यायालय और बल न्यायालय दोनों द्वारा विचारणीय हो तो धारा 102 में निर्दिष्ट कोई अधिकारी -

(i) (क) जहां बल के सदस्य के रूप में उसकी ड्यूटी के कार्यनिष्पादन के दौरान अभियुक्त द्वारा अपराध किया गया है, या

(ख) जहां सरकार या बल की सम्पत्ति के संबंध में अपराध किया गया है; या कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन है, या

(ग) इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपराध किसी व्यक्ति द्वारा किया गया है, अधिनियम के अधीन अभिकथित व्यक्ति ने अपराध किया हो, तो उसका विचारण बल न्यायालय द्वारा होगा; और

(ii) किसी अन्य मामले में, इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किसी ऐसे बल न्यायालय द्वारा विचारण करने के लिए दावा चाहे अनुशासन बनाए रखने के हित में आवश्यक हो या न हो, ऐसे किसी अपराध को किए जाने का अभिकथन है, विनिश्चय किया जाएगा।

(2) किसी बल न्यायालय द्वारा किसी अपराधी के विचारण करने के लिए अपराधी का दावा का विनिश्चय लेने में धारा 102 में निर्दिष्ट कोई आफिसर निम्नलिखित में से सभी या किसी एक तथ्य को ध्यान में रखेगा, अर्थात् -

(क) अपराधी सक्रिय सेवा में है या उसे सक्रिय सेवा के लिए चेतावनी दी जा चुकी है और यह देखा गया है कि वह ऐसी ड्यूटी से बचने का प्रयास कर रहा है;

(ख) अपराधी प्रशिक्षणाधीन एक युवा व्यक्ति है, और उसका अपराध गंभीर नहीं है और दण्ड न्यायालय द्वारा विचारण कराने से उसके प्रशिक्षण पर सारतः प्रभाव पड़ेगा;

(ग) मामले की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, अपराधी का इस अधिनियम के अधीन संक्षिप्त विचारण किया जा सकता है।

45. वे मामले, जिनका विचारण बल न्यायालय द्वारा नहीं की जा सकेगा - नियम 44 के उपनियम (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, किसी अपराधी को साधारणतया बल न्यायालय द्वारा निम्नलिखित स्थितियों में विचारण का दावा नहीं कर सकेगा:-

(i) जहां उसके द्वारा किया गया अपराध किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ किया जाता है जो इस अधिनियम के अधीन नहीं है, जिसकी पहचान ज्ञात है; या

(ii) जहां उसके द्वारा अपराध, छुट्टी पर या बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहने के दौरान किया गया है।

अध्याय - 8

आरोपों का अन्वेषण और संक्षिप्त निपटारा

आरोप की सुनवाई

46. अनंतिम आरोप पत्र - जहां यह अभिकथित हो कि इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति ने अधिनियम के अधीन दण्डनीय अपराध किया है, तो उस अभिकथन को संक्षेप में परिशिष्ट-4 में दिए गए प्ररूप में लिखा जाएगा।

47. आरोप की सुनवाई: (1) इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध प्रत्येक आरोप की सुनवाई अभियुक्त की उपस्थिति में कमाण्डेंट द्वारा की जाएगी और कार्यवाही को परिशिष्ट-5 में दिए गए प्ररूप में संक्षेप में लिखा जाएगा। अभियुक्त को यह पूर्ण स्वतन्त्रता होगी कि वह अपने विरुद्ध किसी साक्षी की प्रति परीक्षा करें और अपनी प्रतिरक्षा के लिए आवश्यक ऐसे साक्षियों को बुलाएं और कथन कराएं।

परन्तु जहां किसी जांच न्यायालय के अन्वेषण के परिणाम स्वरूप अभियुक्त के विरुद्ध आरोप उत्पन्न होता है, वहाँ अभियुक्त के संबंध में नियम 183 के उपनियम (8) के उपबंध का अनुपालन होगा तो कमाण्डेंट उपनियम (1) में दी गई प्रक्रिया से अभिमुक्त कर सकेगा।

(2) उपर्युक्त उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, धारा 62 के अधीन कोई विनिर्दिष्ट आफिसर किसी अभ्यावेशित व्यक्ति के विरुद्ध निम्नलिखित स्थितियों में कार्यवाही कर सकेगा यदि—

(क) आरोप को संक्षेपतः निपटाया जा सकता है;

(ख) कमाण्डेंट द्वारा मामले का स्वयं निपटान करने के लिए आशंकित न किया गया हो; और

(ग) अभियुक्त गिरफ्तार नहीं है।

और उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन आरोप की सुनवाई के पश्चात् विनिर्दिष्ट आफिसर या तो परिशिष्ट-6 में नियत सीमा में दण्ड देने के लिए सशक्त है, या मामले को कमाण्डेंट के पास आगे के निपटान के लिए निर्दिष्ट करेगा।

(3) कमाण्डेंट, उसके समक्ष लगाए गए आरोप को रद्द कर देगा, यदि उसकी राय में, साक्ष्य से यह दर्शित करती है, कि इस अधिनियम के अधीन अपराध किया गया है और यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि आरोप पर आगे कार्यवाही नहीं की जा सकेगी;

परन्तु कमाण्डेंट उस आरोप को रद्द नहीं करेगा जिसे वह धारा 96 के उपधारा (2) के अधीन उसमें यथा विनिर्दिष्ट किसी वरिष्ठ प्राधिकारी निर्देश के लिए भेजे बिना विवर्जित करने का प्रयास किया हो :

परन्तु यह और भी कि मृत्यु दण्ड जैसे सभी अपराधों के मामले में कमाण्डेंट संक्षिप्त साक्ष्य को अभिलिखित करने के लिए मामले को प्रतिप्रेषित करेगा।

(4) उपनियम (1) के अनुपालन के पश्चात्, यदि कमाण्डेंट की यह राय हो कि आरोप पर आगे कार्यवाही की जानी चाहिए, तो वह युक्तियुक्त समय में निम्नलिखित कार्यवाही करेगा :—

(क) धारा 62 के अधीन परिशिष्ट-6 में दी गई रीति और प्ररूप के अनुसार मामले का निपटान करेगा; या

(ख) उपर्युक्त वरिष्ठ प्राधिकारी के पास उक्त मामला निर्दिष्ट करेगा; या

(ग) अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य होने के प्रयोजन के मामले को स्थगित करेगा, संक्षेप में लेखबद्ध करेगा; या

(घ) विचारण संक्षिप्त असम राइफल्स न्यायालय द्वारा किए जाने के लिए आदेश देगा।

परन्तु मामले को ऐसे आफिसर, जो पेटी असम राइफल्स न्यायालय को आयोजित करने के लिए सशक्त है, के पास भेजे बिना कमाण्डेंट संक्षिप्त असम राइफल्स कोर्ट में विचारण के लिए तब तक आदेश नहीं देगा जब तक कि—

(i) अपराध ऐसा है, जिसका संक्षिप्त असम राइफल्स न्यायालय द्वारा विचारण उस आफिसर के पास बिना भेजे किया जा सकता हो; या

(ii) उसके विचार में तत्काल कार्रवाई के लिए गम्भीर कारण है और ऐसा निर्देश अनुशासन को उपाय किए बिना को नहीं किया जा सकता है।

(5) जहाँ इस नियम के उपनियम (4) के अनुसार साक्ष्य लिया गया हो वहाँ ऐसे अपराध का प्रकटीकरण होता है जो अपराध अन्वेषण के अधीन नहीं था तो कमाण्डेंट मूल आरोप के अन्वेषण के साथ-साथ इस प्रकार ली गई साक्ष्य के आधार पर उचित आरोप तय कर सकेंगे।

48. आरोप जिन पर संक्षिप्ततः विचार न किया जाय:— सक्रिय सेवा में होने पर किसी अपराध के लिए आरोप धारा 21 या धारा 22 या धारा 23 या जब सक्रिय सेवा में न हो, तो धारा 24 या धारा 25 के खंड (1) या धारा 27 के खंड (क) या धारा 28 या धारा 30 या धारा 31, या धारा 33 के खंड (क) (निकृष्ट आचरण) या धारा 36 के खंड (ख) या धारा 39 या धारा 46 या धारा 47 या धारा 55 (साधारण नुकसान या चोरी के मामलों से भिन्न) या दुष्प्रवृत्ति का आरोप का या इनमें से किसी अपराध को करने के प्रयास से संबंधित अपराधों का विचार संक्षिप्त नहीं किया जायेगा।

49. साक्ष्य का सारांश:— (1) जहाँ मामले में साक्ष्यों को संक्षेप लेखबद्ध करने के प्रयोजन के लिए स्थगित किया गया हो, वहाँ ऐसा आदेश देने वाला आफिसर स्वयं साक्ष्य का संक्षिप्त लेखबद्ध कर सकेगा या किसी अन्य आफिसर को ऐसा करने के लिए भेजेगा।

(2) साक्षी अभियुक्त की उपस्थिति में अपने साक्ष्य देंगे। अभियुक्त को सभी साक्षियों की प्रति परीक्षा पर अधिकार होगा जो उसके विरुद्ध साक्ष्य देते हैं और प्रश्न के साथ उत्तर को साक्ष्य में अभिलिखित किया जायेगा।

(3) अभियुक्त के विरुद्ध सभी साक्षियों का परीक्षण हो जाने के पश्चात् उसे निम्न निबन्धनों में चेतावनी दी जायेगी: "क्या आप कोई कथन देना चाहते हैं? आप कुछ कहने के लिए बाध्य नहीं हैं, जब तक आप की ऐसा करने की इच्छा न हो, लेकिन आप जो भी कथन देते हैं उसे लेखबद्ध किया जायेगा और उसे साक्ष्य के रूप में दिया जायेगा।" इसके बाद अभियुक्त द्वारा दिया गया कोई कथन लेखबद्ध किया जायेगा और उसके सामने पढ़ा जायेगा लेकिन उस पर कोई प्रतिपरीक्षा नहीं की जायेगी। अभियुक्त, उसके बाद अपने प्रतिरक्षा में साक्षियों को बुलायेगा, साक्ष्य को अभिलिखित करने वाला आफिसर साक्षियों द्वारा दिये गये साक्ष्य के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण के लिए आवश्यक प्रश्न पूछ सकेगा।

(4) साक्षियों द्वारा दिये गये साक्ष्य को सामान्यतः वर्णनात्मक अंग्रेजी या हिंदी भाषा में लिखा जायेगा और लेखबद्ध करने वाला आफिसर, अभियुक्त के अनुरोध पर, साक्ष्य के किसी भाग को प्रश्न व उत्तर के रूप में लिखने की अनुमति दे सकता है। साक्षियों के कथन को उनके सामने पढ़ा जायेगा और उसका स्पष्ट किया जायेगा उसके बाद साक्षी कथन पर हस्ताक्षर करेंगे या यदि वह अपना नाम स्वयं नहीं लिख सकता तो उसका साक्ष्य पर साक्षियों की उपस्थिति में सत्यापित किया जायेगा जिससे कि लिखित साक्ष्य की सत्यता सुनिश्चित की जा सके।

(5) साक्ष्य का संक्षिप्त को लेखबद्ध करने वाले आफिसर के समक्ष साक्षी की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए अधिनियम की धारा 111 के उपबंध लागू होंगे।

(6) जहाँ किसी साक्षी को उपस्थित होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता या साक्षी उपलब्ध न हो या उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु अनावश्यक समय व सधन खर्च होगा तब साक्ष्य लेखबद्ध करने वाला आफिसर इस निमित्त एक प्रमाण पत्र देगा और ऐसे साक्षियों द्वारा हस्ताक्षरित कथन को अभियुक्त के समक्ष पढ़ा जायेगा तथा साक्ष्य के संक्षिप्त में सम्मिलित किया जायेगा।

(7) साक्ष्यों को अभिलिखित करने के बाद साक्ष्य को लिखने वाले आफिसर निम्नलिखित प्ररूप में प्रमाण पत्र देगा—

"प्रमाणित किया जाता है कि द्वारा आदेशित साक्ष्य को लेखबद्ध अभियुक्त की उपस्थिति और सुनवाई में किया गया है तथा नियम 49(3) के उपबंध के अनुपालन में किया गया।"

(8) साक्ष्य का लेखबद्ध करने वाले आफिसर के समक्ष किसी भी काउन्सेल या विधि व्यवसायी को उपस्थित होने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

50. साक्ष्य का सार :— (1) जहाँ अभियुक्त के कमाण्डेंट की राय है कि आफिसर, अधीनस्थ आफिसर या अवर आफिसर के विरुद्ध आरोप ऐसी प्रकृति का नहीं है जिसे बल न्यायालय में विचारण के लिए ले जाया जाय, वह आरोप की सुनवाई नियम 47(1) के अनुसार करने के पश्चात्, साक्ष्य का सार तैयार करने के लिए आदेश दे सकेगा।

(2) साक्ष्य के सार को या तो कमाण्डेंट स्वयं तैयार करेगा या उसके द्वारा भेजे गए किसी आफिसर द्वारा तैयार किया जायेगा।

(3) (क) साक्ष्य के सार में निम्नलिखित सम्मिलित होगा:—

(i) जहाँ भी उपलब्ध हो, साक्षियों के हस्ताक्षरित कथन या उसका यथावत, और

(ii) सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ जिन्हें विचारण के दौरान प्रस्तुत किया जाना आश्रित है।

(ख) जहाँ किन्हीं साक्षियों के हस्ताक्षरित कथन उपलब्ध नहीं है, साक्ष्य का यथावत जिसे साक्षियों द्वारा दिये जाने की सम्भावना है, उसे भी सम्मिलित किया जायेगा।

(4) अभियुक्त को साक्ष्य के सार की एक प्रति उसे बनाने वाले आफिसर द्वारा दी जायेगी वह और अभियुक्त यदि वह ऐसा चाहे तो नियम 49 के उपनियम (3) में अधिकथित रीति में अभियुक्त को चेतावनी देने के पश्चात् उसे अपना कथन देने का अवसर दिया जायेगा।

परन्तु अभियुक्त को परिस्थिति के अनुसार ऐसा युक्ति युक्त समय दिया जायेगा लेकिन साक्ष्य का सार प्राप्त होने के बाद के पश्चात् किसी भी दशा में चौबीस घंटे से कम समय नहीं होगा।

51. साक्ष्य का सारांश या सार अभिलिखित करने के बाद मामले का निपटारा :— (1) नियम 49 या नियम 50 के अनुसरण में तैयार किये गये साक्ष्य पर कमाण्डेंट द्वारा विचारण किया जायेगा जो उसके पश्चात् या तो :—

(क) आरोप को खारिज करेगा; या

(ख) असम राइफल्स अधिनियम की धारा 62 या धारा 66, जो भी लागू हो मामले को संक्षिप्त निपटारा करेगा; या

(ग) मामले को सक्षम वरिष्ठ आफिसर के पास निपटारे के लिए भेजेगा; या

(घ) किसी बल न्यायालय द्वारा विचारण के लिए अभियुक्त को प्रतिप्रेषण करेंगे।

(2) यदि अभियुक्त को बल न्यायालय में विचारण के लिए प्रतिप्रेषित किया जाता है तो कमाण्डेंट बिना किसी अनावश्यक विलम्ब के :—

(क) समरी असम राइफल्स न्यायालय को (जब ऐसा निर्देश आवश्यक हो, धारा 96 की उप धारा (2) के अनुसार निर्देश करने के पश्चात् गठित करेगा या

(ख) यथास्थिति, जनरल या पेंटी असम राइफल्स न्यायालय, संयोजित करने के लिए सक्षम वरिष्ठ प्राधिकारी को आवेदन करेंगे।

52. न्यायालय के लिए आवेदन:- किसी पेंटी बल न्यायालय या जनरल बल न्यायालय के लिए आवेदन परिशिष्ट-7 में दिये गये प्ररूप में कमाण्डेंट द्वारा किया जाएगी और उसके साथ, साक्ष्य के संक्षिप्त या सार और आरोप पत्र तथा आवेदन पत्र में उल्लिखित ऐसे अन्य दस्तावेजों की पांच प्रतियां भेजेगा।

53. आफिसर, अधीनस्थ आफिसर या वारंट आफिसर के विरुद्ध आरोपों का संक्षिप्त निपटारा:-

(1) जहाँ किसी आफिसर, अधीनस्थ आफिसर या वारंट आफिसर के विरुद्ध आरोप के निपटारे के लिए प्राधिकारी को धारा 64, धारा 65 व धारा 66 में दी गई शक्तियों के अधीन उक्त आरोप का संक्षिप्त विचार के लिए सशक्त किया गया है, को प्रति प्रेषित किया गया है, और उसे साक्ष्य का संक्षिप्त या सार के साथ आरोप की प्रतिलिपि उसके तैयार करने के पश्चात् यथाशीघ्र दिया जायेगा और किसी भी दशा में कार्यवाही प्रारंभ होने के चौबीस घंटे से अन्यून नहीं होगी।

(2) जहाँ प्राधिकारी धारा 64, धारा 65 और धारा 66 के अंतर्गत प्राधिकारी किसी आफिसर, अधीनस्थ आफिसर या वारंट आफिसर के विरुद्ध आरोप पर संक्षिप्त विचार करने का विनिश्चय करता है, वह जब तक कि वह आरोप खारिज नहीं करता है या जब तक अभियुक्त ने साक्ष्यों की उपस्थिति से अभियुक्ति के लिए लिखित में सहमति न दे दी हो वह अभियुक्त की उपस्थिति में साक्ष्य की सुनवाही करेगा। अभियुक्त को पूर्ण स्वतन्त्रता होगी कि वह अपने विरुद्ध किसी साक्षी से प्रतिपरीक्षा करें और वह किसी साक्षी को अपने बचाव में साक्ष्य देने के लिए बुला सकेगा और ऐसे अभिलिखित कथन या उसके भावार्थ को मामले का संक्षिप्त निपटारा करने वाले आफिसर द्वारा कार्यवाहियों से संलग्न किया जायेगा।

(3) यथा साध्य परिशिष्ट-8 में दिये गये प्ररूप के अनुसार कार्यवाही अभिलिखित की जायेगी और प्रत्येक मामले में जिसमें दण्ड अधिनिर्णय किया जाता है, संचालन पत्र, साक्ष्य की संक्षिप्त या सार और अभियुक्त के विरुद्ध गवाहों को बुलाने से अभियुक्ति से लिखित सहमति के साथ कार्यवाहियों विहित वरिष्ठ प्राधिकारी को उचित माध्यम से के पास धारा 64 की उपधारा (2) व धारा 65 की उपधारा (2) के अधीन यथा उपबंधित पुनर्विलोकन के लिए भेजेगा।

(4) धारा 62 और धारा 66 के अधीन मामले के संक्षिप्त निपटारे की दशा में, कार्यवाहियां कमान में उस आफिसर से वरिष्ठ आफिसर को भेजेगा जिसने दण्ड का आदेश अधिनिर्णीत किया है, और यदि अधिनिर्णीत दण्ड ऐसे वरिष्ठ आफिसर को अवैध, अनुचित या अत्यधिक प्रतीत होता है तो वह दण्ड को उसे निरस्त, फेरफार या विप्रक्षिप्त कर सकेगा और ऐसा अन्य निर्देश दे सकेगा जो मामले की परिस्थितियों के अनुसार समुचित है।

(5) धारा 64 की उपधारा (2) और धारा 65 की उपधारा (2) के प्रयोजनों के लिए विहित वरिष्ठ प्राधिकारी केन्द्रीय सरकार, महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्ट अन्य आफिसर होंगे।

अध्याय - 9

विचारण से पूर्ववर्ती आरोपों और विषयों के

सम्बन्ध में आरोप की विरचना

54. आरोप और आरोप पत्र :- (1) आरोप से आरोप पत्र में अंतर्विष्ट कोई अभियोग अभिप्रेत है कि अधिनियम के अधीन व्यक्ति अपराध का दोषी है।

(2) आरोप पत्र में एक समय में विचारण किए जाने वाला पूर्ण विवादक या विवादकों को अंतर्विष्ट विवादकार हो सकेंगे, (किया जाएगा या किए जाएंगे) और यदि आरोप समान तथ्यों पर आधारित हो, या अपराधों की श्रृंखलाओं का भाग हों या समान स्वरूप के हो तो उसमें एक से अधिक आरोप अंतर्विष्ट हो सकेंगे :-

परन्तु धारा 25, धारा 26, धारा 38 और धारा 41 के अधीन किसी आरोप को इस बात के होते हुए भी, किसी आरोप पत्र में सम्मिलित किया जा सकेगा कि उस आरोप पत्र में अन्य आरोप समान तथ्यों पर आधारित नहीं है या समान अपराधों की श्रृंखला का भाग समान या स्वरूप के अपराधों की भाग नहीं हैं।

(3) प्रत्येक आरोप पत्र इन नियमों के परिशिष्ट-4 में दिये गये समुचित नमूने के अनुसार तैयार किया जायेगा।

55. आरोप पत्र का प्रारम्भ :- प्रत्येक आरोप पत्र का प्रारम्भ आरोपित व्यक्ति के नाम और विवरण उसका नम्बर, रैंक, नाम और उसकी यूनिट जिसका वह है से किया जायेगा,

56. आरोप की विषय वस्तु :- (1) प्रत्येक आरोप में केवल एक अपराध का ही कथन किया जायेगा और किसी भी दशा में किसी अपराध को समान आरोप में विकल्प के रूप में वर्णित नहीं होगा।

(2) (क) यदि कोई एक कार्य या कार्यों की श्रृंखला की प्रकृति ऐसी है कि यह संदेहात्मक हो गया हो कि विभिन्न अपराधों में से कौन सा तथ्य साबित किया जा सकता है, तो अभियुक्त पर ऐसे अपराधों के सभी या किसी किन्हीं आरोपों को लगाया जा सकेगा और

उनका विचारण एक बार में की जायेगी या उसके ऊपर वैकल्पिक रूप में आरोप लगाया जा सकेगा कि उक्त अपराधों में से कोई अपराध अभियुक्त ने किया।

(ख) अधिक गम्भीर अपराध के लिए आरोप के बाद में कम गम्भीर अपराध पर कार्यवाही की जाएगी।

(3) प्रत्येक आरोप को दो भागों में विभाजित किया जायेगा:—

(क) अपराध का कथन; और

(ख) अपराध संगठित करने वाले कृत, उपेक्षा या लोप की विशिष्टियों का कथन।

(4) अपराध को, यदि सिविल अपराध नहीं है तो यथा साध्य अधिनियम के शब्दों में निकटतम रूप से और यदि सिविल अपराध है तो उस अपराध को ऐसे शब्दों में वर्णित किया जाएगा जो उस अपराध को सुसंगत कानूनी उपबंध में वर्णित करने के लिए यथा प्रयुक्त शब्दों में, उस अपराध को पर्याप्त रूप से वर्णित करेगा।

(5) विशिष्टियों में अभिकथित अपराध से संबंधित ऐसी परिस्थितियों का कथन किया जायेगा जो अभियुक्त को पता लगाने में समर्थ बना सके कि उसके विरुद्ध कौन सा कृत्य, उपेक्षा या लोप का साबित किया जाना आशयित है जो अपराध घटित करता है।

(6) एक आरोप की विशिष्टियां को पूर्णतः या अंशतः किसी अन्य आरोप के प्रति निर्देश से विरचित किया जा सकेगा और उस दशा में पश्चातवर्ती विशिष्टियों का उक्त भाग जो इस प्रकार निर्दिष्ट किया गया है, प्रथम उल्लिखित आरोप के साथ अन्य आरोप का भाग समझा जाएगा।

(7) जहाँ किसी तथ्य को साबित किया जाना आशयित है जिनकी बाबत आरोपित अपराध के परिणाम स्वरूप और वेतन और भात्यों से कटौती अधिनिर्णीत की जा सकेगी वहाँ विशिष्टियां उन तथ्यों और हानि या नुकसानी की राशि का कथन करेगी जिनको प्रभावित किए जाने का आशय है।

57. आरोप पत्र पर हस्ताक्षर :— आरोप पत्र अभियुक्त के कमांडेंट के द्वारा हस्ताक्षरित होंगी और ऐसे हस्ताक्षर का स्थान और तारीख अंतर्विष्ट होगी।

58. संयुक्त आरोप:— (1) संयुक्त रूप से किये गये अपराध के लिए किसी भी संख्या में अभियुक्तों को उनके द्वारा किए गए प्रकथित किसी अपराध के लिए संयुक्त रूप से भी आरोपित और साथ-साथ विचारण किया जा सकेगा।

(2) किसी भी संख्या में अभियुक्तों यद्यपि का भी, संयुक्त रूप से आरोपित न किया गया हो, ऐसे किसी अपराध के लिए एक साथ उनका विचारण किया जा सकेगा जिसके बारे में उनमें से किसी एक या अधिक द्वारा कारित किया गया था और अन्य या अन्यो द्वारा दुष्प्रेरित करने का प्रकथन किया गया है।

(3) जहाँ अभियुक्त को उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन इस प्रकार आरोपित किया गया है वहाँ उनमें किसी एक या अधिक को ऐसे किसी अन्य अपराध के लिए आरोपित और विचारण किया जा सकेगा जिसके लिए वे नियम 54 के उप नियम (2) के अधीन आरोपित किया गया हो।

59. आरोप पत्र की विधिमान्यता:—(1) कोई आरोप पत्र केवल इस तथ्य के कारण अविधिमान्य नहीं होगा कि उसके आरोपित व्यक्ति के नाम या विवरण में कोई त्रुटि है परन्तु वह विचारण के दौरान आरोप पत्र के बारे में आक्षेप नहीं करता और आरोपित व्यक्ति के साथ सारवान कोई अन्याय नहीं किया गया है।

(2) किसी आरोप पत्र या आरोप अर्थान्वयन में, प्रत्येक तिवादन को उनके समर्थन के पक्ष में माना जाएगा जिसके बारे में युक्ति रूप से यह उपधारण की जा सकेगी कि वह विवक्षित रूप से उसमें सम्मिलित है यद्यपि उसमें अभिव्यक्ति नहीं है।

अभियुक्त व्यक्ति द्वारा प्रतिरक्षा की तैयारी

60. अभियुक्त का प्रतिरक्षा की तैयारी का अधिकार:— (1) ऐसी अभियुक्त, जिसे विचारण के लिए प्रतिप्रेषित किया गया हो, उसे अपनी प्रतिरक्षा की तैयारी करने का उचित अवसर प्रदान किया जायेगा और उसे प्रतिवाद अधिकारी या काउंसेल और अपने साक्षियों के साथ उचित संसूचित करने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

(2) जब तक अभियुक्त लिखित रूप में यह नहीं कह देता कि वह ऐसी कोई नियुक्ति करना नहीं चाहता किसी ऐसे अभियुक्त की प्रतिरक्षा के लिए जिसे विचारण के लिए प्रतिप्रेषित किया गया, है प्रतिवाद अधिकारी को नियुक्त किया जायेगा।

(3) यदि किसी विधिक रूप से अर्हित आफिसर या काउंसेल द्वारा अभियोजन का कार्य किया जाता है तो इस तथ्य को युक्तियुक्त समय पर अभियुक्त को सूचित किया जाएगा जिससे कि वह यदि वह ऐसी वांछा करे, अपनी प्रतिरक्षा के लिए विधिक रूप से अर्हित आफिसर या काउंसेल की व्यवस्था कर सके।

(4) अभियुक्त व्यक्ति को, यदि उसे विचारण के बिना अड़तालीस दिन से अधिक के लिए गिरफ्तारी के अधीन रखा जाता है या उसे अपनी प्रतिरक्षा की तैयारी के लिए पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं दी जाती है, तो उसे मुख्य विधि आफिसर या विधि आफिसर को आवेदन करने का अधिकार होगा।

(5) किसी अभियुक्त को विचारण के लिए प्रतिप्रेषित करने के पश्चात् यथा साध्य शीघ्र और किसी भी दशा में उसके विचारण से न्यूनतम चार दिन पूर्व, उसे निशुल्क निम्नलिखित दी जाएगी:—

(क) आरोप पत्र की एक प्रति;

(ख) साक्ष्य के संक्षिप्त या उद्धरण की अपरिशोधित प्रति जिसमें उन अंशों को दर्शित किया गया हो जिनमें वरिष्ठ सदस्य को भेजी गई प्रति, में परिशोधन किए गए हैं; और

(ग) किसी अतिरिक्त साक्ष्य की सूचना, जिसे अभियोजन प्रस्तुत करना चाहता है।

(6) उप नियम (2) और उप नियम (3) के उपबंध समरी असम राइफल्स न्यायालय के समक्ष में किसी विचारण को लागू नहीं होंगे।

61. विचारण के लिए अभियुक्त को चेतावनी

(1) जब किसी अभियुक्त को इन नियमों के अनुसरण में आरोप पत्र की प्रति और साक्ष्य के संक्षिप्त या उद्धरण की प्रति दे दी गई हो तब कोई आफिसर :-

(क) उसे उसके विरुद्ध लगाए गए आरोप को स्पष्ट के साथ और यदि अभियुक्त उसे ऐसी भाषा में चाहता है जो वह समझता है तो उसे उसका अनुवाद भी दिया जाएगा।

(ख) उसे यह सूचित करेगा कि उसके द्वारा अपने विचारण से अन्योन्यत चौबीस घंटों पहले किसी साक्षी को (अभियोजन साक्षी से भिन्न) जिसे वह अपनी प्रतिरक्षा में बुलाना चाहता है (ऐसे साक्षी को उसके द्वारा नामित किया जाएगा), उसके विचारण में उपस्थित होने की अपेक्षा करने की अपने कमांडेंट को लिखित अनुरोध करने पर उसके विचारण में किसी ऐसे साक्षी की उपस्थिति उपाप्त करने के लिए इन नियमों के अनुसार युक्तियुक्त उपाय किए जाएंगे।

(ग) अभियुक्त को उन सदस्यों जो न्यायालय का गठन करते हैं के रैंक, नामों, और यूनिटों की जिनसे न्यायालय का गठन होगा और किन्हीं प्रतिक्षा सदस्यों की सूची परिदत्त करेगा।

(2) यदि न्यायालय को ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त पर उसके विचारण में इन नियमों के किसी अनुपालन द्वारा पूर्वाग्रह से ग्रसित होने का दावा है तो न्यायालय अभियुक्त को इस प्रकार पूर्वाग्रह से ग्रसित होने से रोकने का उपाय करेगी और यदि आवश्यक हुआ तो स्थगन कर देगी।

62. प्रतिरक्षा साक्षियों को समन करना— (1) कमाण्डेंट, उप नियम (2) और उप नियम (3) के उपबंध के अधीन रहते हुए अभियुक्त द्वारा इस निमित्त किए गए अनुरोध पर ऐसे साक्षियों को समन करेगा जो अभियुक्त द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

(2) जहाँ कमाण्डेंट का यह समाधान हो जाता है कि किसी साक्षी द्वारा दिये जाने वाले साक्ष्य का विचारण में सारवान रूप से सहायक होने की संभावना नहीं है तो वह ऐसे साक्षी को समन से इंकार कर सकेगा।

(3) कमाण्डेंट किसी साक्षी को समन करने से पहले अभियुक्त से ऐसे साक्षी को उपस्थित कराने का व्यय चुकाने या चुकाने की भार अपने ऊपर लेने की अपेक्षा कर सकेगा और यदि अभियुक्त उपर्युक्त व्यय भार अपने ऊपर की अदायगी करने की उपाप्त लेने से मना कर देता है तो कमाण्डेंट उस साक्षी से उपस्थिति कराने से इंकार कर सकेगा।

(4) जहाँ कमाण्डेंट ने उपनियम (2) और उपनियम (3) के अधीन साक्षी को समन करने से इंकार कर दिया हो, वहाँ अभियुक्त न्यायालय को ऐसे को साक्षी समन करने के लिए आवेदन कर सकेगा और न्यायालय यदि वह न्याय के हित में इसे समीचीन समझे तो ऐसे साक्षी को समन करने का आदेश कर सकेगा और यदि आवश्यक हो तो ऐसे साक्षी को उपस्थित कराने के लिए कार्यवाही को स्थगित कर सकेगा :

परन्तु यह एक मात्र रूप से अभियुक्त पर ही निर्भर होगा कि वह ऐसे किसी साक्षी की उपस्थिति को सुनिश्चित करेगा जिसका साक्ष्य के सार में अंतर्विष्ट नहीं है और जिसकी उपस्थिति के बारे में उपनियम (1) के अधीन अभियुक्त ने अनुरोध नहीं किया है।

जनरल और पेटी असम राइफल्स न्यायालयों आयोजित करना

63. न्यायालय के आयोजन के लिए आवेदन प्राप्त होने पर किसी वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा कार्यवाई—

(1) वरिष्ठ प्राधिकारी को न्यायालय के आयोजन के लिए आवेदन प्राप्त होता है यथाशीघ्र, वह अभियुक्त के विरुद्ध आरोप और साक्ष्य की संवीक्षा करेगा जहाँ आवश्यक हो मुख्य विधि आफिसर या उसके द्वारा अभिहित विधि आफिसर से परामर्श करेगा और वह—

(क) जहाँ अभियुक्त के विरुद्ध साक्ष्य अपर्याप्त है और आगे साक्ष्य उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहाँ कमाण्डेंट को आरोप खारिज करने का निर्देश देगा और यदि वह विचारण को आगे बढ़ाना अनुचित समझता है, तो उसे ऐसा करने का निर्देश दे सकेगा; या

(ख) समरी असम राइफल्स न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने या संक्षिप्त विचार के लिए वापस भेज सकेगा, यदि वह यह समझता है कि उसका इस प्रकार विचारण या विचार उपयुक्त रूप से किया जा सकता है; या

(ग) मामले का प्रशासनिक कार्यवाई द्वारा निपटान कर सकेगा या यदि वह ऐसी कार्यवाई करने के लिए सक्षम नहीं है तो अपनी सिफारिश के साथ वरिष्ठ प्राधिकारी के पास ऐसी कार्यवाई के लिए मामले को अग्रहित कर सकेगा; या

(घ) यदि वह अभिलिखित साक्ष्य को अपर्याप्त समझता है, किन्तु यह समझता है कि और साक्ष्य उपलब्ध हो सकता है तो मामले को और साक्ष्य अभिलिखित करने के लिए वापस भेज सकेगा।

(2) (क) किसी अन्य मामले में वह या तो स्वयं न्यायालय आयोजित कर सकेगा या यदि वह यह समझता है कि उच्चतर प्रकार का न्यायालय आयोजित किया जाना चाहिए और वह ऐसे न्यायालय को आयोजित करने के लिए सशक्त नहीं है, तो मामले को इस सिफारिश के साथ समुचित वरिष्ठ प्राधिकारी को भेज सकेगा कि ऐसा न्यायालय आयोजित किया जाय।

(ख) मामला प्राप्त होने पर वरिष्ठ प्राधिकारी इस नियम के उपनियम (1) में दी गयी शक्तियों में से किसी एक का प्रयोग कर सकेगा :-

परन्तु वरिष्ठ प्राधिकारी जनरल असम राइफल्स न्यायालय या पेट्री असम राइफल्स न्यायालय का आयोजित करने से पहले मुख्य विधि आफिसर या विधि आफिसर (मुख्य विधि आफिसर द्वारा इस प्रयोजन के लिए अभिहित) की सलाह ले सकेगा।

परन्तु यह और कि वरिष्ठ प्राधिकारी न्यायालय का आयोजित करते समय उस आरोप पत्र को पुनः विरचित कर सकेगा जिस पर अभियुक्त का विचारण किया जाना है।

64. जनरल और पेट्री असम राइफल्स न्यायालय में सेवारत आफिसरों की निरर्हता— कोई आफिसर न्यायालय में सेवा करने से निरर्हित होगा यदि वह —

(क) ऐसा आफिसर जिसने न्यायालय आयोजित किया है; या

(ख) वह अभियोजक या अभियोजन के लिए साक्षी है; या

(ग) उसने मामले के अन्वेषण में कोई भाग लिया हो, जिस में उसके लिए साक्ष्य के किसी भाग या मामले के तथ्यों के सम्बन्ध में विवेक का प्रयोग करना आवश्यक हो; या

(घ) वह अभियुक्त का कमाण्डेंट है; या

(ङ) उसके मामले में व्यक्तिगत हित है; या

(च) वह धारा 85(1) के अधीन बल का पुलिस आफिसर है।

65. आफिसरों की अपर्याप्त संख्या के लिए स्थगन— (1) यदि अभियुक्त को दोषारोपित करने से पहले पूरी संख्या में नामित आफिसर ब्यौरे निरर्हता, चुनौती या अन्यथा तामील करने के लिए उपलब्ध नहीं है और यदि कार्य करने में असमर्थ उन आफिसर उनकी जगह लेने के लिए प्रतीक्षा में पर्याप्त संख्या में आफिसर नहीं है तो न्यायालय नये सदस्य नियुक्त किए जाने के प्रयोजन के लिए सामान्यतः स्थगित हो जाएगा किन्तु यदि न्यायालय की यह राय है कि न्याय के हित में और सेवा की अच्छाई के लिए इस प्रकार स्थगन करना समीचीन नहीं है तो वह विधिक न्यूनतम संख्या में कमी नहीं की गई है तो ऐसा मानने के कारण अभिलिखित करने के पश्चात अग्रसर हो सकेगा।

(2) यदि न्यायालय नये सदस्यों की नियुक्ति के प्रयोजन के लिए यह नियमों के अधीन या अन्यथा स्थगित होता है, तो संयोजक आफिसर यदि वह ठीक समझे तो अन्य न्यायालय आयोजित कर सकेगा।

66. जनरल और पेट्री असम राइफल्स न्यायालयों की संरचना— (1) किसी न्यायालय में जहाँ तक व्यवहार्य हो, विभिन्न बटालियन या यूनिटों के आफिसर होंगे।

(2) किसी आफिसर के विचारण के लिए न्यायालय के सदस्य उस आफिसर के रैंक से नीचे के रैंक के आफिसर नहीं होंगे, जब तक कि रैंक के आफिसर संयोजन आफिसर की राय में ऐसे रैंक के आफिसर, लोक सेवा की अत्यावश्यकता का सम्यक ध्यान रखते हुए उपलब्ध नहीं है। ऐसी राय को संयोजन आदेश में अभिलिखित किया जाएगा।

(3) किसी कमाण्डेंट के विचारण के लिए न्यायालय जहां तक संभव हो ऐसे अधिकारियों से मिलकर बनेगा जो कमाण्डेंट हैं

या रहे हैं या जो कोई उच्चतर पद धारण करते हैं या किया है।

67. न्यायालयों के संयोजन के समय संयोजक अधिकारियों के कर्तव्य—

(1) जनरल या पेट्री असम राइफल्स न्यायालय के संयोजन से पहले आफिसर अपने आप को संतुष्ट करेगा कि न्यायालय द्वारा विचारण किये जाने वाले आरोप अधिनियम के अर्थान्तर्गत अपराधों के लिए हैं और साक्ष्य उन आरोपों के विचारण को न्यायोचित ठहराता है। यदि उसका इस प्रकार समाधान नहीं होता है तो वह अभियुक्त को निर्मुक्त करने के आदेश करेगा या मामले को वरिष्ठ प्राधिकारी को भेजेगा।

(2) वह अपना यह भी समाधान करेगा कि मामला उस प्रकार के न्यायालय द्वारा विचारण किए जाने के लिए समुचित है जिसके संयोजन का वह प्रस्ताव करता है।

(3) जब कोई आफिसर न्यायालय का संयोजन करता है तो वह —

- (क) परिशिष्ट-9 में उपवर्णित समुचित प्ररूप में संयोजन आदेश जारी करेगा;
- (ख) इस संबंध में निदेश देगा कि अभियुक्त को किस आरोपों पर विचारण किया जाना है और यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त को उसके कमाण्डेंट द्वारा, इन आरोपों के आधार किसी न्यायालय द्वारा विचारण के लिए प्रति प्रेषित किया गया है;
- (ग) यदि उसकी राय है कि आरोपों को अलग आरोप पत्र में रखा जाय, तो ऐसा करने के लिए निदेश देगा और यह भी निदेश देगा कि किस आदेश के अधीन उनका विचारण किया जाना है;
- (घ) यह निदेश देगा कि यदि एक से अधिक अभियुक्त है तो अभियुक्त का विचारण संयुक्त रूप से या पृथक् रूप से किया जाए;
- (ङ) न्यायालय के सदस्यों और किन्हीं प्रतीक्षा सदस्यों की नियुक्ति करेगा;
- (च) यदि वह निम्नलिखित का संयोजन कर रहा हो -
- (i) जनरल असम राइफल न्यायालय; या
 - (ii) पैटी असम राइफल न्यायालय जिसके बारे में वह यह समझता है कि उसमें विधि आफिसर भी उपस्थित होना चाहिए तो विधि आफिसर की नियुक्ति के लिए वह मुख्य विधि आफिसर द्वारा या उनकी ओर से आवश्यक उपाय करेगा, और विचारण के दौरान उसमें अनुदेश के अधीन कार्य के लिए किसी आफिसर की नियुक्ति करेगा;
- (छ) अधिनियम के अधीन किसी आफिसर को नियुक्त करेगा या अभियोजन की काउन्सिल की सहायता ऐसे आफिसर द्वारा की जाएगी;
- (ज) जहाँ भी आवश्यक हो दुभाषिया की नियुक्ति करेगा;
- (झ) वरिष्ठ सदस्य को, मूल आरोप पत्र, संयोजन आदेश, साक्ष्य के सार या उद्धरण की प्रति भेजेगा जिसमें से उसकी राय में किसी ऐसे साक्ष्य का परिशोधन किया गया है, जो उसकी राय में विचारण में साक्ष्य नहीं होगा;
- (ञ) न्यायालय के प्रत्येक सदस्य और प्रत्येक प्रतीक्षा सदस्य को आरोप पत्र और संयोजन आदेश की प्रति भेजेगा;
- (ट) विधि आफिसर को आरोप पत्र, संयोजन आदेश और साक्ष्य के सार या उद्धरण की अपरिशोधित प्रति उन अंशों को दर्शित करते हुए भेजेगा जिन्हें वरिष्ठ सदस्य को भेजी गई प्रति में परिशोधित किया गया है;
- (ठ) अभियोजक को आरोप पत्र, संयोजन आदेश और साक्ष्य के सार की मूल प्रतियाँ उसकी एक अपरिशोधित प्रति के साथ भेजेगा उन अंशों को दर्शित करते हुए भेजेगा जिन्हें वरिष्ठ सदस्य की प्रति में परिशोधित किया गया है;
- (ड) यह सुनिश्चित करेगा कि कमाण्डेंट ने सभी अभियोजन साक्ष्यों और ऐसे प्रतिरक्षा साक्ष्यों को बुला लिया है जिनको नियम 62 के अधीन बुलाने का अभियुक्त के अनुरोध किया हो।

अध्याय - 10

जनरल और पैटी असम राइफल न्यायालय की प्रक्रिया

भाग - 1

विचारण में प्रक्रिया- समवेत होना, चुनौती देना और शपथ लेना

68. न्यायालय का समवेत होना और विधिक गठन के बारे में जांच- (1) बल न्यायालय के समवेत होने पर, वह संयोजन आदेश जिसमें न्यायालय में कार्य करने के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों के रैंक, नाम और यूनिटें सम्मिलित हैं, आरोप पत्र और साक्ष्य के सार या उद्धरण की प्रति के साथ उसके समक्ष रखा जाएगा और न्यायालय विचारण आरम्भ करने से पूर्व, बंद न्यायालय में अपना यह समाधान करेगा :-

- (क) न्यायालय को इस अधिनियम और इन नियमों के अनुसार संयोजित किया गया है;
- (ख) न्यायालय, में विधि द्वारा अपेक्षित आफिसरों की न्यूनतम संख्या से अन्यून नहीं होंगे;
- (ग) सदस्य अपेक्षित रैंक के हैं;
- (घ) सदस्यों की नियुक्ति सम्यक् रूप से की गई है और वे अधिनियम के अधीन निरर्हत नहीं हैं;
- (ङ) यदि कोई विधि आफिसर है, तो वह सम्यक् रूप से नियुक्त किया गया है, अपेक्षित रैंक का है और उस न्यायालय के सेवा करने के निरर्हत नहीं है;
- (च) आरोप पत्र से पता चलता है कि अभियुक्त अधिनियम के अधीन है और वह न्यायालय की अधिकारिता के अधीन है; और
- (छ) प्रत्येक आरोप विधि के अनुसार सही है और इन नियमों के अनुसार विरचित किए गए हैं और इतने स्पष्ट है कि अभियुक्त के तुरन्त यह समझने में समर्थ हो सकेगा उसे क्या उत्तर देना है।

(2) जहाँ किसी सदस्य के अधिनियम के अधीन निरहित होने या जब न्यायालय संमवेत होती है तब अनुपस्थित रहने के कारण कोई रिक्ति होती है तो पीठासीन अधिकारी उस रिक्ति को भरने के लिए किसी सम्यक रूप से अहित प्रतीक्षा सदस्य को नियुक्त कर सकेगा।

(3) यदि उप नियम (1) में उल्लिखित किसी भी मामले में न्यायालय का समाधान नहीं होता है और वह अधिनियम या इन नियमों के अधीन स्वयं ऐसे मामलों को परिशोधन करने के लिए सक्षम नहीं है, तो वह विचारण आरम्भ होने से पहले संयोजन अधिकारी को उस पर रिपोर्ट देगा, और उस प्रयोजन के लिए स्थगित कर सकेगा।

(4) जब न्यायालय इस नियम का अनुपालन करने पर और विचारण आरम्भ करने के लिए तैयार होने पर पीठासीन अधिकारी, न्यायालय की कार्यवाही शुरू करके विचारण आरम्भ होगा।

69. विचारण का प्रारम्भ, अभियोजक व अभियुक्त का उपसंज्ञात होना — जब न्यायालय ने अपना यह समाधान कर लिया है कि नियम 68 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है, तो वह अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष लाया जाएगा और अभियोजक, जो अधिनियम के अध्याधीन व्यक्ति होगा, न्यायालय में अपना सम्यक् स्थान लेगा।

70. न्यायालय के सदस्यों के आक्षेप के लिए कार्यवाहियाँ — (1) न्यायालय का संयोजन करने वाले आदेश और अभियुक्त के विचारण के लिए नियुक्त आफिसरों के नामों को अभियुक्त की सुनवाई में पढ़ा जाएगा जिसे धारा 106 के अनुसार उन आफिसरों में से किसी के बारे में आक्षेप करने का अवसर दिया जाएगा।

(2) जब किसी न्यायालय में एक से अधिक अभियुक्तों का, विचारण चाहे पृथक् रूप से या संयुक्त रूप से किया जाना है तो प्रत्येक अभियुक्त को पूर्णगामी उपनियम के अनुसार न्यायालय में किसी आफिसर के बारे में आक्षेप करने का अवसर दिया जायेगा और उनसे पृथक् रूप से यह पूछा जायेगा कि क्या उसका कोई ऐसा आक्षेप है या नहीं।

(3) अभियुक्त उन किसी आक्षेप के निपटारे जाने से पूर्व उन सभी अधिकारियों के नाम बताएगा, जिन के बारे में उसका आक्षेप है।

(4) यदि एक से अधिक आफिसर के बारे में आक्षेप किया जाता है तो प्रत्येक आफिसर के आक्षेप का निपटारा पृथक् रूप से किया जायेगा और रैंक में निम्नतम आफिसर के बारे में आक्षेप को पहले निपटारा जायेगा।

(5) अपने आक्षेप के समर्थन में कथन कर सकेगा और साक्ष्य देने के लिए किसी व्यक्ति को बुला सकेगा और ऐसे व्यक्ति से अभियुक्त और न्यायालय द्वारा प्रश्न किए जा सकेंगे।

(6) आफिसर जिसके विरुद्ध अभियुक्त ने आक्षेप किया है, खुले न्यायालय में आक्षेप से सुसंगत कोई बात, चाहे उसके समर्थ में या खंडन में कह सकेगा।

(7) किसी आफिसर से सम्बंधित आक्षेप बन्द न्यायालय में आक्षेप किए गए आफिसर की अनुपस्थिति में न्यायालय के शेष अधिकारियों द्वारा विचार किया जाएगा और वे उस आक्षेप के निपटारे के सम्बंध में किसी बात के होते हुए भी मत देंगे कि आक्षेप उन शेष आफिसरों में से किसी के सम्बंध में किए गए हैं।

(8) जब किसी आफिसर के बारे में कोई आक्षेप धारा 106 की उपधारा (3) के अधीन अनुज्ञात किया जाता है तो वह आफिसर तुरन्त सेवानिवृत्त हो जाएगा और आगे कार्यवाही में भाग नहीं लेगा।

(9) किसी आफिसर के इस प्रकार निवृत्त हो जाने पर या ऐसे किसी कारण से जिसे न्यायालय पर्याप्त समझे सेवा के लिए उपलब्ध न होने पर और इस प्रकार वर्णित प्रतीक्षा में कोई अधिकारी है तो पीठासीन अधिकारी रिक्ति को भरने के लिए ऐसे अधिकारियों में से किसी एक की नियुक्ति करेगा, यदि प्रतीक्षा में कोई आफिसर उपलब्ध न हो, तो न्यायालय नियम 65 द्वारा अपेक्षा कार्यवाही करेगा।

(10) न्यायालय अपना यह समाधान करेगा कि वह प्रतीक्षा सदस्य जो न्यायालय के सदस्य के रूप में स्थान ग्रहण करता है, अपेक्षित रैंक का है और अधिनियम के अधीन वह निरहित नहीं है और अभियुक्त को उसके बारे में आक्षेप करने का अवसर देगा ऐसे किसी आक्षेप के सम्बंध में अधिनियम और इन नियमों में अधीन कार्यवाही करेगा।

71. सदस्यों द्वारा शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना :— न्यायालय के उचित संख्या में ऐसे आफिसरों की जिनके बारे में आक्षेप नहीं किए गए हैं या जिनके सम्बंध में आक्षेपों को नामंजूर कर दिया गया है, गठन किए जाने पर यथाशीघ्र, प्रत्येक सदस्य को अभियुक्त की उपस्थिति में निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक प्ररूप में या उसी तात्पर्य के ऐसे अन्य प्ररूप में शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा जिसे न्यायालय उसके धर्म के अनुसार या अन्यथा उसके अंतःकरण पर बाध्य समझे।

शपथ का प्ररूप

“मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं न्यायालय के सामने साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त (या अभियुक्तों) का भली भाँति और सच्चाई से विचारण करूँगा तथा मैं पक्षपात, अनुग्रह या स्नेह के बिना असम राइफल्स अधिनियम के अनुसार सम्यक रूप से न्याय प्रदान करूँगा तथा मैं यह और शपथ लेता हूँ कि जब तक कि किसी न्यायालय उसका साक्ष्य दिए जाने के लिए अपेक्षित न हो, तबतक, मैं इस न्यायालय के किसी विशिष्ट सदस्य के मत या राय को किसी कारण से किसी भी समय, चाहे जो भी हो प्रकट नहीं करूँगा, या उसका प्रकटीकरण करूँगा।

प्रतिज्ञान का प्ररूप

"मैं सत्य निष्ठा, ईमानदारी, और सही तौर से घोषणा करता हूँ और प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं न्यायालय के सामने साक्ष्य के अनुसार अभियुक्त (या अभियुक्तों) का भली भाँति और सच्चाई से विचारण करूँगा तथा मैं पक्षपात, अनुग्रह या स्नेह के बिना असम राइफल्स अधिनियम के अनुसार सम्यक् रूप से न्याय प्रदान करूँगा और मैं सत्य निष्ठा, ईमानदारी और सही तौर से यह और घोषणा करता हूँ तथा प्रतिज्ञा करता हूँ कि जब तक कि किसी न्यायालय उसका साक्ष्य दिए जाने के लिए अपेक्षित न हो, तब तक, मैं इस न्यायालय के किसी विशिष्ट सदस्य के मत या राय को किसी कारण से किसी भी समय, चाहे जो भी हो प्रकट नहीं करूँगा, या उसका प्रकटीकरण करूँगा।"

72. विधि आफिसर और अन्य द्वारा शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना :- न्यायालय के सभी सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान करने के पश्चात् निम्नलिखित व्यक्तियों को या उनमें से ऐसे व्यक्तियों को जो न्यायालय में उपस्थित हो निम्नलिखित प्ररूप में से ऐसे प्ररूप में या समान तात्पर्य के ऐसे अन्य प्ररूप में शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान करवाया जाएगा जो न्यायालय शपथ लेने वाले या प्रतिज्ञान करने वाले व्यक्ति के धर्म के अनुसार समुचित हो या अन्यथा उनके अंतःकरण पर वाध्यकारी हो।

(क) विधि आफिसर

शपथ का प्ररूप

"मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी सर्वोत्तम योग्यता से असम राइफल्स असम राइफल्स अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार और पक्षपात, अनुग्रह या स्नेह के बिना विधि आफिसर के कर्तव्यों को कार्यान्वित करूँगा और मैं यह और शपथ लेता हूँ कि जब तक कि किसी न्यायालय में उसका साक्ष्य दिए जाने के लिए अपेक्षित न हो तब तक मैं इस न्यायालय के किसी विशिष्ट सदस्य के मत या राय को किसी कारण से किसी भी समय चाहे जो भी है प्रकट नहीं करूँगा, और न उसका प्रकटीकरण करूँगा।

प्रतिज्ञान का प्ररूप

मैं सत्य निष्ठा ईमानदारी, और सही तौर से घोषणा करता हूँ और प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं अपनी सर्वोत्तम योग्यता से असम राइफल्स अधिनियम और इसके अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार और पक्षपात अनुग्रह या स्नेह के बिना विधि आफिसर के कर्तव्यों को कार्यान्वित करूँगा और मैं यह और शपथ लेता हूँ कि जब तक कि किसी न्यायालय में उसका साक्ष्य दिए जाने के लिए अपेक्षित न हो तब तक मैं इस न्यायालय के किसी विशिष्ट सदस्य के मत या राय को किसी कारण से किसी भी समय चाहे जो भी है प्रकट नहीं करूँगा, और न उनका प्रकटीकरण करूँगा।

(ख) अनुदेश के प्रयोजनों के लिए हाजिर रहने वाला आफिसर

शपथ का प्ररूप

"मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जब तक न्यायालय द्वारा ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए तब तक इस न्यायालय के किसी विशिष्ट सदस्य के मत या राय को किसी भी कारण से किसी भी समय प्रकट नहीं करूँगा, या न उसका प्रकटीकरण करूँगा।।

प्रतिज्ञान का प्ररूप

"मैं सत्य निष्ठा ईमानदारी, और सही तौर से घोषणा करता हूँ और प्रतिज्ञान करता हूँ कि जब तक न्यायालय द्वारा ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए तब तक इस न्यायालय के किसी विशिष्ट सदस्य के मत या राय को किसी भी कारण किसी भी समय चाहे जो भी हो प्रकट नहीं करूँगा या न उसका प्रकटीकरण करूँगा।

(ग) आशुलेखक :-

शपथ का प्ररूप

"मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं अपनी सर्वोत्तम योग्यता से इस न्यायालय के समक्ष दिये जाने वाले साक्ष्य और ऐसे अन्य विषयों को, जिन्हें लिखने की मुझसे अपेक्षा की जायेगी, सही रूप से लिखूँगा और जब अपेक्षा की जाएगी, न्यायालय को उसकी सही अनुलिपि दूँगा।"

प्रतिज्ञान का प्ररूप

मैं सत्य निष्ठा ईमानदारी, और सही तौर से घोषणा करता हूँ कि मैं अपनी सर्वोत्तम योग्यता से इस न्यायालय के समक्ष दिये जाने वाले साक्ष्य और ऐसे अन्य विषयों को जिन्हें लिखने की मुझ से अपेक्षा की जाय, सही रूप से लिखूँगा और जब अपेक्षा की जाए न्यायालय को उसकी सही अनुलिपि, परिदत्त करूँगा।"

(घ) दुभाषिया :-

शपथ का प्ररूप

"मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं इस न्यायालय के सामने रखे जाने वाले विषयों का, जिनका भाषान्तर और अनुवाद करने की मुझसे अपेक्षा की जाए, निष्ठापूर्वक भाषान्तर और अनुवाद करूँगा।"

प्रतिज्ञान का प्ररूप

मैं सत्य निष्ठा, ईमानदारी, और सही तौर से घोषणा करता हूँ और प्रति ज्ञान करता हूँ कि मैं इस न्यायालय के सामने रखे जाने वाले विषयों का, जिनका भाषान्तर और अनुवाद करने की मुझसे अपेक्षा की जाय, निष्ठापूर्वक भाषान्तर और अनुवाद करूँगा।”

73. दुभाषिया या आशुलिपिक के सम्बन्ध में आक्षेप — किसी व्यक्ति को दुभाषिया या आशुलेखक के तौर पर शपथ नहीं दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान नहीं कराया जाएगा, यदि उसके बारे में अभियुक्त द्वारा आक्षेप किया गया हो तबतक दुभाषिये या आशुलेखक के रूप में शपथ नहीं दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान नहीं कराया जाएगा तब तक न्यायालय ने अभियुक्त और अभियोजक की सुनवाई करने के पश्चात् उसे आक्षेप को अयुक्तियुक्त रूप में ना मंजूर कर दिया हो।

74. विधि आफिसर और अभियोजक के बारे में आक्षेप — अभियुक्त को विधि आफिसर या अभियोजक के बारे में आक्षेप करने की अनुमति नहीं होगी।

75. शपथ ग्रहण और प्रतिज्ञान कराने वाले व्यक्ति — सभी शपथ ग्रहण और प्रतिज्ञान, विधि आफिसर, न्यायालय के सदस्य या ऐसी शपथ दिलाए या प्रतिज्ञा करने के लिए न्यायालय द्वारा सशक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कराये जायेंगे।

भाग — 2अभियोजन, प्रतिरक्षा और निष्कर्ष

76. दोषारोपण — (1) न्यायालय और विधि आफिसर के शपथ लेने या प्रतिज्ञान होने के बाद अभियुक्त के विरुद्ध आरोपों के बारे में दोषारोपण किया जायेगा जिसके अंतर्गत आरोपों को पढ़ना और अभियुक्त से पूछना भी है कि क्या वह आरोपों के विरुद्ध दोषी होने या न होने का अभिवाक् करता है।

(2) यदि अभियुक्त के विरुद्ध एक से अधिक आरोप हो, तो उसे प्रत्येक आरोप के लिए अलग से अभिवाक् करना अपेक्षित होगा।

(3) यदि न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के विरुद्ध एक से अधिक आरोप पत्र हो, तो न्यायालय पहले आरोप पत्र पर कार्यवाही शुरू करेगा और उसके निष्कर्ष की उद्घोषणा करेगा और यदि अभियुक्त ने दोषी होने का अभिवाक् किया हो, नियम 93 का अनुपालन किया जायेगा इस आरोप पत्र में दिये गये आरोपों के विरुद्ध दोषारोपण किया जाएगा।

77. अधिकारिता के बारे में अभिवाक् — (1) अभियुक्त आरोप पर अभिवचन करने से पूर्व न्यायालय की अधिकारिता के बारे में अभिवाक् प्रस्थापना कर सकेगा, और ऐसे मामले में :-

(क) अभियुक्त, अभिवाक् के समर्थन में साक्ष्य दे सकेगा और अभियोजक उसके उत्तर में साक्ष्य दे सकेगा; और

(ख) अभिवाक् के उत्तर में अभियोजक न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक के संबोधन का उत्तर दे सकेगा।

(2) यदि न्यायालय अभिवाक् को अनुज्ञात कर लेता है तो अपना विनिश्चय और उसके कारणों को भी उल्लिखित करेगा और संयोजन प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा और न्यायालय स्थगित हो जायेगा।

(3) इस नियम के अधीन जब न्यायालय संयोजन प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा, तो संयोजन प्राधिकारी:-

(क) यदि वह न्यायालय के निर्णय को अनुमोदिन करके अभिवाक् को स्वीकार करता है, तो न्यायालय को विघटित कर देगा।

(ख) यदि वह न्यायालय के निर्णय को अस्वीकृत करता है, या तो - -

(i) मामले को न्यायालय में इस निदेश के साथ वापस भेज देगा कि विचारण को आगे बढ़ाया जाये; या

(ii) अभियुक्त के विचारण के लिए नये न्यायालय का संयोजन करेगा।

78^ए आरोप के प्रति आक्षेप:- (1) अभियुक्त किसी आरोप के विरुद्ध अभिवाक् करने से पहले इस आधार पर आक्षेप कर सकता है कि यह विधि के अनुसार सही नहीं है या इन नियमों के अनुसार गठन नहीं किया गया है, और यदि वह ऐसा करता है तो अभियोजक आक्षेप के उत्तर में न्यायालय को संबोधित करेगा और अभियुक्त अभियोजक के सम्बोधन का उत्तर देगा।

(2) यदि न्यायालय आक्षेप को मान्य ठहराता है, तो वह आरोप को यदि वह नियम 79 के अधीन अनुज्ञेय है संशोधन करेगा या स्थगित करेगा और संयोजन प्राधिकारी को उसकी रिपोर्ट भेजेगा।

परन्तु यदि न्यायालय के समक्ष अन्य आरोप या अन्य आरोप पत्र हैं तो इस नियम के अधीन स्थगन से पहले, अभियुक्त के विरुद्ध ऐसे आरोप या आरोप पत्र पर विचारण की कार्यवाही जारी रखेगा।

(3) इस नियम के अधीन जब न्यायालय संयोजक प्राधिकारी को रिपोर्ट भेजता है, तो संयोजन प्राधिकारी -

(क) यदि वह न्यायालय के निर्णय का अनुमोदन करके आक्षेप को स्वीकार करता है तो -

- (i) न्यायालय को विघटित कर देगा; या
 - (ii) जहाँ न्यायालय के समक्ष अन्य आरोप या अन्य आरोप पत्र है जिससे आक्षेप संबंधित नहीं है और जिसका न्यायालय ने विचारण न किया हो, तो न्यायालय को निदेश देगा कि अभियुक्त की विचारण केवल ऐसे आरोप या आरोप पत्र पर की जाए; या
 - (iii) यदि नियम 77 के अधीन अनुज्ञेय से संबंधित आक्षेप से संबंधित आरोप को संशोधित करेगा और यथा संशोधित के अनुसार विचारण करने के लिए न्यायालय को निदेश देगा।
- (ख) यदि न्यायालय के विनिश्चय को अनुमोदित करके आक्षेप को अनुज्ञात करता है तो —
- (i) आरोप के विचारण के लिए न्यायालय को निदेश देगा; या
 - (ii) अभियुक्त के विचारण के लिए नये न्यायालय का संयोजन करेगा।

79. न्यायालय द्वारा आरोप का संशोधन —

- (1) विचारण के दौरान किसी समय यदि न्यायालय को यह उपसंज्ञात होता है कि आरोप पत्र में—
 - (क) अभियुक्त के नाम या वर्णन में भूल है; या
 - (ख) ऐसी भूल है जो कि लिपिकीय भूल या चूक के कारण हुई हो, तो न्यायालय भूल को सही करने के लिए आरोप पत्र को संशोधित कर सकेगा।
- (2) यदि किसी विचारण के दौरान किसी समय जहाँ विधि आफिसर उपस्थित है या निष्कर्ष देने से पहले न्यायालय को प्रतीत होता है कि न्याय के हित में आरोप में कुछ जोड़ना, लोप या परिवर्तन करना वांछनीय है, जिसे इस नियम के उप नियम (1) के अधीन नहीं किया जा सकता है। तो न्यायालय विधि आफिसर की सहमति से आरोप में जोड़ने, लोपक से या परिवर्तन करने से संबंधित संशोधन करेगा यदि ऐसे जोड़ने, लोपक से नये या परिवर्तन करने से अभियुक्त के साथ कोई अक्रृजु के बिना होना चाहिए।
- (3) किसी विचारण के दौरान किसी भी समय जहाँ विधि आफिसर न हो, निष्कर्ष देने से पहले न्यायालय को प्रतीत होता है कि न्याय के हित में आरोप/आरोपों में कुछ जोड़ना, लोप करना या परिवर्तन करना वांछनीय है जिसे इस नियम के उपनियम(1) के अधीन नहीं किया जा सकता तो न्यायालय स्थगित हो जायेगा और अपनी राय संयोजन प्राधिकारी को भेजेगा जो कि —
 - (क) यदि नियम 80 के अधीन अनुज्ञेय हुआ तो आरोप में संशोधन करेगा और न्यायालय को निदेश देगा कि यथा संशोधित अभियुक्त को संशोधन की सूचना देने के बाद विचारण की कार्यवाही करें; या
 - (ख) न्यायालय को निदेश देगा कि आरोप पर विचारण की कार्यवाही बिना संशोधन किए, जारी रखा जाएगा; या
 - (ग) अभियुक्त के विचारण के लिए नये न्यायालय का संयोजन करेगा।

80. संयोजन प्राधिकारी द्वारा आरोप का संशोधन :— जहाँ न्यायालय, संयोजन प्राधिकारी को नियम 78 या 79 के अधीन रिपोर्ट करता है, तो वे आरोप में कुछ जोड़कर, लोप करके या परिवर्तन करके संशोधन कर सकेगा जिसके बारे में न्यायालय ने रिपोर्ट की है, जो उनकी राय में, न्याय के हित में वांछनीय है और जिसके बारे में उसका समाधान हो जाता है कि अभियुक्त के साथ अक्रृजु किए बिना इसे किया जा सकता है।

81. विचारण में वर्जन का अभिवाक्—

- (1) किसी भी आरोप के विरुद्ध अभिवचन करने से पहले अभियुक्त यह अभिवाक् कर सकेगा कि विचारण धारा 97 या धारा 98 या निम्न आधार पर विचारण का वर्जन कर दिया जाय —
 - (क) नियम 47 के उपनियम (3) में यथा उपवन्धित अपराध के बारे में आरोप खारिज किया जा चुका है; या
 - (ख) सक्षम वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा अपराध का क्षमादान किया जा चुका है या माफ दी जा चुकी हो।
- (2) यदि वह ऐसा अभिवाक् करता है :—
 - (क) अभियुक्त अपने अभिवाक् के समर्थन में साक्ष्य देगा और अभियोजक उसके उत्तर में साक्ष्य दे सकेगा; और
 - (ख) अभियोजक अभिवाक् के उत्तर में न्यायालय को संबोधित करेगा और अभियोजक के संबोधन का अभियुक्त उत्तर दे सकेगा।
- (3) यदि न्यायालय अभिवाक् को मंजूर करता है तो वह उसके समर्थन में संक्षिप्त कारणों के साथ उसे अभिलिखित करेगा और स्थगित करेगा और संयोजन प्राधिकारी को इसकी रिपोर्ट भेजेगा।

परन्तु यदि न्यायालय के समक्ष अन्य आरोप या अन्य आरोप पत्र है, तो न्यायालय इस नियम के अधीन स्थगित होने से पहले अभियुक्त के विरुद्ध ऐसे अन्य आरोप या अन्य आरोप पत्र की विचारण की कार्यवाही करेगा।
- (4) जब न्यायालय संयोजन प्राधिकारी को इस नियम के अधीन रिपोर्ट करता है, तो संयोजन प्राधिकारी —
 - (क) यदि वह न्यायालय के विनिश्चय को अनुमोदित करके अभिवाक् को अनुज्ञात करता है तो —

(i) न्यायालय को विघटित करेगा; या

(ii) जहाँ न्यायालय के समक्ष अन्य आरोप या अन्य आरोप पत्र है, जिससे अभिवाक् संबंधित नहीं है और न्यायालय ने विचारण नहीं किया है, तो न्यायालय को निदेश दे सकता है कि अभियुक्त पर केवल ऐसे अन्य आरोप या आरोप पत्र पर विचारण की कार्यवाही जारी रखें।

(ख) यदि वह न्यायालय के निर्णय को अनुमोदित करके अभिवाक् को अनुज्ञात करवाता है तो -

(i) न्यायालय को निदेश देगा कि आरोप पर अभियुक्त की विचारण करे; या

(ii) जहाँ न्यायालय के समक्ष अन्य आरोप या अन्य आरोप पत्र है जिससे अभिवाक् संबंधित नहीं है और न्यायालय ने उसकी विचारण नहीं किया है तो न्यायालय को निदेश दे सकता है कि अभियुक्त ऐसे अन्य आरोप या आरोप पत्र पर जांच की कार्यवाही जारी रखें।

(iii) अभियुक्त के विचारण के लिए नये न्यायालय का संयोजन करेगा।

82. पृथक विचारण के लिए आवेदन:- (1) जहाँ दो या अधिक अभियुक्तों पर संयुक्त रूप से आरोप लगाया गया हो तो अभियुक्तों में से कोई एक, आरोप में अभिवचन करने से पहले न्यायालय का आवेदन कर सकता है कि उनकी विचारण इस आधार पर अलग से किया जाए यदि उसका विचारण अलग से न किया तो उसकी प्रतिरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(2) जहाँ अभियुक्त ऐसा आवेदन करता है तो अभियोजक न्यायालय को उसके उत्तर में संबोधित करेगा और अभियुक्त अभियोजक के संबोधन का उत्तर दे सकेगा।

(3) जहाँ न्यायालय की राय में न्याय के हित में ऐसा आवश्यक हो, तो वह आवेदन को स्वीकृत करके आवेदन करने वाले अभियुक्त का अलग से विचारण करेगा।

83. पृथक आरोप पत्र पर विचारण के लिए आवेदन :- (1) जहाँ किसी आरोप पत्र में एक से अधिक आरोप सम्मिलित हों तो आरोपों पर अभिवचन प्रारंभ करने से पहले, अभियुक्त न्यायालय को आवेदन कर सकेगा कि उस आरोप पत्र में किसी भी आरोप की विचारण इस आधार पर अलग से किया जाए, यदि उसकी विचारण पृथक से न किया गया तो उसकी प्रतिरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

(2) जहाँ अभियुक्त ऐसा आवेदन करता है तो अभियोजक न्यायालय को उसके उत्तर में संबोधित करेगा और अभियुक्त अभियोजक के संबोधन का उत्तर दे सकेगा।

(3) जहाँ न्यायालय की राय है कि न्याय के हित में ऐसा आवश्यक हो तो वह आवेदन को स्वीकृत करके उससे संबधित आरोप का विचारण अलग से इस प्रकार करेगा मानो वह आरोप पृथक आरोप पत्र में सम्मिलित किया गया हो।

84. आरोप पर अभिवचन :- (1) नियम 77 और नियम 81 के अधीन किसी अभिवाक् और नियम 78 के अधीन आक्षेप और नियम 82 व नियम 83 के अधीन किसी आवेदन पर कार्रवाई हो जाने के पश्चात्, अभियुक्त उपनियम (2) के अधीन प्रत्येक आरोप जिस पर दोषारोपण किया गया है, दोषी होने या न होने का अभिवाक् करेगा। प्रत्येक आरोप पर अभियुक्त के दोषी होने या न होने के अभिवाक् को अभिलिखित किया जायेगा।

(2) जहाँ किसी न्यायालय को धारा 115 के द्वारा सशक्त किया गया है कि अभियुक्त किसी ऐसे अन्य अपराध का दोषी हो जिसके बारे में आरोप न लगाया गया हो या ऐसी परिस्थितियों में अपराध करने का दोषी हो जिसमें कम दंड का हो या जहाँ साक्ष्यों की सुनवाई करके दोषी के बारे में नियम 107 के अनुसार अपवाद या परिवर्तन के अधीन विशेष निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके, तो अभियुक्त ऐसे अन्य अपराध या आरोप लगाये गये अपराध को ऐसी परिस्थितियों में करने का दोषी हो जिसमें कम दंड का उपबंध हो या आरोप लगाये गये अपराध ऐसे अपवाद या परिवर्तन स्वरूप हो, तो वह दोषी होने का अभिवाक् करेगा।

85. दोषी होने के अभिवाक् की स्वीकृति:- (1) जहाँ नियम 84 के उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन अभियुक्त आरोप पर दोषी होने का अभिवचन करता है, तो पीठासीन आफिसर या विधि आफिसर न्यायालय द्वारा अभिवाक् स्वीकार करने से पहले अभियुक्त को आरोप की प्रकृति और उसके अभिवाक् के सामान्य प्रभाव के बारे में समझायेगा और विशेष रूप से अभियुक्त के दोषी होने या न होने के अभिवचन की प्रक्रिया में अन्तर को भी समझायेगा।

(2) जहाँ अभियुक्त दोषी होने का अभिवचन करता है, तो ऐसे अभिवाक् और इस नियम के उपनियम (1) के अनुपालन को निम्नलिखित रीति में अभिलिखित किया जायेगा -

“अभियुक्त के दोषी होने के अभिवाक् को अभिलिखित करने से पहले, न्यायालय ने अभियुक्त को आरोप (आरोपों) का अर्थ समझाया जिनके बारे में उसने दोषी होने का अभिवचन किया था और सुनिश्चित किया कि अभियुक्त ने आरोप की प्रकृति को समझ लिया था जिस पर उसने दोषी होने का अभिवचन किया था। न्यायालय ने अभियुक्त को अभिवाक् के सामान्य प्रभाव और प्रक्रिया के अन्तर को भी समझाया, जिन पर उक्त अभिवाक् के परिणामस्वरूप कार्रवाई की जायेगी। न्यायालय स्वयं का समाधान हो जाने पर कि अभियुक्त आरोप (आरोपों) को समझता है और दोषी होने के अभिवाक् के प्रभावों को स्वीकार करता है और उसको अभिलिखित करेगा। इस प्रकार नियम 85(1) के उपबंधों का अनुपालन किया जाता है।”

(3) नियम 84 के उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन कोई दोषी होने का अभिवाक् स्वीकार नहीं करेगा यदि -

(क) न्यायालय का समाधान नहीं हुआ है कि अभियुक्त आरोप की प्रकृति या उसके अभिवचन के प्रभाव को समझता है; या

(ख) पीठासीन अधिकारी सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विचार करेगा कि अभियुक्त दोषी होने का अभिवाक् करे; या

(ग) यदि अभियुक्त दोष सिद्ध होता है तो मृत्यु दण्डादेश का दायी होगा;

(4) (क) नियम 88 के अधीन दोषी होने के अभिवाक् कर की दशा में, न्यायालय अभिवाक् स्वीकार नहीं करेगा, जब तक कि संयोजक प्राधिकारी सहमति न दें और यह ऐसी अनुक्रम में न्याय का समाधान है।

(ख) संयोजन प्राधिकारी की सहमति पर अभियोजक द्वारा किया गया हो।

(5) जब नियम 84 के उपनियम (1) या उपनियम 2 के अधीन दोषी होने का अभिवाक् न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है या दोषी होने के आरोप के अभिवाक् के लिए इकार करता है या समझे जाने वाला अभिवाक् नहीं करता है, तो न्यायालय दोषी न होने का अभिवाक् अभिलिखित करेगा।

(6) जब न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि नियम 84 के उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन दोषी होने के अभिवाक् को उचित रूप से स्वीकार किया जा सकता है, तो नियम 88 के उपबन्धों का अनुपालन करते हुए, दोषी होने के निष्कर्ष को अभिलिखित किया जाए।

86. अनुकल्पी आरोप पर अभिवाक् -

(1) जब अभियुक्त पहले दो या अधिक अनुकल्पी आरोपों का दोषी होने का अभिवाक् करता है तब न्यायालय अगर दोषी होने का अभिवाक् स्वीकार करता है तो, पहले आरोप का दोषी होने के निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा और अभियोजक आरोपी पर लगाए गए अन्य अनुकल्पी आरोपों को वापस लेगा।

(2) जब कोई अपराधी दो में से एक या अधिक आरोपों के दोषी होने का अभिवाक् करता है, जो कि ऐसे आरोप से भिन्न अनुकल्पी रूप से लगाए गए हैं तो न्यायालय -

(क) इस प्रकार कार्यवाही करेगा जैसे कि अभियुक्त ने सभी आरोपों के दोषी न होने का अभिवाक् किया हो; या

(ख) (i) संयोजन प्राधिकारी की सहमति से (जिस पर अभियोजक द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे) जिसमें अपराधी द्वारा दोषी होने के अभिवाक् और आरोप पत्र में प्रस्तुत किए गए किसी अनुकल्पी आरोप में दोषी न होने के निष्कर्ष के आधार पर अभियुक्त पर दोषी होने के निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा।

(ii) जब न्यायालय ऐसे निष्कर्ष को अभिलिखित करता है तब अभियोजक अभियुक्त के सामने उस पर लगाए गए दोषारोपण के किसी आरोप को वापस ले सकेगा जो आरोप के का अनुकल्पी हैं जिसे न्यायालय ने अभियुक्त को दोषी पाया है और जो आरोप पत्र के अन्त में सम्मिलित किए गए हैं।

87. जहाँ विचारण का आदेश जहाँ दोषी होने या न होने का अभिवाक् किया गया है -

(1) न्यायालय द्वारा दोषी का निष्कर्ष अभिलिखित करने के पश्चात् यदि उसी आरोप पत्र जिसमें अपराधी ने दोषी न होने का अभिवचन किया है और उसी आरोप पत्र में कोई अन्य आरोप नहीं है दोषी न होने का अभिवचन की है, तो नियम 88 के दिए गए निर्देश के अनुसार विचारण की कार्यवाई की जाएगी।

(2) जहाँ आरोप पत्र में दूसरा आरोप हो जिसके लिए अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवचन या है कि (या यहां कोई अन्य अभियुक्त है जिसने दोषी न होने का अभिवचन किया हो), तो न्यायालय नियम 85 का अनुपालन नहीं करेगा, जब तक कि इसे ऐसे अन्य अभियुक्त के साथ कार्यवाही नहीं की जाएगी या ऐसे अन्य अभियुक्त के साथ विचारण नहीं किया जाएगा और घोषणा की गई हो और दोनों के संबंध में निष्कर्ष को अभिलिखित किया गया हो।

88. दोषी होने के अभिवाक् पर प्रक्रिया- (1) जब न्यायालय ने दोषी होने का अभिवाक् अभिलिखित किया हो जिस आरोप के संबंध में अभियुक्त ने दोषी होने का अभिवचन किया है और अभियोजक साक्ष्यों के सारांश या संक्षिप्त सार को पढ़ेगा और इसे कार्यवाई के साथ संलग्न करेगा या न्यायालय को उसमें दिए गए तथ्यों के बारे में बताएगा :-

परंतु यदि साक्ष्य का सारांश या संक्षिप्त सार की परिशोधित प्रति पीठासीन आफिसर को भेजी गयी थी तब अभियोजक, साक्ष्य के सारांश या संक्षिप्त सार को न्यायालय में नहीं पढ़ेगा जिसके बारे में न्यायालय को परिशोधित कर सूचित कर दिया गया है और जबतक न्यायालय में विचारण समाप्त न होने तक मूल सारांश या साक्ष्य के संक्षिप्त सार प्रस्तुत नहीं करेगा।

(2) उप नियम (1) का अनुपालन किए जाने के पश्चात् अभियुक्त -

(क) चरित्र के साक्ष्य और दंड में कमी करने से संबंधित कागजात को प्रस्तुत कर सकेगा और

(ख) दंड में कमी के बारे में न्यायालय को बता सकेगा।

(3) यदि अभियुक्त के कथन या साक्ष्य का सारांश या सार से, या अन्यथा न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त यह नहीं समझता है कि 'दोषी होने' के उसके अभिवाक् का क्या प्रभाव होगा तो न्यायालय अभिलेख में परिवर्तन करेगा और दोषी न होने का अभिवाक् प्रविष्ट करेगा और तदनुसार आगे विचारण जारी रखेगा।

(4) उप नियम (2) और उपनियम (3) का अनुपालन किया जाने पर, न्यायालय नियम 85 के उपनियम (6) और नियम 109 के निर्देशानुसार कार्यवाई जारी रखेगा।

89. अभिवाक् में परिवर्तन — (1) अभियुक्त जिसने दोषी न होने का अभिवचन किया है वह विचार विमर्श समाप्त होने से पहले किसी भी समय न्यायालय के सामने दोषी न होने के अभिवाक् को वापस लेकर इसके निष्कर्ष को बंद कर सकता है और दोषी होने का अभिवाक् दर्ज कर सकता है (इसमें नियम 86 के अधीन दोषी होने का अभिवाक् भी सम्मिलित है) और ऐसे मामले से यदि न्यायालय का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों के अधीन अभियुक्त का परिवर्तित अभिवाक् स्वीकार किया जा सकता है तब अभियुक्त परिवर्तित अभिवचन के अनुसार निष्कर्ष अभिलिखित करें या और जहां तक आवश्यक हो नियम 88 के निर्देशानुसार कार्यवाही जारी रखेगा।

(2) जहाँ विचारण के दौरान किसी भी समय, जब न्यायालय में यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त जिसने दोषी होने का अभिवचन किया है वह अपने अभिवाक् के प्रभाव या आरोप की प्रकृति को नहीं समझता है तो न्यायालय दोषी न होने का अभिवाक् दर्ज करेगा और तदनुसार विचारण जारी रखेगा।

(3) यदि अनुकल्पी रूप में कोई आरोप लगाया गया है जिसे अभियोजक नियम 86 के अधीन वापस लेकर ऐसे अनुकल्पी आरोप को पुनः स्थापित करता है तब न्यायालय उप नियम (2) के अधीन किसी परिवर्तन बदलाव के संबंध में दोषी न होने का अभिवचन अभिलिखित करेगा और अभियुक्त पर दोषारोपण किया जाता है और इसे कभी वापस न लिया हुआ समझते हुए विचारण जारी रखा जायेगा।

90. दोषी न होने के अभिवाक् पर प्रक्रिया: किसी आरोप का दोषी न होने का अभिवाक् अभिलिखित किए जाने के पश्चात् —

(क) न्यायालय अभियुक्त से पूछेगा कि क्या वह विचारण के पूर्व की प्रक्रिया से संबंधित नियमों में से किसी एक का अनुपालन नहीं किया गया है, और इसका इस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या इस आधार पर कि उसे अपनी प्रतिरक्षा की तैयारी करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिला है, के आधार पर स्थगन के लिए आवेदन करना चाहता है; और न्यायालय उसका उत्तर अभिलिखित करेगा :-

(ख) जहां अभियुक्त किसी स्थगन के लिए आवेदन करता है;

(i) अभियुक्त अपने आवेदन के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत करेगा और अभियोजक उसके उत्तर के साक्ष्य प्रस्तुत करेगा; और

(ii) अभियोजक आवेदन के उत्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक के संबोधन का उत्तर दे सकेगा।

(ग) न्यायालय न्याय हित में ऐसा करना अपेक्षित समझने पर स्थगन दे सकेगा।

91. प्रारंभिक संबोधन — (1) अभियोजक, यदि वह ऐसी इच्छा करे या यदि न्यायालय द्वारा यह अपेक्षित हो तो आरोप और उसकी प्रकृति तथा साक्ष्य के सामान्य प्रभावों के बारे में जिन्हें वह प्रस्तुत करना चाहता है व्याख्या करते हुए प्रारंभिक संबोधन करेगा।

(2) तब अभियोजन साक्षियों को बुलाया जाएगा और वे अपना साक्ष्य देंगे।

(3) यदि अभियोजक द्वारा अभियोजन पक्ष को मामले के तथ्य के साक्ष्य देना जरूरी होगा तो वह अपना संबोधन देने के पश्चात् इन्हें देगा और यथास्थिति पहले वह शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा तथा अपना साक्ष्य देगा। अभियुक्त द्वारा या उस की ओर से प्रतिपरीक्षा की जाएगी और इनके पश्चात् भी कोई कथन दे सकता है जिन्हें पुनःपरीक्षा के दौरान साक्षियों द्वारा किया गया है।

92. अतिरिक्त साक्षी — जहाँ अभियोजक साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहता है जो अभियुक्त द्वारा दिए गए साक्ष्यों के सारांश में या संक्षिप्त सार में नहीं है तब साक्ष्य प्रस्तुत करने से पहले युक्तियुक्त समय देकर अभियुक्त को प्रस्तावित साक्ष्य के पूरे विवरण के साथ जहां तक व्यवहार्य हों, ऐसे आशय की सूचना दी जाएगी। यदि ऐसा साक्ष्य ऐसी सूचना या विवरण के बिना दिया जाता है तब न्यायालय, यदि अभियुक्त चाहे साक्ष्य प्राप्त करने के बाद स्थगन कर सकता है या उक्त साक्ष्य से उत्पन्न प्रतिपरीक्षा की अनुज्ञात कर सकेगा और न्यायालय अभियुक्त को स्थगित करने या मुत्तवी करने के लिए आवेदन करने के अधिकार की सूचना देगा।

93. साक्षियों को छोड़ना:— अभियोजक, अभियुक्त के विरुद्ध सभी साक्षियों को बुलाने के लिए बाध्य नहीं है जिनके साक्ष्य, जिसके साक्ष्य साक्ष्यों के सारांश में दिये गये हैं, न ही किसी साक्षी को जिसे अभियुक्त को अधिसूचित किया गया है कि वह नियम 92 के अधीन उसे बुलाना चाहता है, परंतु यदि अभियोजक ऐसे गवाह को साक्ष्य देने के लिए नहीं बुलाना चाहता, तो वह अभियुक्त द्वारा उसे प्रतिपरीक्षा के लिए प्रस्तुत करेगा या अभियुक्त को युक्तियुक्त सूचना देगा कि वह गवाह को नहीं बुलाना चाहता और जहाँ तक व्यवहार्य हो अभियुक्त को उससे संपर्क की अनुज्ञात किया जा सकेगा और उसे प्रतिपक्ष के साक्षी के रूप में बुलाया जाएगा यदि अभियुक्त ऐसा चाहता है तथा साक्षी उपलब्ध है।

94. आवश्यक साक्षी की अनुपस्थिति होने की स्थिति में प्रक्रिया — यदि कोई साक्षी, जिसे न्यायालय के समवेत होने के पूर्व युक्तियुक्त रूप से उपाप्त नहीं कराया जा सका है, जो अभियोजन या प्रतिरक्षा के लिए अनिवार्य है, तो न्यायालय—

(क) ऐसे साक्षी की परीक्षा के लिए कमीशन जारी कराने को उपाप्त करने के लिए उपाय करेगा; या

(ख) यदि यह जनरल या पैटी असम राइफल्स न्यायालय है, तो मामला स्थगित करेगा और परिस्थितियों की रिपोर्ट संयोजन अधिकारी को करेगा; या

- (ग) यदि वह समरी असम राइफल्स न्यायालय है तो, साक्षी को उपस्थित होने के लिए समर्थ करने के लिए मामला स्थगित करेगा या ऐसा अन्य अनुक्रम करेगा जैसा विचारण करने वाले आफिसर को न्याय के लिए सर्वोत्तम प्रतीत हो।
95. न्यायालय से साक्षियों का वापिस किया जाना : विचारण के दौरान अभियोजक या अभियुक्त से भिन्न कोई साक्षी, न्यायालय को इजाजत के बिना न्यायालय में जब वह परीक्षा के अधीन नहीं है, उपस्थित नहीं होगा और यदि जब वह परीक्षा के अधीन है उसके साक्ष्य के भावत कोई चर्चा विमर्श उत्पन्न होती है, चाहे किसी प्रश्न को अनुज्ञात किया गया हो या नहीं तो न्यायालय साक्षी को ऐसी चर्चा के दौरान बाहर जाने के लिए निर्देश दे सकता है।
96. साक्षियों की परीक्षा : (1) बुलाने वाले व्यक्ति द्वारा साक्षी की परीक्षा की जा सकेगी और कार्यवाहीयों के दौरान विरोधी पक्षकार द्वारा प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी और किसी ऐसी प्रतिपरीक्षा के निष्कर्ष पर उस व्यक्ति द्वारा पुनः परीक्षण किया जा सकेगा जिसने प्रतिपरीक्षा से उत्पन्न मामलों के लिए बुलाया गया है।
- (2) (क) साक्षी की परीक्षा करने वाला व्यक्ति मौखिक रूप से अपने प्रश्न पूछेगा और साक्षी, न्यायालय, विधि आफिसर या अभियोजक द्वारा आक्षेप न किए जाने पर, साक्षी तुरंत उत्तर देगा।
- (ख) जहां ऐसा कोई आक्षेप किया जाता है साक्षी तब तक उत्तर नहीं देगा जब तक कि आक्षेप का निपटान न हो जाए।
- (3) न्यायालय स्थगित किए गए साक्षी की प्रतिपरीक्षा या पुनः परीक्षा की अनुमति दे सकेगा।
- (4) साक्षी की परीक्षा से पहले, वह निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी में या समान आश्रय के ऐसे अन्य प्ररूप में जैसा न्यायालय साक्षी के धर्म के अनुसार या अन्यथा उसकी आत्मा पर आबद्धकर अभिनिश्चित करें, शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा।
- शपथ का प्ररूप**
- “मैं, सर्व शक्तिमान् ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं जो कहूँगा सत्य कहूँगा, पूर्ण सत्य कहूँगा और सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा।”
- प्रतिज्ञान का प्ररूप**
- “मैं, सत्यनिष्ठा से, सत्यतापूर्वक और शुद्धहृदय से घोषणा करता हूँ और प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं जो कहूँगा, पूर्णतया सत्य कहूँगा और सत्य के सिवाय कुछ नहीं कहूँगा।”
97. न्यायालय द्वारा प्रश्न (1) पीठासीन अधिकारी, विधि आफिसर और न्यायालय का कोई सदस्य उपस्थित विधि आफिसर या पीठासीन अधिकारी के माध्यम से साक्षी से प्रश्न पूछ सकेगा।
- (2) किसी ऐसे प्रश्न का उत्तर दिए जाने पर अभियोजक और अभियुक्त, साक्षी से उत्तर से संबंधित कोई ऐसा प्रश्न पूछ सकेगा जिसे न्यायालय उपयुक्त प्रतीत हो।
98. साक्ष्य को पढ़ना
- (1) (क) साक्षी द्वारा दिए गए साक्ष्य का अभिलेख उसके न्यायालय छोड़ने से पहले उसे पढ़कर सुनाया जाएगा और ऐसा करते समय वह उसके द्वारा दिए गए साक्ष्य के अभिलेख की ठीक करने या व्याख्या करने के लिए कह सकेगा।
- (ख) जहां ऐसी शुद्धियां की जाती हैं या स्पष्टीकरण किए जाते हैं तब अभियोजक और अभियुक्त शुद्धियों और व्याख्या के संबंध में गवाह से प्रश्न पूछ सकेंगे जो न्यायालय युक्तियुक्त प्रतीत हों।
- (2) जहां आशुलेखक नियोजित हैं तो उप नियम (1) का अनुपालन करना अनिवार्य नहीं होगा, यदि न्यायालय और विधि आफिसर के राय से ऐसा करना आवश्यक न हो :
- परन्तु कोई साक्षी यह मांग करता है कि उप-नियम (1) का अनुपालन किया जाएगा।
99. न्यायालय द्वारा साक्षियों को बुलाना या पुनः बुलाना—
- (1) (क) यदि न्यायालय के राय में ऐसा करना न्याय के हित आवश्यक हो तो न्यायालय इसके निष्कर्ष के लिए विचारविमर्श को समाप्त होने से पहले किसी भी समय या यदि कोई विधि आफिसर है तो वह इसे समाप्त करने से पहले, साक्षी को एक बार या पुनः बुला सकता है।
- (ख) जहां न्यायालय इस नियम के अधीन साक्षी को बुलाता है या पुनः बुलाता है तो अभियोजक और अभियुक्त, साक्षी से प्रश्न पूछ सकते हैं जिन्हें न्यायालय उचित समझे।
- (2) अभियोजक और अभियुक्त किसी भी समय न्यायालय के समक्ष निष्कर्ष पर व विचार विमर्श को समाप्त कर सकते हैं या यदि वहां कोई विधि आफिसर है तो वह समाप्त करने से पहले न्यायालय की अनुमति से साक्षी को पुनः बुला सकता है और अभियोजक और अभियुक्त, साक्षी से प्रश्न पूछ सकते हैं जो न्यायालय उचित समझे।

100. कोई मामला न होने का अभिवाक—

- (1) (क) अभियोजन की ओर से मामले की समाप्ति पर, अभियुक्त किसी आरोप के बारे में न्यायालय में अनुरोध करे कि अभियोजन यह उत्तर देने में असफल रहा है कि उसके विरुद्ध किसी आरोप को प्रथम दृष्टया स्थापित है और उसे उक्त आरोप में अपनी प्रतिरक्षा करने के लिए बुलाने नहीं चाहिए।
(ख) जब अभियुक्त इस प्रकार का अनुरोध करता है, तो अभियोजक उसके उत्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजन के संबोधन का उत्तर दे सकेगा।
- (2) न्यायालय तब तक अनुरोध को अनुज्ञात नहीं करेगा जब तक कि उसका समाधान न हो जाए कि —
(क) अभियोजन ने लगाये गये आरोप पर प्रथम दृष्टया मामला स्थापित नहीं किया है; और
(ख) धारा 115 या नियम 107 के उपनियम (4) के अधीन साक्ष्यों पर विशेष निष्कर्ष बनाना संभव नहीं है।
- (3) (क) जहां न्यायालय अनुरोध करने के अनुज्ञात करता है और अभियुक्त आरोप का दोषी नहीं है जिससे संबंधित है और तो पुष्टि के अधीन निष्कर्ष को यथाशीघ्र खुले न्यायालय के उद्घोषित किया जाएगा।
(ख) जहां न्यायालय प्रस्तुत करने की अनुज्ञात करता है तब लगाए गए आरोप के अधीन विचारण कार्यवाई जारी रखी जाएगी।
- (4) न्यायालय अपने स्वयं के प्रस्ताव में अभियोजन के लिए मामले की सुनवाई बंद होने के पश्चात् और अभियोजक की सुनवाई के पश्चात् अभियुक्त को आरोप में दोषी न पाए जाने पर पुष्टि के लिए न्यायालय में अपने निष्कर्ष यथाशीघ्र खुले न्यायालय में सुनाए।
- (5) जब अभिवाक के निष्कर्ष पर पहुंचने पर नियम 107 के उपनियम (1) के अनुसार न्यायालय कारणों को संक्षिप्ततः अभिलिखित करेगा।

101. प्रतिरक्षा के लिए मामला —

- (1) (क) प्रत्येक विचारण के दौरान, अभियुक्त को व्यक्तिगत रूप से उसके विरुद्ध लगाए गए साक्ष्यों में उपसंज्ञात परिस्थिति के बारे में स्पष्ट के उद्देश्य से न्यायालय या विधि आफिसर—
(i) अभियुक्त को पूर्व चेतावनी दिए बिना विचारण के किसी प्रक्रम पर न्यायालय उससे आवश्यक समझे जाने वाले प्रश्न पूछ सकेगा।
(ii) उपर्युक्त प्रयोजन के लिए, जिन पर अभियोजन के साक्षियों का परीक्षण करने के पश्चात् और उसको अपने बचाव के लिए बुलाए जाने से पहले उससे साधारण या उन मामलों पर प्रश्न पूछ सकेगें।
(ख) अभियुक्त को परीक्षा के दौरान खंड (क) के अधीन शपथ या प्रतिज्ञान कराया जाएगा।
(ग) अभियुक्त ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने से मना करने या असत्य उत्तर देकर अपने आप को सजा के लिए जिम्मेवार नहीं बनाएंगें।
- (2) ऐसे विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा दिए गए उत्तर पर विचार किया जाएगा और किसी अन्य जांच या विचारण के लिए उसके पक्ष या विपक्ष में साक्ष्य रखी जाएगी जिसमें ऐसे उत्तर से यह प्रतीत होता है कि उसने कोई अन्य अपराध किया है।
- (3) अभियोजन के लिए मामला समाप्त होने के पश्चात्, पीठासीन आफिसर या विधि आफिसर, अभियुक्त को स्पष्ट करेंगे कि —
(क) यदि वह चाहे तो साक्षी के रूप में शपथ लेकर साक्ष्य दे सकता है या बिना शपथ या प्रतिज्ञान के कथन कर सकता है, किन्तु वह ऐसा करने के लिए वाध्य नहीं है।
(ख) यदि वह शपथ के साथ साक्ष्य देता है तो वह अभियोजक द्वारा प्रतिपरीक्षा लेने और न्यायालय द्वारा प्रश्न पूछे जाने का दायी होगा।
- (4) यदि अभियुक्त मामले का तथ्य के साक्षी का अपने से भिन्न किसी साक्षी को बुलाना चाहता है तो वह प्रतिरक्षा में साक्ष्य देने से पहले प्रतिरक्षा के लिए मामले के संक्षेप के पहले कथन कर सकेगा।

102. प्रतिरक्षा के लिए साक्षी (1) प्रतिरक्षा के लिए साक्षी के नियम 101 का अनुपालन करने के पश्चात् जिसमें चरित्र के साक्षी भी है, को साक्ष्य देने के लिए बुलाया जाएगा।

- (2) नियम 96, 97 और 98 के उपबंध जो अभियोजन के साक्षियों के साक्ष्य के लिए लागू किए जाते हैं, वह प्रतिरक्षा के साक्षियों के लिए भी लागू होंगे।

103. उत्तर में साक्षी : प्रतिरक्षा के साक्षी द्वारा उनके साक्ष्य देने के पश्चात् अभियोजक, न्यायालय की अनुमति से, अभियुक्त द्वारा अपने प्रतिरक्षा में उठाए गए मामले पर साक्ष्य देने के लिए साक्षी को एक बार बुला सकेगा या पुनः बुला सकेगा, जिन्हें अभियोजन ने पहले न्यायालय में उचित रूप में अधिकृत न कर सका हो या अभियोजन पक्ष युक्ति युक्त रूप से पहले न देख सका हो।

104. समापन संबोधन (1) सभी साक्ष्य देने के पश्चात् अभियोजक समापन संबोधन दे सकेगा और यथास्थिति, अभियुक्त या उसका काउन्सेल या प्रतिवाद आफिसर उत्तर देने का हकदार होंगे।

परंतु जहां अभियुक्त द्वारा विधि से संबंधित कोई बिन्दु उठाया जाता है तब अभियोजक न्यायालय की अनुमति से उस बिन्दु के संबंध में निवेदन करेगा।

(2) यदि एक ही प्रतिवाद अधिकारी या काउन्सेल द्वारा दो या अधिक अभियुक्तों का प्रतिनिधित्व किया जा रहा हो तो वह केवल एक का ही समापन संबोधन कर सकेगा।

105. विधि आफिसर द्वारा उपसंहार करना: समापन संबोधन के पश्चात् यदि जहां विधि आफिसर हो, खुले न्यायालय में साक्ष्य का उपसंहार करेगा और मामले से संबंधित विधि के अधीन पर न्यायालय को सलाह देगा।

106. निष्कर्ष पर विचार — विमर्श : (1) न्यायालय, विधि आफिसर की उपस्थिति में, बंद न्यायालय में अपने निष्कर्ष पर विचार विमर्श करेगा।

(2) न्यायालय का प्रत्येक सदस्य प्रत्येक आरोप पर पृथक-पृथक निष्कर्ष के बारे में अपनी राय मौखिक रूप से देगा जो सबसे कनिष्ठ रैंक से आरंभ होगी।

107. निष्कर्षों का अभिलेख और घोषणा (1) ऐसे प्रत्येक आरोप पर, जिस पर अभियुक्त दोषारोपित किया गया है, निष्कर्ष अभिलिखित किया जाएगा और इन नियमों में जैसा उपबंधित है उसके सिवाय, दोषी होने या दोषी न होने के निष्कर्ष के रूप में अभिलिखित किया जाएगा। प्रत्येक आरोप के निष्कर्ष को अभिलिखित करने के पश्चात् न्यायालय इसके समर्थन में संक्षिप्त कारण देगा। विधि आफिसर या, यदि न हो तो पीठासीन आफिसर अभिलिखित करेगा या कार्यवाई में ऐसे संक्षिप्त कारण के साथ मामला अभिलिखित किया जाएगा। उपरोक्त अभिलेख पीठासीन आफिसर और विधि आफिसर, यदि कोई हो, द्वारा हस्ताक्षरित और तारीखबद्ध किया जाएगा।

(2) जहां किसी आरोप की बाबत न्यायालय की राय है कि साबित किए गए तथ्यों से आरोपित अपराध या ऐसा कोई अपराध कारित नहीं होता है, जिसका कि वह लगाए गए आरोप पर अधिनियम के अधीन वैध रूप से दोषी पाया जा सके तो न्यायालय अभियुक्त की उक्त आरोप से दोषमुक्त कर देगा।

(3) यदि न्यायालय को किसी आरोप की बाबत ऐसा संदेह है कि साबित तथ्यों से यह दर्शित होता है कि अभियुक्त आरोपित अपराध का दोषी पाया जा सकता है, तो वह उस आरोप पर निष्कर्ष अभिलिखित करने से पहले, पुष्टि करने वाले प्राधिकारी को उसकी राय के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा और, यदि आवश्यक हो तो उस प्रयोजन के लिए स्थगित कर सकेगा।

(4) जहां किसी आरोप के बारे में न्यायालय की राय है कि वे तथ्य जो यदि साक्ष्य से साबित हो गए हैं, आरोप में विशिष्टियों के कथन में अधिकथित तथ्यों से तात्त्विक रूप से भिन्न हैं, किन्तु फिर भी आरोप में कथित अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त है, और विभिन्नता इतनी तात्त्विक नहीं है जिससे अभियुक्त की प्रतिरक्षा पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़े, तो "न्यायालय दोषी न होने" के निष्कर्ष की बजाए विशेष निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

(5) विशेष निष्कर्ष में अभियुक्त को किसी आरोप का, उससे विनिर्दिष्ट अपवादों या उसमें विनिर्दिष्ट के कथन के अधीन रहते हुए दोषी ठहराया जा सकेगा।

(6) जहां अनुकल्पी आरोपों की दशा में, और यह साबित हो जाने पर कि तथ्यों से न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि उन वैकल्पिक आरोपों में से किसी में वर्णित अपराध नहीं गठित होता है, न्यायालय उस आरोप पर दोषी न होने का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

(7) न्यायालय, अभियुक्त को अनुकल्पी अधिकथित दो में या अधिक आरोपों में से एक से अधिक को दोषी नहीं पाता है भले ही एक आरोप पर संयुक्त दोषसिद्धि से आवश्यक रूप से अनुकल्पी आरोप या आरोपों का दोषी होने का संकेत मिलता हो।

(8) यदि न्यायालय का बिचार करता है कि साबित हो गए तथ्यों से दो या अधिक अनुकल्पी आरोपों में कथित अपराधों में से कोई एक बनता है किन्तु उसे इस बाबत संदेह है कि उन तथ्यों से विधितः कौन सा अपराध बनता है तो वह, उन आरोपों पर निष्कर्ष अभिलिखित करने से पूर्व, उन तथ्यों को उपवर्णित करते हुए, जिनके बारे में उसका निष्कर्ष है कि वे साबित हो गए हैं और यह कथन करते हुए कि वे संदेह में हैं कि उन तथ्यों से ऐसे एक या अन्य आरोपों में कथित अपराध विधितः बनता है या नहीं, पुष्टि करने वाले प्राधिकारी को उसकी राय के लिए निर्दिष्ट कर सकेगा और यदि आवश्यक हो तो इस प्रयोजन के लिए स्थगित हो सकेगा।

(9) प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष, पुष्टिकरण किए जाने के अधीन रहते हुए खुले न्यायालय में तत्काल उद्घोषित किया जाएगा।

108. दोषमुक्त किए जाने की दशा में प्रक्रिया : यदि सभी आरोपों पर दोषी न होने का निष्कर्ष है तो पीठासीन अधिकारी निष्कर्ष पर हस्ताक्षर करेगा और तारीख लिखेगा और सम्पूर्ण कार्यवाही ऐसे हस्ताक्षर से अधिप्रमाणीकृत हो जाएगी, और विधि आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित कर दिए जाने पर कार्यवाहियां पुष्ट किए जाने के लिए तुरंत पारंपरिक कर दी जाएगी।

109. दोषसिद्ध होने की दशा में प्रक्रिया : (1) यदि किसी आरोप पर दोषी होने का निष्कर्ष है तो न्यायालय, दण्डादेश अवधारित करने में अपने मार्गदर्शन के लिए और दण्डादेश पर विचार करने में पुष्टि करने वाले प्राधिकारी के मार्गदर्शन के लिए, दण्डादेश अवधारित करने के पूर्व अभियुक्त के साधारण चरित्र, आयु, सेवा, रैंक और उसको वीरतापूर्ण मान्यताप्राप्त कार्यों का या उसके विशिष्ट आचरण का और बल के न्यायालय या दण्ड न्यायालय द्वारा अभियुक्त की पूर्व दोषसिद्धियों का यथास्थिति, धारा 65, धारा 67, धारा 68, या धारा 69 के अधीन प्राधिकार का प्रयोग करने वाले किसी अधिकारी द्वारा अभियुक्त के बारे में अधिनिर्मित किए गए किसी पूर्व दण्ड का उस अवधि का जिसमें वह किसी पूर्व दण्ड के लिए गिरफ्तार या बंदी रहा है, और किसी अलंकरण या इनाम का, जो उसके कब्जे में है या जिसका वह हकदार है, साक्ष्य लेगा और उसे अभिलिखित करेगा।
- (2) किसी साक्षी द्वारा ऐसा कथन सत्यापित करके उपर्युक्त मामलों में साक्ष्य दिया जा सकेगा जिसमें सेवा पुस्तिका में अभियुक्त की बाबत प्रविष्टियों सारांश होगा और उस सारांश में निर्दिष्ट व्यक्ति के रूप में अभियुक्त की पहचान की जाएगी।
- (3) अभियुक्त किसी ऐसे साक्षी की प्रतिपरीक्षा कर सकेगा और ऐसे साक्ष्य का खण्डन करने के लिए साक्षियों को आहूत कर सकेगा; और यदि अभियुक्त ऐसा निवेदन करता है तो सेवा पुस्तिका और उनकी तात्त्विक प्रविष्टियों की सम्यक् प्रमाणित प्रतिलिपि पेश की जाएगी और यदि अभियुक्त अभिकथित करता है कि सारांश किसी विषय में सेवा पुस्तिका या ऐसी प्रमाणित प्रतिलिपि के अनुसार नहीं है तो न्यायालय सारांश की तुलना में उन पुस्तिकाओं या प्रतिलिपि से करेगा और यदि यह निष्कर्ष निकलता है कि सारांश उनके अनुसार नहीं है तो वह सारांश को शुद्ध कराएगा या अभियुक्त के आक्षेप को अभिलिखित किया जाएगा।
- (4) जब उपर्युक्त मामलों पर सभी साक्ष्य दे दिए जाएं तब अभियुक्त उनके बारे में और दण्ड को कम करने के बारे में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा।
110. दण्डादेश : न्यायालय सारे अपराधों की बाबत, जिनका अभियुक्त दोषी पाया जाता है, एक दण्डादेश अधिनिर्णीत करेगा और जहां ऐसा दण्डादेश विधिक रूप से दिया जा सकता है, अधिनिर्णीत समझा जाएगा और जहां ऐसा दण्डादेश विधिक नहीं दिया जा सकता, अधिनिर्णीत नहीं समझा जाएगा।
111. दया की सिफारिश :- (1) यदि न्यायालय दया की सिफारिश करता है तो वह अपनी सिफारिश के कारणों का उल्लेख करेगा।
- (2) उन राय की संख्या, जिससे इस नियम में वर्णित दया या उससे संबंधित किसी प्रश्न के बारे में सिफारिश स्वीकार की जा सकती है या अस्वीकार की जाती है उसे कार्यवाहियों में दर्ज किया जायेगा।
112. दण्डादेश का आख्यापन और कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करना और उनका पारेषण - (1) दया की किसी सिफारिश और ऐसी सिफारिश के कारणों सहित दण्डादेश खुले न्यायालय में तत्काल आख्यापित किए जाएंगे। दण्डादेश पुष्ट किए जाने की शर्त के अधीन स्थापित किया जाएगा।
- (2) न्यायालय द्वारा दण्डादेश अधिनिर्णीत किए जाने पर, पीठासीन अधिकारी दण्डादेश पर हस्ताक्षर करेगा और तारीख डालेगा और ऐसे हस्ताक्षर से सम्पूर्ण कार्यवाही अधिप्रमाणीकृत हो जाएगी और विधि आफिसर यदि कोई हो द्वारा हस्ताक्षरित कर दिए जाने पर कार्यवाहियां पुष्ट किए जाने के लिए तुरंत पारेषित कर दी जाएंगी।

पुष्टि और पुनरीक्षण

113. पुनरीक्षण -
- (1) (क) जहाँ निष्कर्ष धारा 135 के अधीन पुनरीक्षण के लिए वापिस भेजा जाता है तो न्यायालय खुले न्यायालय में पुनः समवेत होगा, पुनरीक्षण आदेश पढ़ा जाएगा और यदि न्यायालय को नए सिरे से साक्ष्य लेने के लिए निर्देश है तो, ऐसा साक्ष्य खुले न्यायालय में लिया जाएगा;
- (ख) जहाँ न्यायालय द्वारा नये साक्ष्य लेने का निदेश मिलने के सिवाय नये साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए जाएंगे;
- (ग) जहाँ अभियुक्त के अनुरोध से भिन्न जहाँ नये साक्ष्य अभिलिखित किए जाते हैं वहाँ अभियुक्त को ऐसे नए साक्ष्य से उत्पन्न मामलों के आगे साक्ष्य देने का अवसर दिया जाएगा ;
- (घ) न्यायालय, अभियोजक के अनुरोध पर न्याय के हित में प्रतिरक्षा के साक्षी द्वारा पुनरीक्षण के दौरान दिए गए किसी सारवान कथन का खंडन करने के लिए साक्षी को बुलाने या पुनः बुलाने की अनुज्ञात कर सकेगा।
- (ङ) उपर्युक्त खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) के अनुसार, यदि कोई साक्ष्य दिए गए हों तो अभियोजक और अभियुक्त को नियम 104 में यथा अधिकथित आदेश में, नये साक्ष्य के संबंध में न्यायालय को संबोधित करने का अवसर दिया जाएगा।
- (च) विधि आफिसर यदि कोई हो, अतिरिक्त साक्ष्य का उपसंहार करेगा और न्यायालय को मामलों के संबंध में विधि पर सलाह देगा।
- (2) जहाँ निष्कर्ष के पुनरीक्षण में जहाँ नए साक्ष्य शामिल नहीं हैं, वहाँ अभियुक्त के पुनरीक्षण आदेश में उठाए गए मामले पर न्यायालय को संबोधित करने का अवसर दिया जाएगा।
- (3) (क) अतः न्यायालय, बंद न्यायालय में अपने निष्कर्ष पर विचार विमर्श करेगा और यदि न्यायालय अपने पूर्व निष्कर्ष का समर्थन नहीं करता है तो निष्कर्ष और दंडादेश को प्रतिसंहरण किया जाएगा और नियम 107 में अभिकथित रीति

में नए निष्कर्ष अभिलिखित किया जाएगा और यदि नए निष्कर्ष में दंडादेश अतर्वलित है तो नियम 109 का अनुपालन करने के पश्चात् नया दंडादेश पारित करेगा।

(ख) जहां मूल निष्कर्ष में कोई दोषी न पाया गया हो, तो न्यायालय दंडादेश पारित करने के पहले नियम 109 और 110 का अनुपालन करेगा।

(4) (क) जहां केवल दण्डादेश ही पुनरीक्षण के लिए वापस भेजा जाता है वहां पुनरीक्षण आदेश खुले न्यायालय में पढ़ा जाएगा और अभियुक्त को पुनरीक्षण आदेश में दिए गए मामलों पर न्यायालय को संबोधित करने का अवसर दिया जाएगा।

(ख) न्यायालय, बंद न्यायालय में अपने दंडादेश पर पुनः विचार करेगा और यदि वह दंडादेश का समर्थन नहीं करता तो उसे रद्द करके और नए दंडादेश पारित करेगा।

(5) जहां केवल दंडादेश ही पुनरीक्षण के लिए वापस भेजा जाता है, वहां न्यायालय निष्कर्ष का पुनरीक्षण नहीं करेगा।

(6) पुनरीक्षण के पश्चात्, पीठासीन आफिसर, न्यायालय के विनिश्चय पर तारीख डालेगा और हस्ताक्षर करेगा और विधि आफिसर, यदि कोई हो, द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने पर कार्यवाहियां पुष्ट करने के लिए तुरंत पारित कर दी जाएंगी।

114.

पुष्टिकरण - (1) जब पुष्टि प्राधिकारी द्वारा न्यायालय की कार्यवाहियों का अभिलेख मिलने पर, इसमें दिया गया निर्णय और कोई दंडादेश और कोई आदेश जिन्हें परिशिष्ट-10 में दिए गए कार्यवाहियों के अभिलेख से धारा 127 के अधीन किए गए हैं और उसके निर्णय का यह अभिलेख कार्यवाहियों का अभिलेख समझा जाएगा।

(2) जब कोई न्यायालय नियम 85 के अधीन दोषी होने का अभिवाक् स्वीकार करता है, तो पुष्टिकरण प्राधिकारी अपने निष्कर्षों की पुष्टि करेगा, यदि पुष्टि प्राधिकारी की राय में ऐसा करना न्याय के हित में है फिर चाहे न्यायालय ने संयोजक प्राधिकारी की सहमति के बिना अभिवाक् स्वीकार कर लिया हो।

(3) (क) जब कोई न्यायालय, न्यायालय का अधिकारिता के अभिवाक् या विचार के लिए वर्जन के अभिवाक् को नामंजूर कर देता है या किसी आरोप के आक्षेप के विरुद्ध निर्णय देता है, तब पुष्टिकरण प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन करने, विशेषकर न्यायालय के निर्णय को अनुमोदन करना जरूरी नहीं है, किन्तु अभिवाक् या आक्षेप से संबंधित आरोप के निष्कर्ष की पुष्टि पर अनुमोदन समाविष्ट किया जाएगा।

(ख) जहाँ अभिवाक् रद्द करने के लिए न्यायालय के विनिश्चय या आक्षेप के विरुद्ध निर्णय को अनुमोदित किया जाता है तो अभिवाक् या आक्षेप से संबंधित आरोप के निष्कर्ष की पुष्टि करने से इंकार किया जाएगा।

(4) पुष्टिकरण प्राधिकारी किसी भी मामले में पुष्टि न करने के कारणों को अभिकथित करेगी किन्तु यदि न्यायालय ने अधिकारिता का अभिवाक् रद्द किया गया है या विचारण के वर्जन के अभिवाक् या आरोपों पर किसी आक्षेप को नामंजूर कर दिया है यदि यह नियमों के उल्लंघन पर पुष्टि रोकी जाती है क्योंकि वे न्यायालय के इस विनिश्चय को अनुमोदन करते हैं, तब वे उप नियम (1) के अधीन पुष्टि रोकने का कारण अभिलिखित करते हुए अपने विनिश्चयों को अभिलिखित करेंगे।

(5) जहां न्यायालय के दण्डादेश की अभिव्यक्ति सही रूप में न की गई हो तो पुष्टि करने वाला प्राधिकारी दण्डादेश की पुष्टि करते समय उसके प्ररूप में फेरफार कर सकेगा जिससे कि वह उचित प्ररूप में हो जाएं, और यदि दण्डादेश द्वारा अधिनिर्णीत दण्ड विधि द्वारा प्राधिकृत दण्ड से अधिक है तो पुष्टि करने वाला प्राधिकारी दण्डादेश में फेरफार कर सकेगा, जिससे कि दण्डादेश विधि द्वारा प्राधिकृत दण्ड से अधिक न हो और पुष्टि करने वाला प्राधिकारी सेना न्यायालय के ऐसे फेरफार किए गए निष्कर्ष और दण्डादेश की पुष्टि कर सकेगा।

(6) जब ऐसा प्रतीत हो कि नियम 85 के उपनियम (1) या उपनियम (2) के अधीन न्यायालय के निष्कर्ष को न्याय संगत बनाने के लिए दोषी होने के अभिवाक् के पर्याप्त साक्ष्य है तब ये निष्कर्ष और अन्य विधिमान्य दंडादेश की पुष्टि की जाएगी और यदि अभियुक्त पर इन परिवर्तनों का कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा तो इन नियमों में विचलन के होते हुए भी इनकी पुष्टि की जाएगी और यह विधिमान्य होंगे।

(7) धारा 132 के अधीन जारी वारंट में दिए गए ऐसे प्रतिबंध, आरक्षण या शर्तों यदि लगाना अपेक्षित हो तो पुष्टिकरण प्राधिकारी, पुष्टि के लिए ज्येष्ठ आफिसर को आरक्षित कर सकेगा।

115.

पुष्टिकरण के दौरान दण्ड कम किया जाना - (1) जब निष्कर्ष की पुष्टि के दौरान पुष्टिकरण प्राधिकारी या तो बिना शर्त या अभियुक्त द्वारा स्वीकार शर्तों के अधीन दण्डादेश में कमी या दण्ड का किसी भाग माफ दे सकेगा या धारा 57 में दंड को कम करने माफ को दंड को लघुकरण कर सकता है।

(2) जहां विभिन्न आरोपों में अपराधों की बाबत किसी न्यायालय द्वारा किसी दण्डादेश अधिनिर्णीत किया गया है और पुष्टि करने वाला प्राधिकारी ऐसे आरोपों में से कुछ के निष्कर्षों की पुष्टि करता है किन्तु ऐसे सभी आरोपों की नहीं, तो वह प्राधिकारी ऐसी अपुष्टिकरण के तथ्य पर विचार करेगा और यदि उसे न्यायसंगत प्रतीत होता है तो उन निष्कर्षों की बाबत जो पुष्ट कर दिए गए हैं, आरोपों में अपराधों का ध्यान रखते हुए, अधिनिर्णीत दण्ड को, जैसा उसे न्यायसंगत प्रतीत हो उसके अनुसार कम करेगा, उसका परिहार करेगा या लघुकरण करेगा।

(3) जहां किसी न्यायालय द्वारा विभिन्न आरोपों के अपराधों की बाबत दण्डादेश अधिनिर्णीत किया है और उसकी पुष्टि कर दी जाती है तथा ऐसे आरोपों में से कोई एक या उन निष्कर्षों में से कोई एक अधिविधान्य पाया जाता है तो दण्डादेश द्वारा अधिनिर्णीत दण्ड को कम करने, उसका परिहार करने या परिवर्तन करने की शक्ति रखने वाले प्राधिकारी ऐसी अधिविधान्यता के तथ्य पर विचार करेगा और यदि उसे न्यायसंगत प्रतीत होता है तो उन आरोपों में अपराधों को ध्यान में रखते हुए, जो

और जिनके निष्कर्ष अविधिमान्य नहीं हैं, अधिनिर्णीत दण्ड को, जैसा उसे न्यायसंगत प्रतीत हो उसके अनुसार, कम करेगा, उसका परिहार करेगा या लघुकरण करेगा और इस प्रकार उपांतरित के दण्डादेश का लघुकरण वैसे ही विधिमान्य होगा मानो वह केवल उन अपराधों की बाबत मूलरूप से अधिनिर्णीत किया गया था।

116. प्रख्यापन—(1) जब कोई पुष्टिकरण प्राधिकारी निष्कर्ष या न्यायालय के दंडादेश की पुष्टि करता है या उसकी पुष्टि को रोकता है तब कार्यवाहियों का अभिलेख अभियुक्त के कमांडेंट को अभियुक्त के आरोप, निष्कर्ष और दण्डादेश और दया की सिफारिश या सच्चाई के प्रख्यापन के लिए भेजा जाएगा, जिसके कारण पुष्टि को रोका गया था।

(2) प्रख्यापन का तथ्य परिशिष्ट-11 में दिए गए प्ररूप में कार्यवाहियों के अभिलेख को अभिलिखित किए जाएंगे।

(3) पुष्टिकरण प्राधिकारी न्यायालय की अधिकारिता का अभिवाक् नामजूर करने या विचारण का वर्जन के अभिवाक् या आरोप पर नियमों का आक्षेप को नामजूर करने पर न्यायालय के विनिश्चय को अस्वीकृत करते हुए पुष्टि को रोकता है तो अभियुक्त को इसके बारे में सूचित किया जाएगा।

(4) जब तक पुष्टि पूर्ण नहीं होता है और निष्कर्ष और दंडादेश को पुष्टि के लिए नहीं रोका जाता तब तक प्रख्यापन प्रभावित होगा।

अध्याय 11

बल न्यायालय और अनुबन्धित मामलों की प्रक्रिया

117. सदस्यों का स्थान : न्यायालय के सदस्य अपनी ज्येष्ठता के अनुसार स्थान ग्रहण करेंगे।

118. पीठासीन अधिकारी के उत्तरदायित्व—(1) पीठासीन अधिकारी विचारण को उचित व्यवस्था में और अधिनियम तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार तथा न्यायालय के अनुकूल रीति में, संचालित किए जाने के लिए उत्तरदायी है।

(2) पीठासीन अधिकारी का यह ध्यान रखने का कर्तव्य है कि अभियुक्त का निष्पक्ष विचारण हो और विचारण के अधीन व्यक्ति के रूप में उसकी स्थिति या उसकी अनभिज्ञता या साक्षियों की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा करने में उसकी अयोग्यता के परिणामस्वरूप या अन्यथा उसका कोई अहित न हो।

119. अभियोजक और अभियुक्त के सम्बन्धन की बाबत न्यायालय की शक्ति—(1) अभियोजक का यह कर्तव्य होगा कि वह न्याय प्रशासन में न्यायालय की सहायता करें, पक्षपात रहित व्यवहार करे, न्यायालय के समक्ष सभी व्यवहार लाएं और अभियुक्त के पक्ष में किसी साक्ष्य का कोई अनुचित लाभ न उठाए या उसे न दबाएं।

(2) अभियोजक, किसी ऐसे विषय को निर्दिष्ट नहीं कर सकेगा, जो उस समय न्यायालय के सामने आरोप या आरोपों से संबंधित नहीं है, और उसे ऐसा करने से रोकना और अभियोजक को अनुचित अतिक्रमण को रोकना तथा अभियोजन युक्तियुक्त की व्यवहार की इच्छा करना न्यायालय का कर्तव्य होगा।

(3) न्यायालय अभियुक्त को अपना बचाव करने के लिए युक्तियुक्त सुविधा प्रदान करेगा, अभियुक्त को उसे न्यायालय के प्रति अवहेलनापूर्ण या अनादरपूर्ण टिप्पणियों से और अन्य के प्रति अशिष्ट और अपमानजनक भाषा के प्रयोग से बचना चाहिए, किंतु वह अपनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए साक्ष्य पर और साक्षियों और अभियोजक के इशारों पर अभियोग लगा सकेगा तथा अन्य व्यक्तियों पर दोषारोपण कर सकेगा और अपराधिता का भी आरोप लगा सकेगा किंतु यदि वह ऐसा करता है तो वह उसके कारण उत्पन्न दायित्व के अधीन होगा। न्यायालय अभियुक्त को उसकी प्रतिरक्षा की अप्रासंगिकता के प्रति सावधान कर सकेगा, किंतु जब तक कि विशेष मामला न हो, उसकी प्रतिरक्षा पूर्ण रूप से ऐसी अप्रासंगिकता के आधार पर नहीं रोकेगी।

120. बंद न्यायालय में बैठक—(1) न्यायालय, जहां इन नियमों द्वारा ऐसा निदेशित है, बंद न्यायालय में करेगा और किसी अन्य मामले में भी सदस्यों के बीच किसी विचार-विमर्श के लिए, बंद न्यायालय में बैठक कर सकेगा।

(2) बंद न्यायालय में न्यायालय के सदस्यों, विधि आफिसर और अनुदेश के अधीन कोई अन्य आफिसर के सिवाय कोई अन्य व्यक्ति उपस्थित नहीं होगा।

(3) इस नियम के पूर्ववर्ती उपबंधों को प्रभावी करने के प्रयोजन के लिए, न्यायालय या तो निवृत्त हो सकेगा या उस स्थान को ऐसे सभी अन्य व्यक्तियों से खाली करा सकेगा जो वहां उपस्थित होने के हकदार नहीं हैं।

(4) इसमें इसके पूर्व वर्णित के सिवाय, सभी कार्यवाहियां जिसके अंतर्गत किसी स्थान का अवलोकन भी है, खुले न्यायालय में और उपनियम (5) के अधीन रहते हुए, अभियुक्त की उपस्थिति में की जाएगी।

(5) न्यायालय को किसी ऐसे साक्षी को, जिसे अभी साक्ष्य देना है या अभियुक्त से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति को, जो उसकी कार्यवाहियों में हस्तक्षेप करें, हटा देने की शक्ति होगी।

121. न्यायालयों की कार्यवाही सार्वजनिक रूप से होना :—नियम 120 के अधीन वह जगह जहां अधिनियम के अधीन अपराध की जांच के उद्देश्य से न्यायालय आयोजित किया जाता है उसे खुला न्यायालय समझा जाएगा, जहां लोग आसानी से पहुँच सकें और वे वहां आसानी से बैठ सकेंगे।

परन्तु यदि न्यायालय का समाधान हो जाता है कि लोक हित में समीचीन न्याय के उद्देश्य से यह आवश्यक या है तो न्यायालय किसी विशेष मामले के विचारण के दौरान आदेश दे सकता है कि सामान्य लोग या कुछ लोग या कोई विशिष्ट व्यक्ति ऐसी जगह नहीं जा सकते जहां न्यायालय आयोजित किया गया है।

122. विचारण का जारी रखा जाना और स्थगन— (1) न्यायालय जब एक बार समवेत कर दिया जाता है और अभियुक्त दोषारोपित कर दिया जाए जब न्यायालय, विचारण दिन प्रतिदिन जारी रखेगा जब तक कि न्यायालय को यह प्रतीत नहीं हो जाता है कि न्याय की दृष्टि से स्थगन आवश्यक है या विचारण इस प्रकार जारी रखना अनावश्यक है।

(2) (क) न्यायालय समय-समय पर इसकी कार्यवाहियां स्थगित कर सकेगा और ऐसे स्थान पर आयोजित कर सकता है जो सुविधाजनक हो, और

(ख) जब आवश्यक हो, घटना के स्थान का अवलोकन कर सकेगा।

(3) उपस्थित ज्येष्ठ अफसर भी, सेवा की अत्यावश्यकताओं के कारण, न्यायालय का स्थगन कर सकेगा या स्थगन को बढ़ा सकेगा।

(4) न्यायालय, विधि आफिसर की अनुपस्थिति में (यदि किसी को उस न्यायालय के लिए नियुक्त किया गया है) अग्रेसर नहीं होगा और स्थगित हो जाएगा।

(5) यदि वह समय, जिसके लिए स्थगन किया जाता है, विनिर्दिष्ट नहीं है तो, उचित बल प्राधिकारी का अगला आदेश होने तक के लिए स्थगन होगा, और यदि यह स्थान, जिसके लिए स्थगन किया गया है, विनिर्दिष्ट नहीं है तो स्थगन उसी स्थान या ऐसे अन्य स्थान के लिए होगा और उचित बल प्राधिकारी के अगले आदेशों में विनिर्दिष्ट किया जाए।

123. विचारण का निलंबन— (1) जहां न्यायालय की बैठक के समय उत्पन्न किसी बात के परिणामस्वरूप, न्यायालय धारा 93 में विनिर्दिष्ट विघटन के कारण या अन्यथा, विचारण जारी रखने में असमर्थ है तो पीठासीन आफिसर या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित वरिष्ठ संयोजक प्राधिकारी को तथ्यों की तत्काल रिपोर्ट करेगा।

(2) जहां कोई न्यायालय निष्कर्ष के पूर्व या दोषी होने के निष्कर्ष के मामले में, दंडादेश के अधिनिर्णीत करने से पूर्व विसर्जित हो जाता है वहां न्यायालय के सामने की गई सभी कार्यवाहियां रद्द अकृत हो जाएंगी और अभियुक्त का दूसरे न्यायालय के सामने विचारण किया जा सकेगा।

124. अभियुक्त की मृत्यु या बीमारी की दशा में कार्यवाहियां :— अभियुक्त की मृत्यु या ऐसी बीमारी की दशा में, जिसके कारण विचारण जारी रखना असंभव हो जाए, तो न्यायालय साक्ष्य लेकर मृत्यु या बीमारी के तथ्य का पता लगायेगा और उसे अभिलिखित करेगा और स्थगित हो जाएगा और कार्यवाहियों को संयोजन प्राधिकारी को पारित करेगा।

125. पीठासीन अधिकारी की मृत्यु, सेवा निवृत्ति या अनुपस्थिति: पीठासीन आफिसर की मृत्यु, आपत्ति के कारण निवृत्ति या अपरिहार्य अनुपस्थिति की दशा में, अगला ज्येष्ठ आफिसर, पीठासीन आफिसर का स्थान ग्रहण करेगा और यदि न्यायालय अभी भी आफिसरों की उस न्यूनतम संख्या से कम संघटित नहीं है, जो विधि के अनुसार अपेक्षित है तो परीक्षण आगे जारी रहेगा।

126. न्यायालय के सभी सदस्यों का उपस्थित रहना— (1) अभियुक्त के विचारण के दौरान न्यायालय के शेष सभी सदस्य उपस्थित होंगे, न्यायालय का वह सदस्य जो अभियुक्त के विचारण में साक्ष्य के किसी भाग को ग्रहण किए जाने के दौरान अनुपस्थित रहा है, उस न्यायालय द्वारा उस व्यक्ति के विचारण में आगे कोई भाग नहीं लेगा, किंतु न्यायालय पर इसका तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि उसकी संख्या न्यूनतम विधिक संख्या से कम नहीं हो जाती।

(2) अभियुक्त को दोषारोपित किए जाने के पश्चात् न्यायालय में कोई आफिसर शामिल नहीं किया जाएगा।

127. न्यायालय के सदस्यों की राय लेना— (1) न्यायालय के प्रत्येक सदस्य को प्रत्येक प्रश्न पर, जिसका न्यायालय को विनिश्चय करना है, मौखिक राय देनी होगी और इस बात के होते हुए भी कि उसने दोषमुक्ति के पक्ष में अपनी राय दी है उसे दण्डादेश के बारे में भी अपनी राय देनी होगी।

(2) न्यायालय के सदस्यों की राय उत्तरवर्तन के अनुसार ली जाएगी जो निम्नतम ज्येष्ठता सदस्य से आरंभ होगी।

128. आनुषांगिक प्रश्नों पर प्रक्रिया :— यदि विचारण के दौरान विधि, साक्ष्य या प्रक्रिया के किसी विषय पर अभियोजक द्वारा या अभियुक्त द्वारा या उसके निमित्त कोई आक्षेप किया जाता है, तो यथास्थिति, अभियोजक या अभियुक्त या काउन्सेल या प्रतिरक्षा आफिसर को उसका उत्तर देने का अधिकार होगा और आक्षेप करने वाले व्यक्ति को प्रतिउत्तर पाने का अधिकार होगा।

129. साक्ष्य का कब अनुवाद किया जाएगा— (1) जब कोई साक्ष्य ऐसी भाषा में दिया जाता है जिसे न्यायालय की संरचना करने वाले अधिकारी में से कोई, विधि आफिसर, अभियोजक या अभियुक्त या उसका प्रतिरक्षा आफिसर या काउन्सेल नहीं समझता है तो वह साक्ष्य ऐसे आफिसर या व्यक्ति को उस भाषा में भाषान्तरित करने को दिया जाएगा जिसे वह समझता है। यदि संयोजक अधिकारी ने ऐसी भाषा का कोई दुभाषिया नियुक्त किया है और उसे सम्यक् रूप से शपथ दिलाई गई है या प्रतिज्ञान कराया गया है, तो वह साक्ष्य का भाषान्तर करेगा।

(2) यदि ऐसा दुभाषिया नियुक्त नहीं किया गया है और उसे शपथ नहीं दिलाई गई है या प्रतिज्ञान नहीं कराया गया है तो किसी निष्पक्ष व्यक्ति को न्यायालय द्वारा दुभाषिया की शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा।

(3) इस नियम के अधीन किसी व्यक्ति को दुभाषिए के रूप में शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने से पूर्व, अभियुक्त को उस व्यक्ति के बारे में सूचित किया जाएगा जो शपथ दिलाए जाने या प्रतिज्ञान कराए जाने के लिए प्रस्तावित किया गया है, और

अभियुक्त उस व्यक्ति के निष्पक्ष न होने के बारे में या किसी भी युक्तियुक्त कारणों पर आक्षेप कर सकेगा और यदि न्यायालय, यह विचार करता है कि आक्षेप युक्तियुक्त है तो उस व्यक्ति को दुभाषिए के रूप में शपथ नहीं दिलाएगा या प्रतिज्ञान नहीं कराएगा।

(4) जब दस्तावेज औपचारिक तौर पर सबूत के तौर पर रखे जाएं तब उनके उतने भाग का जितना आवश्यक प्रतीत हो, भाषान्तर सुनिश्चित कराना न्यायालय के स्वविवेक में होगा।

130. न्यायालय के संयवहार की कार्यवाहियों का अभिलेख :- (1) न्यायालय में विधि आफिसर यदि कोई है, या यदि कोई पीठासीन आफिसर न्यायालय के सभी संयवहार, हिन्दी या अंग्रेजी भाषा में अभिलिखित करेगा या कराएगा और अभिलेख की (जिसे इन नियमों में कार्यवाहियां निर्दिष्ट किया गया है) परिशुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा, और यदि विधि आफिसर को अभियुक्त ने साक्षी के रूप में आहूत किया है तो पीठासीन अधिकारी विधि आफिसर के साक्ष्य की कार्यवाहियों के अभिलेख की परिशुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा।

(2) साक्ष्य और उसमें प्रयुक्त शब्दों को यथासंभव वृत्तांत प्ररूप में लिखा जाएगा, किंतु ऐसे मामलों में जहां अभियोजक, अभियुक्त, विधि आफिसर या न्यायालय यह महत्वपूर्ण समझता है, वहां प्रश्न और उत्तर शब्दशः लिखे जाएंगे।

(3) जहां किसी प्रश्न पर या किसी साक्ष्य के ग्रहण या न्यायालय की प्रक्रिया पर आरोप किया जाता है, वहां ऐसा आक्षेप, यदि अभियोजक या अभियुक्त ऐसा आवेदन करता है या न्यायालय उचित समझता है तो आक्षेप के आधारों को उन पर न्यायालय के विनिश्चय सहित, कार्यवाहियों में प्रविष्ट किया जाएगा।

(4) जहां अभियोजक या अभियुक्त द्वारा या उसकी ओर से किया गया कोई सम्बोधन लिखित में नहीं है तो उसे आगे या अन्यथा, न्यायालय जैसा उचित समझती है कार्यवाहियों में अभिलिखित करना आवश्यक नहीं होगा, सिवाय उसके जहाँ -

(क) न्यायालय प्रत्येक मामले में अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिरक्षा का ऐसा अभिलेख अभिलिखित करेगा जो पुष्टि करने वाले प्राधिकारी को अभियुक्त द्वारा या उसकी ओर से उसके विरुद्ध हर आरोप पर दिए गए उत्तर का निर्णय करने में समर्थ हो सके; और

(ख) न्यायालय, यथास्थिति, अभियोजक या अभियुक्त द्वारा या उसकी ओर से किए गए सम्बोधन में ऐसे विशिष्ट विषयों को भी अभिलिखित करेगा, जिनका अभियोजक या अभियुक्त अपेक्षा करें।

(5) न्यायालय कार्यवाहियों में कोई टीका-टिप्पणी या ऐसी कोई बात जो न्यायालय के समक्ष नहीं है या कोई रिपोर्ट या कोई तथ्य जो विचारण का भाग नहीं है, कार्यवाहियों में दर्ज नहीं करेगा किन्तु यदि कोई ऐसी टीका-टिप्पणी या रिपोर्ट न्यायालय को आवश्यक प्रतीत होती है तो न्यायालय इसे पीठासीन अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कराकर पृथक दस्तावेज में उचित प्राधिकारी को अग्रप्रेषित कर सकेगा।

131. कार्यवाहियों की अभिरक्षा और निरीक्षण :- कार्यवाहियां विधि आफिसर या यदि कोई नहीं हैं तो, पीठासीन आफिसर की अभिरक्षा में समझी जाएंगी किन्तु, उनकी सुरक्षा के संबंध में उचित सावधानी बरतते हुए, न्यायालय के सदस्य अभियोजक या अभियुक्त निष्कर्ष पर विचार-विमर्श करने के लिए न्यायालय के बंद होने से पूर्व किसी भी उचित समय पर उसका निरीक्षण कर सकेगा।

132. जनरल या पेटी असम राइफल्स न्यायालय की कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन :- असम राइफल्स के सामान्य या पेटी न्यायालय की कार्यवाहियां वह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में कार्यवाहियों की गई हैं उन्हें तुरंत पुनर्विलोकन के लिए नामित प्रमुख विधि आफिसर या अन्य विधि आफिसर को भेजेगा और वह उसे पुष्टिकरण प्राधिकारी को भेजेगा।

133. प्रतिरक्षा प्राधिकारी, अभियुक्त का मित्र और काउन्सेल :- (1) अधिनियम के अधीन असम राइफल्स के किसी जनरल या पेटी न्यायालय में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व किसी आफिसर द्वारा जो प्रतिरक्षा आफिसर कहा जाएगा, किया जा सकेगा या अभियुक्त की सहायता किसी व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी जिसकी सेवाएं वह प्राप्त करने में समर्थ हो सके और उसे "अभियुक्त का मित्र" कहा जाएगा।

(2) प्रतिरक्षा आफिसर के वही अधिकार और कर्तव्य होंगे जो इन नियमों के अधीन काउन्सेल के हैं और वह समान बाध्यताओं के अधीन होगा।

(3) 'अभियुक्त का मित्र' सभी विन्दुओं पर अभियुक्त को सलाह दे सकेगा और साक्षियों से किए जाने वाले प्रश्न सुझा सकेगा, किन्तु वह साक्षियों की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा नहीं करेगा और न न्यायालय को सम्बोधित करेगा।

134. काउन्सेल की उपसंज्ञाति के लिए अपेक्षाएं:- (1) किसी काउन्सेल द्वारा प्रतिनिधित्व कराने का आशय रखने वाला अभियुक्त व्यक्ति अपने कमांडेंट या संयोजक आफिसर को ऐसे आशय की यथाशीघ्र, व्यवहारिक सूचना देगा, और यदि पर्याप्त सूचना नहीं दी गई है तो न्यायालय, यदि वह उचित समझता है, अभियोजक के आवेदन पर विचारण में अभियोजक की ओर से काउन्सेल अभिप्राप्त करने के लिए उसे समर्थ बनाने के लिए स्थगित कर सकेगा।

(2) जहां संयोजक आफिसर ऐसा निदेश करता है, तो काउन्सेल, अभियोजक के साथ उपसंज्ञात हो सकेगा, किन्तु उस दशा में, जब तक कि उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूचना अभियुक्त द्वारा नहीं दी जाती है, काउन्सेल के उपसंज्ञात होने के लिए निदेश की सूचना अभियुक्त को विचारण से पूर्व ऐसे समय जो किसी दशा में सात दिनों से कम नहीं होगा दी जाएगी, जिससे कि अभियुक्त विचारण में सहायता प्राप्त करने के लिए काउन्सेल अभिप्राप्त करने में समर्थ हो सके।

(3) काउन्सेल को, जो न्यायालय के सामने अभियोजक या अभियुक्त की ओर से उपसंज्ञात होता है, अभियोजक या अभियुक्त के समान, जिसके लिए वह उपसंज्ञात होता है, साक्षियों को आहूत करने और मौखिक रूप से उनकी परीक्षा करने साक्ष्यों की

प्रतिपरीक्षा करने और पुनः परीक्षा करने कोई अभिवाक् और करने और कार्यवाहियों का निरीक्षण करने का अधिकार होगा और उस व्यक्ति के स्थान पर, जिसकी ओर से वह उपसंजात होता है, विचारण के अनुक्रम में अन्य कार्य करने का अधिकार होगा वह इन और नियमों के उपबंधों का ऐसे पालन करेगा मानो वह व्यक्ति हो और ऐसी दशा में अभियोजक या अभियुक्त को नियम 102 के उपनियम (2) और नियम 109 के उपनियम (4) द्वारा अनुज्ञात कथन की बाबत के सिवाय अथवा न्यायालय उसे जैसा करने की अनुज्ञा देता है उसके सिवाय उपर्युक्त मामलों में से किसी को स्वयं करने का अधिकार नहीं होगा।

135. विधि आफिसर की निरर्हता - आफिसर किसी न्यायालय में आसीन होने के लिए निरर्हित है वह उस न्यायालय में विधि आफिसर के रूप में कार्य करने के लिए निरर्हित होगा।

136. विधि आफिसर की मृत्यु, बीमारी या अनुपस्थिति में प्रतिस्थापन - यदि विधि आफिसर की मृत्यु या बीमारी से या किसी भी अन्य कारण से उस मामले में उपसंजात होने में असमर्थ है तो न्यायालय स्थगित कर दिया जाएगा और पीठासीन अधिकारी तदनुसार संयोजक प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा और उस रिपोर्ट की प्राप्ति पर संयोजन प्राधिकारी द्वारा अन्य व्यक्ति को नियुक्त किया जा सकेगा और जिसे शपथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा और वह शेष विचारण के लिए या जब तक विधि आफिसर वापिस नहीं लौटता है, विधि आफिसर के रूप में कार्य करेगा।

137. विधि अधिकारी की शक्तियाँ और कर्तव्य- (1) जहां विधि आफिसर, न्यायालय को कार्यवाई के लिए नामित किया गया है, वहां वह, -

(क) जब कभी न्यायालय अभियोजक या अभियुक्त द्वारा अपेक्षा की जाए आरोप या विचारण से संबंधित विधि के किसी प्रश्न पर अपनी राय देगा;

(ख) कार्यवाहियों में किसी अन्य कमियों के बारे में न्यायालय को सूचित करेगा।

(ग) वह आरोप में या न्यायालय के गठन में किसी कमी या त्रुटि की सूचना संयोजक अधिकारी और न्यायालय को देगा;

(घ) वह साक्ष्य का उपसंहार करेगा और न्यायालय के समक्ष उसके निष्कर्ष पर विचार-विमर्श करने से पूर्व मामले में विधि के किसी प्रश्न पर अपनी सलाह देगा।

(2) विधि आफिसर का यह सुनिश्चित करने का कर्तव्य होगा कि अभियुक्त का उसकी उस स्थिति जैसे के परिणामस्वरूप किसी अहित न हो या साक्षियों की परीक्षा करने या प्रतिपरीक्षा करने में उसकी अनभिज्ञता या अक्षमता के या अन्यथा, है और वह इस प्रयोजन के लिए विधि आफिसर न्यायालय की अनुमति से साक्षियों को बुला सकेगा और उनसे ऐसे प्रश्न पूछ सकेगा जो सत्यता को जानने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो।

(3) अपने कर्तव्यों निर्वहन में विधि आफिसर निष्पक्ष दृष्टिकोण बनाए रखेगा।

(4) जहां विधि आफिसर द्वारा न्यायालय को किसी ऐसे मामले पर जो उसके समक्ष है कोई राय दी गई है तो यदि विधि आफिसर और न्यायालय इसे कार्यवाही प्रविष्ट करना चाहता है तो वह उसे कार्यवाहियों में अभिलिखित कर सकेगा।

(5) विधि आफिसर, बल न्यायालय में मुख्य विधि आफिसर का प्रतिनिधित्व करेगा।

138. उन्मत्ता का निष्कर्ष- जहां न्यायालय का निष्कर्ष यह है कि अभियुक्त या तो चित्तविकृति के कारण अपनी प्रतिरक्षा करने में अयोग्य है या उसने अभिकथित कार्य किया है किन्तु चित्तविकृति के कारण वह कार्य की प्रकृति समझने के योग्य नहीं था या यह समझने के योग्य नहीं था कि वह कार्य गलत था या विधि विरुद्ध था तो, पीठासीन अधिकारी या समरी असम राइफल्स न्यायालय की दशा में विचारण करने वाला अधिकारी, निष्कर्ष पर हस्ताक्षर और तारीख डालेगा और विधि आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित किया जाएगा तत्पश्चात् कार्यवाहियां तुरंत यथार्थिथि पुष्टि करने वाले अधिकारी की या समरी असम राइफल्स न्यायालय की दशा में के प्रतिहस्ताक्षरित के लिए सशक्त उपमहानिरीक्षक या अपर उपमहानिरीक्षक को तुरंत पारित कर दी जाएगी।

139. कार्यवाहियों का परिरक्षण- प्रत्येक बल न्यायालय की कार्यवाहियां, प्रख्यापना के पश्चात्, मुख्य विधि आफिसर को भेजी जाएंगी और वहां उन्हें जनरल और पैटी असम राइफल्स न्यायालय की दशा में कम से कम सात वर्ष और समरी असम राइफल्स न्यायालय की दशा में तीन वर्ष या न्यायालय द्वारा अधिनिर्णीत दंडादेश के समाप्त होने तक, जो भी बाद में हो, परिरक्षित की जाएंगी।

140. विचारण किए गए व्यक्ति के कार्यवाहियों की प्रतियों के लिए अधिकार- किसी असम राइफल्स न्यायालय द्वारा विचारण किया गया प्रत्येक असम राइफल्स का व्यक्ति मांग करने पर निष्कर्ष और दण्डादेश की पुष्टि के पश्चात् किसी भी समय यदि ऐसी पुष्टि अपेक्षित है तो कार्यवाहियों के नष्ट किए जाने से पूर्व असम राइफल्स न्यायालय के मामले में ये विचारण करने वाले अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित हुई प्रति के साथ में कार्यवाहियों की पुनरीक्षण प्रति यदि हुआ हो तो मुख्य विधि अधिकारी या न्यायालय से उचित समय पर खर्च दिए बिना प्राप्त करने का हकदार होगा।

141. कतिपय मामलों में कार्यवाहियों की प्रतिलिपि का न दिया जाना- नियम 140 में किसी बात के होते हुए भी, यदि केन्द्रीय सरकार का लेखबद्ध किए गए कारणों के लिए समाधान हो जाता है कि उक्त नियमों के अधीन कार्यवाहियों या उसके किसी भाग की प्रतिलिपि के प्रदान किया जाना राज्य की सुरक्षा के हित में या विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों के विरुद्ध है तो वह ऐसी प्रतिलिपि उपलब्ध नहीं करवाएगा।

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिलिपि की मांग करने वाला व्यक्ति, अधिनियम के अनुसार यादिकार प्रस्तुत करने या किसी निष्कर्ष या दण्डादेश के संबंध में किसी न्यायालय में कोई कार्यवाई संस्थित करने का इच्छुक है तो वह ऐसे व्यक्ति या उसके सलाहकार को, यदि कोई हो निम्नलिखित शर्तों पर कार्यवाहियों का निरीक्षण करने की अनुज्ञा देगा :-

(क) निरीक्षण ऐसे समयों और ऐसे स्थानों पर किया जाएगा जो केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई प्राधिकारी निर्दिष्ट करे; और

(ख) कार्यवाहियों का निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात व्यक्ति ऐसा निरीक्षण करने के पूर्व—

(i) लिखित में यह वचनबद्ध प्रस्तुत करेगा कि वह कार्यवाहियों या उनके किसी भाग की प्रतिलिपियां नहीं बनाएगा और ऐसी कार्यवाहियों में अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेजों का अधिनियम के अनुसार अर्जी प्रस्तुत करने या उक्त निष्कर्ष या दण्डादेश के संबंध में न्यायालय में कार्रवाई संस्थित करने के प्रयोजन से भिन्न किसी भी प्रयोजन के लिए उपयोग नहीं करेगा; और

(ii) एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेगा कि उसे इस बात की जानकारी है कि यदि वह उक्त कार्यवाहियों में अतिरिक्त दस्तावेजों या सूचना के संबंध में शासकीय गुप्त बात अधिनियम 1923 (1923 का 19) की धारा 3 और धारा 5 के अधीन कोई कार्य करता है तो वह उक्त धाराओं के अधीन अभियोजन का दायी होगा।

142. कार्यवाहियों के अभिलेख का खो जाना :— (1) यदि पुष्टि के पूर्व न्यायालय की मूल कार्यवाहियों, जिनकी पुष्टि अपेक्षित है या उनका कोई भाग खो जाता है तो पीठासीन अधिकारी या न्यायालय के विधि आफिसर द्वारा प्रमाणित उसकी एक प्रति, यदि कोई हो, मूल प्रति के स्थान पर स्वीकार की जा सकेगी।

(2) यदि कोई ऐसी प्रति नहीं है और आरोप, निष्कर्ष, दण्डादेश और न्यायालय के संव्यवहारों का पर्याप्त साक्ष्य उपाप्त किया जा सकता है, तो वह साक्ष्य अभियुक्त की सहमति से मूल कार्यवाहियों के उस अभिलेख या उसके भाग के स्थान पर जो खो गया है, ग्रहण किया जा सकेगा।

(3) इस नियम में उपर्युक्त उल्लिखित किसी भी दशा में, निष्कर्ष और दण्डादेश की पुष्टि की जा सकेगी और यह उतना ही विधिमान्य होगा मानो मूल कार्यवाहियां या उसका कोई भाग खोया ही नहीं था।

(4) यदि अभियुक्त उपनियम (2) में निर्दिष्ट सहमति से इंकार करता है तो उसका पुनः विचारण किया जा सकेगा और पूर्व न्यायालय का निष्कर्ष और दण्डादेश, जिसकी कार्यवाहियां खो गई हैं, शून्य हो जाएंगी।

(5) यदि पुष्टि के पश्चात् या किसी ऐसे मामले में जहां पुष्टि अपेक्षित नहीं है, मूल कार्यवाहियां या उसका कोई भाग खो जाता है और आरोप, निष्कर्ष, दण्डादेश और न्यायालय के संव्यवहार और निष्कर्ष और दण्डादेश की पुष्टि (यदि अपेक्षित हो) का पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान है तो वह साक्ष्य सभी प्रयोजनों के लिए विचारण का विधिमान्य और पर्याप्त अभिलेख होगा।

143. साक्षियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा अपराध :— जब किसी न्यायालय की राय है कि धारा 46 और धारा 47 में विनिर्दिष्ट और उसके सामने किए गए या कार्यवाहियों के दौरान उसके ध्यान में लाए गए किसी अपराध की या उसके सामने किए गए या उसकी कार्यवाहियों के दौरान उसके ध्यान में लाए गए किसी कार्य की जो यदि अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा किया गया होता तो ऐसा अपराध बनता, जांच करने के लिए आधार है तो ऐसा न्यायालय निम्नलिखित कार्रवाई कर सकेगा अर्थात्—

(क) यदि वह व्यक्ति जिसके बारे में प्रतीत होता है अपराध का किया जाना अधिनियम के अध्याधीन है तो न्यायालय उसके आचरण को कमांडेंट की जानकारी में ला सकेगा; और उसे इस विचार से कि उसे धारा 61, धारा 64, धारा 65, या धारा 66 के अधीन प्राधिकार का प्रयोग करने वाले अधिकारी द्वारा या बल न्यायालय द्वारा विचारण करके दण्ड दिया जा सके बल की अभिरक्षा में रखे जाने के लिए आदेश भी दे सकेगा।

(ख) यदि वह व्यक्ति जिसके बारे में प्रतीत होता है कि उसने ऐसा कार्य किया है, जिससे संघ के सशस्त्र बल से सम्बन्धित के विधि का संशोधन हो सकता है तो न्यायालय उसके आचरण को, यथास्थिति, संबंधित सशस्त्र बल के उचित प्राधिकारी की जानकारी में ला सकेगा।

(ग) अन्य मामले में यथास्थिति, वह अधिकारी जिसने साक्षी को हाजिर होने के लिए समन किया है या पीठासीन अधिकारी न्यायालय आयोजित करने वाला अधिकारिता रखने वाले निकटतम प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट को लिखित परिवाद भेज सकेगा और ऐसे कार्यों की दशा में जो यदि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया हो जो धारा 46 के खंड (ड) या धारा 47 के अधीन कोई अपराध कारित करता हो तो न्यायालय कोई प्रारम्भिक जांच करने के पश्चात् जो कि आवश्यक हो, मामले को अधिकारिता रखने वाले निकटतम प्रथम वर्ग के मजिस्ट्रेट को दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 340 के अनुसार जांच या विचारण के लिए भेज सकेगा।

अध्याय - 12

समरी असम राइफल्स न्यायालय

144. कार्यवाहियां— (1) विचारण करने वाला अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात् न्यायालय कहा गया है, प्रत्येक समरी असम राइफल्स न्यायालय की कार्यों को हिंदी या अंग्रेजी में अभिलिखित करेगा या अभिलिखित करवाएगा।

(2) साक्ष्य में प्रयुक्त शब्दों को यथा संभव वृत्तांत रूप में लिखा जाएगा, किन्तु किसी दशा में ऐसे किसी मामले में जहां न्यायालय इसे सारवान समझती है वहां प्रश्न और उत्तर को शब्दशः लिखा जाएगा।

145. साक्ष्य का कब अनुवाद किया जाएगा— (1) जब कोई साक्ष्य ऐसी भाषा में दिया जाता है, जिसे न्यायालय या अभियुक्त नहीं समझता है तो साक्ष्य ऐसी भाषा में अनुवाद कि जाएगा, जिसे या यथास्थिति, न्यायालय या अभियुक्त समझता है।
 (2) न्यायालय इस प्रयोजन के लिए या तो दुभाषिया नियुक्त करेगा या स्वयं ही समरी असम राइफल्स न्यायालय में दुभाषिए के लिए विहित शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।
 (3) जब अभिलेख औपचारिक रूप से साबित करने के प्रयोजन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं तब यह न्यायालय के विवेकाधिकार पर होगा कि वह उतने भाग का ही अनुवाद करवाए जितना आवश्यक प्रतीत हो।
146. संवेत होना :— जब न्यायालय, दुभाषिया और विचारण में हाजिर होने वाले अधिकारी या अधिनस्थ अधिकारी संवेत होते हैं, तब अभियुक्त को न्यायालय में लाया जाएगा और नियम 147 में वर्णित व्यक्तियों द्वारा उस नियम में विहित शपथ दिलावाई जाएगी या प्रतिज्ञान करवाया जाएगा।
147. न्यायालय या दुभाषिए द्वारा शपथ लेना या प्रतिज्ञान करना— न्यायालय निम्नलिखित प्रारूपों में से किसी एक में या समान आशय के अन्य प्रारूप में जो या तो उसके धर्म के अनुसार या अन्यथा न्यायालय को गठन करने वाले अधिकारी के अंतःकरण पर आबद्धकर होगा, शपथ लेगा या प्रतिज्ञान करेगा।

शपथ का प्रारूप

मैं, सर्वशक्तिमान् ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं बिना भेदभाव, पक्षपात, या अनुराग के असम राइफल्स अधिनियम के अनुसार, सम्यक् रूप से न्याय प्रदान करूंगा।

प्रतिज्ञान का प्रारूप

मैं, सत्यनिष्ठा से, सद्भावपूर्वक और सच्चाई से यह घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं बिना भेदभाव, पक्षपात, और अनुराग के असम राइफल्स अधिनियम के अनुसार सम्यक् रूप से न्याय प्रदान करूंगा।

(2) न्यायालय या उसके द्वारा इस निमित्त सशक्त किया गया कोई व्यक्ति दुभाषिए को निम्नलिखित प्रारूपों में किसी प्रारूप में या समान आशय के ऐसे अन्य प्रारूप में, जो न्यायालय उस व्यक्ति के जिसे दुभाषिए के रूप में कार्य करना है धर्म के अनुसार या अन्यथा उसके अंतःकरण पर आबद्धकर रूप से अभिनिश्चित करें, शपथ दिलाएगा या प्रतिज्ञान कराएगा।

शपथ का प्रारूप

मैं, सर्वशक्तिमान् ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं इस न्यायालय के समक्ष लाए गए मामले में विश्वसनीय रूप से निर्वचन और अनुवाद करूंगा।

प्रतिज्ञान का प्रारूप

मैं, सत्यनिष्ठा से सद्भावपूर्वक और सत्यता से यह घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं इस न्यायालय के समक्ष लाए गए मामलों में विश्वसनीय रूप से निर्वचन और अनुवाद करूंगा।

(3) शपथ दिलावाए जाने और प्रतिज्ञान करवाए जाने के पश्चात् सभी साक्षी न्यायालय के बाहर चले जाएंगे।

148. अनेक अभियुक्त व्यक्तियों का विचारण करने के लिए न्यायालय द्वारा शपथ लेना—

(1) समरी असम राइफल्स न्यायालय को एक समय पर उसके समक्ष उपस्थित कितने ही अभियुक्त, व्यक्तियों के विचारण के लिए एक बार शपथ दिलाई जा सकेगी या प्रतिज्ञान कराया जा सकेगा, चाहे उन व्यक्तियों का विचारण सामूहिक रूप से या पृथक् रूप से किया जाना हो।

(2) पृथक् रूप से विचारण किए जाने वाले विभिन्न अभियुक्त व्यक्तियों को, न्यायालय शपथ दिलाए जाने या प्रतिज्ञान कराए जाने के पश्चात् किसी एक मामले में कार्यवाही करेगा और न्यायालय अन्य मामलों को मुलतवी करते हुए एक मामले पर कार्यवाही करेगा और उनको उत्तरावर्तन में लेगा।

(3) जहां अनेक अभियुक्त व्यक्तियों का एक संव्यवहार से उद्भूत होने वाले आरोपों पर पृथक् रूप से विचारण किया जाता है, वहां न्यायालय यदि वह न्याय के हित में वांछनीय, समझता है तो ऐसे अभियुक्त व्यक्तियों में से किसी एक या अधिक को अधिनिर्णित किए जाने वाले किसी दण्डादेश के विचार को सभी ऐसे अभियुक्त व्यक्तियों के विचारण पूरे होने तक मुलतवी कर सकेगा।

149. अभियुक्त का दोषारोपण :—(1) न्यायालय और दुभाषिए को उपर्युक्त वर्णित शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान करने के पश्चात् अभियुक्त को उसके विरुद्ध आरोपों से दोषारोपित किया जाएगा।

(2) वे आरोप जिनसे अभियुक्त को दोषारोपित किया गया है, उसे सुनाए जाएंगे और यदि आवश्यक हो तो उसके लिए अनुवाद किया और उसे समझाया जाएगा और उससे हर आरोप पर पृथक् रूप से अभिवचन करने की अपेक्षा की जाएगी।

150. आरोप के बारे में अभियुक्त द्वारा आक्षेप— अभियुक्त, जब किसी आरोप के बारे में अभिवचन करने की अपेक्षा की जाए तब वह इस आधार पर आरोप के बारे में आक्षेप कर सकेगा कि उससे अधिनियम के अधीन कोई अपराध प्रकट नहीं होता है या वह इन नियमों के अनुसार नहीं है।

151. **आरोप का संशोधन—**(1) विचारण के दौरान किसी समय यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि आरोप पत्र में अभियुक्त के नाम या वर्णन में कोई भूल है तो न्यायालय उस भूल को सही करने के लिए आरोप पत्र का संशोधन कर सकेगा।
- (2) यदि किसी आरोप के विचारण में, साक्षियों की परीक्षा प्रारंभ करने से पूर्व किसी भी समय न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि न्याय के हित में आरोप में कोई परिवर्धन या उससे कोई लोप या उसमें कोई परिवर्तन अपेक्षित है तो वह ऐसे आरोप का संशोधन कर सकेगा और अभियुक्त को सम्यक् सूचना देने के पश्चात् और अभियुक्त के विचारण के लिए पैटी असम राइफल्स न्यायालय को संयोजित करने के लिए सशक्त आफिसर की मंजूरी से, ऐसे संशोधित आरोप ऐसी मंजूरी की अपेक्षा करता है, उस संशोधित आरोप के सम्बन्ध में विचारण के लिए अग्रसर हो सकेगा।
152. **विशेष अभिवाक् :** यदि अभियुक्त द्वारा न्यायालय की साधारण अधिकारिता के बारे में विशेष अभिवाक् या विचारण के वर्जन में अभिवाक् प्रस्थापना की गयी है तो ऐसे अभिवचनों को निपटाने में साधारण और पैटी असम राइफल्स न्यायालय के संबंध में अधिकथित प्रक्रिया, जहां तक लागू हो अनुसरित की जाएगी किन्तु ऐसे अभिवाकों में से किसी पर असम राइफल्स न्यायालय द्वारा किए गए किसी निष्कर्ष के लिए अनुमोदन या पुष्टि अपेक्षित नहीं होगी।
153. **दोषी होने या दोषी न होने का साधारण अभिवाक्—**(1) अभियुक्त व्यक्ति का दोषी होने या दोषी न होने का अभिवाक् या यदि वह अभिवचन करने से इंकार करता है या एक या अन्य आरोपों का दोषी न होने का अभिवचन बोध्यगम्य रूप से अभिवाक् नहीं करता है तो दोषी न होने का अभिवाक् प्रत्येक आरोप की बाबत अभिलिखित किया जाएगा।
- (2) यदि अभियुक्त व्यक्ति दोषी होने का अभिवचन करता है, तो वह अभिवाक् न्यायालय के निष्कर्ष के रूप में अभिलिखित किया जाएगा, किन्तु उसे अभिलिखित किए जाने से पूर्व न्यायालय यह अभिनिश्चित करेगा कि अभियुक्त उस आरोप की प्रकृति समझता है जिसके बारे में उसने दोषी होने का अभिवचन किया है और इसे अभिवाक् का साधारण प्रभाव और विशेषकर उस आरोप का अर्थ जिसके बारे में दोषी होने का अभिवचन किया है और प्रक्रिया का वह अन्तर जो दोषी होने के अभिवाक् के कारण होगा, सूचित करेगा और यदि संक्षिप्त या साक्ष्य के उद्धरण या अन्यथा से यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त को दोषी न होने का अभिवचन करना चाहिए तो उसे उस अभिवाक् को वापिस लेने की सलाह देगा।
- (3) जहां अभियुक्त व्यक्ति दोषी होने का अभिवचन करता है वह उस अभिवाक् और इस नियम के उपनियम (2) के अनुपालन के तथ्य को न्यायालय द्वारा निम्नलिखित रीति में अभिलिखित किया जाएगा—
- “अभियुक्त के दोषी होने का अभिवाक् अभिलिखित करने से पहले न्यायालय अभियुक्त को आरोप (आरोपों) जिनके लिए उसने दोषी होने का अभिवाक् किया है का अर्थ स्पष्ट करेगा और यह अभिनिश्चित करेगा कि अभियुक्त ने उन आरोप (आरोपों) की प्रकृति को समझ लिया है जिसके लिए उसने दोषी होने का अभिवाक् किया था। न्यायालय ने अभियुक्त को अभिवचन के सामान्य प्रभाव और प्रक्रिया में अन्तर की भी जानकारी देगा जो अभिवचन के परिणाम स्वरूप अनुसरित की जाएगी। न्यायालय अपना यह समाधान होने पर कि अभियुक्त अपने आरोप (आरोपों) और दोषी होने के अभिवाक् के प्रभाव को समझता है, उसे स्वीकार और अभिलिखित करेगा। इस प्रकार नियम 153 (2) के उपबंध का अनुपालन किया जाएगा”।
- (4) जहां कोई अभियुक्त अनुकल्पतः लगाए गए दो या अधिक आरोपों में से प्रथम के लिए दोषी होने का अभिवचन करता है, वहां न्यायालय उपनियम (2) का अनुपालन किए जाने के पश्चात् और अनुकल्पी आरोप या आरोपों पर अभियुक्त को दोषारोपित किए जाने के पूर्व ऐसे को, उसका अभिवाक् करने की अभियुक्त से अपेक्षा किए बिना वापस ले सकेगा जो उस आरोप के अनुसरण में है, अनुकल्पी आरोप या आरोपों का जिसके लिए अभियुक्त ने दोषी होने का अभिवाक् किया और उस आशय का अभिलेख न्यायालय की कार्यवाहियों में किया जाएगा।
154. **दोषी होने के अभिवाक् के पश्चात् की प्रक्रिया—**(1) दोषी होने का अभिवाक् अभिलिखित किए जाने पर, यदि उसी आरोप पत्र में अन्य आरोप है, जिनका अभिवाक् दोषी न होने का है, तो विचारण पहले दोषी उन अन्य आरोपों के संबंध में होगा और उन आरोपों पर निष्कर्ष के पश्चात् उन आरोपों पर जिसकी बाबत दोषी होने का अभिवाक् दर्ज किया गया है, किन्तु यदि वे अनुकल्पी आरोप हैं, तो न्यायालय या तो सभी आरोपों के बारे में ऐसे कार्यवाही करेगा मानो अभियुक्त ने किसी आरोप की बाबत दोषी होने का अभिवचन नहीं किया है या उसका विचारण करने के बजाए उन अनुकल्पी आरोपों में से किसी एक पर जिसके बाबत उसने दोषी होने का अभिवचन किया है, दोषी होने के अभिवाक् का निष्कर्ष और अन्य सभी अनुकल्पी आरोपों की बाबत दोषी न होने का निष्कर्ष अभिलिखित कर सकेगा।
- (2) (क) किसी आरोप की बाबत दोषी होने का अभिवाक् अभिलिखित करने के पश्चात् (यदि किसी अन्य आरोप पर विचारण आगे जारी नहीं रखा जाता) न्यायालय साक्ष्य का संक्षिप्त या उद्धरण पढ़ेगा और उसे कार्यवाहियों में संलग्न करेगा या यदि ऐसा अभिलेख नहीं है, तो पर्याप्त साक्ष्य लेगा और अभिलिखित करेगा जिससे कि वह दण्डादेश का अवधारण करने और पुनर्विलोकन अधिकारी को अपराध से संबंधित सभी परिस्थितियों के जानने में समर्थ बनाया जा सके।
- (ख) दोषी न होने के अभिवाक् के मामले में इन नियमों द्वारा यथा निर्देशित रीति में साक्ष्य लिए जाएंगे।
- (3) अभियुक्त ऐसा साक्ष्य लिए जाने या यथास्थिति, साक्ष्य का संक्षिप्त या उद्धरण पढ़े जाने के पश्चात् आरोप के प्रति निर्देश से और दण्ड कम करने के लिए न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अपने चरित्र के बारे में साक्ष्य आहूत कर सकेगा।
- (4) (क) यदि अभियुक्त के कथन से या साक्ष्य के सार से या अन्यथा, न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त ने दोषी होने का अपने अभिवाक् के प्रभाव होगा को नहीं समझा या तो न्यायालय अभिलेख में परिवर्तन करेगा और दोषी न होने का अभिवाक् प्रविष्ट करेगा और तदनुसार आगे विचारण के लिए अग्रसर होगा।

(ख) उपनियम (1) के अधीन वापस लिए गए अनुकल्पीय आरोपों को आरोप पत्र में पुनः स्थापित किया जाएगा और इस प्रकार विचारण किया जाएगा मानो उन्हें वापस लिया ही न गया हो।

(5) यदि दोषी होने का अभिवाक् कुछ आरोपों के सम्बन्ध में अभिलिखित किया जाता है और विचारण उसी आरोप पत्र के अन्य आरोपों की बावत आगे जारी रहता है तो उपनियम (2) और उपनियम (3) के अधीन कार्यवाहियां उसी आरोप पत्र में अन्य आरोपों पर निष्कर्ष अभिलिखित किए जाने के पश्चात् ही आरम्भ की जाएगी।

(6) जब अभियुक्त दण्ड के कम करने से संबंधित किसी बात का कथन करता है, जिसवर्ग न्यायालय की राय में साबित किया जाना अपेक्षित है और यदि साबित किया जाता है तो दण्ड की मात्रा पर प्रभाव पड़ेगा तो न्यायालय अभियुक्त को उसे साबित करने के लिए साक्षियों को बुलाने की अनुमति दे सकेगा।

155. दोषी न होने के अभिवाक् का वापस लिया जाना : अभियुक्त, यदि वह ठीक समझे तो विचारण के दौरान किसी भी समय दोषी न होने के अपने अभिवाक् को वापस ले सकेगा और दोषी होने का अभिवचन कर सकेगा और ऐसे मामले में न्यायालय तुरंत नियम 153 के उपनियम (2) का अनुपालन के अधीन रहते हुए, दोषी होने के अभिवाक् और निष्कर्ष को अभिलिखित कर सकेगा और जहां तक आवश्यक हो, नियम 154 द्वारा निदेशित रीति में अग्रसर होगा।

156. दोषी न होने के अभिवाक् के पश्चात् प्रक्रिया—(1) किसी आरोप के लिए दोषी न होने का अभिवाक् अभिलिखित किए जाने के पश्चात् अभियोजन के लिए साक्ष्य लिया जाएगा।

(2) अभियोजन के साक्ष्य की समाप्ति पर अभियुक्त से पूछा जाएगा कि क्या उसे अपनी प्रतिरक्षा में कुछ कहना है और वह अपनी प्रतिरक्षा में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा या तब तक के लिए ऐसा सम्बोधन अस्थायित्व कर सकेगा जब तक कि वह साक्षियों को नहीं बुलाता है।

(3) न्यायालय अभियुक्त से उसके कथन या साक्ष्य में उसके विरुद्ध प्रकट होने वाली किन्हीं परिस्थितियों को स्पष्ट करने में उसे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए प्रश्न पूछ सकेगा। अभियुक्त ऐसे प्रश्नों का उत्तर देने से इंकार करके या उनके ऐसे उत्तर देने के कारण जिनके सही न होने की उसे जानकारी है, दण्ड का भागी नहीं बनाएगा। अभियुक्त को कोई शपथ नहीं दिलाई जाएगी।

(4) अभियुक्त तब अपने साक्षियों को, जिसके अन्तर्गत चरित्र के साक्षी भी हैं, बुला सकेगा।

(5) नियम 96, नियम 97 और नियम 98 के उपबन्ध जहां तक हो सके समरी असम राइफल्स न्यायालय में साक्षियों के साक्ष्य को इस प्रकार लागू होंगे जैसे कि वे साधारण या पैटी या लघु असम राइफल्स न्यायालय के साक्षियों के साक्ष्य के सम्बन्ध में लागू होते हैं।

157. प्रतिरक्षा के उत्तर में साक्षी : न्यायालय, यदि वह न्याय के हित में आवश्यक समझता है, तो प्रतिरक्षा के उत्तर में साक्षियों को बुला सकेगा।

158. अधिमत्त : न्यायालय, अभियोजन और प्रतिरक्षा के साक्ष्य सुनने के पश्चात् इस बारे में अपनी राय देगा कि क्या अभियुक्त आरोप आरोपों का दोषी है या दोषी नहीं है।

159. निष्कर्ष का अभिलेख :—(1) ऐसे प्रत्येक आरोप के निष्कर्ष को जिन पर अभियुक्त को दोषारोपित किया गया है, अभिलिखित किया जाएगा और इन नियमों में जैसा उल्लिखित है उसके सिवाय दोषी होने या दोषी न होने के निष्कर्ष के रूप में अभिलिखित किया जाएगा।

(2) जब किसी आरोप की बावत न्यायालय की यह राय है कि साबित किए गए तथ्यों से आरोपित अपराध या ऐसा कोई अपराध प्रकट नहीं होता है जिसका वह लगाए गए आरोप के सम्बन्ध में अधिनियम के अधीन विधिक रूप से दोषी पाया गया हो तो न्यायालय अभियुक्त को उस आरोप से दोषमुक्त कर देगा।

(3) जब किसी आरोप के संबंध में न्यायालय की राय यह है कि वे तथ्य जिनके बारे में उसका निष्कर्ष है कि वे साक्ष्य से साबित हो गए हैं आरोप में विशिष्टियों के कथन में अधिकथित तथ्यों से तात्त्विक रूप से भिन्न हैं, किन्तु फिर भी आरोप में कथित अपराध साबित करने के लिए पर्याप्त है और विभिन्नता इतनी तात्त्विक नहीं है जिससे अभियुक्त की प्रतिरक्षा पर उसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो न्यायालय दोषी न होने के निष्कर्ष के बजाए विशेष निष्कर्ष अभिलिखित करेगा।

(4) विशेष निष्कर्ष में अभियुक्त को किए आरोप का उसमें विनिर्दिष्ट अपवादों या भिन्नता के कथन के अधीन रहते हुए किसी आरोप के सम्बन्ध में दोषी पाया जा सकेगा।

(5) न्यायालय अभियुक्त को अनुकल्पतः अधिकथित दो या अधिक आरोपों में से एक से अधिक का दोषी नहीं ठहराएगा भले ही एक आरोप पर दोषसिद्ध से आवश्यक रूप से अनुकल्पी आरोप या आरोपों का दोषी होने का संकेत मिलता है।

160. दोषमुक्त किए जाने सम्बन्धी प्रक्रिया: जहां आरोप पत्र में प्रत्येक आरोप से संबंधित दोषी न होने का निष्कर्ष दिया है वहां न्यायालय कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करेगा और तारीख डालेगा। निष्कर्षों को खुले न्यायालय में सुनाया जाएगा और अभियुक्त को उन आरोपों के सम्बन्ध से यदि वह गिरफ्तार है तो निर्मुक्त कर दिया जाएगा।

161. दोषी पाए जाने में प्रक्रिया:— (1) जहां किसी आरोप की बावत दोषी होने का निष्कर्ष है वहां न्यायालय अपनी स्वयं की जानकारी के लिए अभियुक्त व्यक्ति के साधारण चरित्र, आयु, सेवा, रैंक और उसके वीरतापूर्ण मान्यताप्राप्त कार्यों का या उसके विशिष्ट आचरण का और बल न्यायालय या दण्ड न्यायालय द्वारा अभियुक्त को पूर्व दोषसिद्धियों का धारा 62 के अधीन

- प्राधिकार का प्रयोग करने वाले किसी अफसर द्वारा अभियुक्त के बारे में अधिनिर्णित किए गए किसी पूर्व दण्ड का उस अवधि का जिसमें वह किसी पूर्व दण्ड के लिए गिरफ्तार या परिरुद्ध रहा है और किसी अलंकरण या इनाम का जो उसके पास है या जिसका वह हकदार है, अभिलिखित करेगा या किसी अभिलिखित का साक्ष्य लेगा।
- (2) जहां न्यायालय अपनी स्वयं की जानकारी के आधार पर इस नियम में वर्णित मामले अभिलिखित नहीं करता है वहां समान साक्ष्य के लिए इन मामलों पर साक्ष्य नियम 109 में निदेशित रीति में लिया जा सकेगा।
162. दण्डादेश : न्यायालय उन सभी अपराधों की बावत जिनका अभियुक्त व्यक्ति दोषी पाया जाता है, एक दण्डादेश अधिनिर्णित करेगा।
163. कार्यवाहियों पर हस्ताक्षर करना:— न्यायालय दण्डादेश पर हस्ताक्षर करेगा और तारीख डालेगा और ऐसे हस्ताक्षर से संपूर्ण कार्यवाही अधिप्रमाणीकृत हो जाएगी।
164. विभिन्न आरोप पत्रों में आरोप :—(1) जब समरी असम राइफल्स न्यायालय द्वारा विचारण में विभिन्न आरोप-पत्रों में आरोप अन्तर्विष्ट हो तो अभियुक्त पर प्रत्येक आरोप पत्र के सम्बन्ध में अलग से विचारण किया जाएगा जिसमें निष्कर्ष की अवस्था भी शामिल है।
- (2) यथास्थिति इसके बाद न्यायालय नियम 160 या नियम 161 का पालन करेगा।
165. न्यायालय खाली करवाना:— (1) विचारण करने वाला अफसर साक्ष्य पर विचार करने और विचारण में हाजिर रहने वाले अधिकारी या अधीनस्थ अफसरों से परामर्श करने के लिए न्यायालय खाली करा सकेगा।
- (2) उपनियम (1) के उपबन्ध के अधीन रहते हुए सभी कार्यवाहियां जिसके अन्तर्गत किसी स्थान का अवलोकन भी है, खुले न्यायालय में और अभियुक्त की उपस्थिति में होंगी।
166. स्थगन :— (1) न्यायालय—
- (क) समय-समय पर कार्यवाहियां स्थगित कर सकेगा और ऐसे स्थानों पर अधिविष्ट होगा जो सुविधाजनक हों; और
- (ख) जहां कहीं आवश्यक हो घटनास्थल का दौरा कर सकेगा।
167. अभियुक्त का मित्र:— समरी असम राइफल्स न्यायालय में विचारण के दौरान अभियुक्त किसी भी व्यक्ति से सहायता ले सकता है, जिसके अन्तर्गत ऐसे विधि व्यवसायी भी हैं जिसे वह आवश्यक समझे।
- परन्तु ऐसा व्यक्ति साक्षियों की परीक्षा या प्रति परीक्षा और न्यायालय को संबोधित नहीं करेगा।
168. कार्यवाहियों से संलग्न किया जाने वाला ज्ञापन:— जहां समरी असम राइफल्स न्यायालय ऐसे किसी अपराध का विचारण करता है, जिसका विचारण धारा 96 की उपधारा (2) वर्णित किसी प्राधिकारी के निर्देश के बिना साधारणतया नहीं किया जाएगा वहां कार्यवाहियों के साथ एक स्पष्टीकरण ज्ञापन संलग्न किया जाएगा।
169. प्रख्यापन — समरी असम राइफल्स न्यायालय का दण्डादेश, उसके सुनाए जाने के पश्चात शीघ्रतम अवसर पर सेवा की सामान्य रीति में प्रख्यापित किया जाएगा और अधिनियम की धारा 136 की उपधारा (2) के उपबन्ध के अधीन प्रख्यापन के पश्चात बिना बिलम्ब कार्यान्वित किया जाएगा।
170. कार्यवाहियों का पुनर्विलोकन:— समरी असम राइफल्स न्यायालय की कार्यवाहियां, प्रख्यापन पर तुरन्त मुख्य विधि आफिसर या उसके द्वारा नामनिर्देशित विधि आफिसर के माध्यम से उप महानिरीक्षक या महानिरीक्षक को भेजी जाएंगी जिसके अधीन अभियुक्त ने सेवा की हो।
171. उप महानिरीक्षक और महानिरीक्षक द्वारा कार्रवाई— (1) जहां उस उप महानिरीक्षक या महानिरीक्षक का जिसे नियम 170 के अधीन समरी असम राइफल्स की कार्यवाहियां अग्रेषित की गई हैं यह समाधान हो जाता है कि कार्यवाहियों में किसी गंभीर अनियमितता के कारण या अन्यथा अभियुक्त के साथ अन्याय किया गया है, वहां वह —
- (क) न्यायालय की कार्यवाहियों को अपास्त कर सकेगा; या
- (ख) दण्डादेश कम कर सकेगा या धारा 57 में दिए गए दंड के मापमान से अधिनिर्णित किए गए दंड को निम्नतर दंड में परिवर्तित कर सकेगा और उसे प्रख्यापन के लिए अभियुक्त की यूनिट को वापस भेज सकेगा।
- (2) जहां उपनियम (1) के अधीन कोई कार्रवाई नहीं की गई है वहां वह कार्यवाहियों पर प्रतिहस्ताक्षर करेगा।
- (3) कार्यवाहियां उपनियम (1) के अधीन प्रख्यापन के पश्चात् या उपनियम (2) के अधीन प्रतिहस्ताक्षर करने के पश्चात् अभिरक्षा के लिए मुख्य विधि आफिसर को अग्रेषित की जाएंगी।
172. वे नियम, जो असम राइफल्स समरी न्यायालय द्वारा किए गए विचारण को लागू नहीं होंगे:— नियमों के अध्याय 9 और 10 के उपबन्ध समरी असम राइफल्स न्यायालय द्वारा किए गए विचारणों को, जहां तक वे समरी असम राइफल्स न्यायालय से सम्बन्धित इस अध्याय में अन्तर्विष्ट अध्याय के किसी उपबन्ध के असंगत हैं, लागू नहीं होंगे।

अध्याय - 13

दण्डादेश का निष्पादन

173. कारावास के दंडादेश के बारे में निदेश :—(1) पुष्टिकर्ता प्राधिकारी या समरी असम राइफल्स न्यायालय की दशा में न्यायालय यह निदेश देगा कि कारावास के दंडादेश किसी सिविल कारागार में या बल की अभिरक्षा में परिरुद्ध कर के भोगा जाएगा।
- (2) ऐसे निदेश को किसी वरिष्ठ आफिसर द्वारा परिवर्तित किया जा सकेगा।
174. वारंट : (1) कारावास के दण्डादेश को भोगने के लिए किसी एक व्यक्ति को सिविल कारागार में सौंपने के लिए या उस व्यक्ति को जरूरी होने पर वापस बल की अभिरक्षा में लाने या उस व्यक्ति को सिविल कारागार से सिद्दाई के आदेश के लिए या किसी वरिष्ठ आफिसर द्वारा कोई भिन्नता किए जाने पर वारंट परिशिष्ट- 12 में वर्णित उचित प्ररूप में जारी किया जाएगा।
- (2) ऐसे वारंट अभियुक्त के कमांडेंट द्वारा या उपमहानिरीक्षक, महानिरीक्षक या महानिदेशक की ओर से स्टाफ आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।
175. मृत्यु के दण्डादेश के मामले में वारंट: (1) जब किसी व्यक्ति को बल न्यायालय द्वारा मृत्यु दण्ड का दंडादेश दिया गया है तब ऐसे व्यक्ति का तत्समय कमांडेंट यदि वह उचित समझे तो परिशिष्ट 13 के प्रारूपों में से किसी में वारंट द्वारा उक्त व्यक्ति को दण्डादेश की पुष्टि या कार्यान्वयन होने तक सिविल कारागार में सुरक्षित अभिरक्षा के लिए सुपुर्द कर सकेगा।
- (2) जब किसी व्यक्ति को फौसी देकर मृत्यु का दण्डादेश दिया गया है तो वहां परिशिष्ट 13 में वर्णित प्ररूप में वारंट, केन्द्रीय सरकार द्वारा दण्डादेश की पुष्टि किए जाने के पश्चात् महानिदेशक द्वारा उस कारागार के अधीक्षक को भेजा जाएगा जहां ऐसे दंडादेश को कार्यान्वित करने की सुविधाएं विद्यमान हैं और अभियुक्त को उसके कमांडेन्ट द्वारा उचित वारंट पर लाया जाएगा।
- (3) जब किसी व्यक्ति को गोली मारकर मृत्यु का दण्डादेश दिया गया है तो महानिदेशक द्वारा महानिरीक्षक या उपमहानिरीक्षक को जिसके अधीन अभियुक्त सेवारत है परिशिष्ट 13 में वर्णित समुचित प्ररूप में वारंट केन्द्रीय सरकार द्वारा दंडादेश की पुष्टि किए जाने, के पश्चात् जारी किया जाएगा और यथास्थिति महानिरीक्षक या उपमहानिरीक्षक दण्डादेश के निष्पादन की व्यवस्था करेगा।
- (4) उपनियम (1) या उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारियों द्वारा मृत्यु वारंट न मिलने तक मृत्यु दण्डादेश को प्रमादी रूप से लागू नहीं किया जाएगा।
- (5) मृत्यु वारंट मिलने पर उपनियम (1) या उपनियम (2) में वर्णित प्राधिकारी :—
- (क) दण्डादिष्ट व्यक्ति को यथासंभव शीघ्र वह तारीख सूचित करेगा जिसको दण्डादेश कार्यान्वित किया जाएगा।
- (ख) यदि दण्डादिष्ट व्यक्ति को नियम 175 के अधीन सिविल कारागार को सुपुर्द किया गया है तो, परिशिष्ट 13 के प्रारूपों में से किसी एक में वारंट जारी करके उसे अभिरक्षा में देगा।
- (ग) आदेश द्वारा अपेक्षित मृत्यु वारंट के अनुसार और उन साधारण या विशेष अनुदेशों के अनुसार जो समय-समय पर महानिदेशक द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन दिए जाएं, दण्डादेश को कार्यान्वित करने के लिए अग्रसर होगा।
- (6) अधिनियम के अधीन पारित मृत्यु दण्डादेश के निष्पादन के दौरान नीचे विनिर्दिष्ट व्यक्तियों के अलावा कोई व्यक्ति उस अधिकारी के प्राधिकार के बिना उपस्थित नहीं होगा जिसने मृत्यु वारंट जारी किया है। निम्नलिखित व्यक्ति मृत्यु के दण्डादेश के निष्पादन के समय उपस्थित होंगे -
- (क) उपनियम (1) या उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी जो इन नियमों के अनुसार दण्डादेश के सम्यक निष्पादन के लिए जिम्मेदार है ;
- (ख) संघ के सशस्त्र बलों का चिकित्सा अधिकारी ;
- (ग) मृत्यु वारंट जारी करने वाले अधिकारी द्वारा नाम निर्देशित अधिकारी, जो दण्डादेश के अधीन - मृत्यु वारंट में वर्णित उस व्यक्ति को जिस पर विचारण किया गया और असम राइफल्स न्यायालय द्वारा उसमें उल्लिखित दण्डादेश दिया गया के रूप में दण्डादेश के अधीन व्यक्ति को उसे पहचानने में समर्थ है ;
- (घ) ऐसा अधीनस्थ आफिसर जिसे उपनियम (1) और उपनियम (2) में वर्णित प्राधिकारियों द्वारा अनुरक्षक और सुरक्षा के प्रयोजन से या दण्डादेश को क्रियान्वयन में सहायता के प्रयोजन से नियुक्त किया गया हो,
- (ङ) यदि असम राइफल्स यूनिट में निष्पादन किया जाता है तो उस यूनिट का कमांडेंट।
- (7) मृत्यु का दण्डादेश दिए जाने के पश्चात् उपनियम (2) में उल्लिखित प्राधिकारी या सिविल कारागार का अधीक्षक यथास्थिति मृत्यु वारंट के भाग II और III को पूर्ण करेगा और पूर्ण करवायेगा मृत्यु वारंट उस अधिकारी को वापस भेज दिया जाएगा जिसने उसे जारी किया है।

176. दण्डादेश में परिवर्तन : जहां कारागार पहले से सुपुर्द किए गए किसी व्यक्ति के दण्डादेश में कोई परिवर्तन किया जाता है वह उस परिवर्तन की संसूचना अनावश्यक विलम्ब के बिना कारागार के अधीक्षक को जिसमें ऐसे व्यक्ति को सौंपा गया है नियम 174 में यथा वर्णित कमांडेंट या ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा परिशिष्ट 14 में उपवर्णित प्ररूप में दी जाएगी।

177. पदच्युति का दण्डादेश— (1) पदच्युति का दण्डादेश उस दण्डादेश के प्रख्यापन की तारीख से या किसी पश्चातवर्ती तारीख से जो प्रख्यापन के समय विनिर्दिष्ट की जाए प्रभावी होगा।

(2) पदच्युति का दण्डादेश सिविल कारागार में भोगे जाने वाले कारावास के साथ तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक ऐसे व्यक्ति को सिविल कारागार में सौंप न दिया गया हो।

अध्याय - 14

याचिकाएं

178. न्यायालय के निष्कर्ष और दण्डादेश के विरुद्ध याचिका - (1) अधिनियम के अधीन ऐसे व्यक्ति को, जिसका किसी न्यायालय द्वारा विचारण किया गया है पुष्टिकरण से पहले पुष्टिकरण प्राधिकारी के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत करने और एक याचिका पुष्टिकरण के पश्चात् धारा 139 में वर्णित किसी अधिकारी को प्रस्तुत करने की अनुमति दी जाएगी।

(2) मृत्यु दण्डादेश को तब तक प्रभावी नहीं किया जाएगा जब तक दण्डादिष्ट व्यक्ति द्वारा नियम 179 के उपनियम (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के दौरान प्रस्तुत की गई पश्चपुष्टि याचिका का निपटान न हो जाए और ऐसी याचिका का अंतिमरूप से निपटारा करने के लिए विधिकरूप से सक्षम प्राधिकारी याचिका पर विचार करने के पश्चात् यह आदेश नहीं कर देता है कि मृत्यु दण्डादेश का प्रभावी किया जा सकता।

(3) समरी असम साइफल्स न्यायालय की दशा में उसे धारा 137 में वर्णित किसी अधिकारी को केवल एक याचिका देने के लिए अनुज्ञात किया जाएगा।

179. परिसीमा की अवधि (1) याचिका को पुष्टि से पूर्व विचारण के समापन से एक मास के भीतर याचिका प्रस्तुत की जाएगी।

(2) पुष्टिकरण के पश्चात् याचिका दण्डादेश के प्रख्यापित किए जाने की तारीख के तीन मास के भीतर प्रस्तुत की जाएगी;

परन्तु ऐसे व्यक्ति द्वारा कार्यवाहियों की प्रति प्राप्त करने में लिए गए समय को तीन मास की इस अवधि की संगणना करने में अपवर्जित कर दिया जाएगा।

180. याचिका प्रस्तुत करने का ढंग—

(1) (क) ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा, जो अभी भी बल का सदस्य है कोई याचिका उसके कमांडेंट के माध्यम से प्रस्तुत की जाएगी।

(ख) ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो बल का सदस्य नहीं रहा है याचिका उस यूनिट के कमांडेंट प्रस्तुत की जाएगी जिसमें विचारण किया गया था।

(2) ऐसा अधिकारी जिसे याचिका प्रस्तुत की गई या जिसे याचिका भेजी गई है एक मास के भीतर उसे अपनी सिफारिश के साथ अगले वरिष्ठ प्राधिकारी को भेजेगा :-

परन्तु ऐसा अधिकारी याचिका को अग्रहित नहीं कर सकेगा यदि वह मांगे गए प्रतितोष को देने में सक्षम है और ऐसा करने का विनिश्चय करता है।

(3) याचिका प्राप्त करने वाला अधिकारी उसे सलाह के लिए मुख्य विधि आफिसर या उसके द्वारा नाम निदेशित विधि आफिसर को भेज सकेगा।

अध्याय- 15

जांच न्यायालय

181. संरचना - (1) जांच न्यायालय में दो या दो से अधिक सदस्य होंगे, जिनमें से एक अधिकारी होगा। जब न्यायालय को विशेष प्रकृति के मामले की जांच करनी हो और अधिनियम के अधीन विशेष अर्हताओं वाले अधिकारी उपलब्ध न हों तब तो ऐसे व्यक्तियों को सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जा सकेगा, जो अधिनियम के अधीन न हों।

(2) जब जांच न्यायालय में किसी अधिकारी का चरित्र या आचरण महत्वपूर्ण होने की सम्भावना हो तो जांच न्यायालय का पीठासीन अधिकारी जहां तक सम्भव हो रैंक में ज्येष्ठ का होगा और दूसरे सदस्य कम से कम उस अधिकारी के रैंक के समतुल्य होंगे।

182. समा - (1) जांच न्यायालय कमांडेंट या कमांडेंट से कमान में उच्चतर किसी अधिकारी या प्राधिकारी के आदेश से संवेत हो सकेगा।

(2) जांच न्यायालय संवेत करने वाले आदेश में, न्यायालय की संरचना उसके संवेत होने का समय और स्थान कथन और उन विषयों का स्पष्ट रूप से कथन होगा जिनकी न्यायालय जांच करेगा। उसमें न्यायालय की प्रशासनिक अपेक्षाओं के लिए भी उपबन्ध होगा।

183. जांच न्यायालयों की प्रक्रिया - (1) जांच न्यायालय की कार्यवाहियां जनता के लिए खुली नहीं होगी। केवल ऐसे व्यक्ति ही कार्यवाहियों में भाग ले सकेंगे जिन्हें ऐसा करने के लिए न्यायालय द्वारा अनुमति दी गई हो।

(2) सभी साक्षियों के साक्ष्य शपथ और प्रतिज्ञान पर लिए जाएंगे और उन्हें पढ़कर सुनाए जाने और स्पष्ट किए जाने के पश्चात् उनके द्वारा हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

स्पष्टीकरण - न्यायालय साक्षियों को इस प्रकार शपथ दिलाएगा या प्रतिज्ञान कराएगा मानो वह न्यायालय बल न्यायालय है।

(3) जब तक न्यायालय यह विचार न करे कि किन्हीं प्रश्नों और उत्तर को उस रूप में अभिलिखित किया जाए तब तक साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य को वृत्तान्त रूप में अभिलिखित किया जाएगा।

(4) न्यायालय ऐसे किसी दस्तावेजों पर भी विचार कर सकेगा जो औपचारिक रूप से साबित नहीं हुए हैं।

(5) न्यायालय साक्षियों से किसी भी रूप का कोई भी प्रश्न पूछ सकेगा जो वह सत्य जानने के लिए ऐसा आवश्यक समझे और किसी साक्ष्य पर विचार कर सकेगा चाहे वह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 (1872 के 1) के अधीन ग्राह्य हो या नहीं।

(6) जांच न्यायालय के समक्ष किसी काउन्सेल या विधि व्यवसायी को हाजिर की उपस्थिति होने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी।

(7) जांच न्यायालय के समक्ष साक्षियों की हाजरी उपाप्त करने के लिए धारा 111 के उपबंध का लागू होंगे।

(8) (i) उस युद्ध कैदी के मामले के सिवाय, जो उस समय तक अनुपस्थित है, जब जांच की विषयवस्तु विशिष्ट व्यक्ति का आचरण, चरित्र या ख्याति होती है, ऐसे व्यक्ति को ऐसे व्यक्ति की जांच के दौरान सहयोग दिया जाएगा और कोई कार्य करने या कोई साक्ष्य देने का जब वह करने या देने की इच्छा करे और किसी ऐसे साक्षी की जिसका साक्ष्य उसकी राय में उसके चरित्र या ख्याति को प्रभावित करेगा की प्रतिपरीक्षा पेश करने का पूर्ण अवसर दिया जाएगा।

(ii) अन्य मामलों में, अधिनियम के अधधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध राय देने से पहले न्यायालय उस व्यक्ति को उसके विरुद्ध किए गए सभी कथनों को जानने, ऐसे किसी साक्षी की प्रति परीक्षा करने, जिसने उसके विरुद्ध साक्ष्य दिया है और अपनी प्रतिरक्षा में कोई कथन करने और साक्षियों को बुलाने का अवसर प्रदान करेगा।

(9) न्यायालय अतिरिक्त साक्षियों की परीक्षा करने या किसी साक्षी की आगे परीक्षा करने या अतिरिक्त सूचना अभिलिखित करने के प्रयोजन के लिए तब पुनः संवेत हो जा सकेगा जब वह अधिकारी, जिसने न्यायालय को संवेत किया है ऐसा निदेश करे। ऐसे मामले में न्यायालय यदि जरूरी समझे तो उप नियम (8) के खंड (ii) के उपबंध का पालन करने के पश्चात् नए सिरे से राय अभिलिखित कर सकेगा।

184. जांच न्यायालय की कार्यवाहियों का साक्ष्य में ग्राह्य न होना : जांच न्यायालय की कार्यवाहियां, या जांच न्यायालय में की गई कोई संस्वीकृति या किया गया कोई कथन या दिया गया कोई उत्तर अधिनियम के अधधीन व्यक्ति के विरुद्ध साक्ष्य में ग्राह्य नहीं होगा और न्यायालय की कार्यवाहियों की बावत कोई साक्ष्य किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध तब के सिवाय नहीं दिया जाएगा जब न्यायालय के सामने जानबूझकर झूठा साक्ष्य देने के लिए ऐसे व्यक्ति का विचारण किया जाए।

परन्तु इस नियम की कोई बात में किसी साक्षियों की प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए अभियोजन या प्रतिरक्षा पक्ष द्वारा कार्यवाहियों का उपयोग किए जाने से निवारित नहीं करेगी।

185. जांच न्यायालय को कब आयोजित किया जाएगा - (1) किसी अनुशासनिक मामले या दूसरे महत्वपूर्ण मामलों की जांच पड़ताल के लिए जांच न्यायालय आयोजित किया जा सकता है।

(2) धारा 84 के अधीन आयोजित किए जाने के लिए अपेक्षित जांच न्यायालय निम्नलिखित मामलों में आयोजित की जाएगी:-

(क) (i) अधिनियम के अधधीन व्यक्तियों या बल लाइन्स के भीतर में अन्य व्यक्तियों की मृत्यु पर जिस पुलिस स्टेशन के क्षेत्राधिकार में आते हैं उसके भारसाधक अधिकारी को ऐसी सभी अप्राकृतिक मृत्यु की घटना की तुरंत रिपोर्ट भेजी जाएगी।

(ii) ऐसे मामलों में जब ऐसी रिपोर्ट किसी अप्राकृतिक मृत्यु की सूचना प्राप्त करने पर युक्तियुक्त समय के भीतर किसी कारणवश तुरंत भेजी नहीं जा सकती हो कमांडेंट या उपस्थित यूनिट का वरिष्ठ आफिसर परिशिष्ट 15 में उपवर्णित प्ररूप में रिपोर्ट तैयार करेगा।

(ख) अधिनियम के अधधीन व्यक्तियों द्वारा सहन की गई सभी क्षतियां, जिनसे पूर्ण या आंशिक निशक्ता होने की सम्भावना है। ऐसे मामलों में न्यायालय यह अवधारित करेगा की ऐसी क्षतियां को सेवा के कारण मानी जाएगी या नहीं।

(ग) सभी वित्तीय हानियां, चोरी और लोप या बल की सम्पत्ति का दुर्विनियोग जहां ऐसी हानि, चोरी या दुर्विनियोग के सम्बन्ध में वरिष्ठ अधिकारी का आदेश लेना अनिवार्य है।

(घ) गुप्त दस्तावेजों और गुप्त या उपरोक्त सुरक्षा वर्गीकरण की किसी अन्य सामग्री की सभी गुप्तशुद्धियां ऐसी जांच न्यायालय का आदेश गुप्तशुद्ध दस्तावेज या सामग्री को अपने भारसाधन में रखने वाले यूनिट कमांडेंट से वरिष्ठ किसी अधिकारी या प्राधिकारी को दिया जाएगा।

(ङ) प्राइवेट व्यक्तियों या सम्पत्ति की ऐसी सभी नुकसानियां जिनकी बाबत सरकार या बल के विरुद्ध दावा किए जाने की सम्भावना है।

186. जांच न्यायालय की कार्यवाहियों के सम्बन्ध में कार्यवाही : पीठासीन अधिकारी द्वारा जांच न्यायालय की कार्यवाहियां उस आफिसर या प्राधिकारी को प्रस्तुत की जाएगी जिसने न्यायालय का आदेश दिया गया हो। ऐसा आफिसर या प्राधिकारी कार्यवाहियां प्राप्त

करने पर यदि वह ऐसा करने के लिए सशक्त है तो कार्यवाहियों के संबंध में अंतिम आदेश पारित कर सकेगा या उन्हें वरिष्ठ प्राधिकारी को भेज सकेगा।

187. जांच न्यायालय की कार्यवाहियों की प्रतियां : अधिनियम के अधीन कोई व्यक्ति जिसके विरुद्ध जांच न्यायालय ने कोई राय दी है या जिसका जांच न्यायालय द्वारा अन्वेषण किए गए मामले से सम्बन्धित आरोप के सम्बन्ध में बल न्यायालय द्वारा विचार किया जा रहा है। उसपर निष्कर्ष और राय के सिवाय जांच न्यायालय की कार्यवाहियों की प्रतियां लेने का तभी हकदार होगा जब महानिदेशक ने उसके द्वारा कारणों को अभिलिखित करते हुए अन्यथा आदेश न किया हो अभिलिखित के लिए अन्य आदेश न दें।

शस्त्र खोना या चोरी

188. राइफलें आदि खो जाने की या चोरी हो जाने की दशा में जांच न्यायालय — (1) जब कभी कोई शस्त्र या शस्त्र का भाग जो कि कम्पनी या अन्य सामान यूनिट के उपस्कर का भाग है और जिसकी हानि या चोरी की बाबत नियम 189 के अधीन जुर्माना अधिरोपित किया जा सकता है, खो जाए या चोरी हो जाए तब उन परिस्थितियों का अन्वेषण करने के लिए जिनके अधीन हानि या चोरी हुई है महानिदेशक, महानिरीक्षक या उपमहानिरीक्षक के आदेशों के अधीन एक जांच न्यायालय संमवेत होगा।

(2) न्यायालय संमवेत करने वाला अधिकारी उस न्यायालय को हानि या चोरी की परिस्थितियों के बारे में राय अभिलिखित करने का निदेश देगा।

189. सामूहिक जुर्माना का अधिरोपित करना — (1) महानिदेशक, महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक हानि या चोरी की परिस्थितियों के बारे में अपनी राय अभिलिखित करेगा और खोए हुए या चोरी हुए प्रत्येक शस्त्र या शस्त्र के भाग के लिए अधिनस्थ आफिसरों, अवर आफिसरों और उस यूनिट के व्यक्तियों या उनमें से उतने व्यक्तियों पर, जिनके बारे में वह यह समझता है कि उन्हें घटना के लिए उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए ऐसे शस्त्र या शस्त्र के भाग के लिए सरकार द्वारा अनुमोदित दर की अधिकतम सीमा तक जुर्माना अधिरोपित कर सकेगा।

(2) ऐसा जुर्माना उन व्यक्तियों के जिस पर यह अधिरोपित किया जा रहा है, वेतन के प्रतिशत के रूप में निर्धारित किया जाएगा।

अध्याय— 16

प्रकीर्ण

190. धारा 13 (1) के प्रयोजन के लिए विहित प्राधिकार — (1) धारा 13 की उप धारा (1) के प्रयोजन के लिए प्राधिकारी निम्नलिखित होगा :-

(क) आफिसर से भिन्न अधिनियम के सभी कार्मिकों के संबंध में महानिदेशक।

(ख) आफिसरों की बाबत केन्द्रीय सरकार।

(2) इस नियम के अधीन पूर्वोक्त किसी आफिसर को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग उससे वरिष्ठ किसी आफिसर द्वारा भी किया जा सकेगा।

191. धारा 60 के प्रयोजन के लिए विहित अधिकारी : धारा 60 के प्रयोजन के लिए विहित आफिसर महानिदेशक या उप महानिदेशक जिसके अधीन विचारण किया गया था या उस यूनिट कमांडेंट होगा जिसमें विचारण किया गया था।

192. धारा 62 के अधीन दंड का विस्तार — (1) यदि कमांडेंट, उप कमांडेंट या उसकी पंक्ति से ऊपर का है तो वह आफिसर धारा 62 में विनिर्दिष्ट एक या अधिक दंड पूर्ण सीमा तक अधिनिर्णीत कर सकेगा।

(2) यदि कमांडेंट, उप कमांडेंट की पंक्ति से निम्न पंक्ति का है तो वह नीचे विनिर्दिष्ट दंड अधिनिर्णीत कर सकेगा:-

(क) धारा 62 के खंड (क) और (ख) में, 14 दिन तक;

(ख) धारा 62 के अन्य खंडों में, पूर्ण सीमा तक।

193. धारा 69 (i) और 71 धारा के अधीन विहित आफिसर (1) धारा 69 (i) और धारा 71 के प्रयोजन के लिए से निम्नलिखित विहित आफिसर होंगे:-

(क) अधिनस्थ आफिसरों, अवर आफिसरों और अभ्यावेशित व्यक्तियों की दशा में महानिरीक्षक;

(ख) आफिसरों के दशा में महानिदेशक।

(2) इस नियम के अधीन उपर्युक्त किसी आफिसरों को प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग उस आफिसर से वरिष्ठ किसी आफिसर द्वारा भी किया जा सकेगा।

194. धारा 75 के अधीन विहित प्राधिकारी : अधिनियम के अध्याय- 6 के अधीन कोई कटौतिया देने वाले प्राधिकारी से वरिष्ठ कोई प्राधिकारी उक्त समस्त कटौतियों या उसके किसी भाग को विप्रेषित करने के लिए सक्षम होगा।

195. धारा 76 और धारा 77 के अधीन विहित प्राधिकारी : धारा 76 और धारा 77 के अधीन निम्नलिखित विहित प्राधिकारी होंगे:-

(क) आफिसरों के मामले में महानिदेशक, असम राइफल्स या उसके द्वारा विनिर्दिष्ट कोई आफिसर ; और

(ख) अन्य सभी मामलों में कमांडेंट, प्रशिक्षण बटालियन, प्रशिक्षण केन्द्र या वह यूनिट जिससे युद्ध कैदी या गुमशुदा व्यक्ति संवद्ध हो या कोई वरिष्ठ प्राधिकारी।

196. धारा 85 (1) के अधीन विहित अधिकारी — धारा 85 की उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए विहित आफिसर महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक, रैंज या प्रशिक्षण संस्थान के कमांडेंट होगा।

197. धारा 118 के अधीन विहित प्राधिकारी — धारा 118 की उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए विहित आफिसर महानिरीक्षक, उपमहानिरीक्षक या उस यूनिट का कमांडेंट जिससे व्यक्ति संबंधित प्रतीत होता हो या उससे संबंधित होने का अभिकथन करता हो या पहले संबंधित रहा हो।

दण्डादेश का निष्पादन

198. और धारा 121 और धारा 122 के अधीन अभिरक्षा की विहित रीति और विहित आफिसर — (1) धारा 122 के प्रयोजन के लिए विहित आफिसर निम्नलिखित होंगे —

(क) समरी असम राइफलस न्यायालय द्वारा विचारण की दशा में, उस यूनिट का कमांडेंट जिससे अभियुक्त संबंधित है या उस कमांडेंट से वरिष्ठ कोई प्राधिकारी;

(ख) किसी अन्य न्यायालय द्वारा विचारण की दशा में, संयोजन अधिकारी या उससे वरिष्ठ कोई प्राधिकारी।

(2) जहां वह अधिकारी जिसने उप-नियम (1) के अधीन विहित अधिकारी के रूप में कार्य करने की प्रस्थापना की है उस अधिकारी के समादेश के अधीन है जिसने धारा 121 की उपधारा (4) के अधीन मामले में कार्यवाही की है तो वह कार्यवाही करने के पूर्व साधारणतया ऐसे अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करेगा, किन्तु यदि उसकी यह राय है कि सेवा की अन्याय्यकताओं या अनुशासन की आवश्यकताओं ने ऐसे अनुमोदन प्राप्त करना असंभव या असमीचीन बना दिया है तो वह ऐसा अनुमोदन प्राप्त किए बिना कार्यवाही कर सकेगा किन्तु अपनी कार्यवाही की और उसके कारणों की ऐसे अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।

(3) धारा 121 की उपधारा (4) के प्रयोजन के लिए अभियुक्त ऐसी रीति में परिरुद्ध किया जाएगा जो उचित बल प्राधिकारी की राय में उसे बिना अनावश्यक कठोरता के सुरक्षित रखने के लिए सर्वोत्तम प्रतीत हो, क्योंकि उसे अपराधी के रूप में नहीं अपितु रोग ग्रस्त व्यक्ति के रूप में समझा जाना चाहिए।

199. धारा 140 के अधीन विहित अधिकारी : धारा 140 के प्रयोजनों के लिए अपर महानिदेशक, महानिरीक्षक, रैंज या प्रशिक्षण संस्थान का उपमहानिरीक्षक उसके द्वारा पुष्टिकृत कार्यवाहियों या उसकी कमांड के अधीन कार्यों के संबंध में विहित अधिकारी होगा।

200. धारा 143 के अधीन विहित अधिकारी : ऐसे दण्डादेश के मामले में जिसकी पुष्टि कर दी गई है, यह निदेश देने के प्रयोजनों के लिए क्या दण्डादेश सिविल कारागार में परिरोध द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा, धारा 143 की उपधारा (1) के अधीन विहित अधिकारी पुष्टि करने वाले अधिकारी से कोई उच्चतर प्राधिकारी होगा और उस दण्डादेश में जिसकी पुष्टि अपेक्षित नहीं है, विचारण करने वाले अधिकारी से कोई उच्चतर प्राधिकार होगा।

201. धारा 150 के अधीन विहित अधिकारी : धारा 150 के प्रयोजनों के लिए विहित अधिकारी सिविल कारागार या किसी अन्य स्थान में दण्डादेश भुगतने वाले व्यक्ति की दशा में, महानिदेशक या महानिरीक्षक या उपमहानिरीक्षक रैंज जिसकी कमान के क्षेत्र में ऐसे दंड के अधीन कैदी तत्समय हो।

202. प्राधिकृत कटौतियां : अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को संदेय वेतन और सभी अन्य परिलब्धियों से निम्नलिखित कटौतियों की जा सकेगी, अर्थात् —

(क) केन्द्रीय सरकार के साधारण और विशेष आदेश पर किसी लोक दावे को, जो उसके विरुद्ध चुकाने के लिए अपेक्षित कोई राशि हो;

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किसी भविष्य निधि या अन्य निधि के अनिवार्य अभिदायों को पूर्ति करने के लिए या किसी ऐसे ऋण को, जो बल की संस्थाओं जैसे मेस, केन्टीन और तत्समान उसी प्रकार के ऋण मददे उससे शोध्य हो, पूर्ति करने के लिए अपेक्षित कोई राशि।

स्पष्टीकरण — (i) "लोक दावे" से कोई लोक ऋण या नामजुरी रकम जिसके अन्तर्गत कोई अधिक जारी किया भी है या लोक धन या भंडार की कोई ऐसी कमी या अनियमित व्यय अभिप्रेत है, जिसका सम्यक् अन्वेषण के पश्चात्, उस व्यक्ति द्वारा केन्द्रीय सरकार को समाधानप्रद स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है जो उसके लिए उत्तरदायी है।

(ii) उपरोक्त कटौतियां अधिनियम में विनिर्दिष्ट कटौतियों के अतिरिक्त होंगी।

203. निरसन और व्यावृत्ति — (1) इन नियमों के अधीन आने वाले विषयों से संबंधित सभी नियम और आदेश, जहां तक वे इन नियमों के उपबंधों के असंगत हो निरसित हो जाएंगे।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी इस प्रकार निरसित नियमों या आदेश या उपबन्धों के अधीन की गई कोई बात या कार्यवाई जहां तक ऐसी बात या कार्यवाई इन नियमों के उपबन्धों से असंगत न हो इन नियमों के उपबन्धों के अधीन इस प्रकार की गई समझी जाएगी मानो उक्त उपबन्ध उस समय प्रवृत्त थे जब ऐसी बात या ऐसी कार्यवाई की गई थी और जबतक इन नियमों के अधीन की गई किसी बात या किसी कार्यवाई द्वारा अधिकांश नहीं की जाती तब तक तदनुसार प्रवृत्त बनी रहेगी।

204. अस्थाई उपबंध : इन नियमों के प्रारम्भ पर बल को लागू होने वाला कोई नियम या आदेश जब तक इन नियमों के विरुद्ध न हो, तब तक केन्द्रीय सरकार या अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा निराकृत या उपान्तरित नहीं किया जाता तब तक लागू रहेगा।

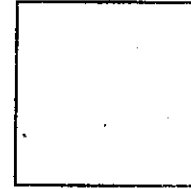
भाग- I

परिशिष्ट- I

(नियम 15 देखिए)

(असम राइफल्स में भर्ती के लिए प्रारूप)

- रक्त समूह जनरल नम्बर
- बटालियन
1. नाम 2. धर्म
3. जाति/जनजाति* 4. पिता का नाम
- * (केवल अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लिए)
5. वारिस
6. जन्म-तिथि (ईस्वीसन् में)
(यथाशक्य अभिनिश्चित निकटतम रूप में)
7. लम्बाई सेंटीमीटर 8. सीना सेंटीमीटर
9. पहचान चिह्न
10. निवास, ग्राम थाना
- जिला राज्य
11. द्वारा चरित्र तथा पूर्ववृत्त का सत्यापन किया गया।
फोटोग्राफ
12. अभ्यावेशन से पहले का व्यवसाय
13. शैक्षिक अर्हताएं, यदि कोई हो
14. अभ्यावेशन की तारीख
15. के रूप में अभ्यावेशित हुए।



फोटोग्राफ की तारीख

अभ्यावेशन का प्रारूप

असम राइफल्स में के रूप में

नं० नाम (स्पष्ट अक्षरों में)

भाग- 1

(अभ्यावेशन से पूर्व किए जाने वाले प्रश्न)

आपको चेतावनी दी जाती है कि यदि अभ्यावेशन के बाद यह पाया जाता है कि आपने निम्नलिखित प्रश्नों में पहले 12 प्रश्नों में से किसी का भी जानबूझकर मिथ्या उत्तर दिया है, तो असम राइफल्स अधिनियम, 2006 तथा उपबंधित आप दंड के दायीं होंगे।

प्रश्न में से किसी का भी उत्तर (सभी उत्तर स्पष्ट अक्षरों में लिखें)

1. आपका नाम क्या है ?
(उपनाम रेखांकित करें)
2. (क) आपका जन्म-स्थान कहां है ?
जन्म का गांव/शहर, जिला और राज्य लिखें।
(ख) आपकी जन्मतिथि क्या है ?
(ईसवी सन् में लिखें)

कृपया ध्यान दें :- व्यक्ति को जन्म तिथि के समर्थन में, समय-समय पर सरकारी आदेशों में विनिर्दिष्ट प्रमाण-पत्र मूल रूप में सत्यापित प्रति के साथ प्रस्तुत करना होगा।

3. आपके घर का स्थायी पता क्या है ?
(क) ग्राम/शहर
(ख) थाना
(ग) परगना/तहसील
(घ) जिला/तालुक
(ङ) राज्य

4. (क) आपका धर्म क्या है ?
(ख) क्या आप अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य हैं ?
(ग) यदि हां, तो जाति या जनजाति का ब्यौरा दें।
 5. (क) क्या आप भारत के नागरिक हैं ? यदि हां, तो क्या जन्म से अथवा वंशज के रूप में अथवा रजिस्ट्रीकरण द्वारा अथवा स्वाभाविक रूप से अथवा इससे अन्यथा भारत के नागरिक हैं ?
(ख) क्या आप नेपाल अथवा भूटान की प्रजा हैं ? यदि हां तो दोनों में किस देश से हैं, इसका उल्लेख करें ?
(ग) यदि आप भारत के नागरिक या नेपाल अथवा भूटान की प्रजा नहीं हैं, तो आपकी राष्ट्रियता क्या है ?
- कृपया ध्यान दें :- व्यक्ति के नेपाल अथवा भूटान से भिन्न किसी अन्य विदेशी राष्ट्रिक का नागरिक होने की दशा में है, केन्द्रीय सरकार की इस संबंध में लिखित सहमति यदि कोई हो, तो अभ्यावेशित होने से पहले इसे प्रस्तुत करनी होगी।
- (घ) क्या आप वर्तमान समय में पाकिस्तान में स्थित किसी स्थान से प्रवासी है, यदि ऐसा है तो प्रवास की तारीख का उल्लेख करें।
 6. आपकी शैक्षिक अर्हता क्या है ?
(मूल प्रतियों के साथ प्रत्येक सत्यापित प्रतियां प्रस्तुत करें।)
 7. क्या आप विवाहित है ?
यदि ऐसा है तो कथन करें,
(क) विवाह (विवाहों) की तारीख
(ख) पत्नी/पत्नियों के नाम
(ग) पत्नी/पत्नियों की नागरिकता
(इसमें विधुर/तलाकशुदा सम्मिलित नहीं है)
 8. (क) आपके पिता का नाम तथा पता क्या है ? यदि देहान्त हो चुका है तो उनका अंतिम पता, जिला और राज्य का कथन करें।
(ख) आपके पिता की क्या राष्ट्रियता है अथवा यदि वे भारतीय नागरिक हैं तो जन्म से, वंशज के रूप में, रजिस्ट्रीकरण द्वारा, स्वाभाविक रूप से या अन्यथा।
 9. क्या आप कभी किसी राजनैतिक, साम्प्रदायिक या सांस्कृतिक प्रकृति के संगठन के सदस्य रहे हैं ? यदि हां तो दल या संगठन का नाम और उसमें अपनी सदस्यता की अवधि के का कथन करें।
 10. (क) क्या आप किसी सरकारी सेवा में है अथवा सरकारी कर्मचारी रहे हैं ? यदि हां तो सेवोन्मुक्त के लिए पूर्व विशिष्टियां और कारणों का कथन करें कि क्या आपको किसी सरकारी सेवा से कभी नहीं निलंबित किया गया, सेवामुक्ति के पूरे ब्यौरे एवं कारण दर्शाएं।
(ख) क्या आप सरकार से कोई भत्ता प्राप्त कर रहे हैं ? यदि हां, तो किस लेखा से ?
 11. (क) क्या आप भारत के किसी सशस्त्र बलों, इन तीनों सेवाओं में से किसी आरक्षित बलों में सहायक वायु सेना, प्रादेशिक सेना, भारतीय पुलिस बल या नेपाल स्टेट आर्मी या विदेश के किसी बल से संबंधित हैं ?
(ख) क्या आपने भारत के किसी सशस्त्र बलों से, तीन सेवाओं में से किसी आरक्षित बलों, सहायक वायु सेना, प्रादेशिक सेना, अथवा भारत के किसी पुलिस बल या नेपाल स्टेट आर्मी या विदेश के किसी बल में कभी सेवा की है ? यदि हां, तो किस बल में और सेवामुक्ति का कारण दर्शाएं। यदि आप उपरोक्त में से किसी एक से अधिक बलों में सेवारत रहे हैं या एक ही बल में दो अलग-अलग समय पर सेवारत रहे हैं, तो प्रत्येक मामलों में सेवामुक्ति के कारण अलग-अलग रूप में दर्शाएं।
(ग) यदि अनुज्ञेय हो क्या आप भारतीय सशस्त्र बलों में अथवा किसी पुलिस बल में अपनी पूर्व की सेवा को वेतन और/या पेंशन के परिकलन के प्रयोजन से गणना करना चाहते हैं ? यदि हां तो आपके पूर्व सेवा के दौरान यदि आपने कोई अपादान प्राप्त किया था और यदि सरकार आपसे छत्तीस मास के समय सीमा तक उक्त रकम आपकी अभ्यावेशन की तारीख से छत्तीस मास के भीतर किस्त में वसूल करे या उपरोक्त अपादान आपके वर्तमान अभ्यावेशन की तारीख से वसूल करे तो क्या आप इसके लिए स्वीकृत होंगे।
 12. क्या आपको भारत में या भारत से बाहर किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया गया, अभियोजन किया गया या बन्दी बनाया गया, आंतरिक बाहरी नजरबन्द किया गया, या इससे अन्यथा कुछ किया गया, यदि हां, तो उक्त विशिष्टि का उल्लेख करें।
 13. क्या आप टीका लगाने या पुनः टीकाकरण और वैक्सीनेशन के लिए इच्छुक हैं ?
 14. क्या आप असम राइफल्स में योद्धक के रूप में अभ्यावेशित होने के लिए इच्छुक हैं ?
 15. क्या आप आदेश दिए जाने पर कहीं भी जल, थल, वायु मार्ग से जाने के लिए तत्पर रहेंगे, तथा जिस ड्यूटी के लिए आपको भर्ती किया गया है उसके निष्पादन में आप जाति या सामाजिक प्रथा की परवाह नहीं करेंगे।
 16. क्या आप इस अभ्यावेशन प्ररूप के भाग-2 में यथा विनिर्दिष्ट सेवा शर्तों के अनुसार सेवानिवृत्त होने तक असम राइफल्स में कार्यरत रहने के इच्छुक हैं ?
 17. क्या आपके सत्यापन के समय आपको निम्नलिखित का वचनबन्ध या अभिपुष्टि करने में कोई आक्षेप है?

शपथ का प्ररूप

मैं.....ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा यथा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा, और मैं कर्तव्य आबद्धता में ईमानदारी और निष्ठा के साथ असम राइफल्स में सेवा करूँगा। आदेश दिए जाने पर कहीं भी वायु, थल, जल मार्ग से जाने के लिए तत्पर रहूँगा तथा मैं, भारत संघ के राष्ट्रपति और किसी आफिसर के समादेशों का पालन जीवन जोखिम होने पर भी करूँगा।

प्रतिज्ञान का प्ररूप

मैं,.....सत्यनिष्ठा से, निष्ठापूर्वक और ईमानदारी से घोषणा और प्रतिज्ञान करता हूँ कि, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा तथा कर्तव्य आबद्धता में मैं ईमानदारी और निष्ठा के साथ असम राइफल्स में सेवा करूँगा और आदेश होने पर कहीं भी वायु, थल, जल मार्ग से जाने के लिए तत्पर रहूँगा तथा मैं, भारत संघ के राष्ट्रपति तथा किसी आफिसर के समादेशों का पालन जीवन जोखिम होने पर भी करूँगा।

प्रमाण-पत्र

मैं,.....सत्यनिष्ठापूर्वक घोषणा करता हूँ कि, मेरे द्वारा दिए गए उपर्युक्त सभी उत्तर सही हैं।
 स्थान :..... (.....)
 तारीख :..... अभ्यावेशित हुए व्यक्ति के हस्ताक्षर
 अभ्यावेशन आफिसर की उपस्थिति में अभ्यावेशित किए गए व्यक्ति के बाएं अंगूठे का निशान।

हस्ताक्षर.....
 साक्षी का नाम.....
 पता.....

* नाम स्पष्ट अक्षरों में

भाग-2सेवा की शर्तें

- *1. अभ्यावेशित होने पर, आप असम राइफल्स अधिनियम, 2006 तथा उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन होंगे।
- *2. सेवा के पहले दो वर्षों के दौरान, यदि आप इस बल के दक्ष सदस्य होने लायक नहीं पाए गए, तो आप सेवानुक्त के दायी होंगे।
3. यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा बल को अथवा बल के किसी भाग को भंग करने का विनिश्चय किया जाता है तो आप सेवानुक्त के दायी होंगे।

अभ्यावेशित व्यक्ति द्वारा प्रमाण-पत्र

मैंने उपरोक्त शर्तों को समझ लिया है तथा उनका पालन करने के लिए सहमत हूँ।

स्थान :..... (.....)
 तारीख :..... अभ्यावेशित व्यक्ति के हस्ताक्षर

उपरोक्त शर्तें, अभ्यावेशित व्यक्ति के समुख पढ़ा गया/मेरे द्वारा स्पष्ट किया गया है।

स्थान :..... (.....)
 तारीख :..... अभ्यावेशन आफिसर के हस्ताक्षर

भाग-3स्वास्थ्य प्रमाण-पत्र

1. मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैंने असम राइफल्स में नियोजन के लिए.....अभ्यर्थी का परीक्षण कर लिया है। वह असम राइफल्स के लिए अधिकथित चिकित्सा मानदण्डों को पूरा करता है और मुझे इस बात का पता नहीं चल पाया कि उसे कोई रोग, शारीरिक गठन की व्याधि या, शारीरिक अंगशैथिल्य है। उसके स्वयं के कथनानुसार उसकी आयु..... वर्ष है और देखने से..... वर्ष प्रतीत होती है।

लम्बाई.....सेंटीमीटर।

सौना (क) अधिकतम.....सेंटीमीटर।
 (ख) न्यूनतम.....सेंटीमीटर।

स्थान :..... चिकित्सा आफिसर के हस्ताक्षर.....
 तारीख :..... पदनाम

परिशिष्ट- 2

(नियम-41 देखें)

विलम्ब रिपोर्ट का प्ररूप

गोपनीय

सं०.....रैंक.....नाम.....

यूनिट का पता.....

तारीख.....

सेवा में,

(संयोजन आफिसर)

विषय :- असम राइफल्स अधिनियम की धारा 81 और असम राइफल्स नियम 41 के अनुसरण में, पहला, (दूसरा), (तीसरा), (चौथा), आदि, आदि आठ-दिन की विलंब रिपोर्ट।

1. सं०.....रैंक.....नाम.....

2. अपराध.....

3. अपराध की तारीख.....

4. अपराध पता लगाने की तारीख

5. गिरफ्तारी (खुली/बन्द) की तारीख

6. पुनः गिरफ्तारी पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना खुली गिरफ्तारी / छोड़े जाने की तारीख.....

(यदि निर्माचित नहीं किया गया है, तो उसके कारण बताएं)

7.तारीख को अभिलिखित साक्ष्य का सारांश

(यदि अभिलिखित नहीं किया गया है, तो कारण बताएं)

8.तारीख को किए गए विचारण के लिए आवेदन-पत्र।

9. विचारण किए जाने वाली सम्यक् तारीख

10.विलम्ब के कारण।

(कमाण्डेंट)

प्रतिलिपि :-

1. महानिरीक्षक असम राइफल्स (आठवीं और उत्तरावर्ती रिपोर्टों की स्थिति में)
2. मुख्य विधि आफिसर, महानिदेशालय असम राइफल्स (आठवीं और उत्तरावर्ती रिपोर्टों की स्थिति में)
3. महानिदेशक (तीन मास से अधिक अवधि तक अभियुक्त को विचारण के बिना बंद गिरफ्तारी में रहने पर विशेष रिपोर्ट)

परिशिष्ट- IIIगिरफ्तार हुए व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन—प्रारूप

(नियम-42 (2) देखें.)

क्र०सं०	तारीख	अभियुक्त का नाम	आफिसर या अधीनस्थ आफिसर जिनके सम्मुख अनुरोध या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया	अनुरोध या अभ्यावेदन की विशिष्टियाँ	कमाण्डेंट के आदेश	अभियुक्त को कमाण्डेंट के आदेश की मूचना प्रदान करने वाले आफिसर या अधीनस्थ आफिसर के हस्ताक्षर तारीख सहित	अभियुक्तियाँ
1	2	3	4	5	6	7	8

परिशिष्ट- 4

(नियम 46 तथा नियम 54 (3) देखें)

(*अंतिम) आरोप-पत्र

अभियुक्त सं०..... (यदि लागू हो) रैंक..... नाम.....
 बटालियन/यूनिट..... पर

निम्नलिखित आरोप लगाया जाता है :-

अपने वरिष्ठ आफिसर के विधिपूर्ण कमाण्ड की अवज्ञा करना

असम राइफल्स अधिनियम

धारा 28 (2)

यह कि उसने,

तारीख को पर अपने वरिष्ठ आफिसर के विधिपूर्ण कमाण्ड की उसने अवज्ञा की, एक ही
 बटालियन के रैंक नाम कमाण्डेंट की परेड में उपस्थित होने का आदेश मिलने पर, तो उसने
 ऐसा नहीं किया।

स्थान

(.....)

कमाण्डेंट

तारीख

बटालियन

** (साधारण या पेटी असम राइफल्स न्यायालय द्वारा विचारण किया जाए)

*अंतिम शब्द को असम राइफल्स नियम 47 के अधीन आरोप की सुनवाई के मामले में ही सम्मिलित किया जाए, और असम राइफल्स
 नियम 54 (3), जिसे असम राइफल्स के न्यायालयों द्वारा विचारण के लिए और आफिसरों अधीनस्थ आफिसरों, वारंट आफिसरों के संक्षिप्त
 विचारण के लिए तैयार किया गया है, के अधीन इसे सम्मिलित नहीं किया जाए।

स्थान

महानिरीक्षक या उपमहानिरीक्षक

तारीख

** जब असम राइफल्स अधिनियम की धारा 96 (2) के अधीन यथा उपबंधित गंभीर अपराधों के विचारण की स्वीकृति दी जाए,
 तब ये प्रविष्टियां असम राइफल्स नियम 54 (3) में विनिर्दिष्ट आरोप पत्र में की जाए।

परिशिष्ट- 5

(आरोप की सुनवाई का प्ररूप)

(नियम-47 देखिए)

यह प्ररूप असम राइफल्स अधिनियम, 2006 के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध आरोप की सुनवाई के दौरान कमाण्डेंट द्वारा भरा जाएगा।

असम राइफल्स नियम 47 के अधीन कमाण्डेंट के सम्मक्ष कार्यवाहियों के अभिलेख

(मूल यूनिट) के यूनिट नं०..... रैंक..... नाम..... (प्राधिकार का उल्लेख करें)
 के अधीन..... (यूनिट, जिससे वह संबद्ध है) से संबद्ध है, के मामले अधीन में।

कार्यवाहियां

1. अभियुक्त के विरुद्ध आरोप उसे पढ़कर सुनाया गया, समझाया गया जो उपाबंध 1 के रूप में लगा है,

या

2. असम राइफल्स नियम 47 (1) के निबंधानुसार, साक्षी को बुलाने और सुनवाई करने से अभियुक्त कर दिया गया है, क्योंकि अभियुक्त के संबंध में, जांच न्यायालय पर असम राइफल्स नियम 191 (8) के उपबंध का अनुपालन किया गया है।

अभियुक्त के हस्ताक्षर

तारीख.....

टिप्पण : जब कमाण्डेंट असम राइफल्स नियम 47 (1) के निबंधनों में साक्षियों को बुलाने तथा सुनवाई करने से अभियुक्त कर देता है, तो परिशिष्ट के स्तंभ 4 से 6 को, अप्रयोज्य होने पर, काट दें। कमाण्डेंट परिशिष्ट के स्तंभ 7 में उपयुक्त आदेश पारित करेगा।

3. आरोप/आरोपों के सुनवाई तारीख.....को.....बजे प्रारंभ हुई।
4. मैंने निम्नलिखित अभियोजन साक्षियों को अभियुक्त, की उपस्थिति में सुना जिसे उनमें से प्रत्येक प्रतिपरीक्षा की पूर्ण स्वतंत्रता थी :-

तारीख जब कमाण्डेंट द्वारा साक्षी का मौखिक रूप सुना गया	अभियोजन-साक्षी/साक्षियों की व्यक्तिगत विशिष्टियां	प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी साक्ष्य, यदि कोई है, की विशिष्टियां	क्या अभियुक्त द्वारा साक्षी की प्रतिपरीक्षा की गई है या उसने प्रतिपरीक्षा करने से इन्कार कर दिया है (जैसा उपयुक्त हो प्रत्येक साक्षी के नाम के सामने हां अथवा "अस्वीकार" शब्द का प्रयोग करें।)
(1)	(2)	(3)	(4)

5. अभियुक्त को मेरे द्वारा यह सूचित कर दिया गया था कि वह अपनी रक्षा में किसी भी साक्षी को बुलाने तथा कोई भी बयान देने के लिए स्वतंत्र है। अभियुक्त द्वारा दिए गए कथन का संक्षिप्त ब्यौरा इस प्ररूप के उपाबंध 2 में लगा है।

या

अभियुक्त ने कथन करने से इन्कार कर दिया है

6. अभियुक्त निम्नलिखित प्रतिवादी साक्षियों की सुनवाई हुई / अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत प्रतिवादी साक्षी प्रस्तुत नहीं किये गये।

तारीख (तारीखें)	प्रतिरक्षा में साक्षियों की व्यक्तिगत विशिष्टियां	प्रस्तुत किए गए दस्तावेजी साक्ष्य यदि कोई है; तो, उसका वर्णन

7. आरोप (आरोपों) की सुनवाई की समाप्ति पर यह जांच न्यायालय में पूरे साक्ष्य और अभियुक्त के बयान का जायजा लेने के पश्चात, और मैंने निम्नलिखित आदेश दिया है :-

आदेश की तारीख	आदेश

8. असम राइफल्स नियम 47 (1) के अधीन उपरोक्त कार्यवाहियां निम्नलिखित स्वतंत्र साक्षियों की उपस्थिति में, मेरे द्वारा की गई :-

(क)

(ख)

स्थान :

हस्ताक्षर.....

(नाम)

तारीख :

कमाण्डेंट

बटालियन

टिप्पणी :- लागू न होने वाले भाग को काट दें।

अनुदेश

(क) अभियुक्त के कमाण्डेंट की यह व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा कि वह असम राइफल्स अधिनियम, 2006 के अधीन संक्षिप्त विचारण के मामले सहित उसके द्वारा निपटाए गए प्रत्येक अनुशासनिक मामले में इस प्ररूप में भरें।

(ख) असम राइफल्स नियम 47 (1) के परन्तुक में यथा उपबंधित के सिवाए, अभियुक्त किसी भी रीति में दोषी या अपनी सह-अपराधिता/दोषी स्वीकारने का अभिव्यक्त करने के रहते हुए भी सुनवाई के दौरान अभियुक्त द्वारा अभियोजन की साक्षी/साक्षियों का प्रतिपरीक्षा का पूर्ण अवसर देना आज्ञापक है। ऐसे मामले, जहाँ दस्तावेजी साक्ष्य से प्रथम दृष्टया अपराध सिद्ध हो जाता है या अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत साक्षी (साक्षीगण) संबंधित दस्तावेजी साक्ष्य पेश कर रहे हो, तब भी अभियुक्त द्वारा इनकी परीक्षा विधिक आवश्यकता होगी। जिसे साक्षी/साक्षियों की विशिष्टियां इस प्ररूप के स्तंभ 4 में अनिवार्य रूप से अभिलिखित करना होगा।

(ग) सुनवाई समाप्त होने पर, कमाण्डेंट के आदेशों को इस प्ररूप के उपाबंध I में भी अभिलिखित करने के साथ पैरा 7 के अनुसार अभियुक्त को सूचित कर दिया जाएगा। उक्त आदेश निम्नलिखित रूप से अभिलिखित किए जाएंगे:- "साक्ष्य को लेखबद्ध किया जाए" "संक्षिप्त-विचारण किया जाए" या "मैं आरोपों को खारिज करता हूँ आदि"।

(घ) इस प्ररूप के साथ, मूल आरोप(आरोपों) या अभियोग(अभियोगों) के साथ कमाण्डेंट के आदेश और विचारण के लिए आवेदन भी संलग्न होगा।

(ङ) समरी असम राइफल्स न्यायालय द्वारा विचारण की दशा में, यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पुनर्विलोकन के लिए मुख्य विधि आफिसर को प्रस्तुत करते समय कार्यवाही के साथ यह प्ररूप भी संलग्न किया जाए।

(च) इसी तरह, आफिसर, अधीनस्थ आफिसर, वारंट आफिसर और अवर आफिसर के समरी विचारण के मामलों में, उच्च प्राधिकारी के पुनर्विलोकन के लिए कार्यवाही प्रस्तुत करते समय यह प्ररूप संलग्न किया जा सकेगा।

(छ) असम राइफल्स नियम 47 (1) के द्वारा यथा उपबंधित के सिवाए अभियोग की प्रारंभिक सुनवाई के प्रयोजन के लिए जांच न्यायालय द्वारा उपयोग नहीं की जा सकेगी।

(ज) जहाँ ऐसा कोई कथन न होने पर, पैरा 7 में उपसंज्ञात शब्द "और अभियुक्त का कथन" शब्दों को हटा दिया जाएगा।

परिशिष्ट-6

[नियम 47 (2) और (4) देखिए]

असम राइफल्स अधिनियम, की धारा 62 के अधीन अवर आफिसरों तथा अन्य अभ्यावेशित व्यक्तियों की संक्षिप्त कार्यवाहियों पर प्रयुक्त करने के लिए प्ररूप।

*अपराध रिपोर्ट

कम्पनी.....

कम सं०.....

.....को समाप्त होने वाले सप्ताह के लिए
अंतिम रिपोर्ट तारीख..... को प्रस्तुत की गई

न०..... रैंक..... नाम..... के विरुद्ध आरोप

अपराध का स्थान और तारीख	अपराध	अभिवाक	साक्षियों के नाम	निष्कर्ष	अधिनिर्णित दंड	उस आफिसर के हस्ताक्षर रैंक और पदनाम, जिसके द्वारा अधिनिर्णय दिया गया और अधिनिर्णय की तारीख	आचरण प्रपत्र में प्रविष्टि की तारीख	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

बटालियन कमाण्डेंट के हस्ताक्षर

अनुदेश

- स्तंभ 1. छुट्टी के बिना अनुपस्थिति या अभियोजन की दशा में,
"अपराध की तिथि" अनुपस्थित होने के प्रथम दिन होगी।
- स्तंभ 2. असम राइफल्स अधिनियम की धारा और उपधारा, जिसके अधीन आरोप लगाया जाता है,
अपराध के उपरोक्त विवरण को सम्मिलित किया जाएगा।
- स्तंभ 3. अधिकारी ऐसे मामले में, जिसमें वह स्वयं एकमात्र अभियोजन साक्षी है, संक्षिप्ततः कार्यवाही नहीं कर सकेगा।
- स्तंभ 4. शीर्षक के अनुसार भरा जाना चाहिए।

टिप्पण :-

1. *अपराध की रिपोर्ट, अनंतिम आरोप-पत्र के अनुसार होगी तथा अभियोजन की सुनवाई सदैव इसके अनुसार ही संचालित की जाएगी।
2. यह दो प्रतिलिपि में तैयार की जाएगी। जहाँ सारलेख या प्रस्तुत किए गए साक्ष्य के संक्षिप्त सार के साथ तैयार किए गए हो, की एक प्रति उपमहानिरीक्षक को भी भेजी जाएगी।

परिशिष्ट-7

[नियम 52 देखिए]

बल न्यायालय के लिए आवेदन का प्ररूप।

बटालियन या यूनिट

तारीख

स्टेशन

बल न्यायालय के लिए आवेदन।

महोदय,

मैं अपनी कमांड के अधीन..... यूनिट के..... सं..... रैंक..... नाम..... के विरुद्ध..... आरोप/आरोपों को प्रस्तुत करता हूँ और आपसे..... की यह स्वीकृति अनुदत्त या अभिप्राप्त करने का अनुरोध करता हूँ कि उसके विचारण के लिए एक..... बल न्यायालय..... स्थान में संयोजित किया जाए।

मामले का अन्वेषण (क)..... द्वारा किया गया था। जांच न्यायालय (ख) तारीख..... को..... स्टेशन में आयोजित किया गया था। पीठासीन आफिसर का नाम..... रैंक..... यूनिट..... सदस्य.....

उसका साधारण चरित्र (ग)..... हैं। मैं निम्नलिखित दस्तावेज (घ)..... संलग्न करता हूँ।

1. आरोप पत्र..... (प्रतियाँ) (ङ)
2. साक्ष्य का संक्षिप्त (मूल) और 5 प्रतियाँ।
3. मूल प्रदर्श।
4. अभियोजन और प्रतिरक्षा पक्ष (उनके वर्तमान पता सहित) के साक्षियों की सूची
5. प्रदर्शों की सूची
6. पत्राचार
7. अभियुक्त के चरित्र का विवरण और आचरण प्रपत्र
8. अभियुक्त का यह कथन कि वह अपने विचारण में अपने प्रतिनिधित्व के लिए संयोजक आफिसर द्वारा समनुदेशित किसी आफिसर की सेवा का उपयोग करना चाहता है या नहीं (नियम 60)

कमाण्डेंट के हस्ताक्षर

अनुदेश

- (क) यहां निम्नलिखित के नाम लिखें :.....
- (I) वह आफिसर, जिसने आरोपों का अन्वेषण किया।
- (II) उस कम्पनी या समतुल्य कमांडर या कमाण्डेंट का नाम, जिसने मामले में प्रारम्भिक जांच की। (नियम 47)
- (III) वह आफिसर, जिसने साक्ष्य को संक्षिप्त अभिलिखित किया (नियम 49)
- (ख) यह तभी भरा जाए, जब आरोपों से संबंधित किसी विषय के बाबत न्यायिक जांच हुई है, अन्यथा इसे काट दिया जाए। (नियम 64 (ग).)
- (ग) कमाण्डेंट द्वारा व्यक्तिगत रूप से भरा जाए।
- (घ) ऐसी कोई मद, जो लागू न हो काट दिए जाएं।
- (ङ) मद 3, 4, 5, 6, 7 और 8 विचारण की सूचना सहित, अभियुक्त की यूनिट के कमाण्डेंट को लौटा दिए जाएं।

परिशिष्ट-8

[नियम 53 देखिए]

प्रारूप-1

असम राइफल्स अधिनियम की धारा 64 से धारा 66 तक के अधीन आफिसरों, अधीनस्थ आफिसरों और वारंट आफिसरों के समरी विचारण में प्रयोग के लिए प्रारूप।

अभियुक्त.....

न०..... रैंक..... नाम..... यूनिट.....

जब इस मामले में समरी कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी (अभियुक्त की लिखित सहमति से) साक्षियों की उपस्थिति से अभियुक्त देवे का विनिश्चय करता है तब :-

अभियुक्त से पूछे जाने वाले प्रश्न-

1. क्या आपको आरोप-पत्र और साक्ष्य सारांश की प्रति प्राप्त हो गई है ? उत्तर.....
2. क्या आपको अपनी प्रतिरक्षा की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिला था ? उत्तर.....
आरोप पत्र पढ़ा जाता है।
3. क्या आप अपने विरुद्ध लगाए गए उन आरोपों, जो आपको पढ़कर सुनाए गए हैं, के दोषी हैं या दोषी नहीं हैं ?
साक्ष्य-सारांश जोर से पढ़ी जाती है या मामले में संक्षिप्त कार्यवाही उत्तर.....
करने वाला प्राधिकारी अभियुक्त की सूचना देता है कि उसको उसने पहले ही पढ़ लिया है।
4. क्या आप कुछ कथन कहना चाहते हैं ? उत्तर.....

यदि अभियुक्त कोई कथन करना चाहता है तो वह इस समय ऐसा यदि, सुनवाई की समाप्ति पर समरी कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी मामले में यह विचार करता है कि आरोप को खारिज नहीं किया जाना चाहिए तो वह अभियुक्त सेवा अभिलेख या आचरण-प्रपत्र की परीक्षा करेंगे।

यदि इस मामले में समरी कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी किसी आफिसर, अधीनस्थ आफिसर या वारंट आफिसर की दशा में, धिग्दंड, तीव्र धिग्दंड या दाण्डिक कटौतियां से भिन्न कोई दंड अधिनिर्णित करने की प्रस्थापना करता है, तो वह अभियुक्त से निम्नलिखित प्रश्न पूछेगा :-

5. क्या आप चाहते हैं कि आपका विचारण असम राइफल्स न्यायालय द्वारा किया जाए या आप मेरा अधिनिर्णय स्वीकार करेंगे ?
उत्तर.....

निष्कर्ष

अधिनिर्णय

स्टेशन

तारीख

हस्ताक्षर.....

टिप्पण 1 :- प्रश्न 4 के उत्तर में अभियुक्त का मौखिक कथन को या तो अभिलिखित किया जाएगा या उसका सारांश तैयार करके संलग्न किया जाएगा।

टिप्पण 2 :- आरोप के निपटान के पश्चात्, नियम 53 (3) से (5) तक के अनुसार पुनर्विलोकन के लिए कार्यवाहियों के साथ सुसंगत दस्तावेज अग्रेषित किया जाएगा।

प्ररूप 2

असम राइफल्स अधिनियम की धारा 64 से धारा 66 तक के अधीन ऑफिसरों, अधीनस्थ आफिसरों और वारंट आफिसरों के समरी विचारण में उपयोग के लिए प्ररूप

अभियुक्त.....

नाम.....यूनिट.....

जब मामले में समरी कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी साक्षियों की हाजिरी को अभिमुक्ति प्रदान करने का विनिश्चय नहीं करता या तब जब अभियुक्त उनकी हाजिरी की अपेक्षा करता है।

अभियुक्त से पूछे जाने वाले प्रश्न :-

1. क्या आपको आरोप-पत्र और साक्ष्य के सारांश की प्रति प्राप्त हो गई है ? उत्तर :-
2. क्या आपको प्रतिरक्षा की तैयारी करने के लिए पर्याप्त समय मिला है ? उत्तर :-
आरोप-पत्र पढ़ा जाता है।
3. क्या आप अपने विरुद्ध लगाए गए उस आरोप/उन आरोपों के जो आपको पढ़कर सुनाए गए हैं, दोषी हैं या दोषी नहीं हैं जिनको आपने पढ़ते हुए सुना है ? उत्तर :-
साक्षी अपना साक्ष्य देते हैं, अभियुक्त को प्रतिपरीक्षा करने की अनुमति दी जाती है।
4. क्या आप कथन करना चाहते हैं ? उत्तर :-
5. क्या आप किसी साक्षी को बुलाना चाहते हैं ? उत्तर :-
अभियुक्त कथन करता है और उसके साक्षी साक्ष्य देते हैं।

यदि मामले में समरी कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी सुनवाई की समाप्ति पर यह समझता है कि आरोप को खारिज नहीं किया जाना चाहिए तो वह अभियुक्त के सेवा अभिलेख या विचारण प्रपत्र की परीक्षा करेगा।

यदि मामले में समरी कार्यवाही करने वाला प्राधिकारी आफिसर अधीनस्थ आफिसर या वारंट आफिसर की दशा में, धिग्दण्ड, तीव्र धिग्दण्ड या दाण्डिक कटौतियों से भिन्न कोई दण्ड अधिनिर्णित करने की प्रस्थापना करता है तो वह अभियुक्त से निम्नलिखित प्रश्न पूछेगा :-

6. क्या आप चाहते हैं कि आपका विचारण असम राइफल्स न्यायालय द्वारा किया जाए या आप मेरा अधिनिर्णय स्वीकार करेंगे ? उत्तर :-

निष्कर्ष

अधिनिर्णय

स्टेशन

तारीख

हस्ताक्षरित.....

टिप्पण 1:- प्रश्न 4 के उत्तर में अभियुक्त का मौखिक कथन को या तो अभिलिखित किया जाएगा या उसका सारांश तैयार करके संलग्न किया जाएगा।

टिप्पण 2—आरोप के निपटान के पश्चात्, नियम 53 (3) से (5) के अनुसार पुनर्विलोकन के लिए कार्यवाहियों के साथ सुसंगत दस्तावेज अग्रेषित किया जाएगा।

परिशिष्ट-9

[नियम-67 देखिए]

बल न्यायालय संयोजन हेतु प्ररूप

असम राइफल्स अधिनियम, 2006 के अधीन साधारण या पेटी असम राइफल्स न्यायालय के संयोजन के लिए आदेश का प्ररूप
द्वारा आदेश

(स्थान.....तारीख.....)
नं०..... नीचे वर्णित आफिसर.....के.....मास
के.....दिन.....बल न्यायालय द्वारा
रैंक..... विचारण किए जाने के प्रयोजन के लिए संयोजित होंगे।

नाम.....
यूनिट..... पार्श्व में नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) का (और ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों का जो उनके समक्ष लाए जाए)

वरिष्ठ आफिसर ही पीठासीन आफिसर के रूप में आसीन होगा

सदस्य

प्रतिक्षारत सदस्य

विधि आफिसर

.....को विधि आफिसर नियुक्त किया जाता है

दुभाषिया

.....को दुभाषिया नियुक्त किया जाता है।

अभियोजक

.....को अभियोजक नियुक्त किया जाता है।

@ अभियुक्त को चेतावनी दी जाएगी और सभी साक्षियों से हाजिर होने की सम्यक् अपेक्षा की जाए।

कार्यवाहियों (जिसकी केवल तीन प्रतियां अपेक्षित हैं) मुख्य विधि आफिसर के माध्यम सेको अग्रेषित की जाएगी।

20.....के.....मास के दिनहस्ताक्षरित

()

संयोजक आफिसर

* न्यायालय की संरचना की बाबत संयोजन आफिसर की कोई राय (नियम 66 देखिए) यहां इस प्रकार जोड़ा जाना चाहिए

"संयोजन आफिसर की राय में, विभिन्न बटालियनों या यूनिटों के आफिसरों की नियुक्ति करना व्यावहारिक नहीं है।"

"संयोजन आफिसर की राय में अभियुक्त के समान या वरिष्ठ रैंक वाले आफिसर, लोक सेवा की अत्यावश्यकताओं को सम्यक् रूप से ध्यान में रखते हुए उपलब्ध नहीं है।"

@ यहां काउन्सेल की बाबत कोई आदेश लगाएं [नियम 67 (ज) देखिए]

संयोजक आदेश पर संयोजक आफिसर द्वारा व्यक्तिगत रूप से हस्ताक्षर किए जाने चाहिए। संयोजन आदेश की तारीख उस तारीख के पूर्व की नहीं होनी चाहिए जिसको संयोजन आफिसर ने विचारण का आदेश आरोप-पत्र पर पृष्ठांकित किया था।

[नियम 114 (1) देखिए]

(जो अपराध किया गया है, उसके बारे में सम्पत्ति के निपटान का आदेश)

असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 127 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं..... मैं आदेश देता हूँ किपरिदान करें या.....को सदाय करें (अधिहरण या नष्ट)

हस्ताक्षर

(पुष्टि करने वाला प्राधिकारी)

तारीख

स्थान

परिशिष्ट- 11

[नियम 116 (2) देखिए]

(बल न्यायालय के निष्कर्ष और दंडादेश को प्रख्यापित करने के लिए प्ररूप)

जनरल या पेटी असम राइफल्स न्यायालय के निष्कर्ष और दंडादेश.....(विवरण) अभियुक्त के विचारण के लिए.....
.....तारीख.....से तारीख तथा(स्थान) में आयोजित200 के दिन.....
.....(स्थान) में मेरे द्वारा अभियुक्त को प्रख्यापित किया गया था।

यूनिट या बटालियन अभिलेख के लिए सार रख लिए हैं या * निष्कर्ष (निष्कर्षों) का कोई भी अभिलेख अभिलेख नहीं रखा गया है।

हस्ताक्षर

कमाण्डेंट

तारीख

स्थान

* सभी आरोपों पर दोषमुक्ति के मामले में उपयोग करें।

परिशिष्ट - 12

(नियम 174 देखिए)

असम राइफल्स अधिनियम, 2006 की धारा 143 और धारा 147 के अधीन वारन्ट

प्ररूप क

जब किसी कैदी को आजीवन कारावास के लिए दण्डादिष्ट किया गया है के प्रयोग के लिए सुपुर्दगी वारन्ट (धारा 143)

सेवा में

अधीक्षक

(क)कारावास।

20 के मास के दिन आयोजित (ख) जनरल असम राइफल्स न्यायालय ने यूनिट के (संख्यांक, रैंक और नाम) को सिद्धदोष ठहराया था। यथास्थिति "सक्रिय सेवा में होते हुए अभित्यजन", "शत्रु के साथ पत्राचार" (यहां अपराध का संक्षेप में उल्लेख करें)।

और उक्त जनरल असम राइफल्स न्यायालय ने 20 के मास के दिन उक्त (नाम) के लिए निम्नलिखित दण्डादेश पारित किया अर्थात्—

दण्डादेश पूर्ण रूप से लिखा जाए किन्तु उस पर हस्ताक्षर नहीं किए जाए और उक्त दण्डादेश की (ख) द्वारा (ग) विधि द्वारा अपेक्षित रूप से सम्यक् रूप में पुष्टि कर दी गई है।

अतः इस वारन्ट द्वारा आपसे इस बात की अपेक्षा की जाती है और इस बात के लिए आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त (नाम) को विधि द्वारा अपेक्षित रूप में इस वारन्ट सहित, उक्त कारागार में अपनी अभिरक्षा में ग्रहण करें और तब तक रखें, जब तक कि उसे समुचित प्राधिकारी को और उसकी अभिरक्षा में आजीवन कारावास के पूर्वोक्त दण्डादेश को भोगने के प्रयोजन के लिए, उक्त वारन्ट सहित, हवाले नहीं कर दिया जाता। पूर्वोक्त दण्डादेश (घ) से प्रभावी है।

(नाम) द्वारा अन्वेषण जांच, या (घ) उक्त अवधि के दौरान उसी मामले के विचारण और है। उसी मामले के विचारण के दौरान सिविल कारागार/बल कारागार में व्यतीत समय आजीवन कारावास के पूर्वोक्त दण्डादेश का मुजरा मिलेगा।

आज 20 के मास के दिन पर मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(च) हस्ताक्षर

(क) सिविल कारागार का नाम लिखें।

(ख) पुष्टि करने वाले प्राधिकारी का नाम और विवरण।

(ग) यदि आवश्यक हो तो "..... के परिहार सहित" शब्द जोड़ें।

(घ) वह तारीख (वर्ष, मास, दिन) प्रविष्ट करें जिसको मूल दण्डादेश हस्ताक्षरित किया गया जो अन्वेषण जांच, या उसी मामले में विचारण के दौरान सिविल कारागार/बल कारागार में व्यतीत वर्ष।

(ङ) कैदी के कमाण्डेंट या अन्य विहित आफिसर के हस्ताक्षर।

प्ररूप ख

कैदी की दशा में उपयोग के लिए सुपुर्दगी वारंट जब कैदी कारावास से दंडादिष्ट किया गया है जो कि सिविल कारागार में भेजा जाता है (धारा 143)

सेवा में,

अधीक्षक (क) कारागार।

(ख) 20 के मास के दिन आयोजित बल न्यायालय ने यूनिट के संख्या रैंक नाम को (यहां अपराध का संक्षेप में उल्लेख करें, जैसे यथास्थिति 'अभित्यजन' 'चोरी', 'चुराए' हुए माल को अभिप्राप्त करना, 'कपट', 'विधिपूर्ण समादेश की अवज्ञा करना' से) सम्यक् रूप से सिद्धदोष ठहराया गया था।

और, उक्त (ख) बल न्यायालय ने 20 के मास के दिन उक्त नाम के लिए निम्नलिखित दण्डादेश पारित किया, अर्थात्—

..... दण्डादेश पूर्णरूप से लिखा जाए, किन्तु उस पर हस्ताक्षर नहीं किए जाए।

और उक्त दण्डादेश की (ग) द्वारा (घ), (ङ) विधि द्वारा यथा अपेक्षित रूप में सम्यक् रूप से पुष्टि कर दी गई है या पुष्टिकरण के बिना ही विधिमान्य है।

अतः इस वारंट द्वारा आपसे इस बात की अपेक्षा की जाती है और इस बात के लिए आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त (नाम.....) को, वारंट सहित अपनी अभिरक्षा में ग्रहण करें और वहां कारावास के पूर्वोक्त दंडादेश को विधि के अनुसार निष्पादित करें।

नाम..... द्वारा अन्वेषण, जांच या (च) उक्त अवधि और है उसी मामले के विचारण के दौरान सिविल कारागार/बल कारागार में व्यतीत समय आजीवन कारावास के पूर्वोक्त दण्डादेश का मुजरा मिलेगा।

यह 20..... के..... मास के..... दिन..... पर मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(छ) हस्ताक्षर

- (क) सिविल कारागार का नाम प्रविष्ट करें।
- (ख) जनरल, पेटी या समरी।
- (ग) जो शब्द लागू न हो, उसे काट दें।
- (घ) पुष्टि करने वाले प्राधिकारी का नाम और वर्णन।
- (ङ) यदि आवश्यक हो तो "....." के परिहार सहित" जोड़ें।
- (च) वह तारीख प्रविष्ट करें, जिस को मूल दण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- (छ) वह ठीक अवधि लिखें (वर्ष, मास और दिन)
जो अन्वेषण, जांच या उसी मामले में विचारण के दौरान सिविल बल अभिरक्षा में व्यतीत की गई।
- (ज) कैदी के कमाण्डेंट या अन्य विहित आफिसर के हस्ताक्षर।

प्ररूप ग

जब आजीवन कारावास के दण्डादेश को किसी वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा घटा कर किसी कम अवधि के कारावास का दण्डादेश दिए जाने पर उपयोग के लिए वारंट (धारा 147)

सेवा में,

अधीक्षक,

..... कारागार।

यूनिट के नं०..... रैंक..... नाम..... तारीख.....
को..... में आयोजित..... जनरल असम राइफल्स न्यायालय द्वारा पारित (ख).....
के दण्डादेश के अनुसरण में (ग)..... द्वारा जारी किए गए वारंट के अधीन.....
कारागार (क)..... में परिरुद्ध हैं, और (घ)..... ने असम राइफल्स अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त दंडादेश की बावत निम्नलिखित आदेश पारित किया है अर्थात:-
(ङ).....

अतः इस वारंट के द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है और इस बात के लिए आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त (नाम.....) को इस वारंट सहित उक्त कारागार में अपनी अभिरक्षा में विधि के अनुसार, तब तक रखेंगे जब तक कि वह उक्त आदेश के अधीन आजीवन कारावास का दण्ड भोगने के प्रयोजन के लिए आपके द्वारा उक्त वारंट सहित समुचित प्राधिकारी वारंट को, जिसके स्थान पर यह वारंट जारी किया गया है, मुझे वापस कर देंगे।

ऐसे आजीवन कारावास की अवधि की गणना (च)..... से की जाएगी।

नाम..... द्वारा अन्वेषण जांच, या (छ) उक्त अवधि और..... है उसी मामले के विचारण के दौरान सिविल अभिरक्षा/बल अभिरक्षा में व्यतीत समय आजीवन कारावास के पूर्वोक्त दण्डादेश का मुजरा होगा।

20..... के..... मास के..... दिन..... पर मेरे हस्ताक्षर से किया गया।

(ज) हस्ताक्षर

- (क) सिविल कारागार का नाम प्रविष्ट करें।
 (ख) उस आफिसर का नाम या पदनाम लिखें, जिसने मूल वारंट हस्ताक्षर किए हैं।
 (ग) मूल दण्डादेश प्रविष्ट करें (यदि यह पुष्टि करने वाले आफिसर द्वारा या अन्य वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा कम कर दिया गया था, तो दंडादेश इस प्रकार लिखा जाना चाहिए) :-
 ("आजीवन कारावास, पुष्टि करने के लिए आफिसर द्वारा घटा कर 10 वर्ष कर दिया गया है")।
 (घ) दंडादेश में फेर-फार करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम।
 (ङ) पूरा आदेश लिखा जाए।
 (च) वह तारीख प्रविष्ट करें जिस तारीख को मूल दण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे।
 (छ) वह यथावत अवधि लिखें (वर्ष, मास और दिन), जो अन्वेषण जांच, या उसी मामले में विचारण के दौरान सिविल अभिरक्षा/बल अभिरक्षा में व्यतीत किया।
 (ज) विहित आफिसर के हस्ताक्षर।

प्ररूप घ

कैदी को बल अभिरक्षा परिदत्त करने की दशा में उपयोग के लिए वारंट

सेवा में,

अधीक्षक,

(क) कारागार ।

..... यूनिट के नं० रैंक नाम
 (स्थान) में आयोजित (ख) बल न्यायालय द्वारा पारित (ग) के कारावास के
 दण्डादेश के अनुसरण में (घ) द्वारा जारी किए गए वारंट के अधीन (क)
 कारागार में परिरुद्ध है, और (ङ) ने असम राइफल्स अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त दंडादेश की बाबत
 निम्नलिखित आदेश पारित किया है अर्थात:-

(च)

अतः आपसे इस बात की अपेक्षा की जाती है और इस बात के लिए आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त (नाम) को इस वारंट को लाने वाले आफिसर या अधीनस्थ आफिसर के हवाले कर दें।

20 के मास के दिन पर मेरे हस्ताक्षर से किया गया।

(छ) हस्ताक्षर

- (क) सिविल कारागार का नाम प्रविष्ट करें।
 (ख) उस आफिसर का नाम या पदनाम प्रविष्ट करें जिसने वारंट का हस्ताक्षर किए थे ।
 (ग) मूल दण्डादेश प्रविष्ट करें (यदि यह पुष्टि करने वाले आफिसर द्वारा या अन्य वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा कम कर दिया गया था तो दंडादेश इस प्रकार लिखा जाना चाहिए) :-
 "पुष्टि करने वाले अधिकारी द्वारा 2 वर्ष का कठोर कारावास घटा कर 1 वर्ष कर दिया गया है")।
 (घ) जनरल, पेटी और समरी।
 (ङ) आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम।
 (च) पूरा आदेश दिया जाए।
 (छ) विहित आफिसर के हस्ताक्षर।

परिशिष्ट - 13

[नियम 175 (1) देखिए]

प्ररूप ड.

मृत्यु दण्डादेश दिए गए व्यक्ति को सिविल कारागार की अभिरक्षा में परिदत्त करने के लिए वारंट सेवा में,

अधीक्षक (क)

..... कारागार।

20..... के मास के दिन में आयोजित जनरल असम राइफल्स न्यायालय ने यूनिट के सं०..... रैंक..... और नाम..... को (अपराध का संक्षिप्ततः उल्लेख करें) सिद्धदोष पाया था।

और उक्त जनरल असम राइफल्स न्यायालय ने 20..... के मास के दिन उक्त (नाम) को मृत्यु का दंडादेश किया गया था।

अतः आपसे अपेक्षा की जाती है और इस बात के लिए आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त (नाम) को इस वारंट सहित उक्त कारागार में अपनी अभिरक्षा में आपेक्षित विधि अनुसार ग्रहण करेंगे और तब तक रखे रहेंगे, जब तक कि उक्त (नाम) की बाबत कोई और वारंट आपको जारी नहीं कर दिया जाता।

20..... के मास के दिन में, मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

हस्ताक्षर (ख)

(क) सिविल कारागार का नाम प्रविष्ट करें।

(ख) कमाण्डेंट के हस्ताक्षर।

प्ररूप च

सिविल कारागार में मृत्यु दंडादेश के निष्पादन के लिए वारंट

भाग- I

सेवा में,

अधीक्षक (क)

..... कारागार।

20..... के मास के दिन (ख) में आयोजित जनरल असम राइफल्स न्यायालय द्वारा मृत्यु के दंडादेश दिया गया..... (यूनिट) के (संख्यक..... रैंक..... और नाम.....) को आपकी अभिरक्षा में सुपुर्द किया गया..... (ग) द्वारा वारंट जारी किया गया है।

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त दंडादेश की पुष्टि कर दी गई है, केन्द्रीय सरकार के आदेश की एक प्रति यह प्रमाणित करते हुए इसके साथ उपाबद्ध है, से मृत्यु दण्डादेश की पुष्टि की गई।

अतः आपको प्राधिकृत किया जाता है और आपसे अपेक्षा की जाती है,

उक्त (नाम) को (घ) "जब तक उसकी मृत्यु न हो जाए उसे गर्दन से"। उक्त दण्डादेश का निष्पादन किया गया है और इस वारंट को पृष्ठांकन सहित यह प्रमाणित करते हुए कि दण्डादेश का निष्पादन हो गया है, लौटा दें।

20..... के मास के दिन पर मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

हस्ताक्षर (च)

- (क) सिविल कारागार का नाम प्रविष्ट करें।
 (ख) विचारण के स्थान का नाम प्रविष्ट करें।
 (ग) उस आफिसर का नाम प्रविष्ट करें, जिसने मूल वारंट पर हस्ताक्षर किए थे।
 (घ) निष्पादन का, तारीख, समय और स्थान।
 (ङ) महानिदेशक, असम राइफल्स।
 (च) महानिदेशक के हस्ताक्षर।

भाग -2

वारंट की वापसी

(नाम).....(संख्या).....(रैंक).....को पारित उक्त दण्डादेश 20.....के मास.....
 के दिन.....बजे (घ) निष्पादित किया गया।

कारागार अधीक्षक के हस्ताक्षर

प्ररूप छ

मृत्यु के लिए दण्डादेश प्राप्त व्यक्ति को ऐसा दण्डादेश कार्यान्वित करने के लिए सिविल कारागार अभिरक्षा में से लेने के लिए वारंट
 सेवा में,

अधीक्षक

(क)कारागार।

20.....के.....मास के.....दिन.....में आयोजित जनरल असम
 राइफल्स न्यायालय द्वारा मृत्यु के लिए दण्डादिष्ट किया गया.....यूनिट का नं०.....रैंक.....
 नाम.....(ख).....द्वारा जारी किए गए वारंट के अधीन उक्त कारागार में रखा गया है।

और उक्त दण्डादेश की (ग).....द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित सम्पूर्ण रूप से पुष्टि कर दी गई है और उक्त
 दण्डादेश को कार्यान्वित करने के लिए एक आदेश मुझे.....(घ).....(नाम और रैंक).....
 को जारी किया गया है।

आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि आप उक्त (नाम).....को इस वारंट को
 लाने वाले आफिसर या आफिसर के अधीनस्थ आफिसर के हवाले कर दें।

20.....के.....मास के.....दिन.....में, मेरे हस्ताक्षर से जारी किया
 गया।

हस्ताक्षर (ङ.)

- (क) सिविल कारागार का नाम प्रविष्ट करें।
 (ख) उस आफिसर का नाम या पदनाम लिखें जिसने मूल वारंट पर हस्ताक्षर किए थे।
 (ग) पुष्टि करने वाले प्राधिकारी का नाम और विवरण।
 (घ) उस आफिसर का नाम और पदनाम लिखें, जिसे आदेश जारी किया गया है।
 (ङ) उस आफिसर के हस्ताक्षर, जिसके द्वारा वारंट जारी किया गया।

प्ररूप ज

असम राइफल्स प्राधिकारियों द्वारा मृत्यु दण्डादेश को कार्यान्वित करने के लिए वारंट

भाग - I

सेवा में,

महानिरीक्षक या उपमहानिरीक्षक

20.....के.....मास के.....दिन.....(क) आयोजित जनरल असम राइफल्स न्यायालय द्वारा मृत्यु भोगने के लिए दण्डादिष्ट किया गया नाम.....यूनिट का नं०.....रैंक.....
 (ग).....द्वारा जारी किए गए वारंट के अधीन (ख).....कारागार में रखा गया है।

और केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त दण्डादेश की पुष्टि कर दी गई है, पुष्टि प्राधिकारी के आदेश की एक प्रति यह सत्यापित करते हुए कि इससे उपाबद्ध है जिससे दण्डादेश की पुष्टि की गई है। आपसे अपेक्षा की जाती है और प्राधिकृत किया जाता है कि उक्त (व्यक्ति) के उक्त दण्डादेश का निष्पादन करें और उक्त को.....(घ) में गोली मार कर मार दिया जाए और इस वारंट को पृष्ठांकन सहित यह प्रमाणित करते हुए कि दण्डादेश का निष्पादन हो गया है, लौटा दें।

20.....के.....मास के.....दिन.....में
 मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

हस्ताक्षर (घ)

भाग II

वारंट की वापसी

(नाम).....संख्या.....(रैंक).....को पारित उक्त दण्डादेश 20.....
 के मास.....के दिन.....बजे (घ) निष्पादित किया गया।

हस्ताक्षर (घ)

भाग - III

चिकित्सा आफिसर का प्रमाण पत्र

मैं.....(संख्या, रैंक, नाम) यह प्रमाणित करता हूँ कि मैंने नं.....रैंक.....
 नाम.....जिस पर.....(घ) में मृत्यु दण्ड निष्पादित हुआ, के शरीर का परीक्षण किया है और ऐसे परीक्षण में मैंने पाया कि उक्त व्यक्ति मृत था।

20.....के मास.....के दिन.....(स्थान) में हस्ताक्षरित।

हस्ताक्षर

(रैंक और यूनिट)

संघ के सशस्त्र बल का चिकित्सा आफिसर

(क) विचारण का स्थान प्रविष्ट करें।

(ख) कारागार का नाम प्रविष्ट करें।

(ख) द्वारा जारी किए गए वारंट के अधीन (क) कारागार में रखा गया है और (ग) ने असम राइफल्स अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त दंडादेश की बावत निम्नलिखित आदेश पारित किया है, अर्थात् (घ)।

आपसे अपेक्षा की जाती है और इस के लिए आपको प्राधिकृत किया जाता कि आप उक्त (नाम) को इस वारंट सहित अपनी अभिरक्षा में रखें और उक्त आदेश के अधीन विधि के अनुसार कारावास के दण्ड को वहां कार्यान्वित करें।

और आपसे यह अपेक्षा भी की जाती है और आपको इस के लिए भी प्राधिकृत किया जाता है कि आप मूल वारंट को, जिसके स्थान पर कारावास की अवधि की गणना (ड.) से की जाएगी, मुझे वापस कर देंगे।

नाम द्वारा अन्वेषण जांच, या विचारण के दौरान सिविल या बल कारावास में बिताए गए या समय है, उक्त अवधि (च) का आजीवन कारावास के पूर्वोक्त दण्डादेश का मुजरा मिलेगा।

20 के मास के दिन में, मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

हस्ताक्षर (छ)

- (क) सिविल कारागार का नाम प्रविष्ट करें।
- (ख) उस आफिसर का नाम और पदनाम लिखें जिसने मूल वारंट पर हस्ताक्षर किए थे।
- (ग) दण्डादेश को कम करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम।
- (घ) पूरा आदेश लिखें।
- (ड.) वह तारीख लिखें जिसको मूल दण्डादेश पर हस्ताक्षर किए गए थे।
- (च) वह ठीक अवधि लिखें (वर्ष, मास, और दिन) जो अन्वेषण जांच, या उसी मामले में विचारण के दौरान सिविल अभिरक्षा या बल अभिरक्षा में बिताया समय।
- (छ) कमांडेंट के हस्ताक्षर।

प्ररूप ट

किसी व्यक्ति को मृत्यु से दण्डादिष्ट किए जाने के पश्चात् सिविल कारागार की अभिरक्षा में सुपुर्द किए गए किसी व्यक्ति को मृत्यु दण्डादेश कार्यान्वित करने से अन्यथा किसी प्रयोजन के लिए "बल अभिरक्षा में सौंपे जाने की दशा में, उपयोग के लिए वारंट

सेवा में,

अधीक्षक

(क) कारागार।

..... यूनिट का (संख्यांक रैंक नाम) को तारीख को में आयोजित (ख) जनरल असम राइफल्स न्यायालय द्वारा पारित मृत्यु दण्डादेश के अनुसरण में (ख) द्वारा जारी किए गए वारंट के अधीन (क) कारागार में रखा गया है और (ग) ने असम राइफल्स अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त दंडादेश की बावत निम्नलिखित आदेश पारित किया है, अर्थात् (घ)

आपसे अपेक्षा की जाती है और इस के लिए आपको प्राधिकृत किया जाता कि आप उक्त (नाम) को इस वारंट को लाने वाले आफिसर / अधीनस्थ आफिसर के तुरन्त हवाले कर दें।

20 के मास के दिन में, मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

हस्ताक्षर (ड.)

- (क) सिविल कारागार का नाम प्रविष्ट करें।
- (ख) उस आफिसर का नाम तथा पदनाम लिखें जिसने मूल वारंट पर हस्ताक्षर किए थे।
- (ग) आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम।
- (घ) पूरा आदेश लिखें।

(ड.) कमांडेंट के हस्ताक्षर।

प्ररूप ठ

कैदी को क्षमादान देने या उसका विचारण अपास्त कर लिए जाने या पूर्ण दण्डादेश या उसके अपर्यवसित भाग का परिहार्य कर दिए जाने की दशा में उपयोग के लिए वारंट (घास 147) सेवा में,

अधीक्षक

(क) कारागार ।

यूनिट के (संख्यांक रैंक नाम) को तारीख को में आयोजित किए गए (ख) असम हाइफल्स न्यायालय द्वारा पारित (ग) के दण्डादेश के अनुसरण में (घ) द्वारा जारी किए गए वारंट के अधीन (क) कारागार में परिरुद्ध है, और (ड.) ने असम हाइफल्स अधिनियम द्वारा उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पूर्वोक्त दण्डादेश की बावत निम्नलिखित आदेश पारित किया है, अर्थात् (च) ।

आपसे यह अपेक्षा की जाती है और इस के लिए आपको प्राधिकृत किया जाता कि आप उक्त (नाम) को यदि वह किसी अन्य कारण से निरुद्ध किए जाने के दायित्वाधीन न हों, तो अपनी अभिरक्षा से तुरन्त उन्मोचित कर दें और उसे इस प्रकार उन्मोचित करने के लिए यह आपका पर्याप्त वारंट है।

20 के मास के दिन मेरे मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

हस्ताक्षर (छ).....

(क) सिविल कारागार का नाम प्रविष्ट करें।

(ख) उस आफिसर का नाम और पदनाम लिखें जिसने मूल वारंट पर हस्ताक्षर किए थे।

(ग) मूल दण्डादेश लिखें (यदि पुष्टि करने वाले आफिसर या अन्य वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा यदि कम कर दिया गया या तो दण्डादेश इस प्रकार लिखा जाना चाहिए।

“ 2 वर्ष के कठोर कारावास को पुष्टि करने वाले आफिसर द्वारा 1 वर्ष कर दिया गया है” ।

(घ) जनरल, पेटी और (घा) समरी।

(ड.) कैदी को क्षमादान देने वाले, दण्डादेश को कम करने वाले या विचारण को अपास्त करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदनाम,

(च) पूरा आदेश लिखा जाए।

(छ) विहित आफिसर के हस्ताक्षर।

परिशिष्ट- 15

[नियम 186(2)(क) देखिए]

अप्राकृतिक मृत्यु होने पर रिपोर्ट

1. मृत्यु का स्थान या वह स्थान जहां पर मृत शरीर मिला हो (ब्योरे दें) ।
 2. वह तारीख और समय, जब मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई।
 3. उन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम और विवरण, जिन्होंने मृत शरीर की पहचान की हो ।
 4. मृतक व्यक्ति का नाम और विशिष्टियां तथा उसकी प्रारिथिति।
 5. मृतक व्यक्ति द्वारा पहने गए कपड़ों की हालत।
- टिप्पण - यदि डाक्टर द्वारा जांच की प्रतीक्षा है, तो मृतक व्यक्ति के कपड़े आदि उतारे बिना उक्त ब्योरा एकत्र किया जाना चाहिए। अन्य विवरण चिकित्सीय जांच के उपरांत पूरा करना चाहिए।
6. अंगों, आंखों और मुंह की दशा।
 7. चेहरे की अभिव्यक्ति।
 8. मृत शरीर पर संघर्ष के चिन्ह, यदि कोई हो, तो घावों और खरोंचों, उनके आकार और स्थान दर्शाते हुए लिखे जाना चाहिए।

टिप्पण :- क्षति की गहराई को अभिलिखित किया जाना चाहिए, लेकिन क्षति को छूना नहीं चाहिए। यदि चिकित्सक द्वारा परीक्षण प्रतीक्षित हो, तो उपरोक्त सूचना का उल्लेख उसके परीक्षण के बाद किया जाना चाहिए।

9. क्या रक्त बह रहा है या जमा हुआ है। वह जगह जहां से ये निकला और इसकी मात्रा।
10. किस माध्यम, हथियार या उपकरण से चोट या संघर्ष के निशान उपदर्शित हुए हैं।
11. क्या गर्दन के चारों तरफ रस्सी बांधी गई थी या किसी चीज से बांधने के निशान हैं।
12. क्या रस्सी या किसी अन्य चीज से गला घोंटा गया या फांसी लगाई गई, क्या यह वजन उठाने के लिए मजबूत थी और क्या इसका दूसरा किनारा किसी चीज से बांधा गया ?
13. क्या कोई बाहरी चीज जैसे घास आदि बालों में उलझे या उसके हाथ में या शरीर के अन्य दूसरे भाग में उलझे हुए थे ?
14. क्या मृत शरीर किसी मजबूत और शरीर सौष्ठव युक्त आदमी का है ? या यह किसी कमजोर या बूढ़े आदमी का है ?
15. क्या मृत शरीर मजबूत या कमजोर या क्या यह सड़ने की स्थिति में है ?
16. सिर से पैर तक मृत शरीर की लम्बाई।
17. घाव की आकृति और स्थान और पहचान चिन्ह।
18. मृत्यु का दृश्यमान कारण।
19. क्या ऐसी कोई अफवाह या अन्य परिस्थितियां दिखाई पड़ रही हैं कि यह एक आत्महत्या का मामला है ?
मृत शरीर पर मिली वस्तुओं या इसके पास प्राप्त वस्तुओं का ब्यौरा।
20. जो मृत शरीर पर मिली हो (प्रत्येक वस्तु पर एक पर्ची चिपकाई जाएगी, उस पर मोहर लगाई जाएगी।)
21. जो मृत शरीर के नजदीक पाई गई हों (प्रत्येक वस्तु पर सम्यक रूप से मोहर लगी हुई एक पर्ची चिपकाई जाएगी।)
मुहर का ब्यौरा।
22. उस जगह का मानचित्र, जहां मृत शरीर पाया गया हो।
मामले का संक्षिप्त इतिहास

दो या दो से अधिक स्थानीय साक्षियों, जिनकी उपस्थिति में अन्वेषण हुआ हो, के हस्ताक्षर।

स्थान :

मामले का अन्वेषण करने वाले आफिसर के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर :

नाम :

रैंक :

तारीख :

भाग- 2

बल न्यायालयों की कार्यवाहियों के नमूने

(नमूना-1)

असम राइफल्स अधिनियम, 2006 के अधीन जनरल और पेटी असम राइफल्स न्यायालयों की कार्यवाहियों के प्ररूप

क

महानिरीक्षक या उपमहानिरीक्षक असम राइफल्स के तारीख के आदेश तारीख
को में आयोजित जनरल असम राइफल्स न्यायालय की कार्यवाहियां।

पीठासीन अधिकारी

सं०..... रैंक..... नाम..... यूनिट.....

सदस्य

सं०..... रैंक..... नाम..... यूनिट.....

सं०..... रैंक..... नाम..... यूनिट.....
 सं०..... रैंक..... नाम..... यूनिट.....
 सं०..... रैंक..... नाम..... यूनिट.....
 विधि आफिसर.....
 सं०..... रैंक..... नाम..... यूनिट.....
 दुभाषिया.....
 सं०..... रैंक..... नाम..... यूनिट.....
 सं०..... रैंक..... नाम..... यूनिट..... (से सलंगन) का विचारण।

न्यायालय के संयोजन का आदेश, आरोपपत्र और साक्ष्य की समरी न्यायालय के समक्ष रखे जाते हैं।

न्यायालय ने अपना यह समाधान कर लिया है कि सं०..... रैंक..... नाम..... यूनिट.....
 (कारण लिखें) इस कारण कि..... सेवा करने के लिए उपलब्ध नहीं हैं।

..... सं०..... रैंक..... नाम..... यूनिट..... प्रतीक्षारत सदस्य,
 न्यायालय के सदस्य के रूप में उसका स्थान ग्रहण करते हैं।

न्यायालय को असम राइफल्स के नियम 68 द्वारा यथा उपबंधित रूप में अपना समाधान करना चाहिए।

टिप्पण :- यह प्रमाणित करने के पूर्व कि न्यायालय ने असम राइफल्स के नियम 68 द्वारा यथा उपबंधित रूप में अपना समाधान कर लिया है, पीठासीन आफिसर, ऐसे प्रत्येक मामले में, जिसमें न्यायालय जांच किसी ऐसे विषय की बावत हुई है, जिस पर अभियुक्त के विरुद्ध आरोप आधारित किया गया है, "असम राइफल्स के नियम 68" शब्दों के पश्चात् तारक चिन्ह लगाएगा और कार्यवाहियों के प्रथम पृष्ठ के नीचे निम्नलिखित आशय के बाद टिप्पणी पर हस्ताक्षर करेगा।

"मैंने अपना समाधान कर लिया है कि इस न्यायालय के सदस्यों के रूप में कर्तव्य पर लगाए गए आफिसरों में से किसी ने भी इस न्यायालय के समक्ष आरोप/आरोपों से संबंधित विषय वस्तु की बावत किसी जांच न्यायालय में पहले सेवा नहीं की है।"

स्थान : पीठासीन आफिसर के हस्ताक्षर
 तारीख :

अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष लाया गया है।

अभियोजक..... (विधिक अर्हताएं लिखें)

अभियोजन काउन्सेल (यदि कोई हो) नाम..... (अर्हताएं).....

अधिवक्ता (न्यायालय जहां व्यवसाय (वकालत) कर रहे हों)

प्रतिरक्षा आफिसर (विधिक अर्हताएं लिखें)

प्रतिरक्षा काउन्सेल, यदि कोई हो..... (अर्हताएं).....

अधिवक्ता..... (न्यायालय जहां व्यवसाय (वकालत) कर रहे हों)

विचारण..... बजे प्रारम्भ होता है।

न्यायालय के संयोजन का आदेश पढ़ा जाता है और उसे..... चिन्हित किया जाता है, विधि आफिसर (पीठासीन आफिसर) द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है तथा कार्यवाहियों में संलग्न किया जाता है। न्यायालय के पीठासीन आफिसर तथा सदस्यों के नाम अभियुक्त की सुनवाई में पढ़े जाते हैं और वे उनके नामों का पृथक-पृथक रूप में उत्तर देते हैं।

\$ प्रश्न 1 :- क्या आपको पीठासीन आफिसर के रूप में मेरे द्वारा, या किसी ऐसे आफिसर, जिनके नाम आपने सुने या पढ़े हैं, द्वारा विचारण करने पर कोई आक्षेप है ?

उत्तर :-

प्रश्न 2 :- आपको उस (कनिष्ठतम आफिसर का नाम जिसके बारे में आपेक्ष किया गया है) के बारे में क्या आक्षेप है ?

अभियुक्त..... के बारे में आक्षेप के समर्थन में..... आदि को बुलाने की अनुमति का अनुरोध करता है। सं०..... रैंक..... नाम..... को न्यायालय में बुलाया जाता है और अभियुक्त द्वारा उससे प्रश्न पूछा जाता है।

सदस्य (जिसके बारे में आक्षेप किया जाता है) उत्तर में कहते हैं—

न्यायालय (आक्षेप किए गए आफिसर) की अनुपस्थिति में आक्षेप पर विचार करने के लिए बंद किया जाता है।

न्यायालय आक्षेप की अनुमति देने से इंकार/मंजूर करने का विनिश्चय करता है।

न्यायालय पुनः खोला जाता है और अभियुक्त को इसके समक्ष पुनः लाया जाता है। उक्त विनिश्चय खुले न्यायालय में घोषित किया जाता है।

@ प्रतीक्षारत सदस्य न्यायालय के सदस्यों के रूप में अपना स्थान ग्रहण करते हैं।

@ (यहां केवल तब लागू होता है जब न्यायालय का कोई प्रतीक्षारत सदस्य है)

न्यायालय ने अपना यह समाधान कर लिया है कि संख्यांक रैंक नाम यूनिट इस न्यायालय की सेवा करने के लिए पात्र है और निहित नहीं है।

प्रश्न 3 :- क्या आपको (प्रतीक्षारत सदस्य) द्वारा विचारण किए जाने पर कोई आक्षेप है ?

उत्तर :-

(यदि वह आक्षेप करता है तो आक्षेप के संबंध में उसी रीति से कार्यवाही की जाएगी जैसी पहले आक्षेप के संबंध में की गई हो)।
टिप्पण

* ऐसा सभी मुद्रित भाग, जो आयोजित किए गए विशिष्ट न्यायालय के लिए लागू न हो, उसे काट दिया जाए और अभिलेख के लिए उत्तरदायी आफिसर द्वारा अदयाक्षरित किया जाए। (नियम 130)

सभी प्रश्नों और उत्तरों को कार्यवाहियों के प्रारम्भ से अंत तक क्रमानुसार संख्यांकित किया जाएगा।

\$ पीठासीन आफिसर द्वारा यह प्रश्न अभियुक्त से पूछा जाएगा (नियम 70)।

ख (नया पृष्ठ)

पीठासीन आफिसर, सदस्यों और विधि आफिसर को सम्यक् रूप से शपथ दिलाई जाती है या प्रतिज्ञान कराया जाता है।

प्रश्न 4:- क्या आपको दुभाषिण के रूप में श्री (या संख्यांक रैंक नाम) के बारे में कोई आक्षेप है ?

उत्तर :-

संख्यांक रैंक नाम यूनिट को दुभाषिण के रूप में सम्यक् रूप से शपथ दिलाई जाती है या प्रतिज्ञान कराया जाता है।

प्रश्न 5:- क्या आपको आशुलेखक के रूप में श्री (या संख्यांक रैंक नाम) यूनिट के बारे में कोई आक्षेप है ?

उत्तर :-

संख्यांक रैंक नाम यूनिट को आशुलेखक के रूप में सम्यक् रूप से शपथ दिलाई जाती है या प्रतिज्ञान कराया जाता है।

@ आरोप पत्र

ख-2 आरोप पत्र पर विधि आफिसर (पीठासीन आफिसर) द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं और उसे ख-2 चिह्नित किया जाता है और कार्यवाहियों के साथ संलग्न किया जाता है। अभियुक्त को ऊपर वर्णित आरोप-पत्र में प्रत्येक आरोप के लिए बोधायित किया जाता है।

प्रश्न 6 :- क्या आप अपने विरुद्ध (प्रथम) आरोप के, जो आपको पढ़कर सुनाया गया है, दोषी हैं या दोषी नहीं हैं ?

उत्तर 6 :-

प्रश्न 7 :- क्या आप अपने विरुद्ध (द्वितीय) आरोप के, जो आपको पढ़कर सुनाया गया है, दोषी हैं या दोषी नहीं हैं ?

उत्तर 7:—

टिप्पण

1. यदि अभियुक्त किसी आरोप (आरोपों) के प्रति दोषी होने का अभिवचन करता है, तो असम राइफल्स नियम 85 के उपबंधों का पालन किया जाए।
2. यदि विचारण एक से अधिक आरोप पत्र की बाबत अग्रसर है, तो प्रत्येक आरोप पत्र पर विचारण दोषारोपण से लेकर निष्कर्ष तक पृथक और सुनिश्चित रखा जाएगा।
3. यदि विचारण ऐसे किसी आरोप के संबंधी में अग्रसर है, जिसका "दोषी न होने" का अभिवाक है, तो न्यायालय तब तक "दोषी होने" के अभिलिखित किए गए अभिवाक पर तब कार्यवाही नहीं करेगा जब तक वह अन्य आरोप के बारे में निष्कर्ष पर नहीं पहुंच जाता नियम 87 (2)।

परिवर्तन

आरोप के बारे में आक्षेप (असम राइफल्स, नियम 78)

अभियुक्त इस आधार पर आरोप के प्रति आक्षेप करता है कि (उल्लेख करें)

(अनुदेश - असम राइफल्स नियम 128 के उपबंधों का ऐसे अनुषंगिक संबंधी सभी मामलों के संबंध में, जैसे नीचे दर्शाए गए हैं, पालन किया जाएगा।)

अभियोजक उत्तर देता है (उल्लेख करें)

अभियुक्त (या प्रतिरक्षा आफिसर) उत्तर देता है (उल्लेख करें)

न्यायालय आक्षेप को अनुज्ञात करने का विनिश्चय करता है (या न्यायालय आक्षेप को मंजूर करने का विनिश्चय करता है और संयोजक प्राधिकारी को रिपोर्ट करने के लिए सहमत होता है।)

न्यायालय पुनः खुलता है और अभियुक्त को उसके समक्ष पुनः लाया जाता है और उक्त विनिश्चय खुले न्यायालय में सुनाया जाता है।

न्यायालय विचारण की कार्यवाही में अग्रसर होता है (या स्थगन होता है)

आरोप में संशोधन (असम राइफल्स, नियम, 79/80)

न्यायालय यह समाधान हो जाने पर कि अभियुक्त का नाम (या विवरण) और वह नहीं है जो आरोप पत्र में उल्लिखित है तदनुसार आरोप पत्र में संशोधन करता है।

न्यायालय यह विचार है कि इसके पूर्व कि किन्हीं साक्षियों की परीक्षा की जाए, आरोप में निम्नलिखित परिवर्तन (या लोप या परिवर्तन) न्याय के हित में अपेक्षित है (उल्लेख करें) और वह अपना मत संयोजन प्राधिकारी को रिपोर्ट करने के लिए आस्थगित हो जाता है।

अधिकारिता के बारे में अभिवाक (असम राइफल्स नियम 77)

अभियुक्त न्यायालय की साधारण अधिकारिता के बारे में अभिवचन करता है कि (उल्लेख करें)।

प्रश्न 8 :- क्या आप अपने अभिवाक के समर्थन में कोई साक्ष्य पेश करना चाहते हैं ? (उल्लेख करें)

शपथ लेने (या प्रतिज्ञान कराने) पर साक्षी की परीक्षा की जाती है। (उल्लेख करें)

(अनुदेश— अभियुक्त द्वारा बुलाए गए किसी साक्षी की अभियोजक द्वारा उत्तर में बुलाए गए किसी साक्षी की परीक्षा वैसे ही की जाएगी, जैसा विचारण के तथ्यों के साक्षियों के मामले में नीचे बताया गया है।

असम राइफल्स नियम 128 के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा।)

अभियुक्त (या प्रतिरक्षा आफिसर) उत्तर देता है (उल्लेख करें) न्यायालय (क) अभिवाक को नामंजूर करने का विनिश्चय करता है और विचारण में अग्रसर होता है।

या

न्यायालय (ख) अभिवाक अनुज्ञात करने का विनिश्चय करता है और संयोजन प्राधिकारी को रिपोर्ट करने और कार्यवाही स्थगित करने का विनिश्चय करता है।

न्यायालय पुनः खुलता है। अभियुक्त उसके समक्ष लाया जाता है और उक्त विनिश्चय खुले न्यायालय में सुनाया जाता है।

न्यायालय विचारण के लिए अग्रसर होता है (या स्थगित हो जाता है)

विचारण के वर्जन का अभिवाक् (असम राइफल्स, नियम 89)

अभियुक्त दोषी होने के (या दोषी न होने के) अभिवाक् के उत्तर में विचारण के वर्जन का अभिवाक् इस आधार पर करता है कि (उल्लेख करें)

प्रश्न 9 :- क्या आप अपने अभिवाक् के समर्थन में साक्ष्य पेश करना चाहते हैं ? (उल्लेख करें)

(अनुदेश— अभियुक्त द्वारा बुलाए गए किसी साक्षी की और अभियोजक द्वारा उत्तर में बुलाए गए किसी साक्षी की परीक्षा वैसे ही की जाएगी जैसा विचारण के तथ्यों के साक्षी की दशा में नीचे निर्दिष्ट है। असम राइफल्स, नियम 128 के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा।)

अभियोजक उत्तर देता है (उल्लेख करें)

अभियुक्त (या प्रतिरक्षा आफिसर) उत्तर देता है (उल्लेख करें)

न्यायालय अपने विनिश्चय पर विचार करने के लिए बंद हुआ।

न्यायालय अभिवाक् अनुज्ञात करने का विनिश्चय करता है और स्थगन का संकल्प करता है और संयोजक प्राधिकारी को रिपोर्ट करने का विनिश्चय करता है (या किसी अन्य आरोप पर विचारण में अग्रसर होने का या न्यायालय अभिवाक् को नामजूर करने का विनिश्चय करता है)।

न्यायालय पुनः खुलता है और अभियुक्त उसके समक्ष लाया जाता है और उक्त विनिश्चय को खुले न्यायालय में, संयोजक आफिसर के अनुमोदन के अधीन सुनाया जाता है।

न्यायालय स्थगित हो जाता है (या किसी अन्य आरोप पर विचारण में अग्रसर होता है) (या विचारण में अग्रसर होता है)

अभिवचन करने से इंकार (नियम 85 (5))

चूंकि अभियुक्त उपर्युक्त आरोप की बावत बोधगम्य रूप से अभिवचन नहीं करता (या अभिवचन करने से इंकार करता है) अतः न्यायालय "दोषी न होने" का अभिवचन दर्ज करता है।

अभियुक्त ने.....आरोप का दोषी होने का अभिवचन किया है इसलिए असम राइफल्स, नियम 84 के उपबंधों का अनुपालन किया जाता है।

Ⓔ (नया पृष्ठ)

दोषी न होने के अभिवाक् की दशा में कार्यवाहियां

प्रश्न 10 :- क्या आप इस आधार पर स्थगन के लिए आवेदन करना चाहते हैं कि विचारण के पूर्व (नियम 98) प्रक्रिया से संबंधित किसी नियम का अनुपालन नहीं किया गया है और क्या उसका आप पर कोई प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है या इस आधार पर स्थगन के लिए आवेदन करना चाहते हैं कि आपको अपना प्रतिरक्षा को तैयार करने के लिए पर्याप्त अवसर नहीं मिल पाया है?

उत्तर 10 :-

(अनुदेश — स्थगन के लिए अनुरोध की दशा में न्यायालय के विनिश्चय सहित अभियुक्त का कथन अभिलिखित किया जाएगा।)

अभियोजक प्रारम्भिक लिखित संबोधन करता है, जो पढ़ा जाता है चिन्हित किया जाता है, "....." विधि आफिसर (पीठासीन आफिसर) द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है और कार्यवाहियों में संलग्न किया जाता है।

अभियोजक साक्षियों को बुलाने के लिए अग्रसर होता है।

अभियोजक का प्रथम साक्षी।

अभियोजक साक्षी -1

संख्यांक.....रैंक.....नाम.....यूनिट.....को सम्यक् रूप से शपथ दिलाए या प्रतिरक्षा किए जाने के पश्चात अभियोजक या (अभियोजन काउन्सेल) द्वारा उसकी परीक्षा की जाती है।

अभियुक्त (या प्रतिरक्षा आफिसर काउन्सेल) द्वारा प्रतिपरीक्षा की जाती है।

अभियोजक (अभियोजन काउन्सेल) द्वारा पुनः परीक्षा की जाती है।

न्यायालय द्वारा प्रश्न किए जाते हैं।

टिप्पण 1. प्रत्येक साक्षी के साक्ष्य के अन्त में असम राइफल्स नियम, 98 के उपबंधों का अनुपालन किया जाएगा तथा अभिलिखित किया जाएगा।

2. यदि पीठासीन आफिसर, विधि आफिसर या कोई सदस्य साक्षी से कोई प्रश्न पूछता/करता है, तो असम राइफल्स नियम, 97 का अनुपालन किया जाना चाहिए और उसे अभिलिखित किया जाना चाहिए।

3. शपथ या प्रतिज्ञान प्ररूप के लिए असम राइफल्स नियम, 98 (4) देखिए।

परिवर्तन

प्रतिपरीक्षा मुत्तवी करना

(असम राइफल्स नियम 96)

न्यायालय, अभियुक्त के अनुरोध पर, साक्षी की प्रति परीक्षा मुत्तवी करने के लिए अनुज्ञात करता है।

साक्ष्य या प्रक्रिया के बारे में आक्षेप

(असम राइफल्स नियम 128)

अभियुक्त (या काउन्सेल या प्रतिरक्षा आफिसर या अभियोजक) निम्नलिखित प्रश्नों पर इस आधार पर आक्षेप करता है कि..... (उल्लेख करें)।

अभियोजक (यथास्थिति काउन्सेल या प्रतिरक्षा आफिसर या अभियुक्त) उत्तर देता है कि..... (उल्लेख करें)

अभियुक्त (या काउन्सेल या प्रतिरक्षा आफिसर या अभियोजक) उत्तर देता है कि (उल्लेख करें) न्यायालय अपने विनिश्चय पर विचारण के लिए बन्द हुआ।

न्यायालय आक्षेप को नामंजूर (अनुज्ञात) करने का विनिश्चय करता है।

न्यायालय पुनः खुलता है अभियुक्त उसके समक्ष पुनः लाया जाता है और उक्त विनिश्चय खुले न्यायालय में सुनाया जाता है।

न्यायालय विचारण आगे बढ़ाता है।

साक्ष्य का स्पष्टीकरण या संशोधन

(असम राइफल्स, नियम 106)

साक्षी, जिसको उसका साक्ष्य पढ़कर सुनाया जाता है, निम्नलिखित स्पष्टीकरण या शुद्धि करता है (उल्लेख करें)

उपर्युक्त स्पष्टीकरण या संशोधन के बारे में अभियोजक द्वारा परीक्षा की गई।

उपर्युक्त स्पष्टीकरण या संशोधन के बारे में अभियुक्त द्वारा (या उसकी ओर से) परीक्षा की गई।

अभियोजक और अभियुक्त (या काउन्सेल या प्रतिरक्षा आफिसर) उपर्युक्त स्पष्टीकरण या संशोधन की भावत उसकी परीक्षा करने से इंकार करता है।

अभियोजक साक्षी-2 अभियोजन का दूसरा साक्षी

* को सम्यक् रूप से शपथ दिलाई जाती है या प्रतिज्ञान कराया जाता है, अभियोजक द्वारा परीक्षा की जाती है। (इसकी और प्रत्येक अन्य साक्षी की परीक्षा आदि वैसे ही होगी, जैसे प्रथम साक्षी की दशा में होती है।)

नं०, रैंक, नाम, यूनिट और पदनाम या अन्य कोई विवरण लिखें।

* यहां पर उसका

परिवर्तन

स्थगन

न्यायालय तारीख.....को.....बजे तारीख.....को.....बजे तक के लिए स्थगित हो गया है।

तारीख.....को बजे.....न्यायालय स्थगन के अनुसरण में पुनः संयोजित होता है, वही सदस्य और विधि आफिसर जो तारीख.....को थे, उपस्थित है।

(अनुदेश - (1) यदि पुनः संयोजन पर कोई सदस्य अनुपस्थित है और उसकी अनुपस्थिति से न्यायालय की विधिक न्यूनतम संख्या कम हो जाती है, उपस्थित सदस्यों को यह प्रतीत होता है कि अनुपस्थित सदस्य युक्ति युक्त समय के भीतर उपस्थित नहीं हो सकता, तो पीठासीन आफिसर या उपस्थित वरिष्ठ सदस्य तब मामले की रिपोर्ट संयोजक प्राधिकारी को करेगा। (असम राइफल्स नियम 123)

2. यदि विधि आफिसर अनुपस्थित है और वह उचित समय के भीतर उपस्थित नहीं हो सकता है, तो न्यायालय का स्थगन हो जाएगा और पीठासीन आफिसर तब मामले की रिपोर्ट संयोजक प्राधिकारी को करेगा।

(असम राइफल्स, नियम 136)

सदस्य की अनुपस्थिति

(संख्यांक.....रैंक.....नाम.....यूनिट.....) की अनुपस्थिति के कारण एक चिकित्सा प्रमाणपत्र (या पत्र या जैसा भी मामला हो) प्रस्तुत किया जाता है, पढ़ा जाता है.....चिन्हित किया जाता है और कार्यवाहियों में संलग्न किया जाता है।

न्यायालय.....तक के लिए स्थगित होता है।

या

.....सदस्य (जो न्यूनतम विधिक संख्या से कम नहीं है) उपस्थित है इसलिए आगे विचारण होता है।

.....की परीक्षा (प्रतिपरीक्षा) आगे जारी रही।

@ घ (नया पृष्ठ)

अभियोजन पक्ष की ओर से सुनवाई समाप्त हुई।

प्रतिरक्षा

अभियुक्त से प्रश्न

(नियम 109 (1))

विधि आफिसर (पीठासीन आफिसर) असम राइफल्स, नियम 101 के उपबंधों को पढ़ते हैं और स्पष्ट करते हैं। यह अभिनिश्चित कर लेने के पश्चात् कि अभियुक्त उसको पढ़कर सुनाए गए उपबंधों को समझता है न्यायालय (विधि आफिसर) निम्नलिखित प्रश्न पूछता है :-

प्रश्न 11 :-के साक्ष्य में यह कहा गया है कि। क्या आप उसी बारे में कुछ कहना चाहते हैं ?

उत्तर 11:-

प्रश्न 12 :-

उत्तर 12 :-

प्रश्न 13 :-

उत्तर 13 :-

न्यायालय के लिए अनुदेश

1. अभियुक्त से प्रश्न उसे स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान करने के लिए हो और जहां ऐसे स्पष्टीकरण के अभाव में उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता हो, वहां पूछे जाने चाहिए, यदि वह ऐसी इच्छा रखता हो।

2. उससे पूछे गए प्रश्न ऐसे होने चाहिए, जिनमें वह उसके विरुद्ध आने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करने में समर्थ हो सके और यदि वे स्पष्ट नहीं की जाती हो, तो परिणामतः दोषसिद्ध हो सकती है।

3. अभियुक्त से प्रश्न अभियोजन के मामले की प्रतिपूर्ति करने के लिए नहीं पूछे जाने चाहिए।

4. अभियुक्त से पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर जहां तक संभव हों, शब्दशः अभिलिखित किए जाएंगे।

(नियम 101 (3))

प्रश्न 14 :-
चाहते हैं ?

क्या आप साक्षी के रूप में शपथ के बारे में साक्ष्य देने की इच्छा रखते हैं या बिना शपथ लिए को कथन देना

उत्तर 14 :-

* अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा में कहता है.....या लिखित सम्बोधन करता है और जो विधि आफिसर (पीठासीन आफिसर) द्वारा पढ़ा जाता है.....चिन्हित किया जाता है और हस्ताक्षर किया जाता है और कार्यवाहियों में संलग्न किया जाता है या अभियुक्त कोई विवरण देने से इंकार करता है।

टिप्पण - * यदि अभियुक्त शपथ के बारे में साक्ष्य देने की इच्छा करता है, उसकी किसी अन्य साक्षी द्वारा परीक्षा की जाएगी।

(नियम-101 (4))

प्रश्न 15 :-

क्या आप अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी को बुलाना चाहते हैं ?

उत्तर :-

प्रश्न 16 :-

क्या वह केवल चरित्र के बारे में कोई साक्षी है ?

न्यायालय के लिए अनुदेश

जब उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर अभिलिखित कर लिए गए हों तो न्यायालय असम राइफल्स, नियम 101 के उपबंधों का अनुपालन करेगा।

प्रतिरक्षा के लिए साक्षियों के साक्ष्य (जिसमें चरित्र के बारे में साक्षी भी है) के प्रश्नों के पश्चात् लिया जाएगा यदि कोई हो, अभियुक्त से कोई प्रश्न किया गया हो अभियुक्त संवोधित करेगा।

@ घ 2 (नया पृष्ठ)

अभियुक्त के (काउन्सेल या प्रतिरक्षा आफिसर) आरंभिक संबोधन करते हैं, या एक लिखित आरंभिक संबोधन प्रदान करते हैं जो पढ़ा जाता है.....चिन्हित किया जाता है विधि आफिसर (पीठासीन आफिसर) द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है तथा कार्यवाहियों में संलग्न किया जाता है।

अभियुक्त निम्नलिखित साक्षियों को बुलाता है (चरित्र के अनुसार) प्रतिरक्षा साक्षी - ।

प्रतिरक्षा हेतु प्रथम साक्षी (चरित्र के अनुसार)*

श्री नं०.....रैंक.....नाम.....यूनिट को सम्यक रूप से शपथ दिलाई गई (या प्रतिज्ञान कराया गया) को अभियुक्त (या काउन्सेल या प्रतिरक्षा आफिसर) द्वारा परीक्षा की जाती है।

टिप्पण:- प्रत्येक साक्षी के साक्ष्य की समाप्ति के पश्चात् असम राइफल्स, नियम 97 और नियम 98 के उपबंधों का यथास्वीकार्य, का अनुपालन किया जाएगा तथा तथ्य अभिलिखित किए जाएंगे।

* यदि साक्षी चरित्र के अनुसार न बुलाए गए हों, तो इन शब्दों को काट दिया जाए।

साक्षियों को पुनः बुलाना

(असम राइफल्स, नियम 99)

(1) अभियोजक (या अभियुक्त) के अनुरोध परको पुनः बुलाया जाता है और पीठासीन आफिसर (या विधि आफिसर) के माध्यम से उसकी परीक्षा से पूर्व शपथ/प्रतिज्ञान पर की जाती है और वह निम्नलिखित कथन करता है :- (उल्लेख करें)

(2) अभियोजक न्यायालय की इजाजत से या प्रतिरक्षा पक्ष की ओर से किसी साक्षी द्वारा किए गए किसी तात्त्विक कथन का खण्डन करने के प्रयोजन के लिएको बुलाता (या पुनः बुलाता है।

साक्षी को सम्यक् रूप से शपथ दिलाई जाती है (या प्रतिज्ञान कराया जाता है) और वह (या साक्षी अपनी पूर्व शपथ या प्रतिज्ञान पर) अभियुक्त द्वारा परीक्षा किए जाने पर, निम्नलिखित कथन करता है :-

(यदि कोई प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा आदि की गई है तो उसका उल्लेख करें।) या

(3) अभियोजक, अभियुक्त द्वारा बुलाए गए चरित्र संबंधी साक्षी (साक्षियों) के प्रत्युत्तर मेंको बुलाता है (या पुनः बुलाता है) साक्षी को सम्यक् रूप से शपथ दिलाई जाती है (या प्रतिज्ञान कराया जाता है) और वह (साक्षी अपनी पूर्व शपथ प्रतिज्ञान पर) अभियोजक द्वारा परीक्षा किए जाने पर निम्नलिखित कथन करता है :-

(यदि कोई प्रतिपरीक्षा और पुनः परीक्षा आदि की गई है, तो उसका उल्लेख करें) या

(4) न्यायालय असम राइफल्स, नियम 99 के अनुसारको बुलाता है या पुनः बुलाता है, जो सम्यक् रूप से शपथ लेने (या प्रतिज्ञान करने) के पश्चात् (या अपनी पूर्व शपथ प्रतिज्ञान पर) पीठासीन आफिसर (या विधि आफिसर) के प्रश्नों के उत्तर में (उल्लेख करें)

अनुदेश - (1), (2) और (3) में साक्षियों को अभियुक्त की ओर से समापन सम्बोधन के पूर्व बुलाया या पुनः बुलाया जाना चाहिए। (4) में साक्षियों को न्यायालय द्वारा निष्कर्ष के पहले किसी भी समय बुलाया या पुनः बुलाया जा सकता है। ऐसी दशा में अभियुक्त या काउन्सेल या प्रतिरक्षा आफिसर और अभियोजक को न्यायालय के माध्यम से प्रश्न पूछने का अवसर दिया जाना चाहिए।

(सम्बोधन आदि तैयार करने के लिए स्थगन)

न्यायालय, अभियुक्त (काउन्सेल या प्रतिरक्षा आफिसर) के अनुरोध परतक के लिए स्थगित होता है जिससे कि वह अपना सम्बोधन तैयार कर सके।

न्यायालय अभियोजक के अनुरोध परतक के लिए स्थगित होता है जिससे कि वह अपना उत्तर तैयार कर सके।

न्यायालय विधि आफिसर के अनुरोध परतक के लिए स्थगित होता है जिससे कि वह अपना मूल्यांकन तैयार कर सके।

अभियोजक निम्नलिखित उत्तर देता है (या लिखित रूप में उत्तर देता है)

जो पढ़ा जाता है (मौखिक रूप से अनुदित किया जाता है)चिन्हित किया जाता है और पीठासीन आफिसर (या विधि आफिसर) द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है तथा कार्यवाहियों में संलग्न किया जाता है।

अभियुक्त (काउन्सेल या प्रतिरक्षा आफिसर) निम्नलिखित समापन सम्बोधन करता है (या समापन सम्बोधन लिखित रूप में देता है) जो पढ़ा जाता है (मौखिक रूप से अनुदित किया जाता है)चिन्हित किया जाता है और कार्यवाहियों में संलग्न किया जाता है।

उपसंहार

विधि आफिसर लिखित उपसंहार देता है जो पढ़ा जाता है।

(मौखिक रूप से अनुदित किया जाता है)चिन्हित किया जाता है, और पीठासीन आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है तथा कार्यवाहियों में संलग्न किया जाता है।

टिप्पण :-

1. अभियोजक, अभियुक्त, काउन्सेल या प्रतिरक्षा आफिसर से सभी सम्बोधन चाहे, वे न्यायालय द्वारा अभिलिखित किए गए हैं या जो लिखित में दिए गए हैं (और विधि आफिसर का लिखित उपसंहार) उस कम में, जिसमें वे किए या दिए गए हैं, कार्यवाहियों में संलग्न

किए जाएंगे। लिखित सम्बोधन (और उपसंहार) न्यायालय को पढ़कर सुनाए जाएंगे, चिन्हित किए जाएंगे और पीठासीन आफिसर (विधि आफिसर द्वारा उपसंहार को छोड़कर) हस्ताक्षरित किए जाएंगे।

2. यदि कोई व्यक्ति, जो सम्बोधन करने के लिए हकदार है, ऐसा करने से इन्कार कर देता है तो ऐसा आशय अभिलिखित किया जाएगा।

3. प्रेषिणी कम के लिए असम राइफल्स, नियम 104 और 105 देखें।

@ ग ग (नया पृष्ठ)

दोषी होने के अभिवाक् की दशा में कार्यवाहियां

*न्यायालय पुनः खुल गया है अभियुक्त को उनके समक्ष पुनः लाया जाता है और वह आरोप (आरोपों) जिसके लिए उसने दोषी होने का अभिवचन किया है, उसे पुनः पढ़ कर सुनाया जाता है (सुनाए जाते हैं)।

*यदि दोषी न होने के अभिवाक् नहीं होने की स्थिति में इसे काट दी जाए।

अभियुक्त नं०..... रैंक..... नाम..... यूनिट..... को आरोप (सभी आरोपों) का दोषी पाया जाता है या..... आरोप का दोषी पाया जाता है और..... आरोप का दोषी नहीं पाया जाता है।

निष्कर्ष (निष्कर्षों) की घोषणा

निष्कर्ष खुले न्यायालय में पढ़ा जाता है/पढ़े जाते हैं और यह घोषित किया जाता है कि वह वे पुष्टिकरण के अधीन हैं।

**साक्ष्य की सारांश पढ़ा जाता है, उसे..... चिन्हित किया जाता है, विधि आफिसर (पीठासीन आफिसर) द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है, और कार्यवाहियों में संलग्न किया जाता है।

** यदि जहां साक्ष्य का सारांश नहीं है न्यायालय दंडादेश का अवधारण करने में संदर्भ होने के लिए पर्याप्त साक्ष्य अभिलिखित करेगा।

प्रश्न 17 क्या आप दंड को कम करने के लिए कोई कथन करना चाहते हैं?

उत्तर -17 अभियुक्त, दंड को कम करने के लिए कोई कहता है (या लिखित कथन देता है) जिसे पढ़ा जाता है, उसे चिन्हित किया गया है विधि आफिसर (पीठासीन आफिसर) द्वारा हस्ताक्षरित किया जाता है और कार्यवाहियों में संलग्न किया जाता है।

(अनुदेश- यदि काउन्सेल या प्रतिरक्षा अधिकारी अभियुक्त की ओर से न्यायालय को संबोधित करता है तो उसके सम्बोधन के तात्त्विक भाग अभिलिखित किया जाना चाहिए)।

परिवर्तन

अभिवाक् में परिवर्तन (असम राइफल्स, नियम 89)

अभियुक्त के कथन से या साक्ष्य की सारांश से या अन्यथा न्यायालय का यह समाधान हो जाने पर कि अभियुक्त दोषी होने के अभिवचन के प्रभाव को नहीं समझता हैं, अभिवाक् में परिवर्तन करता है और दोषी न होने का अभिवाक् दर्ज करता है।

अनुदेश :-

(1) यदि लागू न हो, तो (1) काट दें। (नियम 89 (2))

(2) तब न्यायालय आरोप की बाबत उसी प्रकार अग्रसर होगा, जैसे दोषी न होने के अभिवाक् की बाबत होता है।

@ घ घ (नया पृष्ठ)

दोषी होने के अभिवाक् की दशा में प्रतिरक्षा साक्षी

न्यायालय, अभियुक्त को निम्नलिखित कथन साबित करने के लिए साक्षियों को बुलाने की अनुमति देता है (उस कथन का उल्लेख करें, जो साबित किया जाना है)।

(अनुदेश— इस अनुज्ञा के अनुकरण में बुलाए गए साक्षियों की परीक्षा, आदि वैसी ही रीति से होगी जैसे “ दोषी न होने के अभिवाक् की दशा में की जाती है।)

प्रश्न 18 :- क्या आप चरित्र के बारे में किसी साक्षी को बुलाना चाहते हैं ?

उत्तर 18 :-

प्रश्न 19 :- क्या आप आपको दिए गए दण्ड को कम करने के लिए किसी साक्षी को बुलाना चाहते हैं ?

उत्तर 19 :-

दिए गए दण्ड को कम करने के लिए, तथा या चरित्र के बारे में साक्ष्य

श्री नाम..... नं०..... रैंक..... यूनिट..... यथाविधि शपथ दिलाया गया या प्रतिज्ञान कराया गया, को अभियुक्त या काउन्सेल या प्रतिरक्षा आफिसर द्वारा परीक्षा की जाती है।

टिप्पण :- प्रत्येक साक्षी के साक्ष्य के पश्चात, असम राइफल्स, नियम 97 और नियम 98 के उपबंध जो लागू हो, का अनुपालन किया जाएगा तथा तथ्य अभिलिखित किया जाएगा।

Ⓒ ड (नया पृष्ठ)

*निष्कर्ष (निष्कर्ष)

न्यायालय निष्कर्ष के विचार के लिए बन्द हुआ।

* दोषी न होने के अभिवाक् पर कार्यवाही की जाने की दशा के सिवाय इस भाग का लोप किया जाएगा।

(1) सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

न्यायालय ने पाया कि अभियुक्त नं०.....

रैंक..... नाम..... यूनिट..... आरोप (या किसी भी आरोपों का) का दोषी नहीं है।

निष्कर्ष (निष्कर्षों) की घोषणा

न्यायालय पुनः खुल जाने पर अभियुक्त को पुनः इसके समक्ष लाया जाता है। निष्कर्ष पढ़ा जाता है/पढ़े जाते हैं और उसकी/उनकी घोषणा, पुष्टिकरण के अध्यक्षीन रहते हुए, की जाती है।

यह के मास के
दिन हस्ताक्षरित।

(हस्ताक्षर)

विधि आफिसर

(हस्ताक्षर)

पीठासीन आफिसर

(2) कुछ आरोपों से न कि सभी आरोपों से दोषमुक्ति।

.....आरोप (आरोपों) का दोषी नहीं है अपितु

.....आरोप (आरोपों) का दोषी है।

(3) सभी आरोपों के बावत दोषसिद्ध।

आरोप (या सभी आरोपों) का दोषी है।

(4) विशेष निष्कर्ष।

(क)आरोप (आरोपों) का दोषी है और (उल्लेखों)

.....शब्दों को छोड़कर.....आरोप का दोषी है।

या

(ख) सेवा का अभित्यजन करने का दोषी नहीं है परन्तु बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहने का दोषी है।

या

(ग) इस परिवर्तन के साथ आरोप का दोषी है कि "4200.00 रुपये (चार हजार दो सौ रुपये मात्र) अंकों और शब्दों के स्थान पर "3200.00 (तीन हजार दो सौ रुपये मात्र)" अंक और शब्द पढ़े जाए।

अनुदेश :- असम राइफल्स, नियम 107 (4) और नियम (5) द्वारा अनुज्ञात कोई विशेष निष्कर्ष, जहां तक संभव हो, (क) या (ग) के अनुसार अभिलिखित किया जाएगा। असम राइफल्स अधिनियम की धारा 107 द्वारा अनुज्ञात कोई विशेष निष्कर्ष (ख) के अनुसार अभिव्यक्त किया जा सकेगा।

उन्मत्ता (असम राइफल्स, नियम 138)

न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि अभियुक्त (नं०.....रैंक.....नाम.....यूनिट.....

विकृत चित्त है और परिणामतः अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है।

या

अभियुक्त ने वे कार्य किए हैं, जिनसे आरोप (आरोपों) में विनिर्दिष्ट अपराध बनता है (बनते हैं) परन्तु चित्तविकृति के कारण वह उस कार्य (या उन कार्यों) की प्रकृति जानने में असमर्थ था (या, विकृत चित्त के कारण वह यह जानने में असमर्थ था कि वह कार्य गलत था (या वे कार्य गलत थे) (या विधि के प्रतिकूल थे)।

निष्कर्ष (निष्कर्षों) की घोषणा

न्यायालय पुनः खुलने पर, अभियुक्त को पुनः उसके समक्ष लाया जाता है। निष्कर्ष खुले न्यायालय में पढ़ा जाता है, या पढ़े जाते हैं और उनकी घोषणा, पुष्टि के अधीन रहते हुए की जाती है।

केमास के दिन.....

हस्ताक्षरित।

(हस्ताक्षर)

विधि आफिसर

(हस्ताक्षर)

पीठासीन आफिसर

@ च (नया पृष्ठ)

दोषसिद्धि पर कार्यवाहियां

नं०.....रैंक.....नाम.....यूनिट.....को सम्यक् रूप से शपथ दिलाई जाती है या प्रतिज्ञान कराया जाता है।

प्रश्न 20 :- अभियुक्त और उसके चरित्र के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि के सबूत में आप कौन सा अभिलेख पेश करना चाहते हैं ?

उत्तर :- मैं बटालियन या यूनिट के अभिलेखों की अभिरक्षा रखने वाले आफिसर के हस्ताक्षर से प्रमाणित एक विवरण पेश करता हूँ।

विधि आफिसर (पीठासीन आफिसर) द्वारा कथन पढ़ा जाता है,

.....चिन्हित किया जाता है, हस्ताक्षरित किया जाता है और कार्यवाहियों में संलग्न किया जाता है।

प्रश्न 21 :- आपने जो कथन सुना है, क्या उसमें नामित व्यक्ति अभियुक्त ही है ?

उत्तर 21 :-

प्रश्न 22:- क्या आपने उपर्युक्त कथन की अन्तर्वस्तु की बटालियन या यूनिट के अभिलेखों से तुलना की है ?

उत्तर 22:-

प्रश्न 23:- क्या वे बटालियन या यूनिट के अभिलेखों के सही उद्धरण हैं और व्यक्तिकभी प्रपत्र में प्रविष्टियों का कथन क्या इन प्रविष्टियों की सही और सत्य संक्षिप्त है ?

उत्तर 23 :-

प्रश्न 24 :-

उत्तर 24:- अभियुक्त (या काउन्सेल या प्रतिरक्षा आफिसर) द्वारा प्रतिपरीक्षा की गई। पुनः परीक्षा की गई या अभियुक्त साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने से इंकार करता है।

टिप्पण :- असम राइफल्स, नियम 97 और नियम 98, जैसे वे लागू हैं, का पालन किया जाएगा और तथ्य अभिलिखित किया जाएगा।

प्रश्न 25 :- क्या आप दिए गए दण्ड को कम करने के लिए न्यायालय को संबोधित करना चाहते हैं ?

उत्तर 25:-

न्यायालय दण्डादेश पर विचार करने के लिए बंद हुई।

दण्डादेश

न्यायालय दण्डादेश अभियुक्त सं०.....रैंक.....नाम.....

यूनिट या बटालियन.....

(अनुदेश- दण्डादेश प्रत्येक मामले में पार्श्व में लिखा जाएगा)

(क) गर्दन से लटाकाए जाने द्वारा मृत्यु, जब तक कि उसकी मृत्यु न हो जाए, भोगें, (या गोली से मार कर मृत्यु दण्ड भोगें)।

(ख) आजीवन कारावास का दण्ड भोगें।

(ग)का कठिन (या सादा) कारावास का दण्ड भोगें।

(टिप्पणी- कारावास का दण्डादेश जब तक कि वह ठीक एक वर्ष या उससे अधिक के लिए न हो यदि वह एक माह या उससे अधिक की अवधि के लिए है, तो महीनों में अभिलिखित किया जाना चाहिए, वे दण्डादेश जिनमें भागतः मास और भागतः दिन सम्मिलित हैं महीनों और दिनों में अभिलिखित किए जाने चाहिए)।

(घ) सेवा से पदच्युत किया जाना।

(ङ) (किसी आफिसर, अधीनस्थ आफिसर या अवर आफिसर की दशा में)-

रैंक और अग्रतः इस प्रकार धारण करें मानो.....के रूप में उसकी नियुक्ति.....के मास केदिन हुई थी।

या

उसके द्वारा धारण.....की रैंक में इस प्रकार अग्रतः ग्रहण करें, मानो उसका नाम आफिसरों और अधीनस्थ आफिसरों की दशा में असम राइफल्स सूची और अवर आफिसरों की दशा में उसकी रैंक की सूची में (स्थानों की संख्या का उल्लेख करें)।

या

प्रोन्नति के लिए.....सेवा समपद्धत की जाए।

(अनुदेश - यह केवल ऐसे व्यक्ति की दशा में लागू होता है जिसकी प्रोन्नति सेवा की अवधि पर निर्भर करती है और दण्डादेश उसकी सेवा के सभी या किसी भाग की बावत अधिरोपित किया जा सकता है।)

(च) वर्द्धित वेतन (या पेंशन).....के प्रयोजन के लिए उसकी (पूरी या.....वर्ष की या.....माह की) गत सेवा समपद्धत की जाए।

(छ) (आफिसर, अधीनस्थ आफिसर और अवर आफिसर की दशा में) तीव्र धिग्दण्ड (या धिग्दण्ड) दिया जाए।

(ज) अवधि (सक्रिय सेवा में किए गए अपराध के लिए तीन मास से अनधिक अवधि के वेतन और भत्ते समपद्धत किए जाए।

(झ) संकलक पदच्युत किए जाने या पदच्युत किए जाने के समय उसे शोध्य वेतन और भत्ते तथा अन्य सभी लोक धन का बकाया समपद्धत किया जाए।

(ञ) उसके वेतन और भत्ते उस समय तक के लिए रोक दिए जाएं, जब तक कि वह निम्नलिखित वस्तुओं की बावत.....की राशि कीया (और) उनकी कीमत की क्षतिपूर्ति नहीं कर देता है, अर्थात्:-

दया की सिफारिश

न्यायालय अभियुक्त के लिए निम्नलिखित आधार पर दया की सिफारिश करता है, (उल्लेख करें)

दण्डादेश की घोषणा

न्यायालय के पुनः खुल जाने पर अभियुक्त को उसके समक्ष लाया जाता है। दण्डादेश खुले न्यायालय में घोषित किया जाता है।

के मास के दिन हस्ताक्षरित।

विधि आफिसर

पीठासीन आफिसर

पुनरीक्षण

के मास के दिन न्यायालय के आदेशानुसार अपने
पर विचार करने के प्रयोजन के लिए पुनः आयोजित होता है।

वही सदस्य और विधि आफिसर उपस्थित हैं, जो को उपस्थित थे।

(अनुदेश - यदि कोई सदस्य अनुपस्थित है और अनुपस्थित सदस्य से न्यायालय की न्यूनतम विधिक संख्या कम हो जाती है और उपस्थित सदस्यों को यह प्रतीत होता है कि ऐसा अनुपस्थित सदस्य उचित समय के भीतर उपस्थित न हो सकता है, तो पीठासीन आफिसर या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित वरिष्ठ सदस्य, उस मामले की रिपोर्ट संयोजन आफिसर को देगा।)

पुनरीक्षण के लिए न्यायालय के पुनः संयोजन का निर्देश और निष्कर्ष के पुनरीक्षण की अपेक्षा करने के लिए पुष्टि करने वाले प्राधिकारी के कारण पीठासीन आफिसर (या विधि आफिसर) द्वारा पढ़े जाते हैं, चिन्हित किए जाते हैं, और कार्यवाहियों में संलग्न किए जाते हैं।)

अनुदेश - (1) यदि पुष्टि करने वाले प्राधिकारी ऐसा आदेश देता है, तो पुनरीक्षण में अतिरिक्त साक्ष्य लिया जा सकेगा।

(2) यदि किसी नए विधि आफिसर की नियुक्ति की गई है तो उसे शपथ दिलाई जानी चाहिए या प्रतिज्ञान कराया जाना चाहिए और पुनरीक्षण आदेश पढ़ने से पूर्व इस आशय का तथ्य अभिलिखित किया जाना चाहिए।

(3) यदि अभियुक्त या काउन्सेल या प्रतिरक्षा आफिसर न्यायालय को सम्बोधित करना चाहता है, तो उसके सम्बोधन का सारांश लिखा जाना चाहिए, या उसका लिखित सम्बोधन को प्रायिक रूप में पढ़ा जाना चाहिए, चिन्हित किया जाना चाहिए और कार्यवाहियों में संलग्न किया जाना चाहिए (असम राइफल्स, नियम 113 देखें)

(4) यदि विधि आफिसर किन्हीं बातों को स्पष्ट करना चाहता है तो वह अतिरिक्त उपसंहार कर सकेगा, जिसे प्रायिक रूप से पढ़ा जाना चाहिए, चिन्हित किया जाना चाहिए और कार्यवाहियों में संलग्न किया जाना चाहिए।)

न्यायालय अपने निष्कर्ष (निष्कर्षों) और दण्डादेश पर विचार करने के लिए बन्द होती है।

पुष्टि करने वाले प्राधिकारी के विचारों पर और सम्पूर्ण कार्यवाही पर ध्यानपूर्वक विचार करने के पश्चात् न्यायालय—

(क) अब अपने निष्कर्ष और दण्डादेश को प्रतिसंहत करता है और अभियुक्त को आरोप (आरोपों) के लिए दोषी या निर्दोष पाता है और उसे से दण्डादिष्ट करता है।

या

(ख) अब अपना दण्डादेश प्रतिसंहत करता है तथा अभियुक्त को से दण्डादिष्ट करता है।

या

(ग) सम्मानपूर्वक अपने पूर्व दण्डादेश या निष्कर्ष और दण्डादेश को सम्मानपूर्वक अपरिवर्तित रखता है।

अनुदेश 1. इस दशा में जब पुनरीक्षण कुछ आरोपों पर न्यायालय के निष्कर्ष से संबंधित हो, तब तदनुसार उपर (क) को अभिलिखित किया जाना चाहिए। यदि न्यायालय अपने पूर्व निष्कर्ष (निष्कर्षों) में परिवर्तन करता है, तो उन्हें अपने पूर्व निष्कर्ष (निष्कर्षों) और दण्डादेश प्रतिसंहत करने चाहिए और यदि पुनरीक्षित निष्कर्ष (निष्कर्षों) में कोई दण्डादेश अन्तर्बलित है, तो नए दण्डादेश प्रारित करने चाहिए।

2. यदि नए निष्कर्ष में कोई दण्डादेश निहित है, तो दोषसिद्धि पर, यदि आवश्यक हो तो, सामान्य कार्यवाहियां अपनाई जानी चाहिए तथा उपर्युक्त (क) पर दिए गए प्रारूप में तदनुसार संशोधन करना चाहिए।

3. निष्कर्ष और दण्डादेश की बावत न्यायालय के सभी विनिश्चयों को खुले न्यायालय में यह बताकर सुनाया जाना चाहिए कि वे पुष्टिकरण के अधीन हैं और इस आशय का तथ्य सामान्य रीति में अभिलिखित किया जाना चाहिए।

के मास के दिन हस्ताक्षरित।

(हस्ताक्षर)

(हस्ताक्षर)

विधि आफिसर

पीठासीन आफिसर

छ (नया पृष्ठ)

पुष्टिकरण

1. की गई पुष्टि।

*मैं यह निदेश देता हूँ कि (कठोर या सादा) कारावास का दण्डादेश सैनिक अभिरक्षा (या सिविल कारागार में) परिरुद्ध रख कर निष्पादित किया जाएगा।

सिविल कारावास की दशा में अभियुक्त को डिवीजन "क" या "ग" (या III) के लिए जब वह सिविल कारागार में दण्ड भोग रहा हो, सिफारिश की जाती है। यदि कैदियों के केवल दो डिवीजन हैं, तो, अभियुक्त की "डिवीजन" "क" (या i) या "ख" (या ii) के लिए सिफारिश की जाती है।

या

2. मैं दण्डादेश में परिवर्तन करता हूँ ताकि यह निम्न प्रकार का होगा और इस प्रकार परिवर्तित किए गए निष्कर्ष और दण्डादेश की पुष्टि करता हूँ।

या

3. मैं न्यायालय के निष्कर्ष और दण्डादेश की पुष्टि करता हूँ, परन्तु उसे कम करता हूँ (या उसका परिहार या लघुकरण करता हूँ।)

या

4. (जहां निष्कर्ष की पुष्टि नहीं की गई है)
वहाँ पुष्टि नहीं की गई है।

या

5. जहां न्यायालय यह पाता है कि अभियुक्त विकृतचित्त है और परिणाम: स्वरूप अपनी प्रतिरक्षा करने में असमर्थ है या यह कि उसने अभिकथित कार्य किया था परन्तु वह विकृतचित्तता के कारण वह उस कार्य की प्रकृति या यह जानने में यह जानने में कि वह कार्य गलत या विधि के प्रतिकूल था, असमर्थ था।

"पुष्टि की गई (या पुष्टि नहीं गई)"।

या

6. मैं प्रथम आरोप पर न्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टि करता हूँ, परन्तु दूसरे आरोप पर निष्कर्ष की पुष्टि नहीं करता हूँ।
मैं दण्डादेश की पुष्टि करता हूँ परन्तु उसे कम करता हूँ (उसका परिहार करता हूँ या उसका लघुकरण करता हूँ।)

तारीख

को हस्ताक्षरित।

(पुष्टि करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर)

(अनुदेश - पुष्टि करने वाले प्राधिकारी की कोई पृथक टिप्पणियां अभ्युक्ति होनी चाहिए और वह कार्यवाहियों की भाग नहीं बननी चाहिए।)

प्रख्यापन

(नियम 124)

साधारण या पैटी असम राइफल्स न्यायालय के (स्थान) पर आज के दिन से
दिन तक अभिनिर्धारित निष्कर्ष (निष्कर्षों) और दण्डादेश अभियुक्त के विचारण के लिए (विशिष्टियां)
..... स्थान पर तारीख को मेरे द्वारा अभियुक्त को प्रख्यापित किया गया था। बटालियन या
यूनिट अभिलेख के कार्यवाहियों के लिए सारांश किए गए हैं या सभी आरोपों से दोषमुक्ति की दशा में उपयोग में लाया जाएगा।
निष्कर्षों का कोई अभिलेख नहीं रखा गया है।

स्थान.....

हस्ताक्षर

तारीख:

(कमाण्डेंट)

* सभी आरोपों पर दोषमुक्ति के मामले में उपयोग किया जाए।

(नमूना-2)

असम राइफल्स अधिनियम, 2006 के अधीन समरी असम राइफल्स की कार्यवाहियों के लिए प्ररूप

क

तारीख को पर कमाण्डेंट बटालियन या यूनिट द्वारा ऐसे सभी अभियुक्त व्यक्तियों के विचारण के लिए, जिसको वह सम्यक् रूप से उसके समक्ष ला सका है, विचारण के लिए आयोजित किए गए समरी असम राइफल्स न्यायालय की कार्यवाहियां।

उपस्थित

कमाण्डेंट

विचारण में उपस्थित

दुभाषिया

अभियुक्त का मित्र

आफिसर को में समवेत होते हैं और विचारण बजे प्रारम्भ होता है।

..... का अभियुक्त सं० रैंक नाम
न्यायालय में लाया जाता है (यदि अवर आफिसर है तो, बुलाया जाता है)

..... न्यायालय को शपथ दिलाई जाती है या प्रतिज्ञान कराया जाता है।

..... को दुभाषिए के रूप में शपथ दिलाई जाती है या प्रतिज्ञान कराया जाता है।

(अनुदेश - यदि अभियुक्त का कमाण्डेंट (अर्थात् न्यायालय) दुभाषिए के रूप में कार्य करता है, तो उसे न्यायालय के लिए विहित शपथ के अतिरिक्त दुभाषिए की शपथ भी लेनी चाहिए।)

सभी साक्षियों को न्यायालय से बाहर जाने का निदेश दिया जाता है।

*1. विचारण कर रहे अधिकारी का नाम और रैंक दर्ज करें।

2. पूरी कार्यवाहियों के दौरान न्यायालय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

3. अप्रयोज्य भाग का लोप किया जाए और न्यायालय द्वारा आद्याक्षरित किया जाए।

(ख) (नया पृष्ठ)

आरोप पत्र पढ़ा जाता है, (अनुदित किया जाता है) और अभियुक्त को स्पष्ट किया जाता है, ख-2 चिह्नित किया जाता है, न्यायालय द्वारा हस्ताक्षर किया जाता है और उसे कार्यवाहियों में संलग्न किया जाता है।

(अनुदेश - असम राइफल्स न्यायालय द्वारा संक्षिप्त विचारण के लिए ज्येष्ठ प्राधिकारी की स्वीकृति की प्रविष्टि; उस प्राधिकारी के हस्ताक्षर तारीख सहित आरोप-पत्र के नीचे की जानी चाहिए। (असम राइफल्स नियम 95 (2))

दोषारोपण

*प्रश्न- आप कैसे कहते हैं कि आप, नं० रैंक नाम यूनिट
अपने विरुद्ध लगाए गए प्रथम आरोप या आरोप के दोषी हैं या नहीं हैं ?

उत्तर - टिप्पणी - यदि
अभियुक्त ने आरोप का दोषी होने का अभिवचन किया है, तो असम राइफल्स नियम 153 (2) के उपबन्धों का अनुपालन किया जाएगा।

****अभियुक्त ने.....** आरोप का दोषी होने का अभिवचन किया है, न्यायालय द्वारा अभियुक्त को उसके द्वारा आरोप (आरोपों) का दोषी होने का अभिवचन के प्रभाव के बारे में स्पष्ट किया जाएगा और यह अभिनिश्चित किया जाएगा कि अभियुक्त उस आरोप (आरोपों) की प्रकृति को पूर्णतया समझता है, जिसके लिए उसने दोषी होने का अभिवचन दिया है। न्यायालय अभियुक्त को यह भी सूचित करता है कि ऐसे अभिवचन का साधारण प्रभाव क्या है और उक्त अभिवचन की परिणाम स्वरूप अनुसरित की जाने वाली कार्यवाही में अंतर क्या है। न्यायालय का यह समाधान हो जाने पर कि अभियुक्त आरोप (आरोपों) को और दोषी होने के अभिवाक् के परिणाम को भी समझता गया है और उसे स्वीकार किया है, अभिलिखित करता है। नियम 153 (2) के उपबंधों का अनुपालन किया जाता है।

* एक से अधिक आरोपों की दशा में, अभियुक्त से अलग-अलग प्रश्न पूछे जाने चाहिए।

****** ऐसे दोषारोपण की दशा में जब अभियुक्त आरोप की बावत दोषी होने का अभिवाक् करता है, नियम 161 (2) के बारे में अभियुक्त को स्पष्ट कर दिया जाना चाहिए और दोषी होने के निष्कर्ष अभिलिखित करने से पहले उपरोक्त कार्यवृत्त कार्यवाहियों में अभिलिखित किया जाना चाहिए।

(ग) (नया पृष्ठ)

दोषी होने के अभिवचन के संबंध में प्रक्रिया

अभियुक्त नं०..... रैंक..... नाम..... को.....
..... आरोप (सभी आरोपों) का दोषी पाया गया है।

..... न्यायालय द्वारा साक्ष्य की संक्षिप्त पढ़ दी गई है (अनूदित की गई है) स्पष्ट की गई है चिन्हित की गई है, हस्ताक्षरित की गई है और कार्यवाहियों से संलग्न कर दी गई है।

* अभियुक्त से पूछा गया प्रश्न

* प्रश्न — क्या आप आरोप के संदर्भ में या दण्ड को कम करने के लिए कोई कथन करना चाहते हैं?

उत्तर —

प्रश्न— क्या आप चरित्र के बारे में किसी साक्षी को बुलाना चाहते हैं ?

उत्तर —

(अनुदेश — यदि विचारण ऐसे किसी आरोप पर, जिसका दोषी न होने का अभिवचन है की ओर अग्रसर होता है, तो न्यायालय दोषी होने के अभिवाक् के अभिलेख पर तब तक कार्यवाही नहीं करेगा, जब तक कि वह अन्य आरोपों पर निष्कर्ष पर न पहुंच जाए, और उस दशा में वह आरोप जिस पर अभिलेख दोषी होने का अभिवाक् अभिलिखित किया गया है, अभियुक्त को पुनः पढ़कर सुनाया जाना चाहिए। असम राइफल्स नियम 153 (1) देखें।)

\$ परिवर्तन

अभियुक्त के कथन (या साक्ष्य की संक्षेप से या अन्यथा) न्यायालय का यह समाधान हो जाने पर कि अभियुक्त दोषी होने के अभिवाक् के प्रभाव को नहीं समझता है, इसलिए न्यायालय अभिलेख में परिवर्तन करता है और दोषी न होने के अभिवाक् को दर्ज करता है।

\$ अभियुक्त द्वारा संक्षिप्त विचारण में दिए गए उसके कथन या असम राइफल्स नियम 154 (4) (क) में यथाउल्लिखित अन्य परिस्थितियों के कारण, यदि उसका दोषी होने का अभिवाक् अर्थहीन हो जाए तो ऐसी दशा में लागू होगी।

(घ) (नया पृष्ठ)

दोषी न होने के अभिवाक् के संबंध में कार्यवाहियां

अभियोजन

अभियोजन के लिए प्रथम साक्षी

अभियोजन साक्षी 1 सं०..... रैंक..... नाम..... को सम्यक् रूप से शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के पश्चात् न्यायालय द्वारा उसकी परीक्षा की जाती है।

अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा की जाती है।

न्यायालय द्वारा पुनः परीक्षा की जाती है।

टिप्पण— यदि अभियोजन के लिए अभियुक्त किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने से इन्कार करता है, तो यह तथ्य अभिलिखित किया जाना चाहिए। प्रत्येक साक्षी के साक्ष्य के निष्कर्ष पर यह तथ्य अभिलिखित किया जाना चाहिए कि असम राइफल्स नियम 98 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

घ-2 (नया पृष्ठ)

अभियोजन के लिए दूसरा साक्षी

अभियोजन साक्षी-2 सं०..... रैंक..... नाम..... के..... को सम्यक् रूप से शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के पश्चात् न्यायालय द्वारा उसकी परीक्षा की जाती है।

अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा की जाती है।

न्यायालय द्वारा पुनः परीक्षा की जाती है।

अभियोजन के लिए अभियुक्त किसी साक्षी की प्रतिपरीक्षा करने से इन्कार करता है, तो यह तथ्य अभिलिखित किया जाना चाहिए। प्रत्येक साक्षी के साक्ष्य के निष्कर्ष पर यह तथ्य अभिलिखित किया जाना चाहिए कि असम राइफल्स नियम 98 के उपबंधों का अनुपालन किया गया है।

ड. (नया पृष्ठ)

अभियोजन पक्ष की ओर से सुनवाई बन्द हुई।

प्रतिरक्षा

अभियुक्त से पूछा गया प्रश्न

(नियम 156 (3))

न्यायालय द्वारा असम राइफल्स नियम 156 (3) के उपबंधों को पढ़ा जाता है और स्पष्ट किया जाता है। यह अभिनिश्चित करने पर कि अभियुक्त ने उसके सम्मुख पड़े गए उपबंधों को समझ लिया है। अभियुक्त से प्रश्न पूछने के लिए न्यायालय की कार्यवाही आरंभ करती है।

प्रश्न :- के साक्ष्य में यह कथन किया गया है कि क्या आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं ?

उत्तर :-

प्रश्न :-

उत्तर :-

न्यायालय का अनुदेश

1. अभियुक्त से प्रश्न केवल उसे स्पष्टीकरण देने का अवसर प्रदान करने के लिए और तब ही पूछे जाएंगे, जब ऐसे स्पष्टीकरण के अभाव में उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है, परंतु यह तब जब कि वह ऐसी इच्छा प्रकट करे।
2. अभियुक्त से पूछे गए प्रश्न ऐसे होने चाहिए जिनसे वह साक्ष्य में उसके विरुद्ध आने वाली परिस्थितियों को स्पष्ट करने में समर्थ हो सके और यदि वे स्पष्ट नहीं की जाती तो परिणामतः दोषसिद्धि हो सकता है।
3. अभियुक्त से प्रश्न अभियोजन के मामले की प्रतिपूर्ति करने के लिए नहीं पूछे जाने चाहिए।
4. अभियुक्त से पूछे गए प्रश्न और उनके उत्तर जहां तक सम्भव हो, अक्षरशः अभिलिखित किए जाएंगे।
5. अभियुक्त को कोई शपथ नहीं दिलाई जाएगी।

(असम राइफल्स नियम 156 (2) के अधीन अभियुक्त से पूछे गए प्रश्न)

प्रश्न - क्या आप अपनी प्रतिरक्षा में कुछ कहना चाहते हैं ?

उत्तर -

(असम राइफल्स नियम 156 (2) के अधीन अभियुक्त से प्रश्न)

प्रश्न - क्या आप अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी को बुलाना चाहते हैं ?

उत्तर -

च (नया पृष्ठ)

प्रतिस्का के लिए प्रथम साक्षी

प्रतिस्का साक्षी - 1.....रैंक.....नाम.....को शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के पश्चात् न्यायालय द्वारा उसकी परीक्षा की जाती है।

न्यायालय द्वारा प्रतिपरीक्षा की जाती है।

अभियुक्त द्वारा पुनः परीक्षा की जाती है।

टिप्पण - 1. प्रत्येक साक्षी के साक्ष्य की समाप्ति पर यह तथ्य अभिलिखित किया जाना चाहिए कि असम राइफल्स नियम 98 का अनुपालन किया गया है।

2. एक से अधिक साक्षी होने की दशा में, उनका कथन परवर्ती पृष्ठ च-2, च-3 आदि के रूप में अभिलिखित किया जाएगा।

प्रतिस्का पक्ष की सुनवाई बंद हुई।

छ (नया पृष्ठ)

उत्तर (नियम 157)

सं०.....रैंक.....नाम.....को शपथ दिलाने या प्रतिज्ञान कराने के पश्चात् न्यायालय द्वारा उसकी परीक्षा की जाती है।

ज (नया पृष्ठ)

न्यायालय का निर्णय

(सभी आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।)

मेरे समक्ष जो साक्ष्य हैं, उनके आधार पर मेरा यह मत है

कि.....

का अभियुक्त सं०.....रैंक.....नाम.....के आरोप (आरोपों) का दोषी नहीं हैं और उसे इन आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

निर्णय पढ़कर सुनाया जाता है और अभियुक्त को निर्मुक्त किया जाता है।

आज तारीख.....को माह के.....दिन.....स्थान पर मैं.....हस्ताक्षरित

(कमाण्डेंट)

विचारण करने वाला आफिसर

विचारण.....बजे बंद होता है।

टिप्पण - यह पृष्ठ सिर्फ ऐसे मामलों में उपयोग में लाया जाए, जब अभियुक्त सभी आरोपों का "दोषी नहीं" पाया जाता है।

झ (नया पृष्ठ)

न्यायालय का निर्णय

मेरे समक्ष जो साक्ष्य हैं उसके आधार पर मेरा यह मत है कि अभियुक्त सं०.....रैंक.....नाम.....
.....(आरोप का दोषी है या प्रथम और द्वितीय आरोप का दोषी नहीं है या सभी आरोपों का दोषी है।)

(विशेष निष्कर्ष)

(क) आरोप/आरोपों का दोषी है और.....आरोप का (उल्लिखित) शब्दों को छोड़ कर दोषी है।

या

(ख) सेवा का अभित्यजन करने का दोषी नहीं है परंतु छुट्टी के बिना स्वयं को अनुपस्थित रखने का दोषी है।

या

(ग) इस परिवर्तन के साथ आरोप का दोषी है कि 4200.00 रुपए (चार हजार दो सौ रुपये मात्र) अंको और शब्दों के स्थान पर 3200.00 (तीन हजार दो सौ रुपए मात्र) अंक और शब्द पढ़े जाएं।

(अनुदेश—असम राइफल्स नियम 159 (3) द्वारा अनुज्ञात कोई विशेष निष्कर्ष, जहां तक संभव हो (क) या (ग) के अनुसार अभिलिखित किया जाएगा। असम राइफल्स अधिनियम की धारा 115 द्वारा अनुज्ञात कोई विशेष निष्कर्ष (ख) के अनुसार अभित्यक्त किया जा सकेगा।)

दण्डादेश के पूर्व कार्यवाहियां

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित कार्यवृत्त पढ़ा जाता है और स्पष्ट किया जाता है।

(अनुदेश—यदि न्यायालय अभियुक्त की दोषसिद्धि और चरित्र को अपने नाम के आधार पर अभिलिखित नहीं करता है तो इन विषयों की बावत साक्ष्य न्यायालय कार्यवाहियों के लिए लिया जाएगा।)

.....के अभिलेखों से मुझे यह जानकारी है कि अभियुक्त.....को सेना या दाण्डिक न्यायालय द्वारा पहले दोषसिद्धि किया जा चुका है। (जब आवश्यक हो, पूर्व दोषसिद्धि की पूर्ण विशिष्टियों का एक पृथक् विवरण संलग्न किया जाएगा।)

निम्नलिखित संक्षिप्ति उसके व्यक्तिक्रम प्रपत्र की प्रविष्टियों की उचित और सही संक्षिप्ति है, जिसके अन्तर्गत सेना न्यायालय या किसी दाण्डिक न्यायालय द्वारा निर्णित दोषसिद्धियां सम्मिलित नहीं हैं।

विगत बारह माह के भीतर

अभ्यावेशन के समय से

.....के लिए.....बार

.....के लिए.....बार

.....के लिए.....बार

यह कि वह इस समय.....दण्डादेश भोग रहा है। इस विचारण को ध्यान में लाए बिना यह है कि उसका साधारण चरित्र.....रहा है। यह कि उसकी आयु.....है वह.....सेवा कर चुका है और उसकी रैंक.....है। (गिरफ्तारी की तारीख)

यह कि उसे.....दिनों के लिए गिरफ्तार/परिरुद्ध किया गया है।

* यह कि उसके पास निम्नलिखित सैनिक अलंकार और इनाम है—

* वीरतापूर्ण या विशिष्ट आचरण के प्रत्येक मान्यताप्राप्त कार्य की प्रविष्टियां यहां की जानी चाहिए।

अ (नया पृष्ठ)

न्यायालय का दण्डादेश

इन सभी विषयों पर विचार करने के पश्चात् मैं.....के अभियुक्त नं०.....रैंक.....नाम.....को दण्डादिष्ट करता हूँ। (दण्डादेश के प्रारूप के लिए पृष्ठ एफ की साधारण या लघु असम राइफल्स न्यायालय का नमूना देखें।)

आज.....तारीख.....के.....को हस्ताक्षरित।

(कमाण्डेंट)

विचारण करने वाला आफिसर

विचारण बजे बंद होता है।

पुनर्विलोकन अधिकारी की टिप्पणियां (असम राइफल्स अधिनियम की धारा 137)..... के नं०

असम राइफल्स अधिनियम के अधीन संक्षिप्त असम राइफल्स न्यायालय द्वारा विचारण।

..... में के नं०.....

आज के दिन..... आज की तारीख.....

..... का
रजिस्ट्रकृत.....

मुख्य विधि आफिसर

असम राइफल्स नियम 100 के अधीन अभियुक्त का चरित्र और पूर्व दोषसिद्धि के विवरण के लिए प्रोफार्मा

1. अभियुक्त का नाम और नं० :
2. वर्तमान रैंक :
3. असम राइफल्स में भर्ती या नियुक्ति की तारीख :
4. वर्तमान रैंक में पदोन्नति की तारीख :
5. अवधि सेवा की कुल अवधि :
6. जन्म तिथि और आयु :
7. विचारण आरंभ होने तक गिरफ्तारी या
परिरोध की अवधि :
8. अलंकार और पुरस्कार
(वीरतापूर्ण या विशिष्ट आचरण के प्रत्येक
मान्यताप्राप्त कार्य की प्रविष्टियां यहां दर्ज की जानी चाहिए।)
9. उपाबंध के अनुसार असम राइफल्स न्यायालय और
अपराधिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि के विवरण :
10. असम राइफल्स अधिनियम की धारा
धारा 62, धारा 64, धारा 65, धारा 66 के प्राधिकार का प्रयोग करते हुए
किसी आफिसर द्वारा अधिनिर्णीत दण्ड
गत 12 मास के भीतर
(क) समय के लिए..... धारा के अधीन (क) समय..... के लिए..... धारा के अधीन
(ख) समय के लिए..... धारा के अधीन (ख) समय..... के लिए..... धारा के अधीन
(ग) समय के लिए..... धारा के अधीन (ग) समय..... के लिए..... धारा के अधीन
11. यह कि वह इस समय दण्डादेश भुगत रहा है

12. यह कि इस विचारण का विचार किए बिना उसका साधारण चरित्र..... है।
(वर्तमान विचारण से पूर्व, उसका अभिलेख के आधार पर इसका मूल्यांकन किया जाए।

(हस्ताक्षर)

कमाण्डेंट या सेवा अभिलेख या गोपनीय

फाइल अभिरक्षा में रखने वाला आफिसर

उपाबंध

असम हाइफ्ल्स न्यायालय या आपराधिक न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि का विवरण

न्यायालय का अधिभत

क्रम सं०	विचारण की तारीख	आरोप की विशिष्टियां	बल न्यायालय या दंडिक न्यायालय द्वारा	निष्कर्ष	दण्डादेश	टिप्पणियां
----------	-----------------	---------------------	--------------------------------------	----------	----------	------------

भाग—III

साक्षियों के समनों का प्ररूप

- (क) साक्ष्य की संक्षेप की दशा में
सेवा में,

बल न्यायालय द्वारा विचारणीय (किसी अपराध के किए जाने का एक आरोप (नं०..... रैंक..... नाम.....
यूनिट.....) के विरुद्ध मेरे सम्मुख लाया गया है और मैंने..... (स्थान)
पर आज..... के..... माह के..... दिन..... बजे साक्ष्य की संक्षेप लिखित
रूप में लेने का निदेश दिया है, अतः मैं इस समन द्वारा आपको (नाम)..... उक्त स्थान और समय पर साक्षी के रूप में
उपस्थित होने के लिए और इनमें इसके पश्चात् वर्णित दस्तावेज अर्थात्..... अपने साथ लाने के लिए) आपको समन
करता हूँ और आपसे ऐसा करने की अपेक्षा करता हूँ।

उपस्थित होने में असफल रहने पर आप जोखिम के भागी होंगे।

आज..... के..... माह के..... दिन मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

अभियुक्त का समादेशक।

(हस्ताक्षर)

- (ख) बल न्यायालय द्वारा विचारण के मामले में।
सेवा में,

आपको ज्ञात हो कि..... बटालियन के..... के विचारण के लिए तारीख..... को
समवेत होने के लिए..... बल न्यायालय ने आदेश दिया गया है, अतः मैं आपको (क)..... (ख)
को इसके द्वारा तारीख..... के दिन..... बजे (..... स्थान पर) उक्त न्यायालय की बैठक में
साक्षी के रूप में हाजिर होने के लिए और प्रतिदिन इस प्रकार हाजिर होने के लिए (और इनमें इसके पश्चात् वर्णित दस्तावेज, अर्थात्.....
अपने साथ लाने के लिए) समन करता हूँ और आपसे ऐसा करने की तब तक अपेक्षा करता हूँ जब तक कि आपको सम्पूर्ण रूप से
उन्मोचित न कर दिया जाए उपस्थित होने में असफल रहने पर आप जोखिम के भागी होंगे।

आज..... के..... मास के..... दिन मेरे हस्ताक्षर से जारी किया।

(हस्ताक्षर)

संयोजक आफिसर या विधि आफिसर

या पीठासीन आफिसर या
अभियुक्त का समादेशक

(ग) जांच न्यायालय मामलों में।

सेवा में,

आपको ज्ञात हो कि के विचारण के लिए तारीख को समवेत होने के लिए जांच न्यायालय ने आदेश दिया गया है, अतः मैं आपको,

(क) (ख) को मैं इसके द्वारा तारीख के दिन बजे (..... स्थान पर) उक्त न्यायालय की बैठक में साक्षी के रूप में हाजिर होने के लिए और प्रतिदिन इस प्रकार हाजिर होने के लिए (और इनमें इसके पश्चात् वर्णित दस्तावेज, अर्थात् अपने साथ लाने के लिए) समन करता हूँ और आपसे ऐसा करने की तब तक अपेक्षा करता हूँ जबतक कि आपको सम्यक् रूप से उन्मोचित न कर दिया जाए उपस्थित होने में असफल रहने पर आप जोखिम के भागी होंगे।

आज के मास के दिन मेरे हस्ताक्षर से जारी किया।

(हस्ताक्षर)

जांच न्यायालय के लिए समवेत हुए
आफिसर

159

भाग—4

वारंट

असम राइफल्स अधिनियम 2006 के अधीन असम राइफल्स न्यायालय के संयोजन के लिए वारंट

सेवा में,

(महानिरीक्षक या अपर महानिदेशक) असम राइफल्स

असम राइफल्स अधिनियम 2006, के उपबंधों के अनुसरण में, मैं आपको या आपकी अनुपस्थिति में कमांडेंट से अन्यून रैंक ऐसे अधिकारी को जिसे कमान सौंपी जाएगी विधिवत सशक्त करता हूँ, समय-समय पर आवश्यकतानुसार, उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन जनरल असम राइफल्स न्यायालय का संयोजन, आपके कमान के अधीन कोई भी व्यक्ति, जो असम राइफल्स अधिनियम और उक्त अधिनियम के अधीन किसी अपराध के लिए आरोपित किया गया हो, जनरल असम राइफल्स न्यायालय द्वारा विचारण के लिए दायी होगा।

और इसको कार्यान्वित करने के लिए यह आपको और जिनको इससे सरोकार है, उनके लिए एक पर्याप्त वारंट होगा।

आज के माह के दिन मेरे द्वारा दिया गया।

महानिदेशक असम राइफल्स

असम राइफल्स अधिनियम, 2006 के अधीन जनरल असम राइफल्स न्यायालय के निष्कर्ष और दिया दण्डादेश की पुष्टि करने के लिए वारंट

सेवा में,

महानिदेशक, असम राइफल्स,

असम राइफल्स अधिनियम, 2006 के उपबंधों का अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा आपको या किसी अधिकारी को जिसमें आपकी अनुपस्थिति के दौरान आपकी कमांड न्यागत होती है, कमांड की रैंक के अधीन नहीं है जो उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में या असम राइफल्स अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को विचारण के लिए की गई जनरल असम राइफल्स न्यायालय की कार्यवाहियों को प्राप्त करने के लिए, और उसके दण्डादेश की पुष्टि के लिए सशक्त करती है तथा उन न्यायालयों और उनके द्वारा विचरित व्यक्तियों के संबंध में शक्तियां उक्त अधिनियम द्वारा पुष्टिकरण आफिसर में उस रीति में जो बल के सर्वोत्तम हितमें हो निहित करेगी,

परन्तु जनरल असम राइफल्स न्यायालय के दण्डादेश द्वारा असम राइफल्स अधिनियम के अध्याधीन किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड उसे दिया जा युका है, तो ऐसे मामले में किसी अन्य सामान्य असम राइफल्स न्यायालय की दशा के समान भी जिसमें आप जैसा करना ठीक समझें पुष्टि आरक्षित करें और केन्द्रीय सरकार को कार्यवाहियों को प्रेषित करें।

और ऐसा करने के लिए यह अन्य व्यक्तियों जिनका इससे सम्बन्ध हो के साथ साथ आपका एक पर्याप्त वारंट होगा।

आज के माह के दिन मेरे द्वारा प्रदान किया गया।

सचिव, केन्द्रीय सरकार,
गृह मंत्रालय के आदेश द्वारा

असम राइफल्स अधिनियम, 2006 के अधीन

जनरल असम राइफल्स न्यायालय के निष्कर्ष और दंडादेश के पुष्टि के लिए वारंट

सेवा में,

(महानिरीक्षक या उपमहानिरीक्षक) असम राइफल्स

असम राइफल्स अधिनियम, 2006 के उपबंधों का अनुसरण में केन्द्रीय सरकार द्वारा आपको या किसी अधिकारी को जिसमें आपकी अनुपस्थिति के दौरान आपकी कमांड न्यागत होती है, कमांड की रैंक के अधीन नहीं है जो उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसरण में या असम राइफल्स अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को विचारण के लिए की गई जनरल असम राइफल्स न्यायालय की कार्यवाहियों को प्राप्त करने के लिए, और उसके दंडादेश की पुष्टि के लिए सशक्त करती है तथा उन न्यायालयों और उनके द्वारा विचारित व्यक्तियों के संबंध में शक्तियां उक्त अधिनियम द्वारा पुष्टिकरण अधिकारी में उस रीति में जो बल के सर्वोत्तम हितमें हो निहित करेगी;

यदि किसी जनरल असम राइफल्स न्यायालय के दंडादेश द्वारा असम राइफल्स अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति को मृत्युदण्डादेश दिया जा चुका है तो ऐसे मामलों में और इसके साथ संलग्न यथाविनिर्दिष्ट ऐसे मामलों में भी पुष्टिकरण को रिजर्व रखते हुए कार्यवाहियों को ज्येष्ठतर प्राधिकारी को प्रेषित करेंगे।

और ऐसा करने के लिए यह भी अन्य व्यक्तियों के साथ जिनका उससे सम्बन्ध है के साथ आपका एक पर्याप्त वारंट होगा।

आज के माह के दिन मेरे द्वारा प्रदान किया गया।

सचिव,

केन्द्रीय सरकार, गृह मंत्रालय के आदेश द्वारा

1. जनरल असम राइफल्स न्यायालय को कार्यवाहियां जहां नीचे स्तंभ के अधीन विनिर्दिष्ट दण्डादेशों में से किसी में पारित की गई है, नीचे स्तंभ 2 के अधीन विपरीत में विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा पुष्टि के लिए आरक्षित रखा जाएगा।

I	II
(I) मृत्यु दण्डादेश	केन्द्रीय सरकार
(II) आफिसरों के लिए पारित किये गये सभी दण्डादेश	महानिदेशालय असम राइफल्स

2. सभी आफिसरों के मामलों में, जनरल असम राइफल्स न्यायालय द्वारा दोषी नहीं पाए जाने के निष्कर्षों की स्थिति में कार्यवाहियों की पुष्टि करने या पुष्टिकरण नहीं करने की शक्ति महानिदेशालय असम राइफल्स के पास होगी।

असम राइफल्स अधिनियम 2006 के अधीन पैटी असम राइफल्स न्यायालय के संयोजन और पुष्टि करने के लिए वारंट

सेवा में,

असम राइफल्स, (उपमहानिरीक्षक)

जहां असम राइफल्स अधिनियम 2006 के अधीन जनरल असम राइफल्स न्यायालय का संयोजन करने की शक्ति है और इस अधिनियम के अधीन किसी आफिसर के जनरल असम राइफल्स न्यायालय का संयोजन करने की शक्ति है, वे किसी भी आफिसर को जिसे अंतिम निर्दिष्ट आफिसर की कमांड के अधीन किसी व्यक्तियों उस अधिनियम के अधीन विचारण करने के लिए लघु असम राइफल्स न्यायालय का संयोजन करने और निष्कर्षों की पुष्टि और उसके अधीन दण्डादेश देने के लिए सशक्त कर सकता है।

उक्त अधिनियम के अधीन मुझमें निहित शक्ति के आधार, मैं आपको या आपकी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे अधिकारी को जो कमाण्डेंट रैंक के नीचे का न हो जिसे कमांड न्यामत है उनके सशक्त करता हूँ, समय-समय पर आवश्यकतानुसार, अवसर पर उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए नियमों के अधीन लघु असम राइफल्स न्यायालय का संयोजन वाले आपके कमान के अधीन कोई भी

व्यक्ति जो असम राइफल्स अधिनियम के अधीन उक्त अधिनियम में निर्दिष्ट किसी अपराध के लिए किया गया हो, पैटी असम राइफल्स न्यायालय द्वारा विचारण के लिए दायी होगा।

आरोपित आपकी अनुपस्थिति में किसी अधिकारी को जो कमाण्डेंट की रैंक से नीचे नहीं है जिसमें आपकी अनुपस्थिति के दौरान ऐसे न्यायालयों की कार्यवाहियां और उनके द्वारा विचारण किए गए व्यक्ति तथा उक्त अधिनियम द्वारा अतिरिक्त शक्तियां पुष्टिकरण आफिसर में ऐसा रीति में जो बल के सर्वोत्तम हित में हो प्राप्त करने के लिए सशक्त करता है।

और ऐसा करने के लिए यह अन्य व्यक्तियों जिनका इससे संबंध हो के साथ साथ आपका एक पर्याप्त वारंट होगा।

आज के माह के दिन मेरे द्वारा प्रदान किया गया।

स्टाफ आफिसर के हस्ताक्षर

असम राइफल्स न्यायालय के संयोजन
करने में सक्षम आफिसर के हस्ताक्षर

भाग - V

आरोपों के नमूने

सं० 1

असम राइफल्स अधिनियम
धारा 21 (क)

किसी चौकी को, जो उसके भारसाधन में सुपुर्द किया गया है, लज्जास्पद रूप से परित्यक्त करना,

यह कि उसने,

..... स्थान पर तारीख को जब वह सेक्टर
..... में चौकी सं० का भारसाधक था और

जब उस पर शत्रु ने आक्रमण किया तब उसने शत्रु का प्रतिरोध करने का कोई प्रयत्न किए बिना उक्त चौकी को लज्जास्पद रूप से परित्यक्त कर दिया था।

सं० 2

असम राइफल्स अधिनियम
धारा 21 (ख)

किसी व्यक्ति को असम राइफल्स अधिनियम के अध्वधीन शत्रु के विरुद्ध कार्य करने से प्रविरत रहने के लिए किन्हीं साधनों का साशय उपयोग करना, यह कि उसने, पर, तारीख को, जब वह और उसके बटालियन का नं० रैंक नाम यूनिट दोनों अग्रिम चौकी सं० पर दोनों शत्रु फायर में अग्रिम पद स्थान में थे उक्त से कहा कि (देशी भाषा में शब्द लिखें)।

* हमारी मारे जाने की संभावना है। अपनी पत्नी और बच्चों का ख्याल करो। हमें पदस्थान छोड़कर भाग जाना चाहिए और निकटस्थ नाले में छिप जाना चाहिए।" या तदर्थक शब्द टिप्पण:— असल में कहे गये शब्दों को दर्ज करें या उस प्रभाव वाले शब्द दर्ज करें।

सं० 3

असम राइफल्स अधिनियम
21 (ग)

शत्रु की उपस्थिति में ऐसी रीति से कदाचार करना जिससे धारा कायरता प्रकट होती है

यह कि उसने,

..... पर, तारीख को जब बटालियन के क्वार्टर गार्ड के एक संतरी, ने उक्त गार्ड के एक सिपाही को घातक रूप से चोट पहुंचाई थी और दूसरे की गंभीर रूप से घायल कर

दिया था और जब वह अपनी राइफल्स सभी ओर चला रहा था तब उक्त क्वार्टर गार्ड का परित्याग करके और स्वयं ने छिप कर कायरता दिखाई थी।

सं०—4

असम राइफल्स अधिनियम

धारा 21 (घ)

विश्वासघातपूर्वक शत्रु को आसूचना देना

यह कि उसनेपरतारीख को शत्रु की सहायता के आशय से, शत्रु को (शत्रु एजेंसी को विनिर्दिष्ट करें) तारीखके पत्र को मार्फत 3 असम राइफल्स की बी कम्पनी के जवानों कीकी पर तैनाती के बारे में आसूचना दी।

सं०—5

भारतीय दंड संहिता की धारा 34 के साथ पठित

असम राइफल्स अधिनियम

धारा 21 (ङ)

गोला बारूद से शत्रु की सहायता करना

यह कि उन्होंने एक साथ, जब वेपर

तारीख को सक्रिय ड्यूटी पर थे, सामान्य आशय के अनुसरण में सरकार की सम्पत्ति 303 बाल अम्युनिशन केचक्र का शत्रु को विक्रय किया दो व्यक्तियों अर्थात्औरके माध्यम से संघ के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह किया।

सं०—6

असम राइफल्स अधिनियम

धारा 21 (च)

संघर्ष के समय में अपने पिकेट की बिना छुट्टी छोड़ देना

यह कि उसने,पर, तारीखकी, संघर्ष के समय, 2000 बजे और 2200 बजे के बीचपिकेट पर कर्तव्यरूढ़ होते हुए, बिना छुट्टी उक्त पिकेट छोड़ दिया था।

सं०—7

असम राइफल्स अधिनियम

धारा 21 (च)

संघर्ष के समय में अपने पोस्ट को बिना छुट्टी छोड़ देना

यह कि उसने युद्धक्षेत्र परको जबकम्पनी द्वितीय कमान अधिकारी के दिशानिर्देश में थी औरक्षेत्र में शत्रु के गोलीबारी और शत्रु के साथ संघर्ष के समय उसी दिन 0900 बजे से 2000 बजे तक पोस्ट पर कर्तव्यरूढ़ होते हुए बिना छुट्टी उक्त पोस्ट छोड़ दिया था।

सं०—8

असम राइफल्स अधिनियम

(ज)

संतरी होते हुए, युद्ध के दौरान, अपनी चौकी पर सो जाए धारा 21

यह कि वह, तारीखकोबजे सेतक के बीच संतरी होते हुए युद्ध के दौरान

नं० (मैगजीन गार्ड की चौकी) पर सोया हुआ पाया गया।

सं०—9

असम राइफल्स अधिनियम

धारा 23 (क)

संतरी का अतिक्रमण में करना, यह कि उसने, तारीख

कोपर रैजी मेंकी सं०रैंकनामके द्वारा जो चौकी सं०पर संतरी था, अतिक्रमण न करने की चेतावनी दिए जाने के पश्चात् भी उक्त संतरी का अतिक्रमण किया था।

सं०—10

असम राइफल्स अधिनियम

धारा 23 (ख)

लूटपाट की तलाश में यह कि उसने किसी गृह में अनाधिकृत प्रवेश करना तारीख.....को.....सक्रिय सेवा में होते हुए, लूटपाट की तलाश में.....श्री.....के गृह में अनाधिकृत प्रवेश किया था।

सं०-11

असम राइफल्स अधिनियम

धारा 23 (ग)

संतरी होते हुए अपनी चौकी पर सो जाना तारीख.....को.....सक्रिय सेवा में होते हुए 0200 और 0300 बजे के बीच जब वह.....चौकी पर संतरी था, अपने पदस्थान पर सोया हुआ था।

सं०-12

असम राइफल्स अधिनियम

धारा 23 (घ)

वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के बिना अपना चौकी छोड़ना, उसने तारीख.....को.....में असम राइफल्स गार्ड के तौर पर 0500 और 0600 बजे के बीच संतरी ड्यूटी पर था, अपने वरिष्ठ अधिकारी के आदेश के बिना अपना चौकी छोड़ दिया था।

सं०-13

असम राइफल्स अधिनियम

धारा 23 (ङ)

साशय बिना किसी कारण कैम्प में झूटी अलार्म उत्पन्न करना यह कि उसने तारीख.....की कैम्प.....में, सक्रिय सेवा में होते हुए, 36 एच ई ग्रेनेड जानबूझकर विस्फोट किए, जिस कारण उक्त कैम्प में झूठा अलार्म हुआ।

सं०-14

असम राइफल्स अधिनियम

धारा 24 (क)

असम राइफल्स में विद्रोह आरम्भ करने के लिए षडयंत्र करना यह कि वे, तारीख.....को.....में, परस्पर और.....बटालियन.....की कम्पनी.....कम्पनी में विद्रोह आरम्भ करने के लिए, अर्थात्, उक्त कम्पनी को तारीख.....को.....कार्य करने के आदेश दिए गए थे, मार्च करने से इंकार करने के लिए, सहमत हुए थे।

सं०-15

असम राइफल्स अधिनियम

धारा 24 (ख)

असम राइफल्स में किसी विद्रोह में सम्मिलित होना। यहां कि उन्होंने एक साथ तारीख.....को.....में,.....कम्पनी.....(यूनिट), के कर्तव्य अन्य सिपाहियों के साथ, विद्रोहात्मक भावना से क्वार्टर गार्ड में बटालियन चाबी बॉक्स में से कोत की चाबियां निकालना चाहा, राइफल्स द्वारा एक राउण्ड यूनिट ग्राउण्ड में फायर किया और.....का नारा दिया या उस प्रभाव वाले शब्द को बोला।

सं०-16

असम राइफल्स अधिनियम

धारा 24 (ख)

असम राइफल्स में किसी विद्रोह में सम्मिलित होना, यह कि उन्होंने एक साथ तारीख.....की रात में, जब वह.....कंपनी में.....के साथ सेवारत था उक्त

यूनिट के कतिपय अन्य कार्मिकों के साथ मिलकर सरकार के गोला-बारूदों के साथ विद्रोह की मंशा से यूनिट छोड़ा।

सं०-17

असम राइफलस अधिनियम
धारा 24 (ग)

असम राइफलस में किसी विद्रोह को दबाने के लिए अपना अधिकतम प्रयास न करके, ऐसे विद्रोह में मौजूद रहना, यह कि वह, तारीख को में, उस समय मौजूद रहते हुए भी जब सिपाही सिपाही और उसी बटालियन के अन्य सिपाहियों ने, रूट मार्च पर उस समय जाने से इंकार कर दिया जब उन्हें कम्पनी कमाण्डर द्वारा ऐसा करने का आदेश दिया गया। उक्त विद्रोह को दबाने के लिए अपने अधिकतम प्रयास करने में असफल रहा।

सं०-18

प्रथम आरोप
असम राइफलस अधिनियम
धारा 25 (1)

सेवा का अभित्यजन करना
यह कि वह, तारीख को पर बटालियन से तब तक अनुपस्थित रहा जब तक कि उसे तारीख की पर सिविल पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं कर लिया गया।

द्वितीय आरोप
असम राइफलस अधिनियम
धारा 39 (क)

सरकारी सम्पत्ति की बाबत चोरी करना, यह कि वह पूर्वोक्त स्थान पर और तारीख की बटालियन से अनुपस्थित रहते हुए, एक राइफलस (वर्णन करें) कीमत की और 303 बाल गोला-बारूद के बीस राउण्ड, कीमत की जो सरकार की सम्पत्ति थी, बेईमानी पूर्वक अपने साथ लेकर, अनुपस्थित रहा।

[टिप्पण 1- नियमतः उस तारीख का और उन परिस्थितियों का सबूत देना जिनमें अनुपस्थित की कलावधि समाप्त हुई थी, न्यायालय को इस बात का विनिश्चय करने में समर्थ बनाने हेतु आवश्यक है कि अनुपस्थिति से अभित्यजन का अपराध बनता है या मात्र बिना छुट्टी के अनुपस्थित होने का। तथापि प्रायः ये तथ्य तात्त्विक नहीं हैं, और उनका सबूत लोक सेवा की अत्यधिक असुविधा के बिना और अत्यधिक विलम्ब के बिना प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में उनको साबित करने की आवश्यकता नहीं है, और इसलिए यह आवश्यक नहीं कि आरोप की विशिष्टियों में उनका प्राक्कथन किया जाए।]

टिप्पण- 2 यह अतात्विक है कि राइफल अभियुक्त को जारी की गई थी या अपने सहयोगी की है, भा० २० सं० की धारा 27 और भा० २० सं० की धारा- 378 दृष्टांत (घ) देखें।]

सं०-19

असम राइफलस अधिनियम
धारा 25 (1)

सेवा का अभित्यजन करना
तारीख को पर, बटालियन से अभित्यजन किया।

टिप्पण—इस प्रारूप का उस समय प्रयोग किया जा सकेगा जब अनुपस्थिति समाप्त होने की तारीख और परिस्थितियां तात्त्विक तथ्य नहीं हैं, और उनकी बाबत सबूत बिना अनुचित विलम्ब या व्यय के प्राप्त नहीं किया जा सकता।

सं०-20

असम राइफलस अधिनियम

सेवा का अभित्यजन करना

धारा 25 (1)

तारीख को, पर जब वह सक्रिय सेवा के आदेशाधीन था और उसे को जाने के लिए तारीख से तक अनुपस्थित रहने की छुट्टी मंजूर की गई थी उसने उक्त छुट्टी की समाप्ति पर में पुनः कार्यभार नहीं संभाला अपितु ऐसी सक्रिय सेवा से बचने के आशय से अनुपस्थित रहा।

(टिप्पण— मंजूर की गई छुट्टी के बाद भी अनुपस्थित रहना अनुकल्पी की विरचना करना सदैव उचित होगा पर्याप्त हेतु के बिना आगे आरोप देखें।)

सं०-21

असम राइफल्स अधिनियम

धारा 25 (1)

सेवा के अभित्यजन करने का प्रयत्न करना,

यह कि उसने तारीख को, में स्त्री के रूप में छिपकर सेवा का अभित्यजन करने के आशय से, अपनी बटालियन की लाइनों को छोड़ने का प्रयत्न किया।

सं०-22

असम राइफल्स अधिनियम

धारा 25 (2)

असम राइफल्स अधिनियम के अधीन व्यक्ति को, यह जानते हुए कि वह अभित्यजक है संश्रय देना,

यह कि उसने तारीख को, में, नं० रैंक नाम बटालियन को अपने घर में छिपा कर रखा जबकि उसे ज्ञात था कि वह उक्त बटालियन का अभित्यजक था।

सं०-23

असम राइफल्स अधिनियम

धारा 25 (3)

असम राइफल्स अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के

अभित्यजन होने का ज्ञान होते हुए भी तत्काल अपने या किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को उसकी सूचना न देना। यह कि उसने तारीख को, में, उसी यूनिट के नं० रैंक नाम बटालियन के अभित्यजन का ज्ञान होते हुए भी अपने या किसी अन्य वरिष्ठ अधिकारी को उसकी तुरंत सूचना नहीं दी थी।

सं०-24

असम राइफल्स अधिनियम

धारा 26 (क)

बिना छुट्टी के अनुपस्थित रहना।

यह कि वह में, तारीख से तक यूनिट की लाइन से छुट्टी के बिना अनुपस्थित रहा।

सं०-25

असम राइफल्स अधिनियम

धारा 26 (ख)

मंजूर की गई छुट्टी के उपरान्त पर्याप्त कारण के बिना

अनुपस्थित रहना।

यह कि वह, तारीख की में, जब उसे को जाने के लिए तारीख से तक छुट्टी मंजूर की गई थी, उक्त छुट्टी की समाप्ति पर तारीख की, में अपने कर्तव्य पर वापस आने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहा।

सं०-26

असम राइफल अधिनियम

धारा 26 (ग)

छुट्टी पर अनुपस्थिति के दौरान उचित प्राधिकारी से यह

सूचना मिलने पर कि उस बटालियन की, जिसका वह है, सक्रिय सेवा पर जाने का आदेश दिया गया है, अविलम्ब कार्यालय पर वापस आने में पर्याप्त हेतु के बिना असफल रहना, यह कि वह, तारीख..... की जब वह में अनुपस्थित छुट्टी पर था..... से यह सूचना मिलने पर कि बटालियन की सक्रिय सेवा के लिए आदेश दिया गया है, कर्तव्य पर अविलम्ब वापस आने में पर्याप्त कारण के बिना असफल रहा।

सं०-27

असम राइफल अधिनियम

धारा 26 (घ)

कर्तव्य के लिए नियुक्त स्थान पर, नियत समय पर,

उपस्थित होने में, पर्याप्त कारण के बिना असफल रहना। यह कि वह, तारीख..... की..... में, उस स्थान पर पी० टी० के लिए (कमान अफसर की) परेड के लिए नियत किया गया था..... बजे हाजिर होने में पर्याप्त कारण के बिना, असफल रहा था।

सं०-28

असम राइफल अधिनियम

धारा 26 (ड.)

अपने वरिष्ठ अधिकारी से इजाजत लिए बिना मार्च की

लाइन छोड़ना। यह कि वह, तारीख..... को, में, जब वह..... से..... तक प्रगमन पथ पर था, अपनी कम्पनी के कमान अधिकारी से इजाजत लिए बिना मार्च से बाहर हो गया।

सं०-29

असम राइफल अधिनियम

धारा 27 (क)

अपने वरिष्ठ अधिकारी पर आपराधिक बल का प्रयोग करना,

यह कि उसने तारीख..... को, में, बटालियन के नं०..... रैंक..... नाम..... बटालियन..... के सिर पर डंडे से आघात किया था।

सं०-30

असम राइफल अधिनियम

धारा 27 (क)

अपने वरिष्ठ अधिकारी पर हमला करना।

यह कि उसने तारीख..... को में, सक्रिय सेवा पर, जब उसे उसी यूनिट के वरिष्ठ अधिकारी नं०..... रैंक..... नाम..... में उस दिन..... बजे उसे रिपोर्ट करने का आदेश दिया गया, उसने एक पत्थर उठाया और उसे उक्त..... पर फेंक कर मारने की धमकी दी।

सं०-31

असम राइफल अधिनियम

धारा 27 (ग)

अपने वरिष्ठ अधिकारी के प्रति अनधीनता द्योतक भाषा का प्रयोग करना।

यह कि उसने तारीख..... को में उसी यूनिट के वरिष्ठ अधिकारी नं०..... रैंक..... नाम..... से कहा "तुम्हें तो सिर्फ हर रोज शराब पीना आता है। तुम बकवास आदमी हो" या इसी आशय के शब्द कहे थे।

सं०-32

असम राइफल अधिनियम

अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा अपने कर्तव्य के निष्पादन में स्वयं दिए गए

धारा 28 (1)

किसी विधिपूर्ण समादेश की ऐसी रीति से अवज्ञा करना जिससे प्राधिकारी का जानबूझकर तिस्कार करना परिलक्षित हो।

यह कि उसने तारीख को में जब उसे गार्ड कमाण्डर नं० रैंक नाम ने संतरी के पदस्थान पर जाने का आदेश दिया था तब उसने कहा "मैं नहीं जाऊंगा जो चाहे कर ले" और वह गार्ड रूम से संतरी के पदस्थान में नहीं गया।

सं०-33

असम राइफलस अधिनियम
धारा 28 (2)

अपने वरिष्ठ अधिकारी द्वारा दिए गए विधिपूर्ण समादेश की अवज्ञा करना,

यह कि उसने,

तारीख की में जब उसे उसी बटालियन के नं० रैंक नाम ने आदेश दिया कि वह अपना खाना खाले पर उसने ऐसा नहीं किया।

सं० 34

असम राइफलस अधिनियम
धारा 34

अपने वरिष्ठ आफिसर द्वारा दिए गए विधिपूर्ण समादेश को अवज्ञा

अवज्ञा करना,

यह कि उसने, तारीख को में जब उसे उसी बटालियन के नं० रैंक नाम द्वारा पी.टी. परेड के लिए खड़े होने का आदेश दिया तो उसने ऐसा नहीं किया।

सं० 35

असम राइफलस अधिनियम
धारा 29 (ख)

किसी ऐसे व्यक्ति पर, जिसकी अभिरक्षा में उसे विधिपूर्वक रखा गया

है, आपराधिक बल का प्रयोग करना,

यह कि उसने,

तारीख को में, जब उसे उसी यूनिट के नं० रैंक नाम की अभिरक्षा में नं० रैंक नाम द्वारा रखा गया तो उसने अपनी बेल्ट से *उक्त के सिर पर आघात किया।

सं० 36

असम राइफलस अधिनियम
धारा 29 (ख)

किसी ऐसे व्यक्ति पर जिसकी अभिरक्षा में उसे विधिपूर्वक

रखा गया है, आपराधिक बल का प्रयोग करना,

यह कि उसने,

तारीख को में, जब उसे पुलिस स्टेशन के सिविल पुलिस कांस्टेबल नं० नाम की अभिरक्षा में विधिपूर्वक रखा गया था तब उसके सिर पर आघात किया।

सं० 37

असम राइफलस अधिनियम
धारा 29 (ङ)

बटालियन आदेशों का पालन करने में उपेक्षा करना,

यह कि उसने,

तारीख को में, मीना बजार में प्रवेश करके बटालियन दैनिक आदेश भाग 1, सं० तारीख के पालन में उपेक्षा की जबकि उक्त आदेश से उक्त स्थान वर्जित क्षेत्र था।

सं० 38

असम राइफलस अधिनियम

सेना पुलिस के अपने कर्तव्य के निष्पादन में उसकी सहायता

धारा 29 (च)

की अपेक्षा की जाने पर उनसे इंकार करना,

यह कि उसने,

तारीख.....की.....में, मुख्यालय.....के सहायक
सेना पुलिस नं०.....रैंक.....नाम.....द्वारा उससे यह
अपेक्षा करने पर कि वह एक अपराधी नं०.....रैंक.....नाम.....
यूनिट, को गिरफ्तार करने में उसकी सहायता करें, उसने ऐसा
करने से इंकार कर दिया।

सं० 39

असम राइफल अधिनियम
धारा 31

अभ्यावेशन के समय उस आफिसर द्वारा, जिसके समक्ष कोई व्यक्ति
अभ्यावेशित किए जाने के प्रयोजन के लिए उपस्थित होता है, अभ्यावेशन के
विहित प्रारूप में उपवर्णित में से पूछे गए प्रश्न के उत्तर में जानबूझकर मिथ्या
उत्तर देना,

यह कि उसने,

तारीख.....को.....में.....असम राइफल में
सेवा के लिए अभ्यावेशित होने के प्रयोजन के लिए, जब अभ्यावेशन आफिसर,
नं०.....रैंक.....नाम.....के समक्ष उपस्थित हुआ था, उससे
पूछे गए इस प्रश्न के उत्तर में कि "क्या आपको कभी दंड न्यायालय द्वारा दोषी
दिया गया है ?" उत्तर दिया "नहीं" जब कि उसे भलीभांति जानकारी कि थी,
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, ईम्फाल, पश्चिम द्वारा तारीख.....को भारतीय
दण्ड संहिता की धारा.....के अधीन दोष सिद्ध किया गया है।

सं० 40

असम राइफल अधिनियम
धारा 32

आफिसर होते हुए ऐसी रीति से व्यवहार करना, जो उसके पद और उससे
प्रत्याशित आचरण की दृष्टि से अशोभनीय है,

यह कि उसने,

तारीख.....को.....में, पदोन्नति-परीक्षा भाग-‘जेड’ के दौरान
‘टेकिट्स’ पेपर के उत्तर लिखते समय, ‘पर्वत रक्षकों’ की सहायता करता है”
नाम सारलेखन, से प्रश्न नं० 1 के उत्तर की नकल की थी।

सं० 41

असम राइफल अधिनियम
धारा 32

आफिसर होते हुए ऐसी रीति से व्यवहार करना, जो उसके पद और उससे
प्रत्याशित आचरण की दृष्टि से अशोभनीय है,

यह कि उसने,

तारीख.....को.....में अपनी बकाया राशि, रु०.....(रु०
.....और.....मात्र) का, एक चैक अपनी यूनिट की सी.एस.
डी(आई) कैन्टिन आफिसर कैप्टन.....को दिया था जो भारतीय स्टेट
बैंक की.....शाखा.....के नाम था, जिनको प्रस्तुत किए जाने
पर भुगतान नहीं किया गया और उसने ऐसा भलीभांति यह जानते हुए किया था
कि बैंक की उक्त शाखा में उक्त चैक की राशि के बराबर पर्याप्त धन उसके
खाते में नहीं था और उसके पास यह मानने के लिए भी कोई
युक्तियुक्त आधार नहीं था कि उक्त चैक यदि प्रस्तुत किया जाएगा, तो उसका
भुगतान कर दिया जाएगा।

सं० 42

असम राइफल अधिनियम
धारा 33 (क)

अशिष्ट प्रकार का कलंकास्पद आचरण करना,

यह कि वह,

तारीख.....को.....में, लगभग 2330 बजे बुरे आशय से उसी
आशय से उसी रेजिमेंट के नं०.....रैंक.....नाम.....
के बिस्तर में घुस गया था।

सं० 43

असम राइफल्स अधिनियम

धारा 33 (ख)

रोगी होने का बहाना करना,

यह कि उसने,

तारीख.....को.....में, चिकित्सा अधिकारी कैप्टन.....से मिथ्या रूप से यह बहाना किया था कि उसका टखना उतर गया है।

सं० 44

असम राइफल्स अधिनियम

धारा 33 (ख)

रोगी होने का बहाना करना,

यह कि उसने,

तारीख.....को.....में.....बजे और.....बजे के बीच क्वार्टर गारद के सदस्य के रूप में अपने कर्तव्य से बचने के लिए गुंगेपन का रोग होने का बहाना किया।

सं० 45

असम राइफल्स अधिनियम

धारा 33 (ख)

स्वयं में रोग उत्पन्न करना,

यह कि उसने,

तारीख.....को.....में.....चिकित्सा अधिकारी.....से यह बहाना किया कि उसके सिर और कमर से नीचे अत्यधिक दर्द था, जब कि वह इस प्रकार से पीड़ित नहीं था।

सं० 46

असम राइफल्स अधिनियम

धारा 33 (ख)

निरोग होने में साशय विलम्ब करना,

यह कि उसने,

तारीख.....को.....में, जब उसकी टांग में चोट के लिए उसका चिकित्सीय उपचार चल रहा था, उक्त घाव से उसने इस आशय से पट्टियाँ हटा दी कि उसके निरोग होने में विलम्ब हो जाए और इस प्रकार उसने निरोग होने में साशय विलम्ब किया।

सं० 47

असम राइफल्स अधिनियम

धारा 33 (ग)

किसी व्यक्ति को सेवा के अयोग्य बनाने के आशय से उस व्यक्ति की

स्वेच्छा से उपहंति कारित करना,

यह कि उसने,

तारीख.....को.....में, नं०.....रैंक.....नाम.....के अनुरोध पर उक्त.....की गोली चलाने वाली अंगुली इस आशय से काट दी कि सेवा के अयोग्य हो जाए।

सं० 48

असम राइफल्स अधिनियम

रैंक में अधीनस्थ तथा असम राइफल्स अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करना,

यह कि उसने,

तारीख.....को.....में, सिपाहियों को एक स्कॉड की ड्रिल के समय उसी यूनिट के सिपाही.....के कंधे पर छड़ी से आघात किया।

सं० 49

असम राइफल्स अधिनियम

रैंक में अधीनस्थ और असम राइफल्स अधिनियम के अधीन धारा 34 के व्यक्ति के साथ बुरा बर्ताव करना,

यह कि उसने,

तारीख.....को.....में, उसी यूनिट के नं०.....रैंक.....नाम.....को, पूर्वाह्न 10 बजे से और सायं 4 बजे तक धूप में खड़ा रख कर और उक्त अवधि के दौरान उसे पाके पीने देने की अनुमति न देकर उसके साथ बुरा बर्ताव किया।

सं० 50

असम राइफल्स अधिनियम
धारा 35

मत्तता

यह कि वह,

तारीख.....को.....में, जब वह कर्तव्य पर (कर्तव्य विनिर्दिष्ट करें) था, मत्तता की दशा में था।

सं० 51

असम राइफल्स अधिनियम
धारा 36 (क)

गारद का समावेशन करने के दौरान ऐसे किसी व्यक्ति को, जो उसके भारसाधन के सुपुर्द किया गया है, उचित प्राधिकार के बिना, जानबूझकर निर्मुक्त करना,

यह कि उसने, तारीख.....को.....में, जब वह.....बटालियन के क्वार्टर गारद का समादेशक था, नं०.....रैंक.....नाम.....बटालियन को, जो उक्त क्वार्टर गारद में परिरुद्ध था उसके भारसाधन में सुपुर्द किया गया था, उचित प्राधिकार के बिना जानबूझकर निर्मुक्त कर दिया।

सं० 52

असम राइफल्स अधिनियम
धारा 36 (ख)

ऐसे व्यक्ति को जिस पर पहरा रखना उसका कर्तव्य है, युक्तियुक्त प्रति हेतु के बिना निकल भागने देना,

यह कि उसने, तारीख.....को.....में, जब वह.....बटालियन के नं०.....रैंक.....नाम.....पर संतरी के रूप में पदस्थ था तब उसने उक्त.....को युक्तियुक्त प्रतिहेतु के बिना निकल भागने दिया।

सं० 53

असम राइफल्स अधिनियम
धारा 37 (क)

परिरुद्ध व्यक्ति को विचारण के लिए पेश किए बिना अनावश्यक रूप से निरुद्ध रखना,

यह कि उसने,

तारीख.....को.....में, जब वह.....बटालियन के स्थानापन्न समादेशक आफिसर के रूप में कार्य कर रहा था तब उसने उसी यूनिट के नं०.....रैंक.....नाम.....को विचारण के लिए पेश किए बिना, तारीख.....से.....तक अनावश्यक रूप से निरुद्ध रखा।

सं० 54

असम राइफल्स अधिनियम
धारा 38

विधिपूर्ण अभिरक्षा में से निकल भागना,

यह कि वह,

तारीख.....को.....में, जब यूनिट क्वार्टर गारद में सख्त गिरफ्तारी में था तब वहां से निकल भागा।

सं० 55

असम राइफल्स अधिनियम
धारा 39 (क)

सरकारी सम्पत्ति की चोरी करना,

यह कि उसने,

तारीख.....को.....में, एक राइफल 7.62 एस एल आर, रजिस्ट्रीकृत नं०.....कीमत.....रु०, जो सरकारी सम्पत्ति थी, चोरी की।

सं० 56

असम राइफल्स अधिनियम
धारा 39(क)

असम राइफल्स अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति की सम्पत्ति की चोरी करना,
यह कि उसने,

तारीख.....को.....में, एक घड़ी की जो उसी बटालियन के नं०.....रैंक.....नाम.....की सम्पत्ति थी चोरी की।

सं० 57

असम राइफल्स अधिनियम
धारा 39(ख)

सरकार की सम्पत्ति का बेईमानी से दुर्विनियोग करना,
यह कि उसने,.....में, तारीख.....के, और.....के बीच 7.62 एस एल आर गोलाबुरुद के राउन्डों का, जो.....मूल्य सरकार की सम्पत्ति थी और जिसे.....कंपनी के टार्गेट अभ्यास के लिए उसके भारसाधन में सुपुर्द किया गया था, बेईमानी से दुर्विनियोग किया।

सं० 58

असम राइफल्स अधिनियम
धारा 39(ग)

सरकार की सम्पत्ति के बारे में आपराधिक न्यास भंग करना
यह कि उसने, तारीख.....को.....में,.....रुपए की राशि का, जो सरकार की सम्पत्ति थी और जो उसे फील्ड वर्कशाप के कमान आफिसर के रूप में सुपुर्द की गई थी, बेईमानी से दुर्विनियोग किया।

सं० 59

प्रथम आरोप असम राइफल्स अधिनियम
धारा 39 (घ)

सरकार की सम्पत्ति को यह जानते हुए कि असम राइफल्स अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा उसकी चोरी की गई थी, बेईमानी से उसे प्राप्त करना,
यह कि उसने, दिनांक.....को.....में, 70 एम.टी. के 2 जेरीकन्स, जो सरकार की सम्पत्ति थे और जिनके बारे में उसे यह जानकारी थी कि वे.....बटालियन के नं०.....रैंक.....नाम.....यूनिट.....द्वारा चुराई हुई सम्पत्ति है, बेईमानी से प्राप्त किए।

द्वितीय आरोप असम राइफल्स अधिनियम
धारा 49 (प्रथम आरोप के विकल्प में)

सुव्यवस्था और सैनिक अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कार्य करना,

यह कि उसने, दिनांक.....को.....में, 70 एम टी के दो जेरीकन्स अप्रधिकृत रूप से उसके कब्जे में पाए गए थे।

सं० 60

असम राइफल्स अधिनियम
धारा 39(ङ)

सरकार की किसी सम्पत्ति को, जो उसे न्यस्त की गई हो, जानबूझकर नष्ट करना,
यह कि उसने, दिनांक.....को.....में, एक प्रिन्सी कम्पास, जिसका मूल्य.....रु० था और जो सरकार की सम्पत्ति थी, जो उसके उपयोग के लिए न्यस्त किया गया था जानबूझकर तोड़ कर नष्ट कर दिया।

सं० 61

असम राइफल्स अधिनियम

कपट करने के आशय से असम राइफल्स अधिनियम की धारा 39 के 39(च) खण्ड (च) में वर्णित प्रकार का अपराध करना, यह कि वह तारीख.....को.....में, कपट करने के आशय से श्री.....दुकानदार से यह मिथ्या बहाना करके कि वह कैप्टन.....

यूनिट के कैप्टन, का अर्दली था और यह कि उसे उक्त कैप्टन ने सिगरेट लेने के लिए भेजा था,.....रु० के मूल्य की गोल्ड प्लैक सिगरेट के तीन पैकेट प्राप्त कर लिए।

असम राइफलस अधिनियम
धारा 39 (घ)

सं० 62

किसी व्यक्ति को हानि पहुंचाने के आशय से असम राइफलस की धारा 39 के खण्ड (घ) में वर्णित प्रकार यह कि उसने, तारीख.....को,.....में, नं०.....रैंक.....नाम.....को हानि पहुंचाने के आशय से निस्तारण पंजी वस्त्रों के मद्दे.....रु० की कटौती करके, जो कटौती उसने उक्त.....के वस्त्र लेखा में जमा नहीं की थी, बटालियन.....कंपनी.....की निस्तारण पंजी में.....(रु०) उक्त.....के नाम खाते में डाल दिए।

असम राइफलस अधिनियम
धारा 39 (घ)

सं० 63

किसी व्यक्ति को सदोष अभिलाष पहुंचाने के आशय से असम राइफलस अधिनियम की धारा 39 के खण्ड (घ) में वर्णित प्रकार, यह कि उसने, तारीख.....को,.....में, अपने यूनिट के 'बी' और 'सी' कंपनी में डिटाचमेंट क्लर्क रहने के बावजूद गलत तरीके से अपने को सदोष अभिलाष पहुंचाने के आशय से, अप्रैल 20.....क्रम सं०.....एक्यूटेटेन्स रोल में हेर फेर करके अपने नाम रु० 2000/- (रु० दो हजार मात्र) बढ़ने की जगह रु० 3000/- (रु० तीन हजार मात्र) दर्ज किया।

असम राइफलस अधिनियम
धारा 40 (क)

सं० 64

उद्दापन करना यह कि उसने, तारीख.....को,.....में, उनकी कंपनी के समादेशक आफिसर को ऐसी मिथ्या रिपोर्ट करने की धमकी देकर कि नं०.....रैंक.....नाम.....और सं०.....रैंक.....नाम.....ने मिलकर अप्राधिकृत अपराध किया है, उक्त व्यक्तियों.....में से प्रत्येक.....से रूपए.....का उद्दापन किया।

असम राइफलस अधिनियम
धारा 40 (ख)

सं० 65

उचित प्राधिकार के बिना किसी व्यक्ति से धन का आहरण करना, यह कि उसने, तारीख.....को,.....में, उसी यूनिट के नं०.....रैंक.....नाम.....से उचित प्राधिकारी के बिना.....रूपए का आहरण किया।

असम राइफलस अधिनियम
धारा 41 (क)

सं० 66

ऐसे कपड़े को, जो सरकार की संपत्ति हो और जो उसे उसके उपयोग के लिए दी गई हो उड़ा देना, तारीख.....को,.....में, उसके उपयोग के लिए दी गई कोट कॉम्बेट (मूल्य रूपए.....) जो सरकार की संपत्ति थी रु० में.....को बेच दिया।

असम राइफलस अधिनियम
धारा 41 (ख)

सं० 67

पहचान पत्र को जो सरकारी संपत्ति है और जो उसे उसके उपयोग के लिए दिया गया है उपेक्षा से गंवा देना, यह कि उसने, तारीख.....को,.....में पहचान पत्र सं०.....को जो सरकार की संपत्ति है और जो उसके उपयोग के लिए दिया गया था, उसने उपेक्षा से गंवा दिया।

असम राइफलस अधिनियम

सं०-68

पहचान पत्र जो सरकारी संपत्ति है और जो उसे उसके उपयोग

धारा 41 (ख)

के लिए दिया गया है, उपेक्षा से गवां देना।

यह कि उसने,

पहचान पत्र सं०..... जो सरकार की सम्पत्ति है और उसके उपयोग के लिए दिया गया था तारीख..... को..... में, उसके कब्जे में नहीं पाया गया।

(टिप्पण— सामान्यतः सम्पत्ति के खो जाने की तिथि और परिस्थितियों का प्रमाण प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे मामलों में आरोप की विशिष्टियों में यह प्राक्कथन आवश्यक है कि अभियुक्त के पास विनिर्दिष्ट तिथि को प्रश्नगत सम्पत्ति नहीं थी।

सं०-69

असम राइफल्स अधिनियम

धारा 42 (क)

न्यस्त किए गए गोला-बारूद को, जो सरकार की सम्पत्ति है,

युक्तियुक्त कारण के बिना नष्ट करना,।

यह कि उसने,

तारीख..... को..... में जब वह गोला-बारूद डम्प का भारसाधक अधिकारी था, उसे न्यस्त की गई सरकार की सम्पत्ति 7.62 एस. एल. आर. के गोला बारूद के 1000 राउण्ड के युक्तियुक्त कारण के बिना नष्ट कर दिए।

सं०-70

असम राइफल्स अधिनियम

धारा 43 (क)

असम राइफल्स अधिनियम के अधीन व्यक्ति के विरुद्ध यह जानते

हुए कि अभियोग मिथ्या है, अभियोग लगाना,

यह कि उसने,

तारीख..... की..... में, अपराध का जवाब देने के लिए बटालियन के समादेशक (क)..... (ख)..... के समक्ष, हाजिर होने पर निम्नलिखित आशय का कथन किया यद्यपि वह भलीभांति जानता था कि ऐसा कथन मिथ्या है अर्थात् असिस्टेंट कमाण्डेंट..... अपने काम में कोई रूचि नहीं लेता और वह पूर्णतया प्लाटून कमाण्डर के हाथों में है जो खूब रिश्वत लेते हैं और असिस्टेंट कमाण्डेंट साहब के पास पहुंचने के लिए रिश्वत के बिना किसी को जाने की अनुमति नहीं देते।

सं०-71

असम राइफल्स अधिनियम

धारा 43 (ख)

असम राइफल्स अधिनियम की धारा 16 के अधीन परिवाद में यह

जानते हुए कि कोई कथन मिथ्या है सेना अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति के चरित्र पर प्रभाव डालने वाला कथन कराना।

यह कि उसने

तारीख..... को..... में, असम राइफल्स अधिनियम की धारा 16 के अधीन केन्द्रीय सरकार के किए गए परिवाद में निम्नलिखित कथन यह भलीभांति जानते हुए किया कि कथन मिथ्या है "कमाण्डेंट यूनिट द्वारा वार्षिक प्रशिक्षण अनुदान से प्राप्त की गई धनराशि को खर्च करने में सभी प्रकार के भ्रष्ट तरीके अपना रहा है।

सं०-72

असम राइफल्स अधिनियम

धारा 44 (क)

ऐसे प्रमाणपत्र में जो उसके द्वारा हस्ताक्षरित है, जानते हुए मिथ्या

कथन करना,

यह कि उसने

तारीख..... को..... में, अपने यूनिट से..... तक..... दिनांक..... से..... तक की अवधि के लिए अपने स्थायी कर्तव्य के लिए आउट स्टेशन मेंसिंग के दावे के लिए प्रमाण पत्र में जिसमें उसने स्वयं हस्ताक्षर किए हैं यह कथन किया है कि उसे वाह्य स्थान

पर निशुल्क भोजन नहीं किया जाए जबकि वह भलीभाँति जानता था कि उक्त कथन मिथ्या है।

सं०-73

असम राइफलस अधिनियम
धारा 44 (ज)

जानते हुए और कपट करने के आशय से किसी ऐसी दस्तावेज की, जिसे परिरक्षित रखना उसका कर्तव्य है, गायब कर देना, यह कि उसने, तारीख.....की.....में, जब वह अपनी यूनिट का लेखा अधिकारी था, जानते हुए और कपट करने के आशय से यूनिट के रेजिमेंट के लेखाओं से संबंधित रोकड़ बही को, जो एक ऐसा दस्तावेज थी, जिसको परिरक्षित रखना उसका कर्तव्य था, नष्ट कर दिया।

सं०-74

असम राइफलस अधिनियम
धारा 44 (घ)

जहां किसी विषय पर घोषणा करना उस पद का कर्तव्य है, वहां जानते हुए मिथ्या घोषणा करना, यह कि उसने तारीख.....को.....में, जब वह अपनी यूनिट की वर्गीकृत दस्तावेजों का अभिरक्षक था, उसने उक्त सभी दस्तावेजों की जांच करने और सब दस्तावेज सही पाने का एक त्रैमासिक प्रमाणपत्र, वह भलीभाँति जानते हुए दिया कि उक्त दस्तावेजों में से एक गुप्त दस्तावेज सं०.....उससे गुप्त हो गया था।

सं०-75

असम राइफलस अधिनियम
धारा 44 (ड)

ऐसा मिथ्या कथन करके, जिसके मिथ्या होने की उसे जानकारी है, किसी व्यक्ति के लिए पेंशन अभिप्राप्त करना, यह कि उसने तारीख.....को.....में, जब डिप्टी कमाण्डेंट.....यूनिट.....के सम्मक्ष जो.....निवासी थी। श्री ग.....द्वारा किए गए पारिवारिक पेंशन के दावे की जांच कर रहे थे, अपनी परीक्षा में यह जानते हुए कि यह कथन मिथ्या है यह कथन किया कि वह जानता था कि उक्त श्री (ग) स्वर्गीय राइफलमैन.....बटालियन का पिता है, और इसके परिणामस्वरूप.....रूप पेंशन की पारिवारिक पेंशन उक्त श्री (ग) को स्वीकृत हो गई।

सं०-76

असम राइफलस अधिनियम
धारा 45 (क)

प्रदाय से सम्बद्ध किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करते समय किसी भाग को, जिसके लिए उसका हस्ताक्षर प्रमाणक है, कपटपूर्वक रिक्त छोड़ देना, यह कि उसने तारीख.....को.....में, जब वह उस डिपो.....का कमान अधिकारी, एम.जी.ए.आर.....था और जब वह ठेकेदार द्वारा.....पास के लिए प्रदान की गई वस्तुओं की रसीद.....माह का, पर हस्ताक्षर कर रहा था, उसने कपटपूर्वक वे साम्म खाली छोड़ दिए, जिनमें ठेकेदार से प्राप्त किए गए नए राशन की कुल मात्रा दर्शायी जानी थी।

सं०-77

असम राइफलस अधिनियम
धारा 46 (ग)

असम राइफलस न्यायालय द्वारा वैध रूप से अपेक्षित किसी दस्तावेज जो उसके नियंत्रण में और जिसके पेश किए जाने की अपेक्षा की गई थी, करने से इंकार करना। यह कि उसने

तारीख.....को.....में, जब यह एक साक्षी था नं०.....
 रैंक.....नाम.....यूनिट.....द्वारा उसको लिखे गए
 तारीख.....के पत्र को जो उसके नियंत्रण में था उस समय पेश करने से
 इंकार कर दिया जब उक्त.....का विचारण करने वाले समरी असम
 राइफलस न्यायालय ने उससे (अभियुक्त) से उसे पेश करने की वैध रूप से
 अपेक्षा की।

असम राइफलस अधिनियम
 धारा 46 (ड.)

सं०-78

अपमानकारी भाषा का प्रयोग करके सेना न्यायालय का अपमान
 करना।

यह कि उसने,
 तारीख.....को.....में, जब उसका जनरल सेना न्यायालय द्वारा
 विचारण किया जा रहा था, तो जोर की आवाज में कहा, "प्रतिरक्षा करने का
 मुझे कोई फायदा नहीं है।" संयोजक अधिकारी ने न्यायालय को कह दिया है
 कि मुझे दोषसिद्ध करें और यह वास्तव में ऐसा ही करेगा, या इसी आशय के
 कुछ शब्द कहे थे।

सं०-79

असम राइफलस न्यायालय के समक्ष सम्यक् रूप से प्रतिज्ञान करके
 कोई ऐसा कथन कहना, जिसके मिथ्या होने का उसे ज्ञान है,

यह कि उसने,
 तारीख.....को.....में, जब लघु असम राइफलस न्यायालय
 के समक्ष साक्षी के रूप में उसकी परीक्षा की गई, निष्ठापूर्वक प्रतिज्ञान करके
 यह कहा कि राइफलमैन.....यूनिट.....का राइफलमैन.....
जो वह व्यक्ति है जिस पर उक्त न्यायालय के समक्ष आरोप लगाया गया है,
 दिनांक.....को 0200 बजे और 0500 बजे के बीच उसकी (साक्षी के
) साथ था जबकि वह भली भांति जानता था कि उक्त कथन मिथ्या था।

असम राइफलस अधिनियम
 धारा 48

सं०-80

असम राइफलस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति का वेतन प्राप्त
 करके, उसे शोध्य होने पर, विधि विरुद्ध रोके रखना,

यह कि उसने,
 तारीख.....को.....में, यूनिट के नं०.....रैंक.....
नाम.....की बाबत.....मास के लिए अग्रिम वेतन के रूप
 में.....रुपए प्राप्त करके उक्त.....को वह वेतन देने से तारीख.....
को विधि विरुद्ध तथा इंकार कर दिया।

असम राइफलस अधिनियम
 धारा 49

सं०-81

सुव्यवस्था और सैनिक अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव जानने वाला
 कार्य करना,

यह कि उसने
 तारीख.....को.....में, अपने कमांडेट नं०.....रैंक.....
नाम.....की अनुचित रूप से एक अनाम पत्र लिखा और भेजा
 था जिसमें उसने निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया था, अर्थात्.....

असम राइफलस अधिनियम
 धारा 49

सं०-82

सुव्यवस्था और सैनिक अनुशासन पर प्रभाव डालने वाला कार्य करना,

यह कि उसने,
 तारीख.....को.....में, यान सं०.....3x टन
 की, जो सरकारी सम्पत्ति थी, इतनी उपेक्षापूर्वक चलाया जिससे उक्त यान की...
रुपये की राशि का नुकसान हुआ।

असम राइफलस अधिनियम
 धारा 49

सं०-83

यह कि उसने,
 तारीख.....को.....में, जब वह सार्वजनिक धन की
 देखरेख से संबंधित था, उसने अपने कर्तव्यों का पालन इतनी उपेक्षापूर्वक किया
 कि वह उक्त धनराशि में से.....रुपए का हिसाब देने में असमर्थ रहा।

असम राइफल अधिनियम
धारा 49

सं०-84

ऐसा लोप जो सुव्यवस्था और सैनिक अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है,
यह कि उसने
तारीख.....और.....के बीच.....में, अपनी राइफल
इतनी उपेक्षापूर्वक उठाई कि वह चल गई और उससे यूनिट के नं०.....
रैंक.....नाम.....को क्षति पहुंची।

असम राइफल अधिनियम
धारा 49

सं०-85

सुव्यवस्था और सैनिक अनुशासन पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला
कार्य करना,
यह कि उसने
तारीख.....को.....में, जब वह प्रोमोति परीक्षा भाग जेड
के पत्र-II—टेक्टिकस में सम्मिलित हो रहा था, तो उसके कब्जे में टेक्टिकस
पर एक संक्षिप्ति (प्रेसी) मिली।

असम राइफल अधिनियम
धारा 50 (ख)

सं०-86

पूजा के किसी स्थान को अपवित्र करके किसी व्यक्ति की धार्मिक
भावना को साशय ठेस पहुंचाना,
यह कि उसने
तारीख.....को.....गांव की मंदिर.....में
जानबूझकर जूते (बूट) पहनकर प्रवेश किया, और ऐसे में उक्त मंदिर पर कलंक
लगाया, गांव के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची।

असम राइफल अधिनियम
धारा 50 (ग)

सं०-87

आत्महत्या करने का प्रयत्न करना और ऐसे प्रयत्न में अपराध करने की
दशा में कोई कार्य करना,
यह कि उसने,
तारीख.....को.....में, टिक 20 बोटल पीकर आत्महत्या
करने का प्रयत्न किया।

असम राइफल अधिनियम
धारा 50 (ड)

सं०-88

सेवा में किसी व्यक्ति के लिए अनुपस्थिति छुट्टी प्राप्त करने हेतु
लिए कोई परितोषण अभिप्राप्त करना,
यह कि उसने,
तारीख.....को.....में, "क" कम्पनी के सीएचएम के
कर्तव्यों का पालन करते समय, अगली कम्पनी के नं०.....रैंक.....
नाम.....से उसके लिए तारीख.....से.....तक
की उक्त अनुपस्थिति छुट्टी प्राप्त करने के लिए 500 रुपए का परितोषण
लिया।

असम राइफल अधिनियम
धारा 50 (ड)

सं०-89

किसी व्यक्ति के अभ्यावेशन के लिए इनाम के रूप में अपने लिए कोई
परितोषण अभिप्राप्त करने का प्रयत्न करना।
यह कि उसने,
तारीख.....को.....में, असम राइफल भर्ती रेली के
अभ्यावेशन में लिपिक के रूप में कार्य करते समय, श्री क, ख, का अभ्यावेशन
प्राप्त करने में इनाम के रूप में 2000/-रुपए का परितोषण अभिप्राप्त करने का
प्रयत्न उक्त श्री क, ख से उक्त राशि मांगी।

असम राइफल अधिनियम
धारा 50 (च)

सं०-90

उस देश के, जिसमें वह सेवा कर रहा है, किसी निवासी की
सम्पत्ति के विरुद्ध कोई अपराध करना,
यह कि उसने

तारीख.....को.....में.....के निवासी.....
की मोटरकार के एक टायर में चाकू मार कर उसे विद्वेष पूर्वक क्षति पहुँचाई।

असम राइफलस अधिनियम
धारा 51

सं०-91

भारत के असम राइफलस में विद्रोह उत्प्रेरित करने का प्रयत्न करना और ऐसा प्रयत्न करने में वह अपराध कारित करने की दिशा में कोई कार्य करना,
यह कि उसने,
तारीख.....को.....में, अनायुक्त अधिकारियों और कम्पनी के आदमियों को एक साथ इकट्ठा होने के लिए और खाना खाने से इंकार करने के लिए और उक्त यूनिट के कमांडेंट नं०.....रैंक.....नाम.....से यह मांग करने के लिए उत्प्रेरित किया कि नं०.....रैंक.....नाम.....को, उसके नियोजन से हटाया जाए और उस उद्देश्य से वफादार.....और शाबास.....तथा.....को निम्नलिखित शब्दों से.....संबोधित किया (प्रयोग की गई भाषा का उल्लेख करें।)

असम राइफलस अधिनियम
धारा 51

सं०-92

असम राइफलस अधिनियम की धारा 27 में विनिर्दिष्ट अपराध का दुष्प्रेरण करना जिसके परिणामस्वरूप ऐसा अपराध किया गया,
यह कि उसने,
तारीख.....को.....में, उसी यूनिट के नं०.....रैंक.....नाम.....को उसी यूनिट के नायब सुबेदार.....पर प्रहार करने के लिए दुष्प्रेरित किया जिसके परिणामस्वरूप उक्त.....ने उक्त अधीनस्थ अधिकारी के सिर पर लाठी से प्रहार किया।

असम राइफलस अधिनियम
धारा 53

सं०-93

असम राइफलस अधिनियम की धारा 25 के अधीन मृत्यु से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण करना जिसके परिणामस्वरूप ऐसा अपराध नहीं किया गया।
यह कि उसने
तारीख.....को.....में, जब वह सक्रिय सेवा में था, उसी यूनिट के नं०.....रैंक.....नाम.....को सेवा का अभित्यजन करने के लिए दुष्प्रेरित किया पर उक्त.....ने अपराध नहीं किया।

असम राइफलस अधिनियम
धारा 54

सं०-94

असम राइफलस अधिनियम की धारा 39 में विनिर्दिष्ट और कारावास से दण्डनीय अपराध का दुष्प्रेरण पर जिसके परिणामस्वरूप ऐसा अपराध नहीं किया गया,
यह कि उसने,
तारीख.....को.....में, नं०.....रैंक.....नाम.....को जो उसी यूनिट के नं०.....रैंक.....नाम.....के वैट मैन के रूप में कार्य कर रहा था उक्त.....के ट्रांजिस्टर की चोरी करने के लिए दुष्प्रेरित किया पर उक्त राइफलमैन ने वह नहीं किया।

असम राइफलस अधिनियम
धारा 55

सं०-95

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 304 क के अधीन सिविल अपराध करना, अर्थात् उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण ऐसे कार्य से मृत्यु कारित करना जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आता।
यह कि उसने,
तारीख.....को.....यान सं०.....को उतावलेपन से या उपेक्षापूर्वक चलाकर एक सिविलियन श्री.....की मृत्यु कारित की।

सं०-96

असम राइफलस अधिनियम
धारा 55

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के अधीन सिविल अपराध करना,
अर्थात् हत्या करना,
यह कि उसने,
तारीख.....को.....में, अपने यूनिट के नं०.....रैंक.....
नाम.....की मृत्यु कारित करके हत्या की।

असम राइफलस अधिनियम
धारा 55

सं०-97

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 147 के अधीन सिविल अपराध करना,
अर्थात् बतवा करना,
यह कि वह,
तारीख.....को.....में, ऐसे विधिविरुद्ध जमाव का सदस्य
था जिसने ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को अग्रसर करने में अर्थात् सिविल
पुलिस पर आपराधिक, बल का प्रयोग करने के लिए सिविल पुलिस को लाठियों
से मारा और इस प्रकार बन्दे का अपराध किया।

असम राइफलस अधिनियम
धारा 55

सं०-98

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के अधीन सिविल अपराध करना,
अर्थात् हत्या करने का प्रयत्न करना,
यह कि उसने,
तारीख.....को.....में, उसी यूनिट के नं०.....रैंक.....
नाम.....की हत्या करने के आशय से उस पर अपनी
राइफल से दो बार गोली चलाई और उससे उसकी दाहिने कान और बाई
जांघ को घायल कर दिया।

असम राइफलस अधिनियम
धारा 55

सं०-99

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 325 के सिविल अपराध करना, अर्थात्
स्वेच्छा और उपहति कारित करना।
यह कि उसने,
तारीख.....को.....में, उसी यूनिट के नं०.....रैंक.....
नाम.....की बाई भुजा को लोहे की छड़ से तोड़कर
स्वेच्छा और उपहति कारित की।

असम राइफलस अधिनियम
धारा 55

सं०-100

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 379 के अधीन सिविल अपराध करना,
अर्थात् चोरी करना,
यह कि उसने,
तारीख.....को.....में, सदर बाजार में श्री.....की
दुकान से एक टिन घी ली, जो उक्त श्री.....की सम्पत्ति थी, और
जिसका मूल्य.....रुपए था चोरी किया।

असम राइफलस अधिनियम
धारा 55

सं०-101

भारतीय दण्ड संहिता की धारा 354 के अधीन सिविल अपराध करना,
अर्थात् किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल
का प्रयोग करना,
यह कि उसने,
तारीख.....को.....में, श्री.....की पत्नी श्रीमती.....
की लज्जा भंग करने के आशय से उसकी जांघ पर सीधा हाथ
रखकर आपराधिक बल का प्रयोग किया।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**NOTIFICATION**New Delhi, the 15th December, 2008

G.S.R. 816 (E).— In exercise of the powers conferred by proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, as annexed, namely:—

1. (1) These rules may be called the Assam Rifles Rules, 2008.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- (3) These rules shall apply to all persons subject to the Assam Rifles Act, 2006.

[File No. L-11011/1/2007/-Pres.III]

V.N. GAUR, Jt. Secy. (Police)

ASSAM RIFLES RULES, 2008

In exercise of the powers conferred by Section 165 of the Assam Rifles Act, 2006, (47 of 2006) and in supersession of the Assam Rifles Rules, 1985, the Central Government hereby makes the following rules, namely,—

CHAPTER - I**PRELIMINARY**

1. Short title, commencement and application.— (1) These rules may be called the Assam Rifles Rules, 2008.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(3) These rules shall apply to all persons subject to the Act.

2. Definitions.— In these Rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Assam Rifles Act, 2006.

(b) “Appendix” means any appendix annexed to these rules;

(c) “appointment” means appointment of a person to the Force including enrolment;

(d) “Court” means the Force Court;

(e) “Detachment” includes any part of a unit of the Force required or ordered to proceed on duty away from headquarters;

(f) “Force authority” when used in relation to any power, duty, act or matter, means such Force authority as, in pursuance of these rules, exercises, or performs that power or duty or is concerned with that matter.

(g) “Section” means a Section of the Act;

(h) all other words and expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the same meaning as respectively assigned to them in the Act.

3. Reports and applications.— Any report or application required to be made under these rules to a superior authority or to a Force authority shall be made in writing through proper channel unless the said authority on account of exigencies of service or otherwise, dispenses with the writing.

4. Forms in appendices.— (1) The forms set forth in the appendices, with such variations as the circumstances of each case may require, may be used for the respective purposes therein mentioned, and if used shall be sufficient, but a deviation from such forms shall not, by reason only of such deviation, render invalid any charge, warrant, order, proceedings or any other document relevant to these rules.

(2) Any omission of any such Form shall not, by reason only of such omission render any act or thing invalid.

(3) The directions in the notes to, and the instructions in the form, shall be duly complied with in all cases to which they relate but any omission to comply with any such direction in the notes or instructions shall not, merely by reason of such omission, render any act or thing invalid.

5. Exercise of power vested in holder of an office in the Force.— Any power or jurisdiction given to any person holding any office in the Force to do any act or thing to, or before, any person, may, for the purposes of these rules, be exercised by any other person who may, for the time being, be performing the functions of that office in accordance with the rules and practice of the Force.

6. Cases unprovided for.— In regard to any matter not specifically provided for in these rules, it shall be lawful for the competent authority to do such thing or take such action as it may deem fit and just in accordance with exigencies and circumstances of the case.

CHAPTER - II ORGANISATION

7. Constitution of the Force.— The Assam Rifles shall consist of—

(1) Officers, subordinate officers and enrolled persons appointed to or enrolled into the Assam Rifles who shall be liable for continuous service for the term mentioned in their enrolment form, letter of appointment or in the rules made in this behalf.

(2) Deputationist officers and other personnel appointed to the Assam Rifles who shall serve for the term mentioned in their letter of appointment.

8. The task of the Force and command and control thereto.— (1) For the purpose of sub-Section (1) of Section 4, the Force shall,—

(i) safeguard the security of borders of India and promote sense of security among the people living in border areas;

(ii) prevent trans-border crimes, smuggling, unauthorized entry into or exit from the territory of India and any other illegal activity;

(iii) provide security to sensitive installations, banks, persons of security risk;

(iv) restore and preserve order in any area in the event of disturbance therein.

(2) In discharging the function under sub-rule (1), the responsibility for the command, discipline, administration, morale and training shall—

(a) in the case of Additional Director-General extend to all battalions, units headquarters, establishments and Force personnel placed under him and within the area that may be assigned to him;

(b) in the case of Inspector-General extend to all battalions, units headquarters, establishments and the Force personnel placed under him and within the area that may be assigned to him;

(c) in the case of Deputy Inspector-General and Additional Deputy Inspector-General extend to battalions, units and other personnel placed under him and within the area that may be assigned to him;

(d) in the case of Commandant extend to the battalion or unit placed under him and within the area assigned to him.

(3) During hostilities, the Inspector-General, the Deputy Inspector-General, Additional Deputy Inspector-General and the Commandant shall discharge such functions as may be assigned to them by their respective superiors.

(4) The command, discipline, administration, morale and training of battalion, units and establishment not placed under an Additional Deputy Inspector-General, Deputy Inspector-General or an Inspector-General shall be carried out by such officers and in such manner as may be laid down by the Director-General from time to time.

(5) Any member of the Force shall be liable to perform any duties in connection with the task of the Force mentioned in rule 8 (1), the administration, discipline, training and welfare of the Force and such other duties as he may be called upon to perform in accordance with any law for the time being in force. Any order given in this behalf by a superior officer shall be lawful command for the purpose of the Act.

9. Command.— (1) An officer appointed to command shall have the power of command over all officers and men, irrespective of seniority, placed under his command.

(2) (a) in the contingency of an officer being unable to exercise the command, to which he has been appointed, due to any reason, the command shall devolve on the second-in-command, if one has been so appointed.

(b) if no second-in-command, has been so appointed, it shall devolve on the officer who may be appointed to officiate by the immediate superior of the officer unable to exercise command.

(c) if no such officer has been so appointed, command shall devolve on the senior most officer present.

(d) the inability of an officer to exercise command and its assumption by any other officer in accordance with this sub-rule shall be immediately reported to the next higher authority by the officer who has assumed such command.

(3) If persons belonging to different units are working together—

(a) in regard to the specific task on which they are engaged, the officer appointed to command or in his absence the senior most officer present shall exercise command over all such persons;

(b) in all other matters the senior officer belonging to each unit shall exercise command over persons belonging to his unit.

(4) When officers and other persons belonging to the Force are taken prisoner by an enemy the existing relations of superior and subordinate and the duty of obedience shall remain unaltered and any person guilty of indiscipline or insubordination in this behalf shall, after his release, be liable for punishment.

(5) Subject to the provisions of the Act, disciplinary powers over a person subject to the Act shall be exercised by the officer not below the rank of Commandant of the battalion or unit to which such a person belongs or the officer on whom command has devolved in accordance with sub-rule (2).

(6) Where such a person is doing detachment duty, including attendance at a course of instruction, an officer not below the rank of Commandant of the unit, centre or establishment with which he is doing such duty shall also have all the disciplinary powers of a Commandant.

(7) The Director-General, the Additional Director-General, the Inspector-General, the Deputy Inspector-General and the Additional Deputy Inspector-General may specify one or more officers of the staff who shall exercise the powers of the Commandant respectively in respect of persons belonging to or doing detachment duty at his Headquarters.

(8) The Director-General may also specify officers who shall exercise the disciplinary powers of an Inspector-General, and Deputy Inspector-General or Additional Deputy Inspector-General respectively in respect of persons belonging to or doing detachment duty at his Headquarters.

(9) An Inspector-General may specify an officer who shall exercise the disciplinary powers of a Deputy Inspector-General or Additional Deputy Inspector-General in respect of persons belonging to or doing detachment duty at his Headquarters.

Explanation.— In sub-rules (1), (2) and (3) the word “officer” shall include a subordinate officer and an under officer.

CHAPTER - III

RECRUITMENT

10. Ineligibility.— (1) No person, who has more than one wife living or who having a spouse living marries in any case in which such marriage is void by reason of it taking place during the life time of such spouse, shall be eligible for appointment, enrolment, or employment in the Force.

(2) Any person subject to the Act, who contracts or enters into a second marriage during the life time of his first spouse, shall render himself ineligible for retention in service and may be dismissed, removed or retired from service on ground of unsuitability :

Provided that the Central Government may, if satisfied that there are sufficient grounds for so ordering, exempt any person from the operation of this rule.

11. Ineligibility of aliens.— No person who is not a citizen of India shall, except with the consent of the Central Government signified in writing, be appointed, enrolled or employed in the Force :

Provided that nothing contained in this rule shall bar the appointment, enrolment or employment of a subject of Nepal or Bhutan in the Force.

12. Appointment of officers.— The Central Government may appoint such persons as it considers to be suitable as officers in the force in the following manner, and their conditions of service shall be such as may be provided in the rules made in this behalf by the Central Government —

(a) by direct recruitment;

(b) by transfer on deputation from the Defence Forces, any other armed forces of the Union or any other department of the Central Government or of the State Government;

(c) by promotion as may be prescribed from time to time;

(d) by transfer;

(e) by reemployment.

13. Appointment of subordinate officers and enrolled persons.— Appointment to the posts of Subedar-Majors or Subedars may be made by the Inspector-General and Naib-Subedars or of under officers by the Deputy Inspector-General or Additional Deputy Inspector-General, and of enrolled persons by the commandant or any other officer of the Force who may be appointed as enrolling officer by Director-General respectively in the following manner and their conditions of service shall be such as may be provided in the rules by the Central Government in this behalf—

(a) by direct recruitment;

(b) by transfer on deputation from the Defence Forces and other armed forces of the Union, any other department of the Central Government or of the State Government;

(c) by promotion as may be prescribed from time to time;

(d) by transfer;

(e) by re-employment.

14. Probation.— (1) A person appointed through direct recruitment as an officer, subordinate officer, or enrolled person shall be on probation for a period of two years.

(2) The Central Government in the case of officers and the authority prescribed in rule 13 in the case of subordinate officers and enrolled persons may, for the reasons to be recorded in writing, extend the period of probation for such further period or periods not exceeding two years or may during the period of probation terminate his services without assigning any reasons.

(3) The provision of sub-rules (1) and (2) shall also be applicable to a person on his initial promotion as an officer. Persons who do not complete the period of probation satisfactorily are liable to be reverted to their former rank.

15. Procedure for enrolment, mode of enrolment and other matters connected therewith. (1) Before a person is enrolled as a member of the Force, the Commandant of a unit or any other officer who may be appointed as an enrolling officer by the Director-General, shall read and explain to him, or cause to be read and explained to him in his presence, the conditions of service of the post to which he is to be enrolled and shall put him the questions contained in the form of enrolment as set out in Appendix-I and shall, after having cautioned him that if he makes a false answer to any such question he shall be liable to punishment under the Act, record or cause to be recorded his answer to each such question.

(2) If, after complying with the provisions of sub-rule (1) and such other directions as may be issued in his behalf by the Director-General from time to time, the enrolling officer is satisfied that the person desirous of being enrolled, fully understands the questions put to him and consents to the conditions of service, and if the said officer is satisfied that there is no impediment, he shall sign and shall also cause such person to sign the enrolment form and such person shall thereupon be deemed to be enrolled.

(3) (a) Every person enrolled as a member of the Force under sub-rule (2) shall be administered an oath or affirmation in the form set out in Appendix I.

(b) The oath or affirmation shall as far as possible be administered by an officer not below the rank of Commandant or an officer authorised in writing by such officer in this behalf

(c) The oath or affirmation shall be administered when the person to be attested has successfully completed his training and found fit in all respect.

16. Liability of service.— (1) All officers are liable for service with any other Armed Force of the Union as may be directed by the Central Government. In selecting officers for such service preference may be given to volunteers but if the requisite number of suitable volunteers is not forthcoming, officers may be sent on transfer on deputation or detailed otherwise as considered necessary, by the Central Government.

(2) The provisions of this rule shall apply to and in relation to subordinate officers and enrolled persons as they apply to and in relation to any officer of the Force and the powers vested in the Central Government under sub-rule (1) shall be exercised by the Director-General.

CHAPTER - IV TERMINATION OF SERVICE

17. Termination of service.— Authorities specified in the headings of columns 3 to 6 of the table given below shall be competent to dismiss, remove, discharge, retire or release a member of the Force specified in the columns, on the grounds stated in the corresponding entries in column 2, in accordance with the procedure laid down in this Chapter. Any power conferred by this rule or any provisions of this Chapter on any of the aforesaid authorities may also be exercised by any other authority superior to it :

Provided that the provisions of this Chapter shall not apply to the persons on deputation with the Force.

TABLE

Sl. No.	Grounds on which service can be terminated	Central Government	Inspector General	DIG/ADIG	Commandant
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(i)	Misconduct	Officers	Subedar-Major and Subedar	Naib-Subedar.	Enrolled Person.
(ii)	Unsuitability	Officers	Subedar-Major and Subedar	Naib-Subedar.	Enrolled Person.
(iii)	Unsatisfactory progress in training	Officers	Subedar-Major and Subedar	Naib-Subedar.	Enrolled Person.
(iv)	Furnishing false/wrong information at the time of appointment/enrolment	Officers	Subedar-Major and Subedar	Naib-Subedar.	Enrolled Person.
(v)	Physical unfitness	Officers	Subedar-Major and Subedar	Naib-Subedar.	Enrolled Person.
(vi)	On own request	Officers	Subedar-Major and Subedar	Naib-Subedar.	Enrolled Person.

18. Termination of service of officers by the Central Government on account of misconduct.— (1) When it is proposed to terminate the service of an officer under Section 10 on account of misconduct, he shall be given an opportunity to show cause in the manner specified in sub-rule (2) against such action :

Provided that this sub-rule shall not apply—

(a) Where the service is terminated on the ground of conduct which has led to his conviction by a criminal court or a Force Court; or

(b) Where the Central Government is satisfied that for reasons to be recorded in writing, it is not expedient or reasonably practicable to give to the officer an opportunity of showing cause.

(2) When after considering the reports on an officer's misconduct, the Central Government or Director-General is satisfied that the trial of the officer by a Force Court is inexpedient or impracticable, but is of the opinion, that the further retention of the said officer in the service is undesirable, the Director-General shall so inform the officer together with particulars of allegations and report of investigation (including the statement of witnesses, if any, recorded and copies of document, if any, intended to be used against him) in cases where allegations have been investigated and he shall be called upon to submit in writing, his explanation and defence :

Provided that the Director-General may withhold disclosure of such report or portion thereof if, in his opinion, its disclosure is not in the interest of the security of the State.

(3) In the event of the explanation of the officer being considered unsatisfactory by the Director-General, or when so directed by the Central Government, the case shall be submitted to the Central Government with the officer's defence and the recommendation of the Director-General for termination of the officer's service in the manner specified in sub-rule (4).

(4) When submitting a case to the Central Government under the provisions of sub-rule (2) or sub-rule (3), the Director-General shall give reasons for his recommendation whether the officer's service should be terminated, and if so, whether the officer should be —

- (a) dismissed from the service; or
- (b) removed from the service; or
- (c) compulsorily retired from the service.

(d) called upon to resign.

(5) The Central Government, after considering the reports and the officer's defence, if any, or the judgment of the criminal court or the proceedings of the Force Court, as the case may be, and the recommendation of the Director-General, may dismiss or remove the officer or retire or call upon him to resign from service, and on his refusal to do so, the officer may be compulsorily retired or removed from the service.

19. Termination of service of officers by the Central Government on grounds of unsuitability.— (1) When the Director-General is satisfied that an officer is unsuitable to be retained in service, the officer—

(a) shall be so informed;

(b) shall be furnished with the particulars of all matters adverse to him; and

(c) shall be called upon to urge any reasons he may wish to put forward in favour of his retention in the service :

Provided that clause (a), (b) and (c) shall not apply, if the Central Government is satisfied that for reasons, to be recorded by it in writing, it is not expedient or reasonably practicable to comply with the provisions thereof :

Provided further that the Director-General may not furnish to the officer any matter adverse to him, if in his opinion, it is not in the security of the State to do so.

(2) In the event of the explanation being considered by the Director-General unsatisfactory, the matter shall be submitted to the Central Government for orders, together with the officer's explanation and the recommendation of the Director-General as to whether the officer should be called upon to retire or resign.

(3) The Central Government after considering the reports, the explanation, if any, of the officer and the recommendation of the Director-General, may call upon the officer to retire or resign and on his refusing to do so, the officer may be compulsorily retired from the service.

20. Termination of service of persons, other than officers on account of misconduct.— (1) When it is proposed to terminate the service of a person subject to the Act other than an officer, he shall be given an opportunity by the authority competent to dismiss or remove him to show cause in the manner specified in sub-rule (2) against such action :

Provided that this sub-rule shall not apply—

(a) where the service is terminated on the ground of conduct which has led to his conviction by a Criminal Court or a Force Court; or

(b) where the authority as specified in rule 17 is satisfied that, for reasons to be recorded in writing, it is not expedient or reasonably practicable to give the person concerned an opportunity of showing cause.

(2) When after considering the reports on the misconduct of the person concerned, the authority as specified in rule 17 is satisfied that the trial of such a person by the Force Court is inexpedient or impracticable, but is of the opinion, that his further retention in the service is undesirable, it shall so inform him together with all reports adverse to him and he shall be called upon to submit, in writing, his explanation and defence :

Provided that the authority as specified in rule 17 may withhold from disclosure any such report or portion thereof, if in his opinion, its disclosure is not in the interest of security of the State.

(3) The authority as specified in rule 17 after considering his explanation and defence, if any, or the judgment of the criminal court or the proceedings of the Force Court, as the case may be, may dismiss or remove him from service.

(4) All cases of dismissal or removal, under this rule, shall be reported to the Director-General.

21. Discharge from service on grounds of unsatisfactory progress in training.— (1) When it is proposed to discharge a person subject to the Act from service on account of unsatisfactory progress in training, the Commandant of training establishment where the person is undergoing training, shall make recommendation for suitable action to the Commandant of the battalion or unit to which such person belongs for his discharge from service.

(2) In all cases of recommendations for discharge of a person, the Commandant of the training establishment shall establish clearly the fact that the person has been given suitable warning and sufficient time to show progress, documentary evidence to this effect shall accompany the recommendation.

(3) The Central Government or as the case may be, the authority as specified in rule 17, on receipt of recommendation under sub-rule (1), may discharge or release the person concerned from the service.

22. Termination of service on grounds of furnishing false or incorrect information at the time of appointment or enrolment.—The Central Government, or as the case may be, the authority as specified

in rule 17, may terminate the service of a person subject to the Act on grounds of furnishing false or incorrect information at the time of appointment or enrolment of that person in the service :

Provided that action under this rule shall not be taken without the competent authority giving the person concerned a show cause notice giving one month time to urge grounds, if any, in his defence, and his explanation being found unsatisfactory.

23. Retirement or discharge or release of officers on grounds of physical unfitness.— (1) Where an officer not below the rank of Deputy Inspector-General considers that an officer of the Force is unfit to perform his duties because of his physical condition, the officer shall be brought before a medical board.

(2) The medical board shall consist of such officers and shall be constituted in such manner as may, from time to time, be laid down by the Director-General.

(3) Where the officer is found to be unfit by the medical board for further service, the Central Government shall, if it agrees with the findings of the medical board, communicate to the said officer the findings of the medical board and thereupon, within a period of thirty days of such communication, the officer may make a representation against it to the Central Government supported by a *prima-facie* evidence of error of judgment in the opinion expressed by the medical board. Such an evidence should be from a government doctor not below the status of civil surgeon and should contain specific mention that he has taken into consideration the findings of the medical board before giving his opinion.

(4) The Central Government may, on receiving the representation from the officer, refer the case to be reviewed by a fresh medical board constituted for the purpose and order the retirement or discharge or release of the said officer if the decision of the fresh medical board is adverse to him.

(5) Where no representation is made against the decision of the medical board under sub-rule (3), the Central Government may, if it agrees with the findings of the medical board, order the retirement or discharge or release of the officer.

24. Termination of service of subordinate officers by the authorities as specified in rule 17 on grounds of unsuitability.— (1) Where an officer not below the rank of Commandant is satisfied that a subordinate officer is unsuitable to be retained in service, the subordinate officer shall be—

- (a) so informed;
- (b) furnished with the particulars of all matters adverse to him; and
- (c) called upon to urge any reasons he may wish to put forward in favour of his retention in the service :

Provided that clauses (a), (b) and (c) shall not apply, if the authority as specified in rule 17, is satisfied that for reasons to be recorded by it in writing, it is not expedient or reasonably practicable to comply with the provisions thereof :

Provided further that such competent authority may not furnish to the subordinate officer any matter adverse to him, if in his opinion, it is not in the interest of the security of the State to do so.

(2) In the event of the explanation being considered by the officer not below the rank of Commandant unsatisfactory, the matter shall be submitted to the authority as specified in rule 17 for orders together with the subordinate officer's explanation and the recommendation of such officer.

(3) The authority as prescribed in rule 17 after considering the report and the explanation, if any, of the subordinate officer and the recommendations of the officer not below the rank of Commandant, may call upon the subordinate officer to retire or resign and on his refusing to do so, the subordinate officer may be compulsorily retired or discharged from the service.

25. Termination of service of enrolled persons on grounds of unsuitability.— (1) Where a Commandant is satisfied that an enrolled person is unsuitable to be retained in the service, the enrolled person shall be—

- (a) so informed;
- (b) furnished with the particulars of all matters adverse to him; and
- (c) called upon to urge any reasons he may wish to put forward in favour of his retention in the service:

Provided that clauses (a), (b) and (c) shall not apply, if the Commandant is satisfied that for reasons to be recorded in writing, it is not expedient or reasonably practicable to comply with the provisions thereof;

Provided further that the Commandant may not furnish to the enrolled person any matter adverse to him, if in his opinion, it is not in the interest of the security of the State to do so.

(2) After considering the explanation, if any, the Commandant, may call upon the enrolled person to retire or resign and on his refusing to do so, the enrolled person may be compulsorily retired or discharged from the service.

26. Retirement or discharge of subordinate officers and enrolled persons on grounds of physical unfitness.— (1) Where a Commandant is satisfied that a subordinate officer or an enrolled person is unable to perform his duties by reason of his physical disability, he may direct that the said subordinate officer or enrolled person, as the case may be, be brought before a medical board.

(2) The medical board shall consist of such officers and shall be constituted in such manner as may, from time to time, be laid down by the Director-General.

(3) Where the said subordinate officer or the enrolled person is found by the medical board to be unfit for further service in the Force, as the case may be, the authority as specified in rule 17 shall, if it agrees with the findings of the medical board, communicate to the said person the findings of the medical board and thereupon, within a period of thirty days of such communication, the person may make a representation against it to the competent authority supported by a *prima-facie* evidence of error of judgment in the opinion expressed by the medical board. Such an evidence should be from a government doctor not below the status of civil surgeon and should contain specific mention that he has taken into consideration the findings of the medical board before giving his opinion.

(4) Where the person declared to be unfit for further service makes representation under sub-rule (3) the same shall be forwarded to the next superior officer, who shall have the case reviewed by a fresh medical board constituted for the purpose and order the retirement/discharge of the said person, if the decision of the fresh medical board is adverse to him.

(5) Where no representation is made against the decision of the medical board under sub-rule (3), the authority as specified in rule 17, as the case may be, may (if he agrees with the findings of the medical board) order the retirement or discharge of the person concerned.

27. Resignation.— (1) The Central Government may, having regard to the special circumstances of any case, permit any officer of the Force to resign from the Force before completing the term of engagement :

Provided that before granting such permission the Central Government may require the officer to refund to the Government three months pay and allowances drawn by him or the cost of training imparted to him, whichever is higher.

(2) The Central Government may accept the resignation under sub-rule (1) with effect from such date as it may consider expedient.

(3) The Central Government may refuse to permit an officer to resign.—

(a) if an emergency has been declared in the country either due to internal disturbance or external aggression; or

(b) if it considers it to be inexpedient so to do in the interest of the discipline of the Force; or

(c) if the officer has specifically undertaken to serve for a specified period and such period has not expired.

(4) The provisions of this rule shall apply to and in relation to subordinate officers and enrolled persons as they apply to and in relation to any officer of the Force and the powers vested in the Central Government under sub-rules (1) and (2) shall be exercised in the case of a Subedar-Major and Subedar by an Inspector-General, in the case of a Naib-Subedar by an officer not below the rank of Additional Deputy Inspector-General, and in the case of an enrolled person, by a Commandant.

28. Appeal against orders of dismissal, removal or compulsory retirement.— A person subject to the Act other than an officer who has been dismissed, removed or compulsorily retired from service, shall have the right to put in an appeal against the termination of his service to any authority, higher than the one who has passed the termination order within ninety days of the termination of service.

(2) In case of Officers, appeal shall lie to the Central Government and such appeal shall be filed within ninety days of the termination of service.

(3) Where the appellate authority sets aside the order of dismissal, removal or compulsory retirement under this rule, such authority shall pass such orders as may be necessary in respect of the period of absence from duty of the person whose dismissal, removal or compulsory retirement has been set aside.

29. Date of dismissal, removal, discharge or retirement.— (1) The effective date of dismissal, removal, discharge, retirement shall be—

(a) the date mentioned in the order of dismissal or removal or discharge or retirement, or

(b) if no such date is mentioned, the date on which the person concerned is relieved from duties.

(2) The dismissal, removal, discharge or retirement of a person subject to the Act shall not be from retrospective effect.

CHAPTER - V

RESTRICTION ON FUNDAMENTAL RIGHTS

30. Unauthorised organisation.— No person subject to the Act shall, without the express sanction of the Central Government take official cognisance of, or assist or take any active part in, any society, institution or organisation, not recognised as part of the Armed Forces of the Union; unless it be of a recreational or religious nature in which case prior sanction in writing of the superior officer shall be obtained.

31. Political activities.— (1) No person subject to the Act shall attend, address, or take part in any meeting or demonstration held for a party or political purposes, or belong to or join or subscribe in the aid of, any political association or movement.

(2) No person subject to the Act shall issue an address to electors or in any other manner publicly announce himself or allow himself to be publicly announced as a candidate or as a prospective candidate for election to Parliament, the legislature of a State or a local authority, or any way actively promote or prosecute a candidate's interests.

32. Communications to the press, lectures, etc.— No person subject to the Act shall,—

(a) publish in any form whatever or communicate directly or indirectly to the press any matter in relation to a political question or on a service subject or containing any service information, or publish or cause to be published any book or letter or article or other document on such question or matter or containing such information without the prior sanction of the Central Government, or any officer specified by the Central Government in this behalf.

(b) deliver a lecture or wireless address, on a matter relating to a political question or on a service subject or containing any information or views on any service subject without the prior sanction of the Central Government, or any officer specified by the Central Government in this behalf.

Explanation.— For the purposes of this rule, the expression “service information” and “service subject” include information or subject, as the case may be, concerning the Force, the defence or the external relations of the Union.

CHAPTER - VI

ARREST AND SUSPENSION

33. Forms of arrest.— (1) Arrest may be either open or close arrest.

(2) An arrest, unless otherwise specified, shall mean an open arrest.

(3) An order imposing arrest may be communicated to the person to be arrested either orally or in writing.

34. Authority to order arrest.— (1) No person subject to the Act shall be arrested on a charge under the Act except under and in accordance with the orders of superior officer having power of command over him.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) any person subject to the Act may be placed under arrest by any superior officer—

(a) if he commits an offence against such superior officer; or

(b) if he commits an offence in the view of such superior officer; or

(c) if he is behaving in a disorderly manner and the said superior officer considers it necessary to place such a person under arrest with a view to stop such disorderly behaviour.

(3) A superior officer effecting arrest under sub-rule (2) shall as soon as possible and in any case within twenty-four hours of such arrest send a report to the Commandant of the battalion or unit of which the person arrested is a member and in case of the arrest of an officer of and above the rank of Commandant, to his immediate superior officer.

35. Arrest, how imposed.— (A) **Close arrest.**— (1) (a) close arrest in the case of enrolled persons shall be imposed by informing the person to be arrested and ordering him to be marched to the place of confinement under an escort of another person of similar or superior rank.

(b) where no such escort is available, the person arrested shall be ordered to report himself immediately to the quarter-guard or other place of confinement.

(2) (a) close arrest in the case of officers, subordinate officers or under officers shall be imposed by placing such officer, subordinate officer, or under officer under the custody of another person of similar or superior rank and wherever considered necessary such officer, subordinate officer, or under officer may be confined under charge of a guard.

(b) the person under arrest shall not leave the place of his confinement without permission of the Commandant or a superior officer designated by the Commandant.

(B) Open arrest.— (3) (a) open arrest shall be imposed by informing the person to be arrested that he is under open arrest and that he shall confine himself within such limits as may be specified in this behalf by the concerned superior officer effecting such arrest.

(b) the Commandant may, from time to time, vary the limits referred to in clause (a) above.

36. Release from arrest during investigation.— (1) Any person arrested under rule 34 may be released from arrest under the order of an officer :

Provided that in case of a person placed under arrest by an officer, such person shall be released from arrest under the order of his Commandant or any officer superior to such Commandant.

37. Release without prejudice to re arrest.— Pending the completion of the investigation or convening of a court, any person, who has been placed under arrest, may without prejudice to re-arrest be released by his commandant or by any officer superior to such commandant.

38. Arrest, when to be imposed.— (1) Any person charged with—

(i) an offence under Section 21 clause (a) or clause (b) or Section 23 or Section 24 or Section 27 or sub-Section (1) of Section 28.

(ii) a civil offence punishable with death or imprisonment for life;

(iii) any other offence under the Act—

(a) if the interest of discipline so require, or

(b) if the person concerned deliberately undermines discipline, or

(c) if the person concerned is of violent disposition; or

(d) if the person concerned is likely to absent himself with a view to avoid trial; or

(e) if the person concerned is likely to interfere with witnesses or tamper with the evidence, he shall be placed under arrest.

(2) Where any person arrested shows symptoms of sickness, medical assistance shall be provided for such person.

39. Special provision in case of arrest of a drunken person.— (1) Where a drunken person has been arrested, he shall, as far as possible, be confined separately and shall be visited by duty officer or duty subordinate officer or duty under officer or under officer incharge of the guard, once every two hours.

(2) A drunken person shall not be taken before a superior officer for investigation of his case until he has become sober.

40. Arrest in case of person whose trial has been ordered.— (1) Unless the convening authority has otherwise directed, on the commencement of the trial of a person by the court, the said person shall be placed under arrest by his Commandant and shall remain under arrest during the trial.

(2) Where a sentence lower than that of imprisonment is passed by a court, the arrested person may be released by his Commandant pending confirmation of the finding and sentence :

Provided that the convening authority may rescind, vary or modify the order passed by a Commandant under sub-rule (1) or sub-rule (2) and where no such order is passed by a Commandant, the convening authority may pass such order as it may deem proper :

Provided further that a person who has been sentenced to be dismissed shall not, except while on active duty, be put on any duty.

41. Delay report.— (1) (a) The report on reason for delay as required under Section 81 shall be in the form set out in Appendix II and it shall be sent by the Commandant to the Deputy Inspector-General or Additional Deputy Inspector-General under whom the accused may be serving.

(b) A copy of the eighth delay report and every succeeding report thereof shall also be sent to the Inspector-General under whom the accused may be serving, and to the Chief Law Officer.

(2) Where the accused is kept under arrest for a period exceeding three months without a Force Court being ordered to assemble for his trial, a special report regarding the action taken and the reasons for the delay shall be sent by the Commandant to the Director-General with a copy each to the Deputy Inspector-General or Additional Deputy Inspector-General and the Inspector-General concerned.

42. Rights of a person under arrest.— (1) (a) Any person placed under arrest shall, at the time of being placed under arrest, be given in writing by the officer effecting the arrest of the particulars of the charges against him.

(b) Notwithstanding anything contained in clause (a), where during the investigation other offences committed by the accused are discovered, it shall be lawful to charge such person with those offences.

(2) (a) The duty officer or duty subordinate officer shall every day make a visit to the person under arrest and take the orders of the Commandant on any request or representation made by the person under arrest.

(b) the request or representation made by the person under arrest shall be entered in the form set out in Appendix-III.

43. Suspension.— (1) Notwithstanding anything contained in these rules the disciplinary or appointing authority competent to convene general or petty Force Court may, at its discretion, place a person serving under him, under suspension—

- (i) where disciplinary action under the Act against him is contemplated or is pending ; or
- (ii) where in the opinion of the authority aforesaid, he has engaged himself in activities prejudicial to the interest of the security of the State; or
- (iii) where a case against him in respect of any civil offence is under investigation, inquiry or trial.

(2) A person subject to the Act shall be deemed to have been placed under suspension by an order of the appointing authority—

- (i) with effect from the date of his detention by civil police on a criminal charge or otherwise for a period exceeding 48 hours, or
- (ii) with effect from the date of his conviction by a criminal court on a criminal charge, if the sentence awarded is imprisonment for a term exceeding forty eight hours.

(3) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule shall continue to remain in force until it is modified or revoked by the authority competent to do so.

(4) An order of suspension made or deemed to have been made under this rule, may, at any time, be modified or revoked, by the authority which made the order or by any authority to which that authority is subordinate.

(5) During the period of suspension of a person, powers vested in him shall be in abeyance, but he shall be subject to same responsibilities, discipline, penalties and all other conditions of service to which he would have been subject if he were on duty and cannot leave headquarters declared by the competent authority without prior permission.

(6) When a person remains under suspension for more than 90 days, a report giving reasons for delay in the finalisation of his case shall be submitted to the Director General by the Commandant of the accused, and thereafter, subsequent reports shall be submitted every month till the case is finalised or the order of suspension is revoked whichever is earlier.

CHAPTER — VII

CHOICE OF JURISDICTION BETWEEN FORCE COURT AND CRIMINAL COURT

44. Trial of cases either by Force Court or criminal court.— (1) where an offence is triable both by a criminal court and a Force Court, an officer referred to in Section 102 may,—

- (i) (a) where the offence is committed by the accused in the course of performance of his duty as a member of the Force, or
- (b) where the offence is committed in relation to property belonging to the Government or the Force, or a person subject to the Act; or
- (c) where the offence is committed against a person subject to the Act, direct that any person subject to the Act who is alleged to have committed such an offence, be tried by a Force Court; and

(ii) In any other case, decide whether or not it would be necessary in the interest of discipline to claim for trial by a Force Court any person subject to the Act who is alleged to have committed such an offence.

(2) In taking a decision to claim an offender for trial by a Force Court an officer referred to in Section 102 may take into account all or any of the following factors, namely,—

- (a) the offender is on active duty or has been warned for active duty and it is felt that he is trying to avoid such duty;
- (b) the offender is a young person undergoing training and the offence is not a serious one and the trial of the offender by a criminal court would materially affect his training;
- (c) the offender can, in view of the nature of the case, be dealt with summarily under the Act.

45. Cases which may not be tried by Force Court.— Without prejudice to the provisions of sub-rule (1) of rule 44, an offender may not ordinarily be claimed for trial by a Force Court—

- (i) where the offence is committed by him along with any other person not subject to the Act whose identity is known; or
- (ii) where the offence is committed by him while on leave or during absence without leave.

CHAPTER — VIII
INVESTIGATION OF CHARGES AND SUMMARY DISPOSAL
HEARING OF CHARGE

46. Tentative charge sheet.— Where it is alleged that a person subject to the Act has committed an offence punishable under the Act, the allegation shall be reduced to writing in the form set out in Appendix-IV.

47. Hearing of charge.— (1) Every charge against a person subject to the Act shall be heard by the Commandant in the presence of the accused and the proceedings shall be reduced to writing in the form set out in Appendix-V. The accused shall have full liberty to cross-examine any witness against him, and to call such witness and make such statement as may be necessary for his defence :

Provided that where the charge against the accused arises as a result of investigation by a court of inquiry, wherein the provisions of sub-rule (8) of rule 183 have been complied with in respect of that accused, the Commandant may dispense with the procedure in sub-rule (1).

(2) Notwithstanding anything contained in sub rule (1) above, a specified officer under Section 62 may proceed against an enrolled person if—

- (a) the charge can be summarily dealt with;
- (b) the case has not been reserved by the Commandant for disposal by himself; and
- (c) the accused is not under arrest.

and after hearing the charge under sub-rule (1) above, the specified officer may either award any of the punishments which he is empowered to award in the form set out in Appendix-VI, or refer the case to the Commandant for further disposal.

(3) The Commandant shall dismiss a charge brought before him if, in his opinion, the evidence does not show that an offence under the Act has been committed, and may do so if, he is satisfied that the charge ought not to be proceeded with :

Provided that the Commandant shall not dismiss a charge which he is debarred to try under sub-Section (2) of Section 96 without reference to superior authority as specified therein:

Provided also that, in case of all offences punishable with death, the Commandant shall remand the case for recording of summary of evidence.

(4) After compliance of sub-rule (1), if the Commandant is of opinion that the charge ought to be proceeded with, he shall within a reasonable time—

- (a) dispose of the case under Section 62 in accordance with the manner and form in Appendix-VI; or
- (b) refer the case to the proper superior authority; or
- (c) adjourn the case for the purpose of having the evidence against the accused, reduced to writing; or
- (d) order his trial by a Summary Assam Rifles Court;

Provided that the Commandant shall not order trial by a Summary Assam Rifles Court without reference to the officer empowered to convene a petty Assam Rifles Court for the trial of the alleged offender unless—

- (a) the offence is one which he can try by a Summary Assam Rifles Court without any reference to that officer; or
- (b) he considers that there is grave reason for immediate action and such reference cannot be made without detriment to discipline.

(5) Where the evidence taken in accordance with sub-rule (4) of this rule discloses an offence other than the offence which was the subject of the investigation, the Commandant may frame suitable charge(s) on the basis of the evidence so taken as well as the investigation of the original charge.

48. Charges not to be dealt with summarily.— A charge for an offence under Section 21 or Section 22 or Section 23 when on active duty or Section 24 or clause (1) of Section 25 or clause (a) of Section 27 or Section 28, when on active duty, or Section 30 or Section 31, or clause (a) of Section 33 (disgraceful conduct) or clause (b) of Section 36 or Section 39 or Section 46 or Section 47 or Section 55 (other than that for simple hurt or theft) or a charge for abetment of or an attempt to commit any of these offences shall not be dealt with summarily.

49. Summary of evidence.— (1) Where the case is adjourned for the purpose of having the evidence reduced to writing, the officer ordering the same may either prepare the summary of evidence himself or detail another officer to do so.

(2) The witnesses shall give their evidence in the presence of the accused. The accused shall have right to cross-examine all witnesses who give evidence against him, and the questions together with the answers thereto shall be added to the evidence recorded.

(3) After all the witnesses against the accused have been examined, he shall be cautioned in the following terms; "Do you wish to make any statement? You are not obliged to say anything unless you wish to do so, but whatever you state shall be taken down in writing and may be given in evidence." Any statement thereupon made by the accused shall be taken down and read to him, but he will not be cross-examined upon it. The accused may then call his witnesses in defence and the officer recording the evidence may ask any question that may be necessary to clarify the evidence given by such witnesses.

(4) The statements given by witnesses shall ordinarily be recorded in narrative form in English or Hindi language and the officer recording the evidence may, at the request of the accused, permit any portion of the evidence to be recorded in the form of question and answer. Witnesses shall sign their statements after the same have been read over and explained to them, or if he cannot write his name his statement shall be attested by his mark and witnessed as a token of correctness of the evidence recorded.

(5) The provisions of Section 111 of the Act shall apply for procuring the attendance of the witnesses before the officer recording the summary of evidence.

(6) Where a witness cannot be compelled to attend or is not available or his attendance cannot be procured without an undue expenditure of time or money and after the officer recording the evidence has given a certificate in this behalf, a written statement signed by such witness may be read to the accused and included in the summary of evidence.

(7) After the recording of evidence is completed the officer recording the evidence shall render a certificate in the following form—

"Certified that the record of evidence ordered by was made in the presence and hearing of the accused and the provisions of rule 49 (3) have been complied with."

(8) No counsel or legal practitioner shall be permitted to appear before the officer recording the evidence.

50. Abstract of evidence.— (1) Where the Commandant of the accused is of the opinion that the charge against an officer, subordinate officer or under officer is not of such a nature so as to warrant his trial by a Force Court, he may, after hearing the charge in accordance with the rule 47 (1), order an abstract of evidence to be prepared in the case.

(2) An abstract of evidence shall be prepared either by the Commandant or an officer detailed by him.

(3) (a) The abstract of evidence, shall include —

(i) signed statements of witnesses wherever available or a précis thereof, and

(ii) copies of all documents intended to be produced at the trial.

(b) where signed statements of any witnesses are not available, a précis of the evidence that the witnesses are likely to give shall be included.

(4) A copy of the abstract of evidence shall be given by the officer making the same to the accused and the accused shall be given an opportunity to make a statement if he so desires, after he has been cautioned in the manner laid down in sub rule (3) of rule 49 :

Provided that the accused shall be given such time as may be reasonable in the circumstances but in no case less than twenty four hours after receiving the abstract of evidence to make his statement.

51. Disposal of case after recording summary or abstract of evidence.— (1) The evidence prepared in pursuance of rule 49 or 50 shall be considered by the Commandant who thereupon shall either—

(a) dismiss the charge; or

(b) dispose of the case summarily under Section 62 or Section 66 of Assam Rifles Act, as applicable; or

(c) refer the case to the competent superior officer for disposal; or

(d) remand the accused for trial by a Force Court.

(2) If the accused is remanded for trial by a Force Court, the Commandant shall without unnecessary delay:

(a) assemble a Summary Assam Rifles Court (after making reference as per sub-Section

(2) of Section 96, when such reference is necessary), or

(b) apply to the competent superior authority to convene a general or petty Assam Rifles Court, as the case may be.

52. Application for a court.— An application for a petty Force Court or general Force Court shall be made by the Commandant in the Form set out in Appendix-VII of these rules and shall be accompanied by five copies of the summary or abstract of evidence and charge sheet and such other documents as are mentioned in that application form.

53. Summary disposal of charges against officer, subordinate officer or warrant officer.—(1) Where an officer, a subordinate officer or a warrant officer is remanded for the disposal of a charge against him by an authority empowered under Section 64, 65 and 66, to deal summarily with that charge, the summary or abstract of evidence shall be delivered to him, free of charge, with a copy of the charge as soon as practicable after its preparation and in any case not less than twenty four hours before the commencement of the proceedings.

(2) Where the authority empowered under Sections 64, 65 and 66 decides to deal summarily with a charge against an officer, subordinate officer or warrant officer, he shall unless he dismisses the charge, or unless the accused has consented in writing to dispense with the attendance of the witnesses, hear the evidence in the presence of the accused. The accused shall have full liberty to cross-examine any witness against him, and to call any witness and make a statement in his defence, and such statement or a gist thereof shall be recorded and attached to the proceedings by the officer disposing the case summarily.

(3) The proceedings shall be recorded as far as practicable in accordance with the form in Appendix VIII, and in every case in which punishment is awarded, the proceedings together with the conduct sheet, summary or abstract of evidence and written consent to dispense with the attendance of witnesses of the accused, shall be forwarded through the proper channel to the prescribed superior authority for review as provided under sub-Section (2) of Section 64 and sub-Section (2) of Section 65.

(4) In the case of summary disposal under Section 62 and 66, the proceedings shall be forwarded to the officer superior in command to the officer who awarded the punishment, and if the punishment awarded appears to such superior officer to be illegal, unjust or excessive, he may cancel, vary or remit the same and make such other direction as may be appropriate in the circumstances of the case.

(5) The prescribed superior authority for the purposes of sub Section (2) of Section 64 and sub Section (2) of Section 65 shall be the Central Government, the Director-General or other officer specified by the Director-General.

CHAPTER - IX ON CHARGES AND MATTERS ANTECEDENT TO TRIAL FRAMING OF CHARGES

54. Charge and charge sheet.—(1) A charge means an accusation contained in the charge sheet that a person subject to the Act has been guilty of an offence.

(2) A charge sheet shall contain the whole issue or issues to be tried at one time and may contain more than one charge, if the charges are founded on the same facts or form part of a series of offences of same or similar character :

Provided that a charge under Section 25, Section 26, Section 38, and Section 41 may be included in any charge sheet, notwithstanding that other charges in that charge sheet are not founded on the same facts or do not form part of a series of offences of the same or similar character.

(3) Every charge sheet shall in its layout follow the appropriate specimen set out in Appendix-IV to these rules.

55. Commencement of charge sheet.— Every charge sheet shall begin with the name and description of the person charged and state his number, rank, name and unit to which he belongs.

56. Contents of charge.—(1) Each charge shall state one offence only and in no case shall an offence be described in the alternative in the same charge.

(2) (a) If a single act or series of acts be of such a nature that it is doubtful which of several offences the facts which can be proved will constitute, the accused may be charged with having committed all or any of such offences, and any number of such charges may be tried at once or he may be charged in the alternative with having committed some one of the said offences.

(b) The charge for more serious offence shall precede the one for the less serious offence.

(3) Each charge shall be divided into two parts -

(a) statement of the offence; and

(b) statement of the particulars of the act, neglect or omission constituting the offence.

(4) The offence shall be stated, if not a civil offence, as nearly as practicable in the words of the Act, and if a civil offence, in such words as would sufficiently describe that offence, in words as used to describe the said offence in the relevant statutory provision.

(5) The particulars shall state such circumstances respecting the alleged offence as will enable the accused to know what act, neglect or omission is intended to be proved against him as constituting the offence.

(6) The particulars in one charge may be framed wholly or partly by a reference to the particulars in another charge, and in that case so much of the latter particulars as are so referred to, shall be deemed to form part of the first mentioned charge as well as of the other charge.

(7) Where it is intended to prove any facts in respect of which any deduction from pay and allowances can be awarded as a consequence of the offence charged, the particulars shall state those facts and the sum of the loss or damage it is intended to charge.

57. Signature on charge sheet.— The charge sheet shall be signed by the Commandant of the accused and shall contain the place and date of such signature.

58. Joint charges — (1) Any number of accused may be charged jointly and tried together for an offence averred to have been committed jointly by them.

(2) Any number of accused though not charged jointly may also be tried together for an offence averred to have been committed by one or more of them and abetted by the other or others.

(3) Where the accused are so charged under sub-rule (1) or sub-rule (2), any one or more of them may be charged with, and tried for any other offence with which they could have been charged under sub-rule (2) of rule 54.

59. Validity of charge sheet.— (1) A charge sheet shall not be invalid merely by reason of the fact that it contains any mistake in the name or description of the person charged, provided that he does not object to the charge sheet during the trial, and that no substantial injustice has been done to the person charged.

(2) In the construction of a charge-sheet or charge, there shall be presumed in favour of supporting the same every proposition which may reasonably be presumed to be impliedly included, though not expressed therein.

PREPARATION OF DEFENCE BY ACCUSED PERSON

60. Right of accused to prepare defence.— (1) An accused, who has been remanded for trial, shall be afforded proper opportunity for preparing his defence and shall be allowed proper communication with his defending officer or counsel and with his witnesses.

(2) A defending officer shall be appointed to defend an accused who has been remanded for trial unless the accused states in writing that he does not wish such an appointment to be made.

(3) If the prosecution is to be undertaken by a legally qualified officer or by a counsel, the accused shall be notified of this fact in sufficient time to enable him, if he so desires, to make arrangement for a legally qualified officer or counsel to defend him.

(4) The accused person shall have the right to address an application to the Chief Law Officer or Law Officer, if he is kept under arrest for longer than forty eight days without being brought to trial or is not given full liberty for preparing his defence.

(5) As soon as practicable after an accused has been remanded for trial and in any case not less than four days before his trial, he shall be given free of charge—

(a) a copy of the charge sheet

(b) an unexpurgated copy of summary or abstract of evidence showing passages within, which have been expurgated in the copy sent to the senior member; and

(c) notice of any additional evidence which the prosecution intends to adduce;

(6) The provisions of sub-rules (2) and (3) shall not apply to a trial before a Summary Assam Rifles Court.

61. Warning of the accused for trial.— (1) When an accused is given a copy of the charge-sheet and of the summary or abstract of evidence in accordance with these rules, an officer shall—

(a) explain to him the charges brought against him, and if the accused desires to have it in a language which he understands, a translation thereof shall also be given to him; and

(b) inform him that, upon his making a written request to his Commandant not less than twenty four hours before his trial requiring the attendance at his trial of a witness (other than a witness for the prosecution) whom he desires to call in his defence (such witness to be named by him), reasonable steps will be taken in accordance with these rules to procure the attendance of any such witness at his trial.

(c) deliver to the accused a list of the ranks, names and units of the members who are to form the Court and of any waiting members.

(2) If it appears to the Court that the accused is liable to be prejudiced at his trial by any non-compliance with this rule, the Court shall take steps and, if necessary, adjourn to avoid the accused being so prejudiced.

62. Summoning of defence witnesses.— (1) Subject to the provisions of sub-rules (2) and (3) the Commandant shall, on a request made in this behalf by the accused, summon such witnesses as are specified by the accused.

(2) Where the Commandant is satisfied that the evidence to be given by any witness is not likely to be of material assistance at the trial he may refuse to summon such witness.

(3) The Commandant may before summoning any witness, require the accused to defray or undertake to defray the cost of attendance of such witness and if the accused refuses to defray or undertake to defray the cost aforesaid, the Commandant may refuse to procure the attendance of that witness.

(4) Where the Commandant has refused to summon the witness under sub-rule (2) or sub-rule (3), the accused may make an application to the court for the summoning of such witness and the court may if it considers it to be expedient, in the interest of justice, order the summoning of such witness and, if necessary, adjourn the proceedings for the attendance of such witness :

Provided that it shall rest with the accused alone to secure the attendance of any witness whose evidence is not contained in the summary of evidence and for whose attendance the accused has not made a request under sub rule (1).

CONVENING OF GENERAL AND PETTY ASSAM RIFLES COURTS

63. Action by a superior authority on receiving an application for convening court.— (1) As soon as a superior authority receives an application for convening a court, he shall scrutinize the charge and the evidence against the accused, where necessary in consultation with the Chief Law Officer or a Law Officer designated by him and he :

(a) shall direct the Commandant to dismiss the charge where the evidence against the accused is insufficient and further evidence is not likely to be available and may direct him to do so if he considers it inadvisable to proceed with the trial; or

(b) may return the case to the Commandant for being tried by a Summary Assam Rifles Court or being dealt with summarily if he considers that the same can be adequately so tried or dealt with; or

(c) may dispose of the case by administrative action, or if he is not competent to take such action, forward the case to superior authority with his recommendations for such action.

(d) may return the case for recording further evidence, if he considers the evidence recorded insufficient, but considers that further evidence may be available.

(2) (a) In any other case he may either himself convene a court or if he considers that a higher type of court should be convened and he is not empowered to convene such a court, forward the case to the appropriate superior authority with recommendation that such court may be convened.

(b) the superior authority on receiving the case may exercise any of the powers given in sub-rule (1) of this rule :

Provided that the superior authority before convening a general Assam Rifles Court or a petty Assam Rifles Court shall take the advice of the Chief Law Officer or a Law Officer (designated for this purpose by Chief Law Officer).

Provided further that the superior authority while convening a court may reframe the charge sheet on which the accused is to be tried.

64. Disqualification of officers for serving on general and petty Assam Rifles Courts.— An officer shall be disqualified from serving on a court if he—

(a) is an officer who convened the Court; or

(b) is the prosecutor or a witness for the prosecution; or

(c) has taken any part in the investigation of the case, which would have necessitated his applying mind to any part of the evidence or to the facts of the case; or

(d) is the Commandant of the accused; or

(e) has a personal interest in the case; or

(f) is a Force police officer appointed under Section 85 (1).

65. Adjournment for insufficient number of officers.— (1) If, before the accused is arraigned, the full number of officers detailed are not available to serve, by reason of disqualification, challenge or otherwise, and if there are not a sufficient number of officers in waiting to take the place of those unable to serve, the Court shall ordinarily adjourn for purpose of fresh members being appointed, but if the Court is of opinion that in the interests of justice, and for the good of service, it is inexpedient so to adjourn, it may, if not reduced in number below the legal minimum, proceed, after recording reasons for so doing.

(2) If the Court adjourns for the purpose of appointment of fresh members, whether under these rules or otherwise, the convening officer may, if he thinks fit, convene another Court.

66. Composition of general and petty Assam Rifles Courts.— (1) A court shall consist, as far as practicable, of officers of different battalions or units.

(2) The members of a court for the trial of an officer shall be of a rank not lower than the rank of that officer, unless in the opinion of the convening officer, officers of such rank are not, having due regard to the exigencies of public service, available. Such opinion shall be recorded in the convening order.

(3) A court for the trial of a Commandant shall as far as possible, consist of officers who are or have been Commandants or who hold, or have held, a higher appointment.

67. Duties of convening officers when convening courts.— (1) An officer before convening a general or petty Assam Rifles Court shall first satisfy himself that the charges to be tried by the court are for offences within the meaning of the Act, and that the evidence justifies a trial on those charges. If not so satisfied, he shall order the release of the accused, or refer the case to superior authority.

(2) He shall also satisfy himself that the case is a proper one to be tried by the kind of court which he proposes to convene.

(3) When an officer convenes a court, he shall:

- (a) issue a convening order in the appropriate form set out in Appendix-IX.
- (b) direct upon what charges the accused is to be tried and ensure that the accused has been remanded for trial by a court upon these charges, by his Commandant;
- (c) if he is of the opinion that charges shall be put in separate charge sheets, so direct and shall also direct the order in which they are to be tried;
- (d) direct, if there is more than one accused whether the accused are to be tried jointly or separately;
- (e) appoint members of the court and any waiting members;
- (f) if convening—
 - (i) a general Assam Rifles Court; or
 - (ii) a petty Assam Rifles Court which he considers should be attended by a Law Officer, take necessary steps to procure the appointment of Law officer by or on behalf of the Chief Law officer, and may also appoint an officer to be under his instruction at the trial;
- (g) appoint an officer, subject to the Act or a counsel assisted by such an officer to prosecute;
- (h) appoint an interpreter wherever necessary;
- (i) forward to the senior member, the original charge sheet, the convening order and a copy of the summary or abstract of evidence from which any evidence which in his opinion would be inadmissible at the trial, has been expurgated;
- (j) forward to each member of the court and to each waiting member a copy of the charge sheet and convening order;
- (k) forward to the Law Officer, a copy each of the charge sheet, the convening order and an unexpurgated copy of the summary or abstract of evidence showing the passages which have been expurgated in the copy sent to the senior member;
- (l) forward to the prosecutor copies of the charge sheet and convening order, and the original summary or abstract of evidence; together with an unexpurgated copy thereof showing the passages which have been expurgated in the copy sent to the senior member.
- (m) ensure that the Commandant has summoned all the prosecution witnesses and such defence witnesses as the accused may have requested to be summoned under rule 62.

CHAPTER — X

PROCEDURE FOR GENERAL AND PETTY ASSAM RIFLES COURTS

SECTION - I

PROCEDURE AT TRIAL – ASSEMBLY, CHALLENGE AND SWEARING

68. Assembly of court and inquiry as to legal constitution.— (1) Upon a Force Court assembling, the convening order which includes ranks, names and units of the officers appointed to serve on the court, shall be laid before it together with the charge-sheet and copy of summary or abstract of evidence, and the court shall, before beginning the trial, satisfy itself in closed court—

- (a) that the court has been convened in accordance with the Act and these rules;
- (b) that the court consists of not less than the minimum number of officers required by law;
- (c) that the members are of the required rank;
- (d) that members have been duly appointed and are not disqualified under the Act;

(e) that if there is a Law Officer, he has been duly appointed, is of required rank, and is not disqualified from serving on that court;

(f) that the accused appears from the charge sheet, to be subject to the Act and to be subject to the jurisdiction of the court; and

(g) that each charge is correct in law and framed in accordance with these rules, and is so explicit as to enable the accused readily to understand what he has to answer.

(2) Where a vacancy occurs through a member of the court being disqualified under the Act or being absent when the court assembles, the Presiding Officer may appoint a duly qualified waiting member to fill that vacancy.

(3) If the court is not satisfied on any of the matters mentioned in sub-rule (1) and is not competent to rectify such matters itself under the Act or these rules, it shall before commencing the trial, report thereon to the convening officer, and may adjourn for that purpose.

(4) When the court has complied with this rule and is ready to proceed with the trial, the Presiding Officer shall open the court and the trial shall begin.

69. Commencement of trial, appearance of prosecutor and accused.— When the court has satisfied itself that the provisions of rule 68 have been complied with, it shall cause the accused to be brought before the court, and the prosecutor, who must be a person subject to the Act, shall take his due place in the court.

70. Proceedings for challenges of members of court.— (1) The order convening the court and the names of the officers appointed to try the accused shall be read in the hearing of the accused who shall be given an opportunity to object to any of those officers in accordance with Section 106.

(2) When a court is to try more than one accused whether separately or jointly, each accused shall be given an opportunity to object to any officer on the court in accordance with the foregoing sub-rule and shall be asked separately whether he has any such objection.

(3) An accused shall state the names of all the officers to whom he objects before any objection is disposed of.

(4) If more than one officer is objected to, the objection to each officer shall be disposed of separately and the objection to the lowest in rank shall be disposed of first.

(5) An accused may make a statement and may call any person to give evidence in support of his objection and such person may be questioned by the accused and by the court.

(6) An officer to whom the accused has objected, may state in open court anything relevant to the objection of the accused whether in support or in rebuttal thereof.

(7) An objection to an officer shall be considered in closed court by the remaining officers of the court in the absence of the challenged officer, and they shall vote on the disposal of such objection, notwithstanding that objections have been made to any of those remaining officers.

(8) When an objection to an officer is allowed under sub-Section (3) of Section 106, that officer shall forthwith retire and take no further part in the proceedings.

(9) When an officer so retires or is not available to serve owing to any cause which the court may deem to be sufficient, and there are any officers in waiting detailed as such, the Presiding Officer shall appoint one of such officers to fill the vacancy. If there is no officer in waiting available, the court shall proceed as required by rule 65.

(10) The court shall satisfy itself that a waiting member who takes the place as a member of the court is of the required rank and not disqualified under the Act and shall give the accused an opportunity to object to him and shall deal with any such objection in accordance with the Act and these rules.

71. Swearing or affirming of members.— As soon as the court is constituted with the proper number of officers who are not objected to or objections in respect of whom have been overruled, an oath or affirmation shall be administered to every member in presence of the accused in one of the following forms or in such other form to the same purport as the court ascertains to be according to his religion or otherwise binding on his conscience.

FORM OF OATH

"I, swear by Almighty God, that I will, well and truly, try the accused (or accused persons), before the court, according to the evidence, and that I will, duly administer justice, according to the Assam Rifles Act, without partiality, favour or affection; and I do further swear that I will not, on any account, at any time, whatsoever, disclose or discover, the vote or opinion of any particular member of this court unless required to give evidence there-of by a court of law".

FORM OF AFFIRMATION

"I,do solemnly, sincerely and truly, declare and affirm that I will well and truly, try the accused (or accused persons) before the court, according to the evidence, and that I will, duly administer justice according to the Assam Rifles Act, without partiality, favour or affection; and I do further solemnly, sincerely and truly declare and affirm that I will not, on any account, at any time whatsoever, disclose or discover, the vote or opinion of any particular member of this court unless required to give evidence there-of by a court of law.

72. Swearing or affirmation of Law Officers and others.— After the members of the court are all sworn or have made affirmation, an oath or affirmation shall be administered to the following persons or such of them as are present at the court in such of the following forms as shall be appropriate, or in such other form to the same purport as the court ascertains to be according to the religion or otherwise binding on the conscience of the person to be sworn or affirmed—

(A) LAW OFFICER :

FORM OF OATH

"I,.....swear by Almighty God that I will, to the best of my ability, carry out the duties of Law Officer, in accordance with the Assam Rifles Act and the rules made there is under without partiality, favour or affection, and I do further swear that I will not, on any account at any time whatsoever, disclose or discover the vote or opinion on any matter of any particular member of this court, unless required to give evidence thereof by a court of law".

FORM OF AFFIRMATION

"I,..... do hereby, solemnly, sincerely and truly declare and affirm that I will, to the best of my ability, carry out the duties of Law Officer, in accordance with the Assam Rifles Act and the rules made there-under without partiality, favour or affection, and I do further solemnly, sincerely and truly declare and affirm, that I will not, on any account, at any time, whatsoever, disclose or discover the vote or opinion, on any matter of any particular member of this court, unless required to give evidence thereof by a court of law".

(B) OFFICER ATTENDING FOR THE PURPOSE OF INSTRUCTION :

FORM OF OATH

"I,..... swear by Almighty God that I will not on any account; at any time whatsoever, disclose or discover the vote or opinion of any particular member of this court unless required to give evidence thereof by a court of law".

FORM OF AFFIRMATION

"I,..... do solemnly, sincerely and truly, declare and affirm that I will not on any account, at any time whatsoever, disclose or discover the vote or opinion of any particular member of this court unless required to give evidence thereof by a court of law".

(C) SHORTHAND WRITER :

FORM OF OATH

"I,..... swear by Almighty God that I will truly take down to the best of my ability, the evidence to be given before this court and such other matters as I may be required to take down and will, when required, deliver to the court a true transcript of the same".

FORM OF AFFIRMATION

"I,..... do solemnly, sincerely and truly, declare and affirm that I will truly take down to the best of my ability the evidence to be given before this court and such other matters as I may be required to take down and will, when required, deliver to the court a true transcript of the same".

(D) INTERPRETER :

FORM OF OATH

"I,..... swear by Almighty God that I will faithfully interpret and translate, as I shall be required to do, touching the matter before this court".

FORM OF AFFIRMATION

"I,..... do solemnly, sincerely and truly, declare and affirm that I will faithfully interpret and translate, as I shall be required to do, touching the matter before this court".

73. Objection to interpreter or shorthand writer.— A person shall not be sworn or affirmed as an interpreter or shorthand writer, if he is objected to by the accused, unless the court after hearing the accused and the prosecutor, disallows such objection as being unreasonable.

74. Objection to Law Officer and prosecutor.— The accused shall not be permitted to object to the Law Officer or the prosecutor.

75. Persons to administer oaths and affirmations.— All oaths and affirmations shall be administered by the Law Officer, a member of the court, or some other person empowered by the court to administer such oath or affirmation.

SECTION - 2

PROSECUTION, DEFENCE AND SUMMING UP

76. Arraignment.— (1) When the court and the Law Officer have been sworn or affirmed, the accused shall be arraigned on the charges against him, which includes reading out the charges and asking the accused whether he pleads guilty or not guilty to the charge or charges.

(2) If there is more than one charge against the accused he shall be required to plead separately to each charge.

(3) If there is more than one charge sheet, against the accused, before the court, the court shall proceed with the charges in the first of such charge sheets and shall announce its finding thereon and if the accused has pleaded guilty, comply with rule 93, before it arraigns him upon the charges in any subsequent charge sheet.

77. Plea to jurisdiction.— (1) The accused, before pleading to the charge, may offer a plea regarding the jurisdiction of the court; and in such a case—

(a) the accused may adduce evidence in support of the plea and the prosecutor may adduce evidence in answer thereto; and

(b) the prosecutor may address the court in answer to the plea and the accused may reply to the prosecutor's address.

(2) If the court allows the plea it shall record its decision, and the reasons for it, and report it to the convening authority and adjourn.

(3) When the court reports to the convening authority under this rule, the convening authority shall,—

(a) if it approves the decision of the court to allow the plea, dissolve the court;

(b) if it disapproves the decision of the court; either

(i) refer the matter back to the court and direct them to proceed with the trial; or

(ii) convene a fresh court to try the accused.

78. Objection to the charge.— (1) An accused before pleading to a charge may object to it on the grounds that it is not correct in law or is not framed in accordance with these rules and if he does so, the prosecutor may address the court in answer to the objection and the accused may reply to the prosecutor's address.

(2) If the court upholds the objection, it shall either amend the charge if permissible under rule 79 or adjourn and report to the convening authority :

Provided that if there is another charge or another charge sheet before the court, the court may, before adjourning under this rule, proceed with the trial of the accused on such other charge or other charge sheet.

(3) When the court reports to the convening authority under this rule, the convening authority shall—

(a) if it approves the decision of the court to allow the objection—

(i) dissolve the court; or

(ii) where there is another charge or another charge sheet before the court to which the objection does not relate and which the court has not tried, direct the court to proceed with the trial of the accused on such other charge or charge sheet only; or

(iii) amend the charge to which the objection relates if permissible under rule 77 and direct the court to try it as amended.

(b) if it disapproves the decision of the court to allow the objection—

(i) direct the court to try the charge, or

(ii) convene a fresh court to try the accused.

79. Amendment of the charge by the court.— (1) At any time during a trial, if it appears to the court that there is in the charge sheet;

(a) a mistake in the name or description of the accused; or

(b) a mistake which is attributable to a clerical error or omission, the court may amend the charge sheet so as to correct the mistake.

(2) If at any time during a trial, at which there is a Law Officer, it appears to the court, before it closes to deliberate on its findings, that it is desirable in the interests of justice to make any addition to, omission from or alteration in the charge(s) which cannot be made under sub-rule (1) of this rule, it may, if such addition, omission, or alteration can be made without unfairness to the accused, and with the concurrence of the Law Officer, so amend the charge(s).

(3) If at any time during a trial, at which there is no Law Officer, it appears to the court, before it closes to deliberate on its findings, that in the interests of justice it is desirable to make any addition to,

omission from or alteration in a charge which cannot be made under sub-rule (1) of this rule, it may adjourn and report its opinion to the convening authority, which may—

- (a) amend the charge if permissible under rule 80 and direct the court to try it as amended after due notice of the amendment has been given to the accused; or
- (b) direct the court to proceed with the trial of the charge without amending it; or
- (c) convene a fresh court to try the accused.

80. Amendment of charge by convening authority.— When a court reports to the convening authority under either rule 78 or rule 79, it may amend the charge which the court has reported to it by making any addition to, omission from or alteration in the charge which, in its opinion, is desirable in the interests of justice and which it is satisfied can be made without unfairness to the accused.

81. Plea in bar of trial. - (1) An accused before pleading to a charge may offer a plea that the trial is barred under Section 97 or Section 98 or on the ground that—

- (a) a charge in respect of the offence has been dismissed as provided in sub rule (3) of rule 47; or
- (b) the offence has been pardoned or condoned by competent superior authority.

(2) If he offers such plea—

- (a) the accused may adduce evidence in support of the plea and the prosecutor may adduce evidence in answer thereto, and
- (b) the prosecutor may address the court in answer to the plea and the accused may reply to the prosecutor's address.

(3) If the court allows the plea it shall record the same alongwith brief reasons in support thereof, and adjourn and report to the convening authority :

Provided that if there is another charge or another charge-sheet before the court, the court may, before adjourning under this rule, proceed with the trial of the accused on such other charge or the other charge sheet.

(4) When a court reports to the convening authority under this rule, the convening authority shall—

(a) if it approves the decision of the court to allow the plea—

- (i) dissolve the court; or
- (ii) where there is another charge or another charge sheet before the court, to which the plea does not relate and which the court has not tried, may direct the court to proceed with the trial of the accused on such other charge or charge sheet only.

(b) if it disapproves the decision of the court to allow the plea—

- (i) direct the court to try the accused on the charge; or
- (ii) where there is another charge or another charge sheet before the court, to which the plea does not relate and which the court has not tried, direct the court to proceed with the trial of the accused on such other charge or charge sheet only; or
- (iii) convene a fresh court to try the accused.

82. Application for separate trial.— (1) Where two or more accused are charged jointly, any one of the accused may, before pleading to the charge, apply to the court to be tried separately on the ground that he would be prejudiced in his defence if he were not tried separately.

(2) Where the accused makes such an application, the prosecutor may address the court in answer thereto and the accused may reply to the prosecutor's address.

(3) Where the court is of the opinion that the interests of justice so require it shall allow the application and try separately the accused who made it.

83. Application for trial on separate charge sheet.— (1) Where a charge sheet contains more than one charge, the accused may, before pleading to the charges, apply to the court to be tried separately on any charge in that charge sheet on the ground that he would be prejudiced in his defence if he were not tried separately on that charge.

(2) Where the accused makes such an application, the prosecutor may address the court in answer thereto and the accused may reply to the prosecutor's address.

(3) Where the court is of the opinion that the interests of justice so require it shall allow the application and try the accused separately on the charge to which it relates as if that charge had been inserted in a separate charge sheet.

84. Pleading to the charge.— (1) After any plea under rules 77 and 81 and any objection under rule 78 and any applications under rules 82 and 83 have been dealt with, the accused shall be required subject to sub-rule (2) to plead either guilty or not guilty to each charge on which he is arraigned. The accused person's plea guilty or not guilty shall be recorded on each charge.

(2) Where a court is empowered by Section 115 to find an accused guilty of an offence other than that charged or guilty of committing the offence in circumstances involving a less degree of punishment or where it could after hearing the evidence, make a special finding of guilty subject to exceptions or variations in accordance with rule 107, the accused may plead guilty to such other offence or to the offence charged as having been committed in circumstances involving a less degree of punishment or to the offence charged subject to such exceptions or variations.

85. Acceptance of plea of guilty.— (1) Where an accused pleads guilty to a charge under either sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 84, the Presiding Officer or Law Officer shall, before the court decides to accept the plea, explain to the accused the nature of the charge and the general effect of his plea and in particular the difference in procedure when an accused pleads guilty and when an accused pleads not guilty.

(2) Where an accused pleads guilty, such plea and the factum of compliance of sub-rule (1) of this rule, shall be recorded by the court in the following manner—

“Before recording the plea of guilty of the accused, the court explained to the accused the meaning of the charge (s) to which he had pleaded guilty and ascertained that the accused had understood the nature of the charge (s) to which he had pleaded guilty. The court also informed the accused the general effect of the plea and the difference in procedure, which will be followed consequent to the said plea. The court having satisfied itself that the accused understands the charge (s) and the effect of his plea of guilty accepts and records the same. The provisions of rule 85 (1) are thus complied with.”

(3) A court shall not accept a plea of guilty under either sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 84, if—

(a) the court is not satisfied that the accused understands the nature of the charge or the effect of his plea; or

(b) the Presiding Officer having regard to all the circumstances, considers that the accused should plead not guilty; or

(c) the accused is liable, if convicted, to be sentenced to death;

(4) (a) In the case of plea of guilty under rule 86, a court shall not accept the plea unless the convening authority concurs and it is satisfied of the justice of such course.

(b) the concurrence of the convening authority may be signified by the prosecutor.

(5) When a plea of guilty under either sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 84 is not accepted by the court or the accused either refuses to plead to the charge or does not plead to it intelligibly, the court shall record a plea of not guilty.

(6) When a court is satisfied that it can properly accept a plea of guilty under either sub-rule (1) or sub-rule (2) of rule 84, it shall record a finding of guilty in respect thereof subject to compliance of provisions of rule 88.

86. Plea on alternative charge.— (1) When an accused pleads guilty to the first of two or more alternative charges, the court, if it accepts the plea of guilty, shall record a finding of guilty in respect of the first charge and the prosecutor shall withdraw any alternative charge before the accused is arraigned on it.

(2) When an accused pleads guilty to one of two or more charges which are laid in the alternative other than the first of such charges, the court may—

(a) proceed as if the accused had pleaded not guilty to all the charges; or

(b) (i) with the concurrence of the convening authority (which may be signified by the prosecutor) record a finding of guilty on the charge to which the accused has pleaded guilty and a finding of not guilty on any alternative charge which is placed before it in the charge sheet.

(ii) where the court records such finding, the prosecutor shall before the accused is arraigned on it withdraw any charge which is alternative to the charge of which the court has found the accused guilty and which is placed after it in the charge sheet.

87. Order of trial where plea is guilty and not guilty.— (1) After the court has recorded a finding of guilty, if there is no other charge in the same charge sheet to which the accused has pleaded not guilty and no other accused who has pleaded not guilty to a charge in that charge sheet, it shall proceed with the trial as directed by rule 88.

(2) Where there is another charge in the charge sheet to which the accused has pleaded not guilty (or there is another accused who has pleaded not guilty) to a charge in that charge sheet, the court shall not comply with rule 85 until after it has dealt with such other charge or tried such other accused and has announced and recorded its finding in respect thereof.

88. Procedure on plea of guilty.— (1) When the court has recorded a plea of guilty in respect of the charge to which an accused had pleaded guilty, the prosecutor shall read the summary or abstract of evidence to the court and annex it to the proceedings or inform the court of the facts contained therein :

Provided that if an expurgated copy of the summary or abstract of evidence was sent to the Presiding Officer, the prosecutor shall not read to the court those parts of the summary or abstract of evidence which have been expurgated or inform the court of the facts contained in those parts, and shall not hand over the original summary or abstract of evidence to the court until the trial is concluded.

(2) After sub-rule (1) has been complied with, the accused may—

- (a) adduce evidence of character and in mitigation of punishment; and
- (b) address the court in mitigation of punishment.

(3) If from the statement of the accused or from the summary or abstract of evidence, or otherwise, it appear to the court that the accused did not understand the effect of his plea of guilty, the court shall alter the record and enter a plea of not guilty and proceed with the trial accordingly.

(4) After sub-rules (2) and (3) have been complied with, the court shall proceed as directed by sub-rule (6) of rule 85 and rule 109.

89. Change of plea.— (1) An accused who has pleaded not guilty may at any time before the court closes to deliberate on its finding withdraw his plea of not guilty and enter a plea of guilty (including a plea of guilty under rule 86) and in such a case the court shall, if it is satisfied that it can accept the accused's changed plea under these rules, record a finding in accordance with the accused's changed plea and so far as is necessary proceed as directed by rule 88.

(2) Where at any time during the trial it appears to the court that an accused who has pleaded guilty does not understand the effect of his plea or the nature of the charge the court shall enter a plea of not guilty and proceed with the trial accordingly.

(3) When the court records a plea of not guilty in respect of any charge under sub-rule (2) it shall, if there was a charge laid in the alternative thereto which the prosecutor withdrew under rule 86 reinstate such alternative charge, arraign the accused thereon and proceed with the trial as if it had never been withdrawn.

90. Procedure on plea of not guilty.— After a plea of not guilty to any charge has been recorded—

(a) the court shall ask the accused whether he wishes to apply for an adjournment on the ground that any of the rules relating to procedure before trial have not been complied with and that he has been prejudiced thereby or on the ground that he has not had sufficient opportunity for preparing his defence; and shall record his answer;

(b) where the accused applies for an adjournment;

(i) the accused may adduce evidence in support of his application and the prosecutor may adduce evidence in answer thereto; and

(ii) the prosecutor may address the court in answer to the application and the accused may reply to the prosecutor's address.

(c) the court may grant an adjournment if it thinks the interests of justice so require.

91. Opening address.— (1) The prosecutor may, if he so desires, and shall, if required by the court, make an opening address explaining the charge and the nature and general effect of the evidence which he proposes to adduce.

(2) The witnesses for the prosecution shall then be called and give their evidence.

(3) If it should be necessary for the prosecutor to give evidence for the prosecution on the facts of the case, he shall give it after the delivery of his address, and he must be sworn or affirmed, as the case may be, and give his evidence. He may be cross examined by or on behalf of the accused and afterwards may make any statement which might be made by a witness on re-examination.

92. Additional witness.— Where the prosecutor intends to adduce evidence which is not contained in the summary or abstract of evidence given to the accused, notice of such intention together with the particulars of the proposed evidence shall, when practicable, be given to the accused a reasonable time before the evidence is adduced. If such evidence is adduced without such notice or particulars having been given, the court may, if the accused so desires, either adjourn after receiving the evidence or allow any cross-examination arising out of that evidence to be postponed, and the court shall inform the accused of his right to apply for such an adjournment or postponement.

93. Dropping witnesses.— The prosecutor shall not be bound to call all the witnesses against the accused whose evidence is contained in the summary of evidence, nor a witness when he had notified the accused that he intends to call under rule 92, but if the prosecutor does not intend to call such witness to give evidence, he shall either tender him for cross-examination by the accused, or give the accused reasonable notice that he does not intend to call the witness and that so far as practicable, the accused will be allowed to communicate with him and to call him as a witness for the defence, if he so desires and if the witness is available.

94. Procedure when essential witness is absent.— If any witness whose attendance could not be reasonably procured before the assembly of the court is essential to the prosecution or defence, the court shall—

- (a) take steps to procure the issue of a commission for the examination of such witness; or
- (b) if it is a general or petty Assam Rifles Court, adjourn and report the circumstance to the convening authority; or
- (c) if it is a summary Assam Rifles Court, adjourn to enable the witness to attend, or adopt such other course as appears to the officer holding the trial best calculated to do justice.

95. Withdrawal of witnesses.— During a trial a witness other than the prosecutor or accused shall not, except by leave of the court, be in court while not under examination, and if while he is under examination a discussion arises as to whether a question is to be allowed or not with regard to his evidence, the court may direct the witness to withdraw during such discussion.

96. Examination of witnesses.— (1) A witness may be examined by the person calling him and may be cross examined by the opposite party to the proceedings and on the conclusion of any such cross-examination, may be re examined by the person who called him on matters arising out of the cross-examination.

- (2) (a) The person examining a witness shall put his questions to the witness orally and unless an objection is made by the witness, the court, the Law Officer, the prosecutor or by the accused, the witness shall reply forthwith;
- (b) where such an objection is made, the witness shall not reply until the objection has been disposed of.
- (3) The court may allow the cross-examination or re-examination of a witness to be postponed.
- (4) Before the examination of a witness, he shall be administered an oath or affirmation in the following form or in such other form to the same purport as the court ascertains to be in accordance with his religion or otherwise binding on his conscience.

FORM OF OATH

"I.....swear by Almighty God that whatever I shall state, shall be the truth, the whole truth and nothing but the truth".

FORM OF AFFIRMATION

"I..... do solemnly, truly and sincerely declare and affirm that whatever I shall state, shall be the truth the whole truth and nothing but the truth."

97. Questions by the court.— (1) The Presiding Officer, the Law Officer and any member of the court through the Law Officer if there is any or the Presiding Officer may put questions to a witness.

(2) Upon any such question being answered, the prosecutor and the accused may put to the witness, through the court, such questions arising from the answer which he has given as seem proper to the court.

98. Reading over of evidence.— (1) (a) The record which has been made of the evidence given by a witness shall be read back to him before he leaves the court and when this is done, he may ask for the record to be corrected or explain the evidence which he has given.

(b) where any such correction is made or explanation given, the prosecutor and the accused may put such questions to the witness respecting the correction or explanation as seem proper to the court.

(2) When a short hand writer is employed it shall not be necessary to comply with sub-rule (1), if in the opinion of the court and the Law Officer it is unnecessary to do so :

Provided that if any witness so demands, sub-rule (1) shall be complied with.

99. Calling or recalling of witnesses by the court.— (1) (a) The court may at any time before it closes to deliberate on its finding or if there is a Law Officer, before he begins to sum up, call a witness or recall a witness, if in the opinion of the court it is in the interest of justice to do so.

(b) where the court calls a witness or recalls a witness under this rule, the prosecutor and the accused may put such questions to the witness as seem proper to the court.

(2) The prosecutor and the accused may, at any time before the court closes to deliberate on its finding or if there is a Law Officer before he begins to sum up, recall a witness by leave of the court and the prosecutor and the accused may put such questions to the witness as seem proper to the court.

100. Plea of no case.— (1) (a) At the close of the case for the prosecution, the accused may submit to the court in respect of any charge that the prosecution has failed to establish a *prima facie* case for him to answer and that he should not be called upon to make his defence to that charge.

(b) where the accused makes such submission, the prosecutor may address the court in answer thereto and the accused may reply to the prosecutor's address.

- (2) The court shall not allow the submission unless it is satisfied that—
- (a) the prosecution has not established a *prima facie* case on the charge as laid; and
 - (b) it is not open to it on the evidence to make a special finding under either Section 115 or sub rule (4) of rule 107.
- (3) (a) Where the Court allows the submission, it shall find the accused not guilty of the charge to which it relates and the finding shall forthwith be announced in open Court as subject to confirmation.
- (b) where the court disallows the submission, it shall proceed with the trial of the offence as charged.
- (4) The court may, of its own motion, after the close of the hearing of the case for the prosecution, and after hearing the prosecutor find the accused not guilty of the charge and the finding shall forthwith be announced in open court subject to confirmation.
- (5) The court shall record brief reasons while arriving at the finding on the plea, in accordance with sub rule (1) of rule 107.

101. Case for the defence.—

- (1) (a) In every trial, for the purpose of enabling the accused personally to explain any circumstances appearing in evidence against him, the Court or the Law Officer—
- (i) may at any stage of the trial, without previously warning the accused, put such questions to him as the Court considers necessary; and
 - (ii) shall for the purpose aforesaid, question him generally on the case after the witnesses for the prosecution have been examined and before he is called on for his defence.
- (b) no oath or affirmation shall be administered to the accused when he is examined under clause (a).
- (c) the accused shall not render himself liable to punishments by refusing to answer such questions, or by giving false answers to them.
- (2) The answers given by the accused may be taken into consideration in such trial and put in evidence for or against him in any other inquiry into, or trial for, any other offence which such answers may tend to show he has committed.
- (3) After the close of the case for the prosecution, the Presiding Officer or the Law Officer shall explain to the accused that—
- (a) if he wishes, he may give evidence on oath as a witness or make a statement without being sworn or affirmed, but that he is not obliged to do either.
 - (b) if he gives evidence on oath, he shall be liable to be cross examined by the prosecutor and to be questioned by the court.
- (4) If the accused intends to call a witness to the facts of the case other than himself, he may make an opening address outlining the case for the defence before the evidence for the defence is given.

102. Witnesses for defence.— (1) After rule 101 has been complied with the witnesses for the defence, including witnesses as to character, shall be called to give their evidence.

(2) The provisions of rules 96, 97 and 98 shall apply to the witnesses for the defence as they apply to the evidence of witnesses for the prosecution.

103. Witnesses in reply.— After the witnesses for the defence have given their evidence, the prosecutor may, by leave of the court call a witness or recall a witness to give evidence on any matter raised by the accused in his defence which the prosecution could not properly have mentioned to the court before the accused disclosed his defence or which the prosecution could not reasonably have foreseen.

104. Closing address.— (1) After all the evidence has been given, the prosecutor may make a closing address and the accused or his counsel or the defending officer, as the case may be, shall be entitled to reply :

Provided that where any point of law is raised by the accused, the prosecutor may with the permission of the court, make the submission with regard to that point.

(2) Where two or more accused are represented by same defending officer or counsel he may make one closing address only.

105. Summing up by Law Officer.— After the closing address, if there is a Law Officer, he shall sum up the evidence and advise the court on the law relating to the case in open court.

106. Deliberation on finding.— (1) The court shall deliberate on its finding in closed court in the presence of the Law Officer.

(2) The opinion of each member of the court as to the finding shall be given by word of mouth on each charge separately starting with the junior most in rank.

107. Record and announcement of findings.—(1) The finding on every charge upon which the accused is arraigned shall be recorded and, except as provided in these rules, shall be recorded as findings of guilty or of not guilty. After recording the findings on each charge, the court shall give brief reasons in support thereof. The Law Officer or, if there is none, the Presiding Officer shall record or cause to be recorded such brief reasons in the proceedings. The above record shall be signed and dated by the Presiding Officer and the Law Officer, if any.

(2) Where the court is of opinion as regards any charge that the facts proved do not disclose the offence charged or any offence of which he might under the Act legally be found guilty on the charge as laid, the court shall acquit the accused of that charge.

(3) If the court has doubts as regards any charge whether the facts proved show the accused to be guilty on the charge as laid, it may, before recording a finding on that charge, refer to the confirming authority for an opinion, setting out the facts which it finds to be proved and may if necessary adjourn for that purpose.

(4) Where the court is of opinion as regards any charge that the facts which it finds to be proved in evidence differ materially from the facts alleged in the statement of particulars in the charge but are nevertheless sufficient to prove the offence stated in the charge, and that the difference is not so material as to have prejudiced the accused in his defence, it may, instead of a finding of not guilty record a special finding.

(5) The special finding may find the accused guilty on a charge subject to the statement of exceptions or variations specified therein.

(6) Where there are alternative charges, and the facts proved appear to the court not to constitute the offence mentioned in any of those alternative charges, the court shall record a finding of not guilty on that charge.

(7) The court shall not find the accused guilty on more than one of two or more charges laid in the alternative, even if conviction upon one charge necessarily connotes guilty upon the alternative charge or charges.

(8) If the court thinks that the facts proved constitute one of the offences stated in two or more of the alternative charges, but doubts which of those offences the facts do at law constitute, it may, before recording a finding on those charges, refer to the confirming authority for an opinion, setting out the facts which it finds to be proved and stating that it doubts whether those facts constitute in law the offence stated in such one or other of the charges and may, if necessary, adjourn for that purpose.

(9) The finding on each charge shall be announced forthwith in open court as subject to confirmation.

108. Procedure on acquittal.—If the finding on all the charges is not guilty the Presiding Officer shall affix his signature and date on the finding and such signature shall authenticate the whole of the proceedings, and the proceedings upon being signed by the Law Officer shall be at once transmitted for confirmation.

109. Procedure on conviction.—(1) If the finding on any charge is guilty, then, for the guidance of the court in determining its sentence, and of the confirming authority in considering the sentence, the court, before deliberating on the sentence, shall, whenever possible, take evidence of and record the general character, age, service, rank, any recognized acts of gallantry or distinguished conduct of the accused, any previous convictions of the accused either by Force Court or a criminal court, any previous punishments awarded to him by an officer exercising authority under Section 65, 67, 68 or 69, as the case may be; the length of time he has been under arrest, or in confinement on any previous sentence, and any decoration, or reward, of which he may be in possession or to which he is entitled.

(2) Evidence on the above matters may be given by a witness verifying a statement which contains a summary of entries in the service book respecting the accused and identifying the accused as the person referred to in that summary.

(3) The accused may cross-examine any such witness and may call witness to rebut such evidence; and if the accused so requests, the service books or a duly certified copy of the material entries therein, shall be produced and if the accused alleges that the summary is in any respect not in accordance with the service books or such certified copy, as the case may be, the court shall compare the summary with those books or copy and if it finds that it is not in accordance therewith, shall cause summary to be corrected or the objection of the accused to be recorded.

(4) When all the evidence on the above matters has been given, the accused may address the court thereon and in mitigation of punishment.

110. Sentence.— The court shall award a single sentence in respect of all the offences of which the accused is found guilty, and such sentence shall be deemed to be awarded in respect of which it can be legally given and not to be awarded in respect of which it can not be legally given.

111. Recommendation for mercy.— (1) Where the court makes a recommendation to mercy it shall give its reasons for its recommendation.

(2) The number of opinions by which the recommendation to mercy mentioned in this rule, or any question relating thereto, is adopted or rejected, may be entered in the proceedings.

112. Announcement of the sentence and signing and transmission of proceedings.— (1) The sentence together with any recommendation to mercy and the reasons for any such recommendation shall be announced forthwith in open court. The sentence will be announced as subject to confirmation.

(2) Upon the court awarding the sentence, the Presiding Officer shall affix his signature and date to the sentence and such signature shall authenticate the whole of the proceedings, and the proceedings upon being signed by the Law Officer, if any, shall at once be transmitted for confirmation.

CONFIRMATION AND REVISION

113. Revision.— (1) (a) Where the finding is sent back for revision under Section 135, the court shall re-assemble in open court, the revision order shall be read and if the court, is directed to take fresh evidence such evidence shall be taken in open court;

(b) except where the court is directed to take fresh evidence, no fresh evidence shall be adduced;

(c) where such fresh evidence is recorded otherwise than at the instance of the accused, the accused shall be given a further opportunity to lead evidence in respect of matters brought out in such fresh evidence;

(d) the court may, on a request from the prosecutor, in the interest of justice, allow a witness to be called or re-called for the purpose of rebutting any material statement made by a witness for the defence during revision;

(e) after the evidence, if any, in accordance with clauses (a), (b), (c) and (d) above, have been taken, the prosecutor and the accused shall be given a further opportunity to address the court in respect of the fresh evidence led, in the order as laid down in rule 104;

(f) Law Officer, if any, may sum up the additional evidence and advise the court upon the law relating to the case.

(2) Where the revision of finding does not involve taking of fresh evidence, the accused shall be given an opportunity to address the court in respect of matter raised in the revision order.

(3) (a) The court shall then deliberate on its finding in closed court and if the court does not adhere to its former finding, it shall revoke the finding and sentence and record a new finding in the manner laid down in rule 107 and if such new finding involves a sentence, pass sentence afresh after complying with rule 109.

(b) where the original finding was one of not guilty, the court shall, before passing sentence comply with rules 109 and 110.

(4) (a) Where the sentence alone is sent back for revision, the revision order shall be read in open court and the accused given an opportunity to address the court in regard to matters referred to in the revision order.

(b) the court shall then reconsider its sentence in closed court and if it does not adhere to the sentence; revoke the same and pass sentence afresh.

(5) Where the sentence alone is sent for revision the court shall not revise the finding.

(6) After the revision, the Presiding Officer shall date and sign the decision of the court, and the proceedings, upon being signed by the Law Officer, if any, shall at once be transmitted for confirmation.

114. Confirmation.— (1) When a confirming authority receives the record of the proceedings of a court, it shall record its decision thereon and on any sentence and any order which the court may have made under Section 127 on the record of the proceedings in the form set out in Appendix-X and such record of his decision shall form part of the record of the proceedings.

(2) When a court has accepted a plea of guilty made under rule 85 the confirming authority may confirm its finding notwithstanding that the court has accepted the plea without the concurrence of the convening authority, if, in the opinion of the confirming authority, it is in the interest of justice to do so.

(3) (a) When a court has rejected a plea to the jurisdiction of the court or a plea in bar of trial or has over-ruled an objection to a charge, it shall not be necessary for the confirming authority to approve specifically the decision of the court, but its approval shall be implied from its confirming the finding on the charge to which the plea or objection relates.

(b) where it disapproves the decision of the court to reject the plea or to over rule the objection it shall withhold confirmation of the finding on the charge to which the plea or objection relates.

(4) A confirming authority may state its reasons for withholding confirmation in any case, but if it withholds confirmation where a court has rejected a plea to the jurisdiction or plea in bar of trial or has over ruled an objection to the charges because it disapproves this decision of the court, it shall record its decision under sub-rule (1) stating the reasons for withholding its confirmation.

(5) Where the sentence of court is improperly expressed, the confirming authority may, in confirming the sentence, vary the form thereof so that it shall be properly expressed; and if the punishment awarded by the sentence is in excess of the punishment authorised by law, the confirming authority may vary the sentence so that the sentence shall not be in excess of the punishment authorised by law; and the confirming authority may confirm the finding and the sentence, as so varied, of the court.

(6) Whenever it appears that there is sufficient evidence on a plea of guilty under either sub-rule(1) or sub-rule (2) of rule 85 to justify the finding of the court, such finding and any lawful sentence consequent thereon may be confirmed and if confirmed shall be valid, notwithstanding any deviation from these rules if the accused has not been prejudiced by such deviation.

(7) The confirming authority may reserve confirmation to superior authority if so required owing to such restrictions, reservations or conditions as contained in warrant issued under Section 132.

115. Mitigation of sentence during confirmation.— (1) While confirming the finding, the confirming authority may either unconditionally or subject to conditions which the accused accepts, reduce or remit a portion of the sentence or commute the punishment to one given lower in the scale of punishments in Section 57.

(2) Where a sentence has been awarded by a court in respect of offences in several charges, and the confirming authority confirms the finding on some but not on all of such charges, that authority shall take into consideration the fact of such non confirmation, and shall, if it seems just, mitigate, remit, or commute the punishment awarded as it seems just, having regard to the offences in the charges in respect of the findings which are confirmed.

(3) Where a sentence has been awarded by a court in respect of offences in several charges and has been confirmed, and any one of such charges or the finding thereon is found to be invalid, the authority having power to mitigate, remit or commute the punishment awarded by the sentence shall take into consideration the fact of such invalidity, and if it seems just, mitigate, remit or commute the punishment awarded as it seems just, having regard to the offences in the charges which with the findings thereon are not invalid, and the punishment as so modified shall be as valid as if it had been originally awarded only in respect of those offences.

116. Promulgation.— (1) When a confirming authority has confirmed a finding and a sentence of a court or has withheld confirmation thereof, it shall send the record of the proceedings to the Commandant of the accused for promulgation to the accused of the charge, finding, and sentence and any recommendation to mercy or the fact that confirmation has been withheld, as the case may be.

(2) The fact of promulgation shall be recorded on the record of the proceedings in the form set out in Appendix-XI.

(3) Where confirmation has been withheld because the confirming authority disapproves the court's decision to reject a plea to the jurisdiction or a plea in bar of trial or to over rule an objection to the charge, the accused shall be so informed.

(4) Until promulgation has been effected, confirmation is not complete and the finding and sentence shall not be held to have been confirmed until they have been promulgated.

CHAPTER - XI

PROCEDURE OF FORCE COURTS AND INCIDENTAL MATTERS

117. Seating of members.— The members of a court shall take their seats according to seniority.

118. Responsibility of presiding officer.— (1) The presiding officer is responsible for the trial being conducted in proper order, and in accordance with the Act, rules made there-under and in a manner befitting a court of justice.

(2) It is the duty of the Presiding Officer to see that the accused has a fair trial, and that he does not suffer any disadvantage in consequence of his position as a person under trial, or of his ignorance, or of his incapacity to examine or cross-examine witnesses, or otherwise.

119. Power of court over address of prosecutor and accused.— (1) It is the duty of the prosecutor to assist the court in the administration of justice, to behave impartially, to bring the whole of

the transaction before the court and not to take any unfair advantage of or suppress any evidence in favour of the accused.

(2) The prosecutor may not refer to any matter not relevant to the charge or charges then before the court and it is the duty of the court to stop him from so doing and also to restrain any undue violence of language or want of fairness or moderation on the part of the prosecutor.

(3) The court shall give reasonable facilities to the accused, in making his defence; the accused must abstain from any remarks contemptuous or disrespectful towards the court, and from coarse and insulting language towards others, but he may for the purpose of his defence impeach the evidence and the motives of the witnesses and the prosecutor, and charge other persons with blame and even criminality, subject, if he does so, to any liability which he may thereby incur. The court may caution the accused as to the irrelevance of his defence, but shall not, unless in special cases, stop his defence solely on ground of such irrelevance.

120. Sitting in closed court.— (1) A court shall, where it is so directed by these rules, and may in any other case on any deliberation amongst the members, sit in closed court.

(2) No person shall be present in closed court except the members of the court, the Law Officer and any officers under instruction.

(3) For the purpose of giving effect to the foregoing provisions of this rule, the court may either retire or cause the place where it sits to be cleared of all other persons not entitled to be present.

(4) Except as here-in-before mentioned, all proceedings including the view of any place shall be in open court and in the presence of the accused subject to sub-rule (5).

(5) The court shall have the power to exclude from the court any witness who is yet to give evidence or any other person, other than the accused, who interferes with its proceedings.

121. Courts to be public.— Subject to rule 120, the place in which a court is held for the purpose of trying an offence under the Act shall be deemed to be an open court to which the public generally may have access, so far as the same can conveniently contain them :

Provided that if the court is satisfied that it is necessary or expedient in the public interest or for the ends of justice so to do, the court may at any stage of the trial of any particular case order that the public generally or any portion thereof or any particular person shall not have access to, or be or remain in, the place in which the court is held.

122. Continuity of trial and adjournment.— (1) Once the court is assembled and the accused has been arraigned, the court shall continue the trial from day-to-day unless it appears to the court that an adjournment is necessary for the ends of justice or that such continuance is impracticable.

(2) (a) A court may from time to time adjourn its proceedings and meet at such place as may be convenient, and

(b) wherever necessary, visit the scene of occurrence.

(3) The senior officer on the spot may also, for exigencies of service, adjourn or prolong the adjournment of the court.

(4) A court, in the absence of a Law Officer (if one has been appointed for that court) shall not proceed, and shall adjourn.

(5) If the time to which an adjournment is made is not specified, the adjournment shall be until further orders from the proper Force authority, and, if the place to which an adjournment is made is not specified, the adjournment shall be to the same place or to such other as may be specified in further orders from the proper Force authority.

123. Suspension of trial.— (1) Where in consequence of anything arising while the court is sitting, the court is unable by reason of dissolution as specified in Section 93 or otherwise, to continue the trial, the Presiding Officer or, in his absence the senior member present, shall immediately report the facts to the convening authority.

(2) Where a court is dissolved before the finding, or, in case of a finding of guilty, before award of sentence, the entire proceedings before the court shall be null and the accused may be tried before another court.

124. Proceedings on death or illness of accused.— In case of the death of the accused or of such illness of the accused as renders it impossible to continue the trial, the Court shall ascertain the fact of the death or illness by evidence and record the same and adjourn and transmit the proceedings to the convening authority.

125. Death, retirement or absence of Presiding Officer.— In the case of the death, retirement on challenge or unavoidable absence of the presiding officer, the next senior officer shall take the place of the Presiding Officer and the trial shall proceed if the court is still composed of not less than the minimum number of officers of which it is required by law to consist.

126. Presence of all members of court.— (1) All members of the court shall remain present during the trial of an accused; any member of a court who has been absent while any part of the evidence on the trial of an accused person is taken, shall take no further part in the trial of that person, but the court will not be affected unless it is reduced below the legal minimum.

(2) An officer shall not be added to a court after the accused has been arraigned.

127. Taking of opinions of members of court.— (1) Every member of the court must give his opinion by word of mouth on every question which the court has to decide, and must give his opinion as to the sentence notwithstanding that he has given his opinion in favour of acquittal.

(2) The opinion of the members of the court shall be taken in succession, beginning with the member lowest in seniority.

128. Procedure on incidental questions.— If any objection is raised on any matter of law, evidence or procedure, by the prosecutor or by or on behalf of the accused during the trial, the prosecutor or the accused or counsel or the defending officer, as the case may be, shall have a right to answer the same and the person raising the objection shall have a right to reply.

129. Evidence, when to be translated.— (1) When any evidence is given in a language, which any of the officers comprising the court, the Law Officer, the prosecutor, the accused or his defending officer or counsel does not understand, that evidence shall be interpreted to such officer or person in a language which he does understand. If an interpreter in such language has been appointed by the convening authority, and duly sworn or affirmed, the evidence shall be interpreted by him.

(2) If no such interpreter has been appointed and sworn or affirmed, an impartial person be sworn or affirmed by the court as interpreter.

(3) Before a person is sworn or affirmed as interpreter under this rule, the accused shall be informed of the person who is proposed to be sworn or affirmed, and may object to the person as not being impartial for any reasonable cause, and the court, if it thinks that the objection is reasonable, shall not swear or affirm that person as interpreter.

(4) When documents are produced for the purpose of formal proof, it shall be in the discretion of the court to ensure as much to be interpreted as appears necessary.

130. Record in proceedings of transactions of a court.— (1) At a court, the Law Officer or, if there is none, the Presiding Officer shall record or cause to be recorded in Hindi or English language all transactions of the court, and shall be responsible for the accuracy of the record (in these rules referred to as the proceedings), and if the Law Officer is called as a witness by the accused, the presiding officer shall be responsible for the accuracy of the record in the proceedings of the evidence of the Law Officer.

(2) The evidence shall be taken down in a narrative form in, as nearly as possible, the words used. But in any case where the prosecutor, the accused, the Law Officer or the court considers it material, the question and answer shall be taken down verbatim.

(3) Where an objection has been taken to any question or to the admission of any evidence or to the procedure of the court, such objection shall, if the prosecutor or accused so requests, or the court thinks fit, be entered upon the proceedings together with the grounds of the objection and the decision of the court thereon.

(4) Where any address by, or on behalf of the prosecutor or the accused, is not in writing, it shall not be necessary to record the same in the proceedings further or otherwise than the court thinks proper, except that—

(a) the court shall in every case make such record of the defence, made by the accused as will enable the confirming authority to judge of the reply made by, or on behalf of the accused to each charge against him, and

(b) the court shall also record any particular matters in the address by or on behalf of the prosecutor or the accused which the prosecutor or the accused, as the case may be, may require.

(5) The court shall not enter in the proceedings any comment or anything not before the court, or any report or any fact not forming part of the trial, but if any such comment or report seems to the court necessary, the court may forward it to the proper authority in a separate document, signed by the presiding officer.

131. Custody and inspection of proceedings.— The proceedings shall be deemed to be in the custody of the Law Officer, or, if there is none, of the presiding officer, but may with proper precaution for their safety, be inspected by the members of the court, the prosecutor and accused, at all reasonable time before the court is closed to consider the findings.

132. Review of general or petty Assam Rifles Court proceedings.— The proceedings of general Assam Rifles Court and petty Assam Rifles Court shall be sent by the person having the custody thereof to the Chief Law Officer or any Law Officer nominated by him for review, who shall then forward the same to the confirming authority.

133. Defending officer, friend of accused and counsel.— (1) At any general or petty Assam Rifles Court, an accused person may be represented by a counsel or by any officer subject to the Act who shall be called the defending officer or assisted by any person whose services he may be able to procure and who shall be called "the friend of the accused".

(2) The defending officer shall have the same rights and duties as appertain to a counsel under these rules and shall be under the like obligations.

(3) The 'friend of an accused' may advise the accused on all points and suggest the questions to be put to the witnesses, but he shall not examine or cross-examine the witnesses or address the Court.

134. Requirement for appearance of counsel.— (1) An accused person intending to be represented by a counsel shall give to his Commandant or to the convening officer, an earliest practicable notice of such intention, and if no sufficient notice has been given, the court may, if it thinks fit, on the application of the prosecutor, adjourn to enable him to obtain a counsel on behalf of the prosecutor at the trial.

(2) Where the convening officer so directs, counsel may appear alongwith the prosecutor, but in that case, unless the notice referred to in sub-rule(1) has been given by the accused, notice of the direction for counsel to appear shall be given to the accused at such time, but in any case not less than seven days before the trial, as would, in the opinion of the court, enable the accused to obtain counsel to assist him at the trial.

(3) The counsel, who appears before a court on behalf of the prosecutor or accused, shall have the same rights as the prosecutor or accused, for whom he appears, to call, and orally examine, cross-examine and re examine witnesses, to put in any plea, and to inspect the proceedings, and shall have the right otherwise to act in the course of the trial in place of the person on whose behalf he appears. He shall comply with the provisions of these rules as if he were that person and in such a case that person shall have no right himself to any of the aforesaid matters except as regards the statement allowed by sub-rule (2) of rule 102 and sub-rule (4) of rule 109 or except so far as the court permits him to do so.

135. Disqualification of Law Officer.— An officer who is disqualified for sitting on a court, shall be disqualified for acting as a Law Officer at that court.

136. Substitution on death, illness or absence of Law Officer.— In the case of death or illness or any other case which makes the Law Officer unable to attend in that case, the court shall adjourn, and the Presiding Officer shall report accordingly to the convening officer. On receipt of the report, the convening officer may appoint another person who shall be sworn or affirmed, and act as Law Officer for the residue of the trial, or until the Law Officer returns, as the case may be.

137. Power and duties of Law Officer.— (1) Where a Law Officer has been named to act on the court, he shall,—

(a) give his opinion on any question of law relating to the charge or trial whenever so required by the court, prosecutor or the accused;

(b) inform the court of any irregularity or other infirmity in the proceedings,

(c) inform the convening officer and the court of any infirmity or defect in the charge or in the constitution of the court;

(d) sum up the evidence and give his opinion on any question of law, before the Court proceeds to deliberate upon its findings.

(2) It shall be the duty of the Law Officer to ensure that the accused does not suffer any disadvantage in consequence of his position as such, or because of ignorance or incapacity to examine or cross-examine witnesses, or otherwise and for this purpose the Law Officer may, with the permission of the court, call witnesses and put questions to them which appear to him to be necessary or desirable to elicit the truth.

(3) In the discharge of his duties, the Law Officer shall maintain an attitude of strict impartiality.

(4) Where any opinion has been given by the Law Officer to the court on any matter before it, it may be entered in the proceedings, if the Law Officer or the court desires it to be entered.

(5) The Law Officer shall represent the Chief Law Officer at a Force Court.

138. Finding of insanity.— Where the court finds either that an accused, by reasons of unsoundness of mind, is incapable of making his defence, or that he committed the act alleged but was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing the nature of the act or that it was wrong or contrary to law, the presiding officer or in the case of Summary Assam Rifles Court, the officer

holding the trial, shall affix his signature and the date on the finding which shall also be signed by the Law Officer and thereupon the proceedings, shall, at once, be transmitted to the confirming authority or in the case of Summary Assam Rifles Court, to the Deputy Inspector-General or the Additional Deputy Inspector-General empowered to countersign them.

139. Preservation of proceedings.— The proceedings of every Force Court shall, after promulgation, be forwarded to the office of the Chief Law Officer and be preserved there for not less than seven years, in the case of general and petty Assam Rifles Court and three years in the case of Summary Assam Rifles Court, or until the sentence awarded by the court has expired, whichever is later.

140. Right of person tried to copies of proceedings.— Every Assam Rifles person tried by a Assam Rifles Court shall be entitled to obtain on demand, at anytime after the confirmation of the finding and sentence, when such confirmation is required and in case of Summary Assam Rifles Court after the same is signed by the officer holding the trial, and before the proceedings are destroyed, from the Chief Law Officer or the Court, a copy thereof within a reasonable time and free of cost, including the proceedings upon revision, if any.

141. Copy of proceedings not to be given in certain cases.— Notwithstanding anything contained in rule 140, if the Central Government is satisfied for reasons to be recorded that it is against the interest of the security of the State or friendly relations with foreign States to supply a copy of the proceedings or any part thereof under the said rule, he shall not be furnished with such a copy:

Provided that if the Central Government is satisfied that the person demanding the copy is desirous of submitting a petition in accordance with the Act or instituting any action in a court of law in relation to the finding or sentence, it shall permit inspection of the proceedings by such a person or his legal advisor, if any, on the following conditions :-

(a) the inspection shall be made at such times and such places as the Central Government or any authority authorised by it may direct; and

(b) the person allowed to inspect the proceedings shall, before such inspection, furnish -

(i) an undertaking, in writing that he shall not make copies of the proceedings or any part thereof and that the information or documents contained in such proceedings shall not be used by him for any purpose whatsoever, other than for the purpose of submitting a petition in accordance with the Act or instituting an action in a court of law in relation to the said finding or sentence; and

(ii) a certificate that he is aware that he may render himself liable to prosecution under Section 3 and 5 of the Indian Official Secrets Act, 1923 (19 of 1923) if he commits any act specified in the said Sections in relation to the documents or information contained in the said proceedings.

142. Loss of proceedings.— (1) If, before confirmation, the original proceedings of a court which require confirmation or any part thereof, are lost, a copy thereof, if any, certified by the presiding officer or the Law Officer at the court, may be accepted in lieu of the original.

(2) If there is no such copy, and sufficient evidence of the charge, finding, sentence and transactions of the court can be procured, that evidence may with the assent of the accused, be accepted in lieu of the original proceedings, or parts thereof, which have been lost.

(3) In any case mentioned above in this rule, the finding and sentence may be confirmed, and shall be valid as if the original proceedings, or part thereof, had not been lost.

(4) If the accused refuses the assent referred to in sub-rule (2), he may be tried again, and the finding and sentence of the previous court of which the proceedings have been lost shall be void.

(5) If, after confirmation or in any case where confirmation is not required, the original proceedings or any part thereof are lost, and there is sufficient evidence of the charge, finding, sentence, and transactions of the court and of the confirmation (if required) of the finding and sentence, that evidence shall be a valid and sufficient record of the trial for all purposes.

143. Offences by witnesses and others.— When a court is of opinion that there is ground for inquiring into any offence specified in Sections 46 and 47 and committed before it or brought to its notice in the course of its proceedings, which would, if done by a person subject to the Act, have constituted such an offence, such court may proceed as follows, that is to say—

(a) if the person who appears to have committed the offence is subject to the Act, the Court may bring his conduct to the notice of his Commandant; and may also order him to be placed in Force custody with a view to his punishment by an officer exercising authority under Section 61, 64, 65 or 66 or his trial by a Force Court.

(b) if the person who appears to have done the act is amenable to a law relating to the Armed Force of the Union, the court may bring his conduct to the notice of the proper authority of the concerned Armed Force, as the case may be,

(c) in other case the officer who summoned the witness to appear or the Presiding Officer or officer holding the court, as the case may be, may forward a written complaint to the nearest magistrate of the first class having jurisdiction, and in the case of acts which would, if done by a person subject to this Act have constituted an offence under clause (e) of Section 46 or Section 47, the court, after making any preliminary inquiry that may be necessary, may send the case to the nearest magistrate of the first class having jurisdiction for inquiry or trial in accordance with Section 340 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974).

CHAPTER - XII

SUMMARY ASSAM RIFLES COURTS

144. Proceedings.— (1) The officer holding the trial (here-in-after in this Chapter called the court), shall record, or cause to be recorded in the Hindi or English language, the transaction of every summary Assam Rifles Court.

(2) The evidence shall be taken down in a narrative form in as nearly as possible the words used; but in any case where the Court considers it material, the question and answer shall be taken down verbatim.

145. Evidence when to be translated.— (1) When any evidence is given in a language which the court or the accused does not understand, that evidence shall be translated to the court or accused as the case may be in a language which it or he understands.

(2) The court shall for this purpose either appoint an interpreter, or shall itself take the oath or affirmation prescribed for the interpreter at a summary Assam Rifles Court.

(3) When the documents are produced for the purpose of formal proof, it shall be in the discretion of the court to cause as much to be interpreted as appears necessary.

146. Assembly.— When the court, the interpreter and the officers and subordinate officers attending the trial are assembled, the accused shall be brought before the court and the oath or affirmation prescribed in rule 147 shall be taken by the persons therein mentioned.

147. Swearing or affirming of court and interpreter.— The court shall take oath or affirmation in any one of the following forms or in such other form to the same purport which would, according to the religion, or otherwise, be binding on the conscience of the officer constituting the court.

FORM OF OATH

"I.....swear by Almighty God that I will duly administer justice, according to the Assam Rifles Act without partiality, favour or affection".

FORM OF AFFIRMATION

"I.....do solemnly, sincerely and truly declare and affirm that I will duly administer justice according to the Assam Rifles Act without partiality, favour or affection".

(2) The court, or any other person empowered by it in this behalf shall administer to the interpreter an oath or affirmation in any of the following forms, or in such other form to the same purport as the court ascertains to be according to the religion, or otherwise, binding on the conscience of the person who is to act as interpreter.

FORM OF OATH

"I.....swear by Almighty God that I will faithfully interpret and translate as I shall be required to do, touching the matter before this court".

FORM OF AFFIRMATION

"I.....do solemnly, sincerely and truly declare and affirm that I will faithfully interpret and translate, as I shall be required to do, touching the matter before this court".

(3) The witnesses shall, after the administration of the oath and the affirmation, withdraw from the court.

148. Swearing of court to try several accused persons.— (1) A summary Assam Rifles Court may be sworn or affirmed at the same time to try any number of accused persons then present before it whether those persons are to be tried collectively or separately.

(2) In the case of several accused persons to be tried separately, the court, when sworn or affirmed, shall proceed with one case, postponing the other cases and taking them afterwards in succession.

(3) Where several accused persons are tried separately upon charges arising out of the same transaction, the court may, if it considers it to be desirable in the interests of justice, postpone consideration

of any sentence to be awarded to any one or more such accused persons until the trials of all such accused persons have been completed.

149. Arraignment of accused.— (1) After the court and interpreter are sworn or affirmed as above mentioned, the accused shall be arraigned on the charges against him.

(2) The charges on which the accused is arraigned shall be read and, if necessary, translated to him and explained, and he shall be required to plead separately to each charge.

150. Objection by accused to charge.— The accused, when required to plead to any charge, may object to the charge on the ground that it does not disclose an offence under the Act, or is not in accordance with these rules.

151. Amendment of charge.— (1) At any time during the trial, if it appears to the Court that there is any mistake in the name or description of the accused in the charge sheet, it shall amend the charge sheet so as to correct that mistake.

(2) If on trial of a charge it appears to the court at any time before it has begun to examine the witnesses, that in the interest of justice any addition to, omission from or alteration in, the charge is required, it may amend such charge and may, after due notice to the accused, and with the sanction of the officer empowered to convene a petty Assam Rifles Court for the trial of the accused if the amended charge requires such sanction, proceed with the trial on such amended charge.

152. Special pleas.— If a special plea to the general jurisdiction of the Court, or a plea in bar of trial is offered by the accused, the procedure laid down for general and petty Assam Rifles Court when disposing of such pleas shall, so far as may be applicable be followed, but no finding by a summary Assam Rifles Court on either of such pleas shall require approval or confirmation.

153. General plea of guilty or not guilty.— (1) The accused person's plea of guilty or not guilty or if he refuses to plead or does not plead intelligibly, either one or the other, a plea of not guilty shall be recorded on each charge.

(2) If an accused person pleads guilty, that plea shall be recorded as the finding of the court but before it is recorded, the court shall ascertain that the accused understands the nature of the charge to which he has pleaded guilty and shall inform him of the general effect of that plea, and in particular of the meaning of the charge to which he has pleaded guilty, and of the difference in procedure which will be made by the plea of guilty and shall advise him to withdraw that plea if it appears from the summary or abstract of evidence or otherwise that the accused ought to plead not guilty.

(3) Where an accused pleads guilty, such plea and the factum of compliance of sub-rule (2) of this rule, shall be recorded by the court in the following manner—

“Before recording the plea of guilty of the accused, the court explained to the accused the meaning of the charge(s) to which he had pleaded guilty and ascertained that the accused had understood the nature of the charge(s) to which he had pleaded guilty. The court also informed the accused the general effect of the plea and the difference in procedure, which will be followed consequent to the said plea. The court having satisfied itself that the accused understands the charge(s) and the effect of his plea of guilty, accepts and records the same. The provisions of rule 153 (2) are thus complied with.”

(4) Where an accused person pleads guilty to the first of two or more charges laid in the alternative, the court may after sub-rule (2) has been complied with and before the accused is arraigned on the alternative charge or charges, withdraw such alternative charge or charges which follows the charge to which the accused has pleaded guilty without requiring the accused to plead thereto, and a record to that effect shall be made in the proceedings of the court.

154. Procedure after plea of guilty.— (1) Upon the record of the plea of guilty, if there are other charges in the same charge sheet to which the plea is not guilty the trial shall first proceed with respect to those other charges and after the finding on those charges, shall proceed with the charges on which a plea of guilty, has been entered; but if there are alternative charges, the court may either proceed with respect to all the charges as if the accused had not pleaded guilty to any charge or may, instead of trying him, record a finding of guilty upon any one of the alternative charges to which he had pleaded guilty and finding of not guilty upon all the other alternative charges.

(2) (a) After the record of the plea of guilty on a charge (if trial does not proceed on any other charges) the court shall read the summary or abstract of evidence and annex it to the proceedings, or if there is no such record, shall take and record sufficient evidence to enable it to determine the sentence, and for the reviewing officer to know all the circumstances connected with the offence.

(b) the evidence shall be taken in like manner as is directed by these rules in the case of plea of not guilty.

(3) The accused may, after such evidence has been taken or as the case may be, the summary or abstract of evidence has been read, address the court with reference to the charge and in mitigation of punishment and may call witnesses as to his character.

(4) (a) If from the statement of the accused, or from the summary of evidence, or otherwise, it appears to the court that the accused did not understand the effect of his plea of guilty, the court shall alter the record and enter a plea of not guilty and proceed with the trial accordingly.

(b) any alternative charges withdrawn under sub-rule (1) shall be reinstated in the charge sheet and the trial shall take place as if they had never been withdrawn.

(5) If a plea of guilty is recorded on some charges and the trial proceeds with respect to other charges in the same charge sheet, the proceedings under sub-rules (2) and (3) shall take place after the finding on the other charges in the same charge sheet are recorded.

(6) When the accused states anything in mitigation of punishment which in the opinion of the court requires to be proved, and would, if proved, affect the amount of punishment, the court may permit the accused to call witnesses to prove the same.

155. Withdrawal of plea of not guilty.— The accused may, if he thinks fit at any time during the trial, withdraw his plea of not guilty and plead guilty and in such case the court shall at once, subject to compliance with sub-rule (2) of rule 153 record a plea and finding of guilty and shall, so far as is necessary, proceed in the manner directed by rule 154.

156. Procedure after plea of not guilty.— (1) After the plea of not guilty to any charge is recorded, the evidence for the prosecution will be taken.

(2) At the close of the evidence for the prosecution, the accused shall be asked if he has anything to say in his defence, and may address the court in his defence, or may defer such address until he has called his witnesses.

(3) The court may question the accused on the case for the purpose of enabling him to explain any circumstances appearing in his statement or in the evidence against him. The accused shall not render himself liable to any punishment by refusing to answer such questions, or by giving answers to them which he knows not to be true. No oath shall be administered to the accused.

(4) The accused may then call his witnesses, including also witnesses to character.

(5) The provisions of rules 96, 97 and 98 shall so far as may be, apply to the evidence of witnesses at a summary Assam Rifles Court as they apply to the evidence of witnesses at a general or petty Assam Rifles Court.

157. Witnesses in reply to defence.— The court may, if it thinks it necessary in the interests of justice, call witnesses in reply to the defence.

158. Verdict.— The court shall after the evidence for prosecution and defence has been heard, give its opinion as to whether the accused is guilty or not guilty of the charge or charges.

159. Record of finding.— (1) The finding on every charge upon which the accused is arraigned shall be recorded, and except as mentioned in these rules, shall be recorded as a finding of guilty or of not guilty.

(2) When the court is of opinion as regards any charge that the facts proved do not disclose the offence charged or any offence of which he might under the Act legally be found guilty on the charge as laid, the court shall find the accused not guilty of that charge.

(3) When the court is of opinion as regards any charge that the facts found to be proved in evidence differ materially from the facts alleged in the statement of particulars in the charge, but are nevertheless sufficient to prove the offence stated in the charge, and that the difference is not so material as to have prejudiced the accused in his defence, it may, instead of recording a finding of not guilty, record a special finding.

(4) The special finding may find the accused guilty on a charge subject to the statement of exceptions or variations specified therein.

(5) The court shall not find the accused guilty on more than one of two or more charges laid in the alternative, even if conviction upon one charge necessarily connotes guilty upon the alternative charge or charges.

160. Procedure on acquittal.— Where the finding on each of the charges in a charge-sheet is not guilty, the court shall affix its signature and date the proceedings. The findings will be announced in open court, and the accused will be released if under arrest, in respect of these charges.

161. Procedure on finding of guilty.— (1) Where the finding on any charge is guilty the court may record of its own knowledge, or take evidence of any record, the general character, age, service, rank, and any recognised acts of gallantry, or distinguished conduct of the accused, and previous convictions of the accused either by a Force Court, or a criminal court, any previous punishment awarded to him by an officer

exercising authority under Section 62, the length of time he has been under arrest or in confinement of any previous sentence, and any decoration, or reward of which he may be in possession or to which he may be entitled.

(2) Where the court does not record the matters mentioned in this rule of its own knowledge, evidence on these matters may be taken in the manner directed in rule 109 for similar evidence.

162. Sentence.— The court shall award one sentence in respect of all the offences of which the accused is found guilty.

163. Signing proceedings.— The court shall affix its signature and the date to the sentence and such signature shall authenticate the whole of the proceedings.

164. Charges in different charge sheets.— (1) When the charges at a trial by summary Assam Rifles Court are contained in different charge sheets, the accused shall be tried on each charge sheet separately up to and including the stage of finding.

(2) The court shall, thereafter, comply with rules 160 or 161, as the case may be.

165. Clearing the court.— (1) The officer holding the trial may clear the court to consider the evidence or to consult with the officers, and subordinate officers, attending the trial.

(2) Subject to the provisions of sub-rule (1), all the proceedings, including the view of any place, shall be in open court, and in the presence of the accused.

166. Adjournment.— (1) A court may—

(a) from time to time adjourn its proceedings and meet at such place as may be convenient; and

(b) wherever necessary, visit the scene of occurrence.

167. Friend of the accused.— During a trial at a summary Assam Rifles Court, an accused may take assistance of any person, including a legal practitioner as he may consider necessary:

Provided that such person shall not examine or cross-examine witnesses or address the court.

168. Memorandum to be attached to proceedings.— Where a summary Assam Rifles Court tries an offence which shall not ordinarily be tried without reference to an authority mentioned in sub-Section (2) of Section 96, an explanatory memorandum shall be attached to the proceedings.

169. Promulgation.— The sentence of a summary Assam Rifles Court shall be promulgated in the manner usual in the service, at the earliest opportunity after it has been pronounced and shall subject to the provisions of sub-Section (2) of Section 136 of the Act be carried out without delay after promulgation.

170. Review of proceedings.— The proceedings of a summary Assam Rifles Court shall immediately on promulgation be forwarded through the Chief Law Officer, or a Law Officer nominated by him, to the Deputy Inspector-General or Inspector-General under whom the accused may have been serving.

171. Action by the Deputy Inspector-General or Inspector-General.— (1) Where the Deputy Inspector-General or Inspector-General to whom the proceedings of a summary Assam Rifles Court have been forwarded under rule 170, is satisfied that injustice has been done to the accused by reason of any grave irregularity in the proceedings or otherwise, he may—

(a) set aside the proceedings of the court; or

(b) reduce the sentence or commute the punishment awarded to one lower in the scale of punishment given in Section 57 and return it to the unit of the accused for promulgation.

(2) Where no action under sub-rule (1) has been taken he shall countersign the proceedings.

(3) The proceedings shall, after its promulgation under sub-rule (1), or counter signature under sub-rule (2), be forwarded to the Chief Law Officer for custody.

172. Rules which shall not apply to trial by summary Assam Rifles Court.— The provisions of Chapters-IX and X of the rules shall not apply to trials by summary Assam Rifles Court in so far as they are inconsistent with any of the provisions contained in this Chapter pertaining to summary Assam Rifles Court.

CHAPTER - XIII

EXECUTION OF SENTENCE

173. Direction about sentence of imprisonment.— (1) A confirming authority or in the case of summary Assam Rifles Court, the court, shall direct that the sentence of imprisonment shall be undergone by confinement either in a civil prison or in Force custody.

(2) Such direction may be varied by any superior officer.

174. Warrants.— Warrants for committing a person to a civil prison to undergo sentence of imprisonment or to get such person back into Force custody if so required, or to order the release of such a person from civil prison or any variation done by any superior officer shall be in such form as may be appropriate to each set out in Appendix-XII.

(2) Such Warrants shall be signed by the Commandant of the accused or by a staff officer on behalf of a Deputy Inspector-General, Inspector-General or the Director-General.

175. Warrants in case of sentence of death.— (1) When a person is sentenced by a Force Court to suffer death, the Commandant for the time being of such person may, if he thinks fit, by a warrant in one of the forms in Appendix-XIII, commit the said person for safe custody in a civil prison pending confirmation or carrying out of the sentence.

(2) Where a person is sentenced to death by hanging, a warrant in the form set out in Appendix-XIII shall be sent by the Director-General to the Superintendent of the Prison where facilities for carrying out such a sentence exist, after the sentence has been confirmed by the Central Government, and the accused shall be committed to the same prison by his Commandant on the appropriate warrant.

(3) Where an accused person is sentenced to death by being shot, a warrant on the appropriate form set out in Appendix-XIII shall be issued by the Director-General, to Inspector-General or Deputy Inspector-General under whom the accused may be serving, after the sentence has been confirmed by the Central Government, and the Inspector-General or the Deputy Inspector-General as the case may be, shall arrange for the execution of the sentence.

(4) No sentence of death shall be carried into effect until the death warrant has been received by the authorities specified in sub-rules (1) or (2).

(5) On receipt of the death warrant, the authorities mentioned in sub-rule (1) or (2) shall—

(a) inform the person sentenced as soon as possible of the date on which the sentence will be carried out;

(b) if the person sentenced has been committed to a civil prison under rule 175, obtain the custody of his person by issuing a warrant in one of the forms in Appendix-XIII; and

(c) proceed to carry out the sentence as required by the death warrant and in accordance with any general or special instructions which may from time to time be given by or under the authority of the Director-General.

(6) During the execution of a sentence of death passed under the Act, no person except those specified below, shall be present without the authority of the officer who issued the death warrant. The following persons shall attend the execution of the sentence of death—

(a) the authorities specified in sub-rules (1) or (2) who is responsible for the due execution of the sentence in accordance with these rules;

(b) a medical officer of the armed forces of the Union;

(c) an officer nominated by the officer who issued the death warrant, who is able to identify the person under sentence as the person described in the death warrant as the person who was tried and sentenced by the Assam Rifles Court mentioned therein;

(d) such under officers as may be detailed by the authorities mentioned in sub-rules (1) and (2) for escort and security purposes or to assist in the execution;

(e) if the execution is carried into effect in any Assam Rifles Unit, the Commandant of such unit.

(7) After the sentence of death has been carried into effect, the authorities mentioned in sub-rule (2) or the superintendent of the civil prison, as the case may be, shall complete or cause to be completed parts II and III of the death warrant, and shall, without unnecessary delay return the completed death warrant to the officer who had issued the same.

176. Changes in sentence.— Where any change is made in the sentence of a person already committed to a civil prison, such change shall be communicated to the Superintendent of the Prison to which such person has been committed by the Commandant or such other officer as is mentioned in rule 174 in the form set out in Appendix-XIV.

177. Sentence of dismissal.— (1) Sentence of dismissal shall take effect from the date of promulgation of such sentence or from any subsequent date as may be specified at the time of promulgation.

(2) A sentence of dismissal combined with imprisonment to be undergone in a civil prison shall not take effect until such person has been committed to civil prison.

CHAPTER - XIV PETITIONS

178. Petitions against finding and sentence of court.— (1) A person subject to the Act who has been tried by a court shall be allowed to put in one petition before confirmation, to the confirming authority and one petition after confirmation to any officer mentioned in Section 139.

(2) A sentence of death shall not be carried into effect until the disposal of the post confirmation petition submitted by the person sentenced within the period specified in sub-rule (2) of rule 179, and the authority legally competent to dispose of such petition finally, after considering the petition, orders that the sentence of death may be carried into effect.

(3) In the case of a summary Assam Rifles Court he shall be allowed to put in one petition only to any of the officers mentioned in Section 137.

179. Period of limitation.— (1) A petition, before confirmation, shall be submitted, within one month of the conclusion of the trial.

(2) A petition after confirmation shall be submitted within 3 months of the date on which the sentence was promulgated :

Provided that the time taken by such person to obtain a copy of the proceedings shall be excluded in calculating this period of 3 months.

180. Mode of submitting petitions.— (1) (a) A petition, by a person who is still a member of the Force shall be submitted through his Commandant.

(b) A petition, by a person who has ceased to be a member of the Force shall be submitted to the Commandant of the unit in which the trial was held.

(2) An officer to whom a petition is submitted or to whom a petition has been forwarded shall forward it to the next superior authority within a period of one month along with his recommendations :

Provided that an officer may not forward a petition if he is competent to give the redress asked for and decides to do so.

(3) An officer receiving a petition may send it to the Chief Law Officer or a Law Officer nominated by him, for advice.

CHAPTER - XV COURTS OF INQUIRY

181. Composition.— (1) A court of inquiry may consist of two or more members one of whom shall be an officer. Persons not subject to the Act may be appointed as members when the court is to investigate matters of a specialised nature, and when officers subject to the Act with specialist qualifications are not available to be members.

(2) When the character or conduct of an officer is likely to be material in a court of inquiry, the Presiding Officer of the court of inquiry, wherever possible, will be senior in rank and other members at least equivalent in rank to such officer.

182. Assembly.— (1) A court of inquiry may be assembled by order of a Commandant or any officer or authority superior in command to the Commandant.

(2) The order assembling the court of inquiry shall state the composition of the court, the time and place for its assembly and clearly state the matters which the court will investigate. It will also provide for the administrative requirements of the court.

183. Procedure of courts of inquiry.— (1) The proceedings of a court of inquiry shall not be open to the public. Only such persons may attend the proceedings as are permitted by the court to do so.

(2) The evidence of all witnesses shall be taken on oath or affirmation and signed by them after the same has been read over and explained to them.

Explanation— The court shall administer the oath or affirmation to witnesses as if the court were a Force Court.

(3) Evidence given by witnesses shall be recorded in narrative form unless the court considers that any questions and answers may be recorded as such.

(4) The court may take into consideration any documents even though they are not formally proved.

(5) The court may ask witnesses any questions, in any form, that it considers necessary to elicit the truth and may take into consideration any evidence, whether the same is admissible under the Indian Evidence Act, 1872 (1 of 1872) or not.

(6) No counsel or legal practitioner shall be permitted to appear before a court of inquiry.

(7) Provisions of Section 111 shall apply for procuring the attendance of witnesses before the court of inquiry.

(8) (i) Save in the case of a prisoner of war who is still absent whenever the subject-matter of inquiry is the conduct, character or reputation of particular person, such person shall be associated throughout with the inquiry and be given full opportunity of making any statement, or giving any evidence, he may wish to make or give, and of cross-examination of any witness whose evidence, in his opinion, affects his character or reputation.

(ii) in other cases, before giving opinion against any person subject to the Act, the court shall afford that person the opportunity to know all that has been stated against him, cross-examine any witness who has given evidence against him, and make a statement and call witnesses in his defence.

(9) The court may be reassembled as often as the officer who assembled the court may direct, for the purpose of examining additional witnesses, or further examining any witness, or recording further information. In such a case the court may record fresh opinion if considered necessary after complying with the provisions of clause (ii) of sub rule (8).

184. Proceedings of court of inquiry not admissible in evidence.— The proceedings of a court of inquiry, or any confession, statement, or answer to a question made or given at a court of inquiry, shall not be admissible in evidence against a person subject to the Act, nor shall any evidence respecting the proceedings of the court be given against any such person except upon the trial of such person for willfully giving false evidence before that court :

Provided that nothing in this rule shall prevent the proceedings from being used by the prosecution or the defence for the purpose of cross-examining any witness.

185. Courts of inquiry when to be held.— (1) A court of inquiry may be held to investigate into any disciplinary matter or any other matter of importance.

(2) In addition to a court of inquiry required to be held under Section 84, a court of inquiry shall be held in the following cases—

(a) (i) all unnatural deaths of persons subject to the Act or of other persons within the Force lines, an immediate report shall be sent to the officer-in-charge of the police station within whose jurisdiction such unnatural death has occurred.

(ii) in cases when such report cannot, for any reason be delivered within a reasonable time, immediately on receipt of information of an unnatural death, the Commandant or the senior most officer of the unit present shall prepare a report on the proforma set out in Appendix-XV.

(b) all injuries sustained by persons subject to the Act which are likely to cause full or partial disability. The court shall, in such cases, determine whether such injuries were attributable to service or not.

(c) all financial irregularities, losses, theft and misappropriation of public or Force property, where it is necessary to obtain the order of a superior officer on such irregularities, loss, theft or misappropriation.

(d) all losses of secret documents and any other material of secret or above security classification. Such a court of inquiry shall be ordered by an officer or authority superior to the unit Commandant having the lost document or material on its charge.

(e) all damage to private persons or property in respect of which there is likely to be a claim against the Government or the Force.

186. Action on the proceedings of a court of inquiry.— The proceedings of a court of inquiry shall be submitted by the Presiding Officer to the officer or authority who ordered the court. Such officer or authority on receiving the proceedings may either pass final orders on the proceedings, if he is empowered to do so, or refer them to a superior authority.

187. Copies of court of inquiry proceedings.— A person subject to the Act against whom the court of inquiry has given an opinion or who is being tried by a Force Court on a charge relating to matter investigated by the court of inquiry, shall be entitled to copies of the proceedings of the court of inquiry except the findings and opinion thereon, unless the Director-General for reasons recorded by him orders otherwise.

LOSSES OR THEFT OF ARM

188. Court of inquiry when Rifles, etc., are lost or stolen.— (1) Whenever any weapon or part of a weapon, which forms part of the equipment of a company or other similar unit, and in respect of the loss or theft of which a fine may be imposed under rule 189 is lost or stolen, a court of inquiry shall be assembled, under the orders of the Director-General, Inspector-General or Deputy Inspector-General to investigate the circumstances under which the loss or theft occurred.

(2) The officer who assembled the court shall direct it to record an opinion as to the circumstances of the loss or theft.

189. Collective fines may be imposed.— (1) The Director-General, Inspector-General or Deputy Inspector-General shall then record his opinion on the circumstances of the loss or theft, and may impose for each weapon or part of a weapon lost or stolen, collective fines on the subordinate officers, under officers, and men of such unit or upon so many of them as he considers should be held responsible for the occurrence, to the maximum extent of the rates approved by the Government for such weapon or part of weapon.

(2) Such fine will be assessed as a percentage on the pay of the individuals on whom it falls.

CHAPTER - XVI
MISCELLANEOUS

190. Authority prescribed for the purpose of Section 13 (1).— (1) The authority for the purpose of sub-Section (1) of Section 13 shall be—

- (a) Director-General in respect of all personnel subject to the Act other than officers;
- (b) Central Government in respect of officers.

(2) Any power conferred under this rule on any of the aforesaid officer may also be exercised by any officer superior to that officer.

191. Prescribed officer for the purpose of Section 60.— The prescribed officer for the purpose of Section 60 shall be the Director-General, or the Inspector-General or Deputy Inspector-General under whom the trial was held, or the Commandant of the unit in which the trial was held.

192. Extent of punishment under Section 62.— (1) If the Commandant is of or above the rank of a Deputy Commandant, he may award to the full extent one or more of the punishments specified in Section 62.

(2) If the Commandant is below the rank of a Deputy Commandant, he may award punishment specified—

- (a) in clauses (a) and (b) of Section 62, upto 14 days;
- (b) in other clauses of Section 62, to the full extent.

193. Prescribed officer under Sections 69 (i) and 71.— (1) The following shall be the prescribed officers for the purpose of Sections 69 (i) and 71—

- (a) Inspector-General in case of subordinate officers, under officers and enrolled persons.
- (b) Director-General in the case of officers.

(2) Any power conferred under this rule on any of the aforesaid officers may also be exercised by any officer superior to that officer.

194. Prescribed authorities under Section 75.— Any authority superior to the one awarding any deductions under Chapter-VI of the Act shall be competent to remit the whole or part of the said deductions.

195. Prescribed authorities under Sections 76 and 77.— The prescribed authorities under Sections 76 and 77 shall be—

- (a) in the case of officers, the Director-General Assam Rifles or an officer specified by him; and
- (b) in all other cases, the Commandant, training battalion, training centre, or the unit to which the prisoner of war or missing personnel belonged, or any superior authorities.

196. Prescribed officer under Section 85 (1).— The prescribed officer for the purpose of sub-Section (1) of Section 85 shall be the Inspector-General, Deputy Inspector-General, Range or Commandant of a training institution.

197. Prescribed officer under Section 118.— The prescribed officer for the purposes of sub-Section (1) of Section 118 shall be the Inspector-General, Deputy Inspector-General or Commandant of the unit to which the person appears to have belonged or alleges that he belongs or had belonged.

EXECUTION OF SENTENCE

198. Prescribed manner of custody and prescribed officer under Sections 121 and 122.— (1) The prescribed officer for the purpose of Section 122 shall be—

(a) in case of trial by summary Assam Rifles Court, the Commandant of the unit to which the accused person belongs, or any authority superior to such Commandant;

(b) in the case of trial by any other court, the convening officer or any authority superior to him.

(2) When the officer who proposed to act as a prescribed officer under sub-rule (1) is under the command of the officer who has taken action in the case under sub-Section (4) of Section 121, he shall ordinarily obtain the approval of such officer before he acts but if he is of opinion that service exigencies, or the necessities of discipline, render it impossible or inexpedient to obtain such approval, he may act without obtaining such approval, but shall report his action and the reasons thereof to such officer.

(3) For the purpose of sub-Section (4) of Section 121 the accused shall be confined in such manner as may, in the opinion of the proper Force authority, be best calculated to keep him securely without unnecessary harshness, as he is not to be considered as a criminal but as a person labouring under a disease.

199. Prescribed officer under Section 140.— The prescribed officer for the purpose of Section 140 shall be the Additional Director-General, Inspector-General, Deputy Inspector-General Range or training institution, in respect of proceedings confirmed by him or by a person under his command.

200. Prescribed officer under Section 143.— The prescribed officer under sub-section (1) of Section 143, for the purposes of directing whether the sentence shall be carried out by confinement in a civil prison, in the case of a sentence which has been confirmed, shall be any higher authority than the confirming officer, and in the case of a sentence which does not require confirmation, shall be any higher authority to the officer holding the trial.

201. Prescribed officer under Section 150.—The prescribed officer for the purpose of Section 150, as regards persons undergoing sentence in a civil prison or any other place, shall be the Director-General or the Inspector-General or Deputy Inspector-General Range, with in the area of whose command, the prisoner subject to such punishment may for the time being be.

202. Authorised deductions.— The following deductions may be made from the pay and all other emoluments payable to a person subject to the Act, namely—

(a) upon the general or special order of the Central Government, any sum required to meet any public claim there may be against him;

(b) any sum required to meet compulsory contributions to any provident fund, welfare fund or any other fund approved by the Central Government or to meet any debt that may be due from him towards any Force institutions such as messes, canteens and the like.

Explanation— (i) public claim means any public debt or disallowance including over issue, or a deficiency or irregular expenditure of public money or store of which, after due investigation, no explanation satisfactory to the Central Government, is given by the person who is responsible for the same.

(ii) the aforesaid deductions shall be in addition to those specified in the Act.

203. Repeal and savings.— (1) All rules and orders relating to the matters covered by these rules shall stand repealed in so far as they are inconsistent with any of the provisions of these rules.

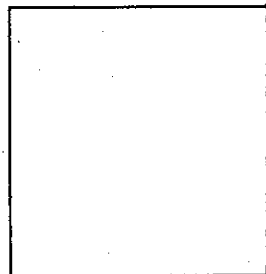
(2) Notwithstanding such repeal any thing done or any action taken under the provisions of the rules or orders so repealed shall, in so far as such thing or action is not inconsistent with the provisions of these rules, be deemed to have been done or taken under the provisions of these rules as if the said provisions were in force when such thing was done or such action was taken and shall continue in force accordingly until superseded by anything done or any action taken under these rules.

204. Transitory provision.— Any rule or order applicable to the Force on commencement of these rules shall, unless repugnant to these rules, continue to apply unless and until abrogated or modified by the Central Government or any other competent authority.

PART- I
APPENDIX- I
(See rule 15)
(Assam Rifles recruiting form)

Blood Group.....General No.....
Battalion.....
1. Name2. Religion.....
3. Caste/Tribe*4. Father's name.....
*(In case of Scheduled Castes and Tribes only).
5. Heir.....
6. Date of Birth by Christian Era.....
(As nearly as can be ascertained).
7. Heightcms 8. Chest.....cms
9. Identification Marks.....
10. Residence, Village.....Thana.....
District.....State.....
11. Character and antecedents verified by.....
.....
12. Occupation prior to enlistment.....
13. Educational qualifications, if any.....
14. Date of enrolment.....
15. Enrolled as.....

Photograph



Date of Photograph.....

FORM OF ENROLMENT
Enrolment of

No.....Name (In Block Letters)..... as
a.....in Assam Rifles.

Part – I

(Question to be put before enrolment)

You are warned that if after enrolment, it is found that you have given a wilfully false answer to any of the first twelve of the following questions you will be liable to be punished as provided in Assam Rifles Act, 2006.

(ALL THE ANSWERS ARE TO BE WRITTEN IN BLOCK LETTERS)

Question

1. What is your Name?
(Underline Surname)
2. (a) What is your place of birth?
State Village/Town, District
and State of Birth
(b) What is your date of birth?
(State in Christian era)

N.B.— to support the date of birth the person being enrolled will be required to produce in original, together with an attested copy, one of the certificates specified in Government orders from time to time.

3. What is your permanent Home address?

- (a) Village/Town
- (b) Thana

- (c) Pargana/Tehsil
- (d) District/Taluka
- (e) State
- 4. (a) What is your religion?
- (b) Are you a member of a Scheduled Caste or Scheduled Tribe?
If so state Caste or Tribe?
- 5. (a) Are you a citizen of India? If so,
whether by birth or descent or registration
or naturalisation or otherwise?
- (b) Are you a subject of Nepal or Bhutan? If so, state
of which of the two?
- (c) If you are not a citizen of India
or a subject of Nepal or Bhutan,
what is your Nationality?

N.B.— In the case of foreign nationals other than subjects of Nepal or Bhutan, consent of the Central Government signified in writing, if any, should be produced before a person is enrolled.

- (d) Have you migrated from areas now in Pakistan? If so,
State the date of your migration.
- 6. What are your educational qualifications?
(Original Certificates, with one attested copy of each,
are to be produced)
- 7. Are you married?*
- If so State
 - (i) Date of marriage(s)
 - (ii) Name (s) of wife/wives.
 - (iii) Nationality of wife/wives.
 *(This does not include widower/divorced).
- 8. (a) What is your father's name and address? If dead, state last address District and State.
(b) What is or was the nationality of your father? If he is or was an Indian Citizen, state
whether by birth, descent, registration, naturalisation or otherwise.
- 9. Are you or have you ever been a member of a party or
organisation or a political, communal or cultural nature? If so,
state the name of the party or organisation with the
period/periods of your membership therein.
- 10. (a) Are you in Government Service or have you been a Government servant? If so, state
full particulars and the reason for discharge and confirm that you were never dismissed from
any Government service.
(b) Are you in receipt of any allowance from the
Government? If so, on what account?
- 11. (a) Do you now belong to any of the Armed Forces of India, the Reserves of any of the
three services, the Auxiliary Air Force, the Territorial Army, any Police Force in India or
the Nepal State Army or any of the Forces of a Foreign Country?
(b) Have you ever served in any of the Armed Forces in India, the Reserves of any of the
three Services, the auxiliary Air Force, the Territorial Army, or any Police Force in India or
Nepal State Army or any of the Forces of a Foreign Country?
If so, state in which and the cause of discharge. If you have
served in more than one of the above named forces, or if you
have served the same Force in two or more distinct periods,
state the cause of discharge separately in each case.
(c) Do you desire your former service in the Indian Armed Force
or any Police Force to count for the purpose of calculation of
Pay and/or Pension, if admissible? If so, do you agree to recovery
being effected of any gratuity you may have received for your
former services in not more than thirty six monthly instalments

- from your pay commencing from the date of this enrolment and undertake to refund to the Government through such recoveries or otherwise the above gratuity in full within thirty six months of the date of your present enrolment?
12. Have you ever been arrested, prosecuted, imprisoned, bound over, interned, externed or otherwise dealt with under any law in force in India or outside? If so, state particulars.
 13. Are you willing to be inoculated or re inoculated and vaccinated?
 14. Are you willing to be enrolled as a combatant in the Assam Rifles?
 15. Are you willing to go wherever ordered by land, sea or air and not to allow any caste or social usages to interfere with the duties for which you are enrolled?
 16. Are you willing to serve in the Assam Rifles until discharged, in accordance with the conditions of service as specified in Part-II of this form of enrolment?
 17. Do you have any objections to take the following or to make the following affirmation at the time of your attestation?

FORM OF OATH

Ido swear in the name of God that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India as by law established and that I will, as in duty bound, honestly and faithfully serve in the Assam Rifles, and go wherever ordered, by air, land or sea and that I will observe and obey all commands of the President of the Union of India and the commands of any officer set over me even to the peril of my life.

FORM OF AFFIRMATION

Ido solemnly, sincerely and truly declare and affirm that I will bear true faith and allegiance to the Constitution of India by law established and that I will as in duty bound, honestly and faithfully serve in the Assam Rifles and go wherever ordered by air, land or sea and that I will observe and obey all commands of the President of the Union of India and the commands of any officer set over me even to the peril of my life.

CERTIFICATE

Ido solemnly declare that the answers furnished by me above are true.

Place.....

Date.....

(.....)*
Signature of the person enrolled

Left thumb impression of the person enrolled taken in the presence of the enrolling officer.

-----Signature
-----Name of witness
-----Address

*Name in Block Letters

Part - II CONDITIONS OF SERVICE

- *1. On enrolment, you shall be subject to the Assam Rifles Act, 2006 and the rules made there under.
- *2. You are liable to be discharged during the first two years of the service if you are not likely to become an efficient member of the Force.

*3. You will also be liable to be discharged if the Central Government decides to disband the Force or a portion of it.

CERTIFICATE BY THE PERSON TO BE ENROLLED

I have understood the above conditions and agree to abide by them.

()
Signature of the person enrolled

Place.....
Date.....

The above conditions have been read/expained to the person being enrolled by me.

Place.....
Date.....

()
Signature of the Enrolling Officer

Part - III HEALTH CERTIFICATE

1. I do hereby certify that I have examined _____-candidate for employment in the Assam Rifles. He fulfils medical standards laid down for the Assam Rifles and I cannot discover that he has any disease, constitutional affliction or bodily infirmity. His age according to his own statement is.....years and by appearance is.....years.

Height.....cms
Chest (a) Maximum.....cms
(b) Minimum.....cms

Signature of the Medical Officer
Designation

Place.....
Date.....

APPENDIX - II (See rule - 41)

FORM OF DELAY REPORT

CONFIDENTIAL

No. _____ Rank _____ Name _____
Unit address _____
Date _____

To _____
(Convening Officer)

Subject: - 1st (2nd), (3rd), (4th), etc. etc., eight-day delay report pursuant to AR Act Section 81 and AR rule 41.

1. No. _____ Rank _____ Name _____
2. Offence _____

3. Date of offence _____
4. Date offence was discovered _____
5. Date of (open/close) arrest _____
6. Date of release to open arrest/release _____ without prejudice to re-arrest
(If not released, reasons) _____
7. Summary of Evidence recorded on _____
(if not recorded, reasons) _____
8. Application for trial made on _____
9. Date due to be tried _____
10. Reason for delay _____

(Commandant)

Copy to:—

1. Inspector General (in case of the 8th and subsequent reports).
2. Chief Law Officer, DGAR (in case of the 8th and subsequent reports).
3. Director General (Special report in case the accused is under close arrest for more than 3 months without a trial).

APPENDIX – III

Form of representation by person under arrest

[See rule – 42 (2)]

Sl. No.	Date	Name of the accused	Name of the Officer or subordinate officer to whom request or representation made.	Particulars of the request or representation	Order of the Commandant	Signature with the of the officer or subordinate officer who conveys the orders of the Commandant to the accused.	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

APPENDIX-IV

[See rules 46 and 54(3)]

(*TENTATIVE) CHARGE SHEET

The accused, No.....(if applicable) Rank
 Name.....battalion or unit.....
 is charged with :-

**DISOBEYING THE LAWFUL COMMAND OF HIS
SUPERIOR OFFICER**

A R Act
Sec 28 (2)

in that he,
 aton....., disobeyed the lawful command of his superior officer,
 Rank.....Name.....
 of the same battalion, to turn out for Commandant's parade, by not turning out.

Place.....
 Date.....

(Commandant)

__ xx __ battalion

** (To be tried by a general or petty Assam Rifles Court)

Place.....

Date.....

Inspector-General or Dy Inspector-General

* The word 'Tentative' to be included only in cases of hearing of charge under AR rule 47, and not to be included for charge sheets under AR rule 54 (3) which is prepared for trial by Assam Rifles Courts and summary trials of officers, subordinate officers and warrant officers.

** These entries are to be made in charge sheet specified in AR rule 54 (3) when sanction is accorded for the trial of grave offences as provided under AR Act Section 96 (2).

APPENDIX - V
(FORM OF HEARING OF THE CHARGE)
(See rule - 47)

Appendix _____

This form is to be filled by the Commandant at the time of hearing of a charge against a person subject to the Assam Rifles Act, 2006.

RECORD OF PROCEEDINGS BEFORE COMMANDANT
UNDER ASSAM RIFLES RULE 47

In the case of No. _____ Rank _____ Name _____ of _____ unit (parent unit),
attached to _____ (Unit to which attached), vide _____ (quote authority).

PROCEEDINGS

1. The charge (s) against the accused has/have been read out, explained to him and attached as Annexure I.

or

2. Calling and hearing of witness, in terms of AR rule 47 (1), have been dispensed with, since provisions of AR rule 183 (8) have been complied with at the Court of Inquiry, in respect of the accused.

Signature of accused

Date _____

(Note: Where the Commandant dispenses with the calling and hearing of witnesses, in terms of Assam Rifles rule 47 (1), columns 4 to 6 of the Appendix, being inapplicable, may be scored out. The Commandant will pass appropriate orders in column 7 of the Appendix).

3. Hearing of the charge (s) commenced on _____ (Date) at _____ hrs.

4. The following prosecution witnesses were heard by me, in the presence of the accused who was given full liberty to cross-examine each of them—

Date (s) on which the witness was heard orally by Commandant	Personal particulars of prosecution witness (es)	Description of documentary evidence produced, if any	Whether accused cross-examined the witness or declined to cross-examine (only state 'yes' or 'declined' before each witness, as applicable)
(1)	(2)	(3)	(4)

5. The accused was informed by me that he was at liberty to make any statement and call any witness in defence. A brief of the statement made by the accused is attached as Annexure-II to this form.

or

The accused declines to make a statement.

6. The following defence witnesses were heard/no witnesses were produced by the accused—

Date (s)	Personal particulars of witnesses in defence	Description of documentary evidence, if any, produced

7. On conclusion of the hearing of the charge(s) or after going through the whole of evidence in the court of inquiry and the statement of the accused, I have given the following orders—

Date of order	Order

8. The above proceedings under Assam Rifles rule 47(1) were held by me in the presence of the following independent witnesses: -

- (a)
(b)

Place :

Dated :

Note. ☐ Strike out inapplicable portion.

Signature

(Name :)

Commandant

Unit:

Instructions

(a) It is the personal responsibility of the Commandant of the accused to fill this form in every disciplinary case dealt with by him including a summary trial under Assam Rifles Act, 2006.

(b) Except as provided in proviso to Assam Rifles rule 47 (1) hearing of prosecution witness (es) is mandatory with due opportunity of cross-examination to the accused notwithstanding his pleading guilty or accepting his complicity/guilt in any manner. Even in a case where prima facie case is made out by documentary evidence, it is a legal necessity to examine the prosecution witness (es), may be he/they produce only the relevant documents. The particulars of such witness (es) MUST be recorded in column 4 of this form.

(c) At the close of hearing, orders of the Commandant will be conveyed to the accused in para 7 as also recorded in Annexure-I to this form. Said orders may be recorded as follows—"evidence to be reduced to writing", or "to be tried summarily" or "I hereby dismiss the charge" etc.

(d) This form, together with the original charge (s) or accusation (s) bearing the orders of the Commandant will invariably accompany the application for trial.

(e) In the case of a trial by summary Assam Rifles Court, it will be ensured that the form is attached with the proceedings while submitting the same to the Chief Law Officer for review.

(f) Similarly, in the case of summary trial of officers, subordinate officers, warrant officers and under officers, this form will be attached to the summary trial proceedings while forwarding the same for review by superior authority.

(g) A court of inquiry, except as provided by proviso to Assam Rifles rule 47 (1), cannot be used for the purpose of preliminary hearing of the charge.

(h) The words, "and the statement of the accused", appearing in para 7 should be deleted where there is no such statement.

APPENDIX – VI

[See rule 47(2) and (4)]

Form for use at summary proceedings of under officers and other enrolled persons under Section 62 of the Assam Rifles Act.

*OFFENCE REPORT

Company _____

Serial No. _____

For week ending _____

Last report submitted on _____

Charge against No. _____ Rank _____ Name _____

Place and date of offence	Offence	Plea	Name of witnesses	Findings	Punishment awarded	Signature, rank and designation of the officer by whom awarded and date of award	Date of entry in conduct sheet.	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Signature of Commandant
of the battalion

Instructions

Col. 1 In cases of absence without leave or desertion the date of offence will be the first day of absence.

Col.2 The Section and sub-Section of the Assam Rifles Act under which the charge is preferred will be inserted above the statement of offence.

Col.3 A n officer cannot deal summarily with a case in which he is the sole prosecution witness.

Col.4 Must be completed strictly in accordance with the heading.

Note: - 1. *Offence report shall be as per the tentative charge sheet on which hearing of charge will invariably be conducted.

2. This will be prepared in duplicate. A copy alongwith a précis or abstract of evidence where made shall be sent to the Deputy Inspector-General

APPENDIX – VII

(See rule 52)

FORM OF APPLICATION FOR A FORCE COURT

Battalion or unit

Station

Dated.....

Application for a Force Court

Sir,

I have the honour to submit charge(s) against No.....Rank.....

Name..... of the unit, under my command, and request you to accord or obtain sanction, ofthat a Force Court may be assembled for his trial at

The case was investigated by (a).....

A court of inquiry was held on (b).....date.....

at.....(station).

Presiding Officer.....Rank, Name and unit.

Members.....

The accused is now at..... His general character is(c). I

enclose the following documents (d).

1. Charge sheet (.....copies) (e).
2. Summary of evidence (original) and 5 copies.
3. Original exhibits.
4. List of witnesses for the prosecution and defence (with their present address).
5. List of exhibits.
6. Correspondence.
7. Statement as to character and the conduct sheet of the accused.
8. Statement by accused as to whether or not he desires to have an officer assigned by the convening officer to represent him at the trial (rule 60).

Signature of Commandant

Instructions

- (a) Here insert name of
- (i) Officer who investigated the charges.
- (ii) Company or equivalent Commander or Commandant who made preliminary hearing into the case (rule 47).
- (iii) Officer who made the record of summary of evidence (rule 49).
- (b) To be filled in if there has been a court of inquiry respecting any matters connected with the charges; otherwise to be struck out [rule 64 (c)].
- (c) To be filled in by the Commandant, personally.
- (d) Any item not applicable to be struck out.
- (e) 3, 4, 5, 6, 7 and 8 to be returned to the Commandant of the unit of the accused with the notice of trial.

APPENDIX – VIII

(See rule 53)

FORM I

Form for use at summary trials of officers, subordinate officers and warrant officers under Sections 64 to 66 of the Assam Rifles Act.

ACCUSED.....
 NO, RANK AND NAME.....
 UNIT.....

When the authority dealing summarily with the case decides (with the written consent of the accused) to dispense with the attendance of witnesses.

Questions to the accused –

1. Have you received a copy of the charge-sheet and summary of evidence?

ANSWER.....

2. Have you had sufficient time to prepare your defence?

ANSWER.....

The charge-sheet is read.

3. Are you guilty or not guilty of the charge(s) against you which you heard read?

ANSWER.....

The summary of evidence is read aloud or the authority dealing summarily with the case informs the accused that he has already perused it.

4. Do you wish to make a statement?
 If the accused desires to make a statement, he should do so now.

ANSWER.....

If at the conclusion of the hearing, the authority dealing summarily with the case considers that the charge should not be dismissed, he is to examine the accused's record of service or conduct sheet.

If the authority dealing summarily with the case proposes to award punishment other than a reprimand, severe reprimand, or penal deductions, in the case of an officer, a subordinate officer or a warrant officer, he shall put the following questions to the accused:-

5. Do you elect to be tried by an Assam Rifles Court or will you accept my award?

ANSWER.....

FINDING.....
 AWARD.....
 STATION.....
 DATE.....

Note 1.— The oral statement of the accused made in answer to question 4 will be either recorded or a gist thereof prepared and attached.

Note 2.— After disposal of a charge, the proceedings alongwith relevant documents shall be forwarded for review in accordance with rule 53 (3) to (5)

FORM 2

Form for use at summary trials of officers, subordinate officers and warrant officers under Sections 64 to 66 of the Assam Rifles Act.

ACCUSED.....
RANK AND NAME.....
UNIT.....

When the authority dealing summarily with the case does not decide to dispense with the attendance of witnesses or when the accused requires their attendance.

Questions to the accused—

1. Have you received a copy of the charge-sheet and summary of evidence?

ANSWER.....

2. Have you had sufficient time to prepare your defence?

ANSWER.....

The charge-sheet is read.

3. Are you guilty or not guilty of the charge (s) against you which you heard read?

ANSWER.....

The witnesses give their evidence, accused being permitted to cross-examine.

4. Do you wish to make a statement?

ANSWER.....

5. Do you desire to call any witnesses?

ANSWER.....

The accused makes a statement and his witnesses give evidence.

If at the conclusion of the hearing, the authority dealing summarily with the case considers that the charge should not be dismissed, he is to examine the accused's record of service or conduct sheet.

If the authority dealing summarily with the case proposes to award a punishment other than a reprimand, severe reprimand or penal deductions, in the case of an officer, a Subordinate Officer or a Warrant Officer, he shall put the following question to the accused:-

6. Do you elect to be tried by an Assam Rifles Court or will you accept my award?

ANSWER.....

FINDING.....

AWARD.....

STATION:

DATE:

Signed.....

Note 1.— The oral statement of the accused made in answer to question 4 will be either recorded or a gist thereof prepared and attached.

Note 2.— After disposal of a charge, the proceedings alongwith relevant documents shall be forwarded for review in accordance with rule 53 (3) to (5)

APPENDIX – IX

(See rule 67)

FORM TO CONVENE FORCE COURT

Form of order for the assembly of a general or petty Assam Rifles Court under the Assam Rifles Act, 2006.

Orders by.....

(Place.....date.....)

No.....

The details of officers as mentioned below will assemble at

..... on the day of for purpose of trying by a

Rank.....

..... Force Court,

Name.....

the accused person (persons) named in the margin (and such Unit.....

other person or persons as may be brought before them).*

The senior officer to sit as Presiding Officer

MEMBERS

.....
.....
.....
.....
.....

WAITING MEMBERS

.....
.....
.....

LAW OFFICER

.....is appointed Law Officer.

INTERPRETER

.....is appointed interpreter.

PROSECUTOR

.....is appointed prosecutor.

@ The accused will be warned, and all witnesses duly required to attend.

The proceedings (of which only three copies are required) will be forwarded through the Chief Law Officer to

Signed this day of20--...

#

()

Convening officer

* Any opinion of the convening officer with respect to the composition of the court (see rule 66) should be added here, thus:-

"In the opinion of the convening officer it is not practicable to appoint officers of different battalions or units".

"In the opinion of the convening officer, officers of equal or superior rank to the accused are not available, having due regard to the exigencies of public service".

@ Add here any order regarding counsel. [See rule 67(g)].

The convening order must be signed by the convening officer personally. The date of the convening order must not be prior to the date on which the order for trial was endorsed by the convening officer on the charge sheet.

APPENDIX – X

[See rule 114 (1)]

[Order of disposal of property regarding which offence is committed]

In exercise of the powers conferred on me by Section 127 of the Assam Rifles Act, 2006, I.....hereby order that be delivered or paid to (be confiscated or destroyed).

Signature
(Confirming authority)

Date.....

Place.....

APPENDIX – XI

[See rule 116 (2)]

[Form for promulgation of finding and sentence of Force Court]

The finding(s) and sentence of the general or petty Assam Rifles Court held at (place) from.....day of.....today of..... for the trial of the accused (particulars)..... were promulgated to the accused by me at(place) onday of 20.....

Extracts for battalion or unit records have been taken or *No record has been kept of the finding(s).

Signature
(Commandant)

Date.....

Place.....

* To be used in case of acquittal on all charges.

APPENDIX –XII

(See rule 174)

WARRANTS UNDER SECTIONS 143 AND 147 OF THE
ASSAM RIFLES ACT, 2006

FORM A

Warrant of commitment for use when a prisoner is sentenced to imprisonment for life (Section 143)

To

The Superintendent
of the (a).....Prison.

Whereas at a general Assam Rifles Court, held at.....on the day of 20..... (No.....Rank..... Name.....Unit.....) was convicted of (the offence to be briefly stated here, as "desertion on active duty", "correspondence with the enemy" or as the case may be).

And whereas the said general Assam Rifles Court on theday of 20 .., passed the following sentence upon the said (Name.....) that is to say.....

(Sentence to be entered in full, but without signature).

And whereas the said sentence had been duly confirmed by (b)as required by law (c).

This is to require and authorise you to receive the said (Name.....) into your custody in the said prison as by law is required, together with this warrant, until he shall be delivered over by you with the said warrant to the proper authority and custody for the purpose of undergoing the aforesaid sentence of imprisonment for life. The aforesaid sentence has effect from the (d).

The period spent by (Name)..... in civil custody/Force custody during the investigation, inquiry or trial of the same case is (e)..... and the said period (e)..... shall be set off against the aforesaid sentence of imprisonment.

Given under my hand at this the day of20

Signature (f)

- (a) Enter name of civil prison.
- (b) Name and description of confirming authority.
- (c) Add if necessary "with a remission of"
- (d) Enter date on which the original sentence was signed.
- (e) Enter the exact period (years, months and days) spent in civil/Force custody during investigation, inquiry or trial in the same case.
- (f) Signature of Commandant of the prisoner or other prescribed officer.

FORM B

Warrants of commitment for use when a prisoner is sentenced to imprisonment which is to be undergone in a civil prison (Section 143)

To

The Superintendent
of the (a)..... Prison.

Whereas at a (b)..... Force Court held at
on the day of20
(No..... Rank..... Name..... Unit.....) was
duly convicted of (the offence to be briefly stated here as 'desertion', 'theft', 'receiving stolen goods', 'fraud', 'disobedience of lawful command' or as the case may be).

And whereas the said (b)..... Force Court on the day of
20 .., passed the following sentence upon the said (Name.....) that is to say.....
(Sentence to be entered in full, but without signature).

And whereas the said sentence (c)..... has been duly confirmed by (d)..... as required by law (e) or is by law valid without confirmation.

This is to required and authorise you to receive the said (Name.....) into your custody together with the warrant and there carry the aforesaid sentence of imprisonment into execution according to law. The sentence has effect from the (f).....

The period spent by (Name)..... in civil custody or Force custody during the investigation, inquiry or trial of the same case is (g)..... and the said period (g)..... shall be set off against the aforesaid sentence of imprisonment.

Given under my hand at this the day of
20.

Signature (h)

- (a) Enter name of civil prison.
- (b) General, petty or summary.
- (c) Strike out inapplicable words.
- (d) Name and description of confirming authority.
- (e) Add if necessary "with a remission of"
- (f) Enter date on which the original sentence was signed.
- (g) Enter the exact period (years, months and days) spent in civil or Force custody during investigation, inquiry or trial in the same case.
- (h) Signature of Commandant of the prisoner or other prescribed officer.

FORM C

Warrant for use when a sentence of imprisonment for life is reduced by superior authority to one of a shorter period (Section 147).

To

The Superintendent
of the (a)..... Prison.

Whereas (No.....Rank.....Name..... of theunit is confined in the (a).....prison under a warrant issued by (b) in pursuance of a sentence of (c).....passed upon him by a general Assam Rifles Court held aton..... and whereas (d)..... has, in the exercise of the powers conferred upon him by the Assam Rifles Act, passed the following order regarding the aforesaid sentence; that is to say :-

(e).....

This is to require and authorise you to keep the said (name)..... in your custody together with this warrant in the said prison as by law is required until he shall be delivered over by you with the said warrant to the proper authority and custody, for the purpose of his undergoing the punishment of imprisonment for life under the said order. And this is further to require and authorise you to return to me the original warrant of commitment in lieu where of this warrant is issued.

* The period of such imprisonment will reckon from the (f).

The period spent by (Name)..... in civil custody or Force custody during the investigation, inquiry or trial of the same case is (g)..... and the said period (g)..... shall be set off against the aforesaid sentence of imprisonment.

Given under my hand atthis the.....day of20

Signature (h)

- (a) Enter name of civil prison.
- (b) Enter name or designation of officer who signed original warrant.
- (c) Enter original sentence (if this was reduced by the confirming officer or other superior authority, the sentence should be entered thus— "Life Imprisonment reduced by confirming officer to 10 years").
- (d) Name and designation of authority varying the sentence.
- (e) Order to be set out in full.
- (f) Enter date on which original sentence was signed.
- (g) Enter the exact period (years, months and days) spent in civil or Force custody during investigation, inquiry or trial in the same case.
- (h) Signature of prescribed officer.

FORM D

Warrant for use when prisoner is to be delivered into
Force custody

To

The Superintendent
of the (a)..... Prison.

Whereas (No.....Rank.....Name..... of theunit is confined in the (a).....prison under a warrant issued by (b) in pursuance of a sentence of (c).....passed upon him by a (d)..... Force Court held aton..... and whereas(e)..... has, in the exercise of the powers conferred upon him by the Assam Rifles Act, passed the following order regarding the aforesaid sentence; that is to say :-

(f).....

This is to require and authorize you to deliver forthwith the said (name) in your custody to the officer or subordinate officer bringing this warrant.

Given under my hand at this the day
of 20

Signature (g)

- (a) Enter name of civil prison.
- (b) Enter name or designation of officer who signed original warrant.
- (c) Enter original sentence (if this was reduced by the confirming officer or other superior authority the sentence should be entered thus :- "2 years rigorous imprisonment reduced by confirming officer to 1 year rigorous imprisonment").
- (d) General, petty or summary.
- (e) Name and designation of authority issuing the order.
- (f) Order to be set out in full.
- (g) Signature of prescribed officer.

APPENDIX—XIII

[See rule 175(1)]

FORM E

Warrant committing to civil prison custody
a person sentenced to death

To

The Superintendent
of the (a) Prison.

Whereas a general Assam Rifles Court held at on the day of
..... 20, (No. Rank
Name of the unit was convicted of
..... (Offence to be briefly stated).

And whereas the said general Assam Rifles Court on the day of
..... 20, passed sentence of death on the said
NAME—

This is to require and authorise you to receive and hold the said (Name) into your
custody in the said prison as by law required, together with this warrant, until such time as a further warrant
in respect of the said (Name) shall be issued to you.

Given under my hand at this the day of ... 20

Signature (b)

- (a) Enter name of civil prison.
- (b) Signature of the Commandant.

FORM F

Warrant of execution of sentence of death in civil prison
PART - I

To

The Superintendent
of the (a) Prison.

Whereas No. Rank Name of (unit) having been sentenced to
suffer death on the day of 20 by a General Assam Rifles
Court held at (b), has been by a warrant issued by (c) committed to your
custody;

AND whereas, the said sentence having been confirmed by the Central Government, a copy of the
order of the Central Government certifying the confirmation of the sentence of death being annexed hereto;

This is to authorise and require you to carry out the said sentence into execution by causing the said..... (Name) TO BE HANGED BY THE NECK UNTIL HE BE DEAD AT (d) and to return this warrant to (e)..... with an endorsement certifying that the sentence has been executed.

Given under my hand at..... this... day of20 .

Signature (f)

- (a) Enter name of civil prison.
- (b) Enter the place of trial.
- (c) Enter name and designation of officer who signed the original warrant.
- (d) Time, date and place of execution.
- (e) Director-General, Assam Rifles.
- (f) Signature of the Director-General.

PART - II

Return of warrant

The above sentence passed on (No)..... (Rank)..... (Name)..... was carried into effect at (d) hours on the day of.....

Signature
Superintendent of Prison.

FORM G

Warrant to obtain person sentenced to death from civil custody in order to carry out such sentence

To

The Superintendent
of the (a)..... Prison.

Whereas, No..... Rank..... Name..... of the unit having been sentenced to suffer death on the day of.....20 , by a general Assam Rifles Court held at..... is held in the said prison under a warrant issued by (b).

And whereas, the said sentence having been duly confirmed by (c)..... as by Law required, an order to carry out the said sentence has been issued to me (d)..... (Name & Rank).....

This is to require and authorize you to deliver forthwith said (Name)..... to the officer or subordinate officer under officer bringing this warrant.

Given under my hand at..... this... day of20 .

Signature (e)

- (a) Enter name of civil prison.
- (b) Enter name or designation of officer who signed original warrant.
- (c) Name and description of confirming authority.
- (d) Name and designation of the officer to whom the order is issued.
- (e) Signature of the officer by whom the warrant is issued.

FORM H

Warrant to carry out sentence of death by Assam Rifles authorities

PART - I

To

The Inspector-General or Deputy Inspector-General

Whereas, No Rank Name of the battalion or unit having been sentenced to suffer death on the day of 20... by a general Assam Rifles Court held at (a), is held in the (b) prison under a warrant issued by (c),

AND WHEREAS, the said sentence, having been confirmed by the Central Government, a copy of the order of the confirming authority certifying the confirmation of the sentence being annexed hereto, this is to authorise and require you to carry the said sentence into execution by causing the said(person) to be shot to death at (d)..... and to return this warrant to (e) with an endorsement certifying that the sentence has been executed.

Given under my hand at.....this the.....day of..... 20 .

Signature (f)

PART – II

Return of warrant

The above sentence passed on (Number) (Rank) (Name) was carried into effect at (d) hours on the day of 20.

Signature (g)

PART – III

CERTIFICATE OF MEDICAL OFFICER

I, (Number, Rank, Name) hereby certify that I have examined the body of Number Rank Name upon whom the sentence of death was carried into effect at (d) and that on such examination I found that the said person was dead.

Signed at (Place) this the day of 20 .

Signature
(Rank and Unit)
Medical Officer of Armed
Forces of the Union

- (a) Enter the place of trial.
- (b) Enter the name of the prison.
- (c) Enter name and designation of officer who signed the original warrant.
- (d) Time, date and place of execution.
- (e) Officer by whom the warrant is issued.
- (f) Signature of the officer by whom the warrant is issued.
- (g) Signature of the officer executing the sentence.

APPENDIX-XIV

(See rule 176)

FORM I

Warrant for use when the sentence of a person under sentence of death and committed to custody in a civil prison is commuted to a sentence of imprisonment for life.

To

The Superintendent of the
(a).....Prison

Whereas No.....Rank.....Name..... of the unit is held in the (a).....prison under a warrant issued by (b).....in pursuance of a sentence of death passed upon him by general Assam Rifles Court held at..... on.....and whereas (c).....has, in exercise of the powers conferred upon him by the Assam Rifles Act, passed the following order regarding the aforesaid sentence; that is to say (d).....

This is to require and authorise you to keep the said (Name.....) in your custody together with this warrant in the said prison as by law is required until he shall be delivered over by you with the said warrant to the proper authority and custody for the purpose of his undergoing the punishment of imprisonment for life, under the said order. And this is further to require and authorise you to return to me the original warrant of commitment in lieu whereof this warrant is issued. The period of such imprisonment for life will reckon from the (e).....

Given under my hand atthis theday of.....20 ..

Signature (f)

- (a) Enter name of civil prison.
- (b) Enter name or designation of the officer who signed original warrant.
- (c) Name and designation of authority commuting the sentence.
- (d) Order to be set out in full.
- (e) Enter date on which original sentence was signed.
- (f) Signature of Commandant.

FORM J

Warrant for use when the sentence of a person under sentence of death and committed to custody in a civil prison is commuted to a sentence of imprisonment to be served in the same prison.

To

The Superintendent of the (a).....Prison.

Whereas (No.....Rank.....Name.....) of theunit is held in the (a) ...prison under a warrant issued by (b)..... in pursuance of a sentence of death passed upon him by a general Assam Rifles Court held at..... on....., and whereas (c)..... has in exercise of the powers conferred upon him by the Assam Rifles Act, passed the following order regarding the aforesaid sentence, that is to say :- (d).....

This is to require and authorise you to keep the said (Name)..... in your custody together with this warrant, and there to carry into execution the punishment of imprisonment under the said order according to law.

And this is further to require and authorise you to return to me the original warrant of commitment in lieu whereof this warrant is issued. The period of such imprisonment will reckon from the (e).....

The period spent by (Name)..... in civil custody or Force custody during the investigation, inquiry or trial of the same case is (f)..... and the said period (f)..... shall be set off against the aforesaid sentence of imprisonment for life.

Given under my hand atthis theday of.....20 ..

Signature (g)

- (a) Enter name of civil prison.
- (b) Enter name or designation of the officer who signed original warrant.
- (c) Name and designation of authority commuting the sentence.
- (d) Order to be set out in full.
- (e) Enter date on which original sentence was signed.

- (f) Enter the exact period (years, months and days) spent in civil or Force custody during investigation, inquiry or trial in the same case.
- (g) Signature of Commandant.

FORM K

Warrant for use when a person who, after having been sentenced to death, has been committed to custody in a civil prison, is to be delivered into Force custody for a purpose other than carrying out the sentence of death.

To

The Superintendent of the (a).....Prison.

Whereas (No.....Rank.....Name.....) of theUnit is held in the (a).....Prison under a Warrant issued by (b)..... in pursuance of a sentence of death passed upon him by a General Assam Rifles Court held at..... on....., and whereas (c)..... has in exercise of the powers conferred upon him by the Assam Rifles Act, passed the following order regarding the aforesaid sentence; that is to say (d).....

This is to require and authorise you to forthwith deliver the said (name)..... to the officer/subordinate officer or under officer bringing this warrant.

Given under my hand atthis theday of.....20 ..

Signature (e)

- (a) Enter name of civil prison.
- (b) Enter name or designation of the officer who signed original warrant.
- (c) Name and designation of authority issuing order.
- (d) Order to be set out in full.
- (e) Signature of Commandant.

FORM L

Warrant for use when a prisoner is pardoned or his trial set aside, or when the whole sentence or the unexpired portion is remitted (Section 147).

To

The Superintendent
of the (a).....Prison.

Whereas, (No.....Rank.....Name.....) of theunit is confined in the (a)... prison under a warrant issued by (b)..... in pursuance of a sentence of (c)..... passed upon him by a (d).... Assam Rifles Court held at..... on....., and whereas (e)..... has in exercise of the powers conferred upon him by the Assam Rifles Act, passed the following order regarding the aforesaid sentence; that is to say (f).....

This is to require and authorise you to forthwith discharge the said (Name)..... from your custody unless he is liable to be detained for some other cause, and for your so discharging him this shall be your sufficient warrant.

Given under my hand atthis theday of.....20 ..

Signature (g)

- (a) Enter name of civil prison.
- (b) Enter name or designation of the officer who signed original warrant.
- (c) Enter original sentence (if this was reduced by the confirming officer or other superior authority, the sentence should be entered thus: '2 years rigorous imprisonment reduced by confirming officer to 1 year').
- (d) General, petty and (or) summary.

- (e) Name and designation of authority pardoning prisoner, mitigating sentence or setting aside trial.
- (f) Order to be set out in full.
- (g) Signature of prescribed officer.

APPENDIX -XV
[See rule 185 (2) (a)]
REPORT ON UNNATURAL DEATH

1. Place of death, or the place where dead body was found (give details).
2. Date and time at which information of death was received.
3. Name and description of two or more persons who identify the dead body.
4. Name and particulars of the deceased and his status.
5. Condition of clothes worn by deceased.

Note:—In case, examination by Doctor is awaited, above details should be collected without removing the clothes etc. of the deceased. The other details should be completed after the Doctor's examination.

6. Condition of limbs, eyes and mouth.
7. Expression of face.
8. Marks of struggle on the dead body if any, injuries and abrasions should be recorded showing their size and location.

Note—Depth of injury should be recorded but injuries should not be touched. If examination by Doctor is awaited the above information should be recorded after his examination.

9. Whether blood is fluid or coagulated. The place from which it came out and its quantity.
10. By which means, weapon or instrument, the injury or marks of struggle appear to have been caused?
11. Was any rope tied around the neck or is there any marks of it being tied by anything?
12. Was the rope or any other thing used to strangle or hang dead body, was it strong enough to sustain the weight and whether its other end was tied to anything?
13. Was any external article like grass etc. sticking to hairs or held in his hands or sticking to any other part of the body?
14. Is the dead body that of a strong and well built man or is it that of a weak or old man?
15. Is the dead body strong or weak or is it in decomposed state?
16. Length of the dead body from head to feet.
17. Identification marks and location and appearance of the wound.
18. Apparent cause of death.
19. Is there any rumour or other circumstances showing that it is a case of suicide?

Details of articles found on the dead body or lying near it.

20. Those found on the dead body (a slip will be affixed on each article which will be stamped).

21. Those found lying near the dead body (a slip duly stamped will be affixed on each article).

Description of seal

22. Map of the place where the dead body was found.

Brief history of the case.

Signature of two or more
respectable witnesses of the
locality in whose presence
investigation was carried
out.

Place _____

Signature of the officer
investigating the case

Date _____

Name

Rank _____

PART - II
(SPECIMENS OF FORCE COURTS PROCEEDINGS)
(Specimen - I)

**FORM OF PROCEEDINGS FOR GENERAL AND PETTY ASSAM RIFLES COURTS UNDER THE
ASSAM RIFLES ACT, 2006**

A

Proceedings of a general Assam Rifles Court held at _____ on the _____ day of
_____ by order of _____ Inspector-General or Deputy Inspector-General Assam
Rifles _____ dated the _____ day of _____

Presiding Officer

No. _____ Rank. _____ Name _____ Unit _____

Members

No. _____ Rank. _____ Name _____ Unit _____

No. _____ Rank. _____ Name _____ Unit _____

No. _____ Rank. _____ Name _____ Unit _____

No. _____ Rank. _____ Name _____ Unit _____

Law Officer

No. _____ Rank. _____ Name _____ Unit _____

Interpreter

No. _____ Rank. _____ Name _____ Unit _____

Trial of No. _____ Rank. _____ Name _____ Unit _____ (attached to _____ unit)

The order convening the court, the charge sheet and the summary of evidence are laid before the court.

The _____ court satisfies itself that No. _____ Rank _____ Name _____ Unit _____ is not available to serve owing to (insert reasons)

No. _____ Rank _____ Name _____ Unit _____, Waiting member takes his place as a member of the court.

The court satisfies itself as provided by Assam Rifles rule 68.

Note.— Before satisfying that the court has satisfied itself as provided by Assam Rifles rule 68, the Presiding Officer will, in every case where a court of inquiry has been held respecting a matter upon which a charge against the accused is founded, insert an asterisk after the words "Assam Rifles rule 68" and sign a footnote at the bottom of the first page of the proceedings, to the following effect:-

"I have satisfied myself that none of the officers detailed as members of this court has previously served upon any court of inquiry respecting the matters forming the subject of the charge (charges) before this court."

Place:

Date :

(Signature of Presiding Officer)

The accused is brought before the court.

Prosecutor _____ (legal qualification to be stated)

Prosecution counsel (if any) Name..... (qualification).....advocate...(court in which practicing)

Defending officer (legal qualification to be stated)

Defence counsel, if any, Name....(qualification).....advocate...(court in which practicing).

At _____ hrs the trial commences.

The order convening the court is read and is marked _____ signed by the Law Officer (Presiding Officer) and attached to the proceedings. The names of the Presiding Officer and members of the court are read over in the hearing of the accused, and they severally answer to their names.

\$ Q-1 Do you object to be tried by me as Presiding Officer, or any of the officers whose names you have heard/read over?

A-1 _____

Q-2 What is your objection to (the junior most officer objected to)?

The accused in support of his objection to requests permission to calletc.,

No. _____ Rank _____ Name _____ is called into court, and is questioned by accused.

The member (objected to) in reply states.

The court is closed to consider the objection in the absence of (the challenged officer).

The court decides to disallow/allow the objection.

The court is re-opened and the accused is again brought before it. The above decision is announced in the open court.

@ Waiting Member takes his place as a member of the court.

@ (This only applies in the case of there being a waiting member of the court).

The court satisfies itself that No..... Rank Name Unit is eligible and not disqualified to serve on this court.

Q-3 Do you object to be tried by (the waiting member)?

A-3 _____

(If he objects, the objection will be dealt with in the same manner as the former objection.)

Note— * All printed matter not applicable to the particular court being held should be struck out and initialled by the officer responsible for the record (rule 130).

All questions and answers will be numbered serially through-out the proceedings.

\$ This question will be asked by the presiding officer to the accused (rule 70).
B (Fresh page)

The Presiding Officer, members and Law Officer are duly sworn or affirmed.

Q-4 Do you object to Shri (or No. ____ Rank ____ Name ____ Unit ____) as interpreter?

A-4

No. ____ Rank ____ Name ____
Unit ____ is duly sworn or affirmed as interpreter.

Q-5 Do you object to Shri ____ (or No. ____ Rank ____ Name ____ Unit ____) as shorthand writer?

A-5

No. ____ Rank ____ Name ____
Unit ____ is duly sworn or affirmed as shorthand writer.

@CHARGE SHEET

B-2 The charge sheet is signed by the Law Officer (Presiding Officer) marked B-2 and annexed to the proceedings. The accused is arraigned upon each charge in the above mentioned charge sheet.

Q-6 Are you guilty or not guilty of the (first) charge against you, which you have heard or read?

A-6

Q-7 Are you guilty or not guilty of the second charge against you, which you have heard or read?

A-7

Note: - 1. If the accused pleads guilty to the charge (s), the provisions of Assam Rifles rule 85 are to be complied with.

2. If the trial proceeds on more than one charge sheet, the trial on each charge sheet, from arraignment to finding, will be kept separate and distinct.

3. If the trial proceeds upon any charge to which there is a plea of not guilty the court will not proceed upon the record of plea of guilty until after the finding on that other charge [rule-87 (2)].

VARIATIONS

OBJECTION TO CHARGE (Assam Rifles rule 78)

The accused objects to the charge on the ground that (set out).

(Instructions.—Provisions of Assam Rifles rule 128 will be followed on all such incidental matters as shown below.)

The prosecutor answers (set out).

The accused (or defending officer) replies (set out).

The court is closed to consider its decision.

The court decides to disallow the objection (or the court decides to allow the objection and agrees to report to the convening authority).

The court being re opened, the accused is again brought before it and the above decision is announced in the open court.

The court proceeds with the trial (or adjourns).

AMENDMENT TO CHARGE (Assam Rifles rules 79/80)

The court, being satisfied that the name (or description) of the accused is and not as stated in the charge sheet, amend the charge sheet accordingly.

The court, before any witnesses are examined, considers that, in the interest of justice, the following addition to (or omission from or alteration in) the charge is required (set out), and adjourns to report its opinion to the convening authority.

PLEA TO THE JURISDICTION (Assam Rifles rule 77)

The accused pleads to the general jurisdiction of the court on the ground that (set out).

Q-8 Do you wish to produce any evidence in support of your plea? (Set out)

Witness is examined on oath (or affirmation). (Set out)

(Instructions.— The examination, etc, of the witnesses called by the accused and of any witness called by the prosecutor in reply, will proceed as directed below in the case of witnesses to the facts of the trial. Provisions of Assam Rifles rule 128 will be complied with.)

The prosecutor answers (set out).

The accused (or defending officer) replies (set out).

The court is closed to consider its decision.

The court (a) decides to overrule the plea and to proceed with the trial;

or

(b) decides to allow the plea and to report to the convening authority and adjourn;

The court is re opened, the accused is brought before it and the above decision is announced in open court.

The court proceeds with the trial (or adjourns).

PLEA IN BAR OF TRIAL (Assam Rifles rule 81)

Accused besides the plea of guilty (or, not guilty) offers a plea in bar of trial on the ground that (set out).

Q-9 Do you wish to produce evidence in support of your plea?

(Set out)

(Instructions.— The examination, etc, of the witnesses called by the accused, and of any witness called by the prosecutor in reply, will proceed as directed below in the case of witnesses to the facts of the trial. Provisions of Assam Rifles rule 128 will be complied with.)

The prosecutor answers (set out).

The accused (or defending officer) replies (set out).

The court is closed to consider its decision.

The court decides to allow the plea and resolve to adjourn and report to the convening officer (or to proceed with the trial on another charge, or the court decides to overrule the plea).

The court is re opened, the accused is brought before it and the above decision is announced in the open court, as being subject to the approval of the convening officer.

The court adjourns (or proceeds with the trial on another charge) (or proceeds with the trial).

REFUSAL TO PLEAD [Rule 85 (5)]

As the accused does not plead intelligibly (or refuses to plead) to the above charge, the court enters a plea of not guilty

The accused having pleaded guilty to the charge the provisions of Assam Rifles rule 84 are here complied with.

@ C (Fresh page)

PROCEEDINGS ON PLEA OF NOT GUILTY

Q-10 *Do you wish to apply for an adjournment on the ground that any of the
(*rule 90) rules relating to procedure before trial have not been complied with
and that you have been prejudiced thereby or on the ground that you have not
had sufficient opportunity for preparing your defence?
A-10 _____

(Instruction— In case of request for an adjournment the accused's statement together with the decision of the court is to be recorded).

The prosecutor hands in a written opening address which is read, marked
“ _____ ” signed by the Law Officer (Presiding Officer) and attached to the proceedings.

The prosecutor proceeds to call witnesses.

First witness for prosecution

PW-1 No. _____ Rank _____ Name _____
Unit _____ being duly sworn or affirmed is examined by the
prosecutor (or prosecution counsel).

Cross examined by the accused (or defending officer or defence counsel)

Re examined by the prosecutor (or prosecution counsel)

Questioned by the court

Notes: 1. At the end of each witness's evidence, provisions of Assam Rifles rule 98 will be complied with and a record made.

2. In case the Presiding Officer, Law Officer or a member address any question to the witness, Assam Rifles rule 97 should be complied with and the fact recorded.

3. For form of oath or affirmation see Assam Rifles rule 96 (4).

VARIATIONS

POSTPONEMENT OF CROSS- EXAMINATION (Assam Rifles rule 96)

The court, at the request of the accused, allows the cross examination of the witness to be postponed.

OBJECTIONS TO EVIDENCE OR PROCEDURE

(Assam Rifles rule 128)

The accused (or counsel or defending officer, or the prosecutor) objects to the following question on the ground that (set out).

The prosecutor (or counsel or defending officer, or accused, as the case may be) answers that (set out).

The accused (or counsel or defending officer or the prosecutor) in reply states that (set out).

The court is closed to consider its decision.

The court decides to over rule (allow) the objection.

The court is re opened, the accused is brought before it and the above decision is announced in open court.

The court proceeds with the trial.

EXPLANATION OR CORRECTION OF EVIDENCE

(Assam Rifles rule 98)

The witness, on his evidence being read to him, makes the following explanation or correction (set out).

Examined by the prosecutor as to the above explanation or correction.

Examined by (or on behalf of) the accused as to the above explanation or correction.

The prosecutor and accused (or counsel or defending officer) decline to examine him respecting the above explanation or correction.

PW-2 Second witness for prosecution.

.....*being duly sworn (or affirmed) is examined by the prosecutor. (The examination, etc., of this and every other witness proceeds as in the case of the first witness).

*Here insert his No, Rank, Name, unit and appointment or any other description.

VARIATIONS ADJOURNMENT

At hrs, on..... the court adjourn until hrs. on

At hrs, on the court re assemble, pursuant to the adjournment; present the same members and the Law Officer as on

[Instructions.—(1) If upon re-assembly a member is absent and his absence will reduce the court below the legal minimum and, it appears to the members present that the absent member cannot attend within a reasonable time, the Presiding Officer or senior member present will thereupon report the case to the convening authority (Assam Rifles rule 123).

(2) If the Law Officer is absent, and cannot attend within a reasonable time, the court will adjourn and the Presiding Officer will thereupon report the case to the convening authority (Assam Rifles rule 136)].

ABSENCE OF MEMBER

(No.....Rank.....Name unit) being absent, a medical certificate (or letter, or as the case may be) is produced, read marked and attached to the proceedings.

The court adjourns until.....

or

There being present(not less than the legal minimum) members, the trial is proceeded with.

Examination (cross-examination) of continued.

@ D (Fresh page)

The prosecution is closed.

DEFENCE QUESTIONS TO THE ACCUSED [Rule 101 (1)]

The Law Officer (Presiding Officer) reads and explains the provisions of Assam Rifles rule 101. Having ascertained that the accused understands the provisions read over to him, the court (Law Officer) proceed -(s) to ask the following questions.

Q-11 It has been stated in the evidence of _____ that _____. Do you wish to say anything about the same?

A-11 _____

Q-12 _____

A-12 _____

Q-13 _____

A-13 _____

Instructions to the court

1. The accused must be questioned only to afford an opportunity of offering an explanation. If he so wishes, where absence of such explanation, would affect him adversely.
2. Questions put to him should be such as will enable him to explain any circumstances appearing against him, which if unexplained, may lead to conviction.
3. Questions must not be put to the accused in order to supplement the case for the prosecution.
4. Questions to the accused and his answers will be recorded verbatim as far as possible.

[Rule-101 (3)]

Q-14 Do you intend to give evidence on oath as a witness or make a statement without being sworn?

A-14 _____

*The accused in his defence says or hands in a written address which is read, marked signed by the Law Officer (Presiding Officer) and attached to the proceedings or the accused declines to make any statement.

Note: - *In case the accused wishes to give evidence on oath, he will be examined as any other witness.

[Rule-101 (4)]

Q-15 Do you intend to call any witness in your defence?

A-15

Q-16 Is he a witness to character only?

A-16

Instructions to the court

When the answers to the above questions have been recorded, the court shall comply with the provisions of Assam Rifles rule 101.

The evidence of the witnesses for the defence (including witnesses as to character) will be taken after the questions, if any, to the accused have been addressed.

@ D2 (Fresh page)

The accused (counsel or defending officer) makes an opening address, or hands in a written opening address which is read, marked..... signed by the Law Officer (Presiding Officer) and attached to the proceedings.

The accused calls the following witness* (as to character).

* DW-I

First witness for the defence (as to character)*

Shri No...Rank...Name....unit... being duly sworn (or affirmed), is examined by the accused (or by counsel or defending officer).

Note.¥ At the end of each witness's evidence, provisions of Assam Rifles rules 97 and 98 as applicable will be complied with and the fact recorded.

*If witnesses are called excepting as to character, these words are to be struck out.

RECALLING WITNESS

(Assam Rifles rule 99)

(1) At the request of the prosecutor (or the accused) is recalled and examined on his former oath or affirmation through the Presiding Officer (or Law Officer) and states as follows—
(set out).

or

(2) The prosecutor with leave of the court, calls (or recalls) for the purpose of rebutting material statement made by a witness for the defence. The witness being duly sworn (or affirmed) is (or on his former oath or affirmation) being examined by the prosecutor states as follows—

(Set out with any cross-examination, re examination etc) or

(3) The prosecutor calls (or recalls) In reply to the witness (es) as to character called by the accused. The witness being duly sworn (or affirmed) is (or on his former oath/affirmation) being examined by the prosecutor states as follows -

(Set out any cross-examination, re-examination etc.) or

(4) The court in accordance with Assam Rifles rule 99 calls (or recalls) _____ who being duly sworn (or affirmed), (or his former oath/affirmation) states in reply to the questions by Presiding Officer (or Law Officer) as follows—
(set out)

[Instructions.— In (1), (2) and (3) witnesses must be called or recalled before the closing address of or on behalf of the accused. In (4) witnesses may be called or recalled by the court at any time before the finding. In this case the accused or counsel or defending officer and the prosecutor should be given the opportunity of asking further question through the court.]

(ADJOURNMENT TO PREPARE ADDRESSES, ETC)

The court, at the request of the accused (counsel or defending officer) adjourn until to enable him to prepare his address.

The court at the request of the prosecutor adjourn until to enable him to prepare his reply.

The court at the request of Law Officer adjourn until to enable him to prepare his summing up.

The prosecutor makes the following reply (or hands in a written reply) which is read (orally translated) marked signed by the Presiding Officer (or Law Officer) and attached to the proceedings.

The accused (counsel or defending officer) makes the following closing address (or hands in a written closing address) which is read (orally translated) marked signed by the Presiding Officer (or Law Officer) and attached to the proceedings.

SUMMING UP

The Law Officer hands in a written summing up which is read (orally translated) marked signed by the Presiding Officer and attached to the proceedings.

Note.¶ 1. All addresses by prosecutor, accused, counsel, or defending officer, whether recorded by the court or handed in writing (and written summing up by Law Officer) will be attached to the proceedings in the order in which they are made. Written addresses (and summing up) will be read to the court, marked and signed by the Presiding Officer (Law Officer except summing up).

2. If any person who is entitled to make an address, declines to do so, a record will be made to that effect.

3. For order of addresses see Assam Rifles rule 104 and 105.

@ CC (Fresh page)

PROCEEDINGS ON PLEA OF GUILTY

*(The court having been re-opened, the accused is again brought before it, and the charge(s) to which the accused pleaded guilty is or are read to him again).

* to be struck out in case no plea of not guilty has been proceeded with.

The accused No _____ Rank _____ Name _____ unit _____
is found guilty of the charge (all the charges) or is found guilty of the
charge and not guilty of the _____ charge.

ANNOUNCEMENT OF FINDING(S)

The finding (s) is or are read in open court and is or are announced as being subject to confirmation.

** The summary of evidence is read, marked _____ signed by the Law Officer (Presiding Officer) and attached to the proceedings.

** If there is no summary of evidence, the court shall record sufficient evidence to enable it to determine the sentence.

Q-17 Do you wish to make any statement in mitigation of punishment?

A-17 The accused, in mitigation of punishment, says (or hands in a written statement which is read, marked _____ signed by the Law Officer (Presiding Officer) and attached to the proceedings.

(Instructions.— If counsel or defending officer addresses the court on behalf of the accused the material portions of his address should be recorded.)

VARIATIONS ALTERATION OF PLEA (Assam Rifles rule 89)

#. The court being satisfied from the statement of the accused or summary of evidence or otherwise that the accused did not understand the effect of the plea of guilty, alters the same and enters a plea of not guilty.

#.Instructions.— (1) To be struck out if not applicable [rule 89 (2)].

(2) The court will then proceed in respect of the charge as on a plea of not guilty.

@ DD (Fresh page)

WITNESSES FOR DEFENCE ON PLEA OF GUILTY

The court permits the accused to call witnesses to prove his above statement that (set out the statement which is to be proved).

(Instructions.— The examination, etc, of witnesses called in pursuance of this permission will proceed in the same manner as on a plea of not guilty.)

Q-18 Do you wish to call any witness as to character?

A-18 _____

Q-19 Do you wish to call any witness in mitigation of punishment?

A-19 _____

Evidence as to character and or in mitigation of punishment.

Shri No...Rank...Name...unit... being duly sworn or affirmed is examined by the accused or by counsel or defending officer.

Note:- At the end of each witness's evidence, provisions of Assam Rifles rules 97 and 98, as applicable, be complied with and the fact recorded.

@ E (Fresh page)
*FINDING(S)

The court is closed for the consideration of the finding.

* to be omitted except in case of a plea of not guilty having been proceeded with.

(1) Acquittal on all charges.

The court find that the accused (No. _____ Rank _____
Name _____ unit _____) is not guilty of the charge (or, of all the charges).

ANNOUNCEMENT OF FINDING(S)

The court being reopened the accused is again brought before it. The finding (s) is or are read in open court, and is/are announced as being subject to confirmation.

Signed at _____ this _____ day of _____

(Signature)
Law Officer

(Signature)
Presiding Officer

(2) Acquittal on some but not all charges.

is not guilty of the _____ charge(s) but guilty of the _____ charge(s).

(3) Conviction on all charges.

is guilty of the charge (or all the charges).

(4) Special finding.

(a) is guilty of the _____ charge(s) and guilty of the _____ charge with the exception of the words (set out) (or, with the exception of _____ the words that (set out)).
or

(b) is not guilty of deserting the service but is guilty of absenting himself without leave.
or

(c) is guilty of the charge with the variation that figures and words "Rs.4200.00 (Rupees four thousand two hundred only)" shall read as "Rs.3200.00 (Rupees three thousand two hundred only)".

[Instructions.— Any special finding permitted by Assam Rifles rule 107 (4) and (5) will be recorded as far as possible in accordance with (a) or (c). Any special finding allowed by Assam Rifles Act Section 107 may be expressed in accordance with (b).]

INSANITY (Assam Rifles rule 138)

The court find that the accused (No. _____ Rank _____ Name _____
unit _____) is of unsound mind and consequently incapable of making his defence.

committed the act (acts) alleged as constituting the offence (offences) specified in the charge (charges) but was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing the nature of that act (or those acts) (or) but was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing that the act was wrong (or those acts were wrong) (or contrary to law).

ANNOUNCEMENT OF FINDING(S)

The court being reopened, the accused is again brought before it. The finding(s) is or are read in open court, and is or are announced as being subject to confirmation.

Signed at _____ this _____ day of _____

(Signature)
Law Officer

(Signature)
Presiding Officer

@ F (Fresh page)

PROCEEDINGS ON CONVICTION

No. _____ Rank _____ Name _____

Unit or battalion _____ is duly sworn or affirmed.

Q-20 What records have you to produce in proof of former convictions against the accused and his character?

A-20 I produce a statement certified under the hand of the officer having custody of the battalion or unit records.

The statement is read, marked _____ signed by the Law Officer (Presiding Officer) and attached to the proceedings.

Q-21 Is the accused, the person named in the statement you have, heard or read?

A-21 _____

Q-22 Have you compared the contents of the above statement with the battalion or unit records?

A-22 _____

Q-23 Are they true extracts from the battalion or unit records, and is the statement of entries in the defaulter sheet, a fair and true summary of these entries?

A-24 _____

Cross examined by the accused (or by counsel or defending officer).

Re examined. or

The accused declined to cross examine the witnesses.

Note: - Provisions of Assam Rifles rule 97 and 98, as applicable, will be complied with and the fact recorded.

Q-25 Do you wish to address the court in mitigation of sentence?

A-25 _____

The court is closed for the consideration of the sentence.

SENTENCE

The court sentence the accused _____ No. _____ Rank _____
Name _____ unit or battalion _____

[Instructions.— The sentence is to be marginally noted in every case.)

(a) to suffer death by being hanged by the neck until he be dead (or to suffer death by being shot to death).

(b) to suffer imprisonment for life.

(c) to suffer rigorous (or simple) imprisonment for _____.

(Note.— Sentences of imprisonment, unless for one or more years exactly, should, if for one month or upwards, be recorded in months. Sentences consisting partly of months and partly of days should be recorded in months and days).

(d) to be dismissed from service.

(e) (in case of an officer, subordinate officer or under officer)—to take rank and precedence as if his appointment as* _____ bore date the _____ day of _____ or

to take precedence in the rank of _____ held by him, as if his name had appeared (to specified number of places) lower in the Assam Rifles list in case of officers and subordinate officers and list of his rank in the case of under officers.

or

to forfeit _____ service for the purpose of promotion.

(Instructions.— This applies, only in case of a person whose promotion depends upon length of service and a sentence can be inflicted in respect of all or any part of his service.)

(f) to forfeit (all or _____ year's or _____ months) past service for the purpose of increased pay (or pension).

(g) (In case of an officer, subordinate officer and under officer) to be severely reprimanded (or reprimanded).

(h) to forfeit pay and allowances for a period of (not exceeding three months for an offence committed on active duty).

(i) to forfeit all arrears of pay and allowances and other public money due to him at the time of his dismissal.

(j) to be put under stoppage of pay and allowances until he has made good the sum of _____ in respect of or (and) until he has made good the value of the following articles, viz—

RECOMMENDATIONS TO MERCY

The court recommend the accused to mercy on the ground that (set out).

ANNOUNCEMENT OF SENTENCE

The court, being reopened, the accused is brought before it. The sentence is announced in open court as being subject to confirmation.

Signed at _____ this _____ day of _____

Law Officer

Presiding Officer

REVISION

At _____ on the _____ day of _____ at _____ hrs the court re assembles by order of _____ for the purpose of reconsidering its _____.

Present the same members and the Law Officer as on the _____.

[Instructions.— If a member is absent and the absence will reduce the court below the legal minimum, and it appears to the members present that such absent member cannot attend within a reasonable time, the Presiding Officer, or in his absence, the senior member present shall thereupon report the case to the convening authority.]

The order directing the reassembly of the court for the revision, and giving reasons of the confirming authority for requiring a revision is read, marked, signed by the Presiding Officer (or Law Officer) and attached to the proceedings.]

[Instructions.— (1) If the confirming authority so orders, additional evidence may be taken on revision.

(2) If a new Law Officer has been appointed, he should be sworn or affirmed and a record to that effect made before the revision order is read.

(3) If the accused or counsel or defending officer wishes to address the court, gist of his address should be taken down or his written address be read, marked and attached to the proceedings as usual (Assam Rifles rule 113 refers.)

(4) If the Law Officer wishes to clear any points, he may make an additional summing-up which should be read, marked and attached to the proceedings as usual.]

The court is closed to reconsider its finding (s) and sentence.

The court having attentively considered the observations of the confirming authority and the whole of the proceedings-

(a) do now revoke its finding and sentence and find the accused guilty/not guilty of the charge(s) and sentence him to....

or

(b) do now revoke its sentence and now sentence the accused to...

or

(c) do now respectfully adhere to its earlier sentence (or finding and sentence) or (finding).

[Instructions.— (1) In case the revision pertains to court's finding on some of the charges only record at (a) above should be made accordingly. If the court does not adhere to its former finding (s) it must revoke its former finding (s) and the sentence, and pass a fresh sentence if revised finding (s) involve (s) a sentence.

(2) If the new finding entails sentence, normal proceedings on conviction should be followed, if necessary and form at (a) above amended accordingly.

(3) All the decisions of the court with respect to the finding and sentence should be announced in open court as being subject to confirmation and a record made to that effect in normal manner.]

Signed atthisday of20.....

(Signature)
Law Officer

(Signature)
Presiding Officer

G (Fresh Page) CONFIRMATION

1. Confirmed.

* I direct that the sentence of (rigorous or simple) imprisonment shall be carried out by confinement in Force custody (or in civil prison).

The accused is recommended division A or C (or III) while undergoing sentence in the civil prison. If there are only two divisions of prisoners, the accused is recommended division A (or I) or B (or II). (In cases of imprisonment in civil prison).

2. I vary the sentence (s) so that it shall be as follows and confirm the finding and the sentence as so varied.

or

3. I confirm the finding and sentence of the court, but mitigate (or remit or commute).

or

4. (Where the finding is not confirmed).

Not confirmed.

5. Where the court finds that the accused is of unsound mind and consequently incapable of making his defence or that he committed the act alleged but was by reason of unsoundness of mind incapable of knowing the nature of the act or that it was wrong or contrary to law.

"Confirmed (or not confirmed)".

or

6. "I confirm the finding of the court on the first charge but do not confirm the finding on the second charge."

I confirm the sentence but mitigate (remit or commute).

Signed at _____ this _____ day of _____.

(Signature of confirming authority)

(Instructions.— Any remark of the confirming authority should be separate and form no part of proceedings.)

PROMULGATION

(Rule 116)

The finding (s) and sentence of the general or petty Assam Rifles Court held at _____ (place) _____ from _____ day to _____ day of _____ for the trial of the accused (particulars) _____ were promulgated to the accused by me at _____ (place) on _____ day of _____. Extracts for battalion or unit records have been taken or *No record has been kept of the findings.

Place _____

Date _____

Signature
(Commandant)

*To be used in case of acquittal on all charges.

(Specimen - 2)

FORM OF PROCEEDINGS FOR SUMMARY ASSAM RIFLES COURT UNDER THE ASSAM RIFLES ACT, 2006

A

Proceedings of a summary Assam Rifles Court held at _____ on the _____ day of _____ by _____ Commandant _____ battalion or unit for the trial of all such accused persons as he may duly have brought before him.

PRESENT

COMMANDANT _____

ATTENDING THE TRIAL

INTERPRETER

FRIEND OF THE ACCUSED

The officers assemble at the _____ and the trial commences at _____ hrs.

The accused No. _____ Rank _____ Name _____ of _____ is brought (called if an under officer) into court.

* _____ the court, is duly sworn or affirmed _____ is sworn or affirmed as interpreter.

(Instructions.— If the Commandant of the accused (i.e. the court) acts as interpreter, he must take the interpreter's oath in addition to the oath prescribed for the court.)

All witnesses are directed to withdraw from the court.

- *1. Enter rank and name of the officer holding the trial.
2. Throughout these proceedings he is referred to as the court.
3. Inapplicable portions be deleted and initialled by the court.

B (Fresh page)

The charge sheet is read (translated) and explained to the accused, marked B-2, signed by the court and attached to the proceedings.

[Instructions.— The sanction of superior authority for trial by summary Assam Rifles Court should be entered with the date and signature of that authority, at the foot of the charge sheet (Assam Rifles rule 95 (2).]

ARRAIGNMENT

*Q-1 How say you No. _____ Rank _____ Name _____ Unit _____ are you guilty or not guilty of the first charge or _____ charge?

Ans-1 _____

Note.— If the accused pleads guilty to any charge the provisions of Assam Rifles rule 153 (2) must be complied with.

**The accused having pleaded guilty to _____ charge, the court explains to the accused the meaning of the charge (s) to which he has pleaded guilty and ascertains that the accused understands the nature of the charge (s) to which he has pleaded guilty. The court also informs the accused the general effect of that plea and the difference in procedure which will be followed consequent to the said plea. The court having satisfied itself that the accused understands the charge (s) and the effect of his plea of guilty accepts and records the same. The provisions of rule 161 (2) are complied with.

* In case of more than one charge accused should be questioned separately.

** In cases where on arraignment, an accused pleads guilty to a charge, rule 153 (2) should be explained to the accused and the above minute should be recorded in the proceedings before recording a finding of guilty.

C (Fresh page)

PROCEEDINGS ON PLEA OF GUILTY

The accused No. _____ Rank _____ Name _____ of _____ is found guilty of the charge (all the charges).

The summary of evidence is read (translated), explained, marked _____ signed by the court and attached to the Proceedings.

*Question to the accused.

*Q- Do you wish to make any statement in reference to the charge or in mitigation of punishment?

Ans- _____

Q- Do you wish to call any witness as to character?

Ans- _____

[Instructions.— If the trial proceeds upon any charge to which there is a plea of not guilty, the court will not proceed upon the record of the plea of guilty until after the finding on those other charges; and in that case the charge on which the record is guilty must be read to the accused again. Assam Rifles rule 153 (1) refers.]

SVARIATIONS

The court being satisfied from the statement of the accused (or the summary of evidence, or otherwise) that the accused did not understand the effect of the plea of guilty alters the record and enters a plea of not guilty.

\$ Applicable in cases where a plea of guilty offered by the accused is negated by his statement in S of E or by other circumstances as mentioned in Assam Rifles rule 154 (4) (a).

D (Fresh page)

PROCEEDINGS ON A PLEA OF NOT GUILTY PROSECUTION

First witness for prosecution

PW-1 No _____ Rank _____ Name _____
_____ of _____ being duly

sworn or

affirmed is examined by the Court.

Cross examined by the accused.

Re examined by the Court.

Note.—

If the accused declines to cross examine witness for the prosecution, the fact must be recorded. The fact that the provisions of Assam Rifles rule 106 have been complied with must be recorded at the conclusion of the evidence of each witness.

D-2 (Fresh page)

Second witness for prosecution

PW-2 No _____ Rank _____ Name _____
_____ of _____ being duly

sworn or

affirmed is examined by the court.

Cross examined by the accused.

Re examined by the court.

Note.—

If the accused declines to cross examine a witness for the prosecution, the fact must be recorded. The fact that the provisions of Assam Rifles rule 98 have been complied with, must be recorded at the conclusion of the evidence of each witness.

E (Fresh page)

The prosecution is closed.

DEFENCE
QUESTIONS TO THE ACCUSED

[Rule 156 (3)]

The court reads and explains the provisions of Assam Rifles rule 156 (3). Having ascertained that the accused understands the provisions read over to him, the court proceed (s) to ask the following questions to the accused.

Q- It has been stated in the evidence of _____ that _____. Do you wish to say anything about the same?

A- _____

Q- _____

A- _____

(Instructions to the court

1. The accused must be questioned only to afford an opportunity of offering an explanation, if he so wishes, where absence of such explanation, would affect him adversely.
2. Questions put to him should be such as will enable him to explain any circumstances appearing against him, which if unexplained, may lead to conviction.
3. Questions must not be put to the accused in order to supplement the case for the prosecution.
4. Questions to the accused and his answers will be recorded verbatim as far as possible.)
5. No oath shall be administered to the accused.

[Question to the accused under AR rule 156 (2)]

Q. Do you wish to say anything in your defence?

A. _____

[Question to the accused under AR rule 156 (2)]

Q. Do you intend to call any witness in your defence?

A. _____

F (Fresh page)

First witness for defence

DW-1 No _____ Rank _____ Name _____
_____ of _____ being duly sworn or affirmed is examined by the court.

Cross examined by the court.

Re examined by the accused.

Notes.—1. The fact that the provisions of Assam Rifles rule 98 have been complied with must be recorded at the conclusion of the evidence of each witness.

2. If there are more than one defence witness, their statements shall be recorded on subsequent pages as F-2, F-3 etc.

Defence is closed.

G (Fresh page)

REPLY (Rule 157)

No _____ Rank _____ Name _____ of _____

being duly sworn or affirmed is examined by the court.

H (Fresh page)

VERDICT OF THE COURT

(Acquittal on all charges)

I am of the opinion on the evidence before me that the accused

No _____ Rank _____ Name _____

of _____ is not guilty of the charge (all the charges) and acquit him of the same.

The verdict is read out and the accused released _____

Signed at _____ this _____ day of _____

(Commandant)
Officer holding the trial

The trial closes at _____ hrs.

Note.—
charges.

This page is to be used only in cases where the accused is found "not guilty" of all the

I (Fresh page)

VERDICT OF COURT

I am of the opinion on the evidence before me that the accused No _____
 Rank _____ Name _____
 of _____ is (guilty of the charge or not guilty of the first charge and
 guilty of the second charge or or is guilty of all the charges).

(Special finding)

(a) is guilty of the _____ charge (s) and guilty of the _____ charge with the
 exception of the words (set out) or, with the exception of _____ the words that (set out).

or

(b) is not guilty of deserting the service but is guilty of absenting himself without
 leave.

or

(c) is guilty of the charge with the variation that figures and words Rs.4200.00
 (Rupees four thousand two hundred only) shall read as Rs.3200.00 (Rupees three thousand two
 hundred only).

[Instructions.— Any special finding permitted by Assam Rifles rule 159 (3) will be recorded as far
 as possible in accordance with (a) or (c). Any special finding allowed by Assam Rifles Act Section 115 may
 be expressed in accordance with (b).]

PROCEEDINGS BEFORE SENTENCE

The following minutes by the court are read and explained.

[Instruction.— If the court does not record the accused person's convictions and character of its own knowledge, evidence as to these matters will be taken.]

It is within my own knowledge from the records of the _____ that the accused has _____ been previously convicted by Force Court or criminal court (a separate statement giving full particulars of any previous conviction to be annexed when necessary).

That the following is a fair and true summary of entries in his defaulter sheet exclusive of convictions by a Force Court or a criminal court.

Within last 12 months

Since enrolment

For _____	times _____	times _____
For _____	times _____	times _____
For _____	times _____	times _____

That he is at present undergoing _____ sentence. That, irrespective of this trial, his general character has been _____. That his age is _____. His service is _____ and his rank is _____ (date since held).

That he has been in arrest/confinement for _____ days.

* That he is in possession of the following decorations and rewards—

* Any recognized acts of gallantry or distinguished conduct should also be entered here.

J (Fresh page)

SENTENCE BY THE COURT

Taking all these matters into consideration, I now sentence the accused No _____ Rank _____ Name _____ of _____ to _____. (for format of sentence refer specimen of general or petty Assam Rifles Court at page F).

Signed at _____ this _____ day of _____.

(Commandant)
Officer holding the trial

The trial closes at _____ hrs.

Remarks by the reviewing officer (Assam Rifles Act Section 137)

No _____ of _____

Trial by summary Assam Rifles Court under the Assam Rifles Act.

No _____ of _____ at _____

on the _____ day of _____.

Registered No. _____ of _____

CHIEF LAW OFFICER

PROFORMA FOR THE STATEMENT OF PREVIOUS CONVICTIONS AND GENERAL CHARACTER OF THE ACCUSED PERSON AS REQUIRED UNDER ASSAM RIFLES RULE 109

1. Name and number of the accused :
2. Present rank :
3. Date of enrolment or appointment in Assam Rifles :
4. Date of promotion in the present rank :
5. Total length of service :
6. Date of birth and age :
7. The period of arrest or confinement till the date of commencement of trial :
8. The decorations and awards (any recognised act of gallantry or distinguished conduct should also be entered here) :
9. The details of convictions by Assam Rifles Court and Criminal Court as per annexure :
10. Punishment awarded by an officer exercising authority under Section 62, 64, 65 or 66 of the Assam Rifles Act :

Within last 12 months

Since enrolment or appointment

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| (a) u/s _____ for _____ times | (a) u/s _____ for _____ times |
| (b) u/s _____ for _____ times | (b) u/s _____ for _____ times |
| (c) u/s _____ for _____ times | (c) u/s _____ for _____ times |

11. That he is at present undergoing _____ sentence.
12. That irrespective of this trial, his general character has been _____.

(It should be assessed on the basis of his record as it stood prior to the present trial).

(Signature)
Commandant or the officer

Having the custody of service
Records or confidential dossiers

Annexure

STATEMENT OF CONVICTIONS BY ASSAM RIFLES COURT
OR CRIMINAL COURT

Verdict of the Court

Sl No	Date of trial	Particulars of the charge	By Force Court or criminal court	Finding	Sentence	Remarks
-------	---------------	---------------------------	----------------------------------	---------	----------	---------

PART - III

FORMS OF SUMMONS TO WITNESS

(a) In the case of summary of evidence

To,

Whereas a charge of having committed an offence triable by Force Court has been preferred before me, against (No _____ Rank _____ Name _____ unit _____), and whereas I have directed a summary of the evidence to be taken in writing at _____ (place) on the _____ day of _____ at _____ hrs; I do hereby summon and require you (name) _____ to attend as a witness at the said place and hour and to bring with you the documents hereinafter mentioned, namely _____.

Whereof you shall fail at your peril.

Given under my hand at _____ on the _____ day of _____.

Commandant of the accused.
(Signature)

(b) In the case of a trial by Force Court

To,

Whereas an Force Court has been ordered to assemble at _____ on the _____ day of _____ for trial of _____ of the _____ battalion, I do hereby summon and require you A _____ B _____ to attend, as a witness at the sitting of the said court at _____ (place) on the _____ day of _____ hrs. (and to bring with you the documents hereinafter mentioned, namely _____), and so to attend from day to day until you shall be duly discharged, whereof you shall fail at your peril.

Given under my hand at _____ on the _____ day of _____.

(Signature)
Convening officer or Law Officer or
Presiding Officer of the court or
Commandant of the accused.

(c) In the case of a court of inquiry

To,

Whereas a court of inquiry has been ordered to assemble at _____ on the _____ day _____ for investigating into _____. I do hereby summon and require you A _____ B _____ to attend as a witness at the sitting of the said court at _____ (place) on the _____ (day), at _____ hrs and to bring with you the documents hereinafter mentioned, namely _____ and so to attend from day to day until you shall be duly discharged, whereof you shall fail at your peril.

Given under my hand at _____ on the _____ day of _____.

(Signature)

Officer assembling the
court of inquiry

PART - IV WARRANTS

Warrants for convening general Assam Rifles Court under the Assam Rifles Act, 2006

To

The (Inspector-General or Additional Director-General) Assam Rifles

In pursuance of the provisions of the AR Act, 2006, I do hereby empower you, or the officer on whom your command may devolve during your absence, not under the rank of Commandant, from time to time, as occasion may require, to convene general Assam Rifles Court for the trial, in accordance with the said Act and the rules made thereunder, of any person under your command who is subject to AR Act and is charged with any offence mentioned in the said Act, and is liable to be tried by a general Assam Rifles Court.

And for so doing, this shall be, as well to you as to all others whom it may concern, a sufficient warrant.

Given under my hand at _____ this _____ day of _____.

Director-General Assam Rifles

Warrant for confirming findings and sentences of general Assam Rifles Courts under the Assam Rifles Act, 2006

To

The Director-General Assam Rifles

In pursuance of the provisions of the AR Act 2006, the Central Government is pleased to hereby empower you, or the officer on whom your command may devolve during your absence, not under the rank of Commandant, to receive the proceedings of general Assam Rifles Courts held for the trial, in accordance with the said Act and the rules made thereunder, of any person subject to AR Act, and confirm the findings and sentences thereof, and to exercise, as respects these courts and the persons tried by them, the powers vested by the said Act in the confirming officer, in such manner as may be best for the good of the Force;

Provided always that if by the sentence of any general Assam Rifles Court, a person subject to AR Act has been sentenced to suffer death, you shall in such case, as also in the case of any other general Assam Rifles Court in which you shall think fit so to do, reserve confirmation and transmit the proceedings to the Central Government.

And for so doing, this shall be, as well to you as to all others whom it may concern, a sufficient warrant.

Given under my hand at _____ this ____ day of _____.

By order of the Central Government
Secretary, Ministry of Home Affairs

Warrant for confirming findings and sentences of general Assam Rifles Courts under the Assam Rifles Act, 2006

To

The (Inspector-General or Additional Director-General) Assam Rifles

In pursuance of the provisions of the AR Act, 2006, the Central Government is pleased to hereby empower you, or the officer on whom your command may devolve during your absence, not under the rank of Commandant, to receive the proceedings of general Assam Rifles Court held for trial, in accordance with the said Act and the rules made thereunder, of any person under your command who is subject to AR Act, and confirm the findings and sentences thereof, and to exercise, as respects these courts and the persons tried by them, the powers created by the said Act in the confirming officer, in such manner as may be best for the good of the Force:

Provided always that if by the sentence of any general Assam Rifles Court a person subject to AR Act has been sentenced to suffer death, you shall in such case, as also in the such cases as specified in annexure attached herewith, reserve confirmation and transmit the proceedings to superior authority.

And for so doing, this shall be, as well to you as to all others whom it may concern, a sufficient warrant.

Given under my hand at _____ this ____ day of _____.

By order of the Central Government
Secretary, Ministry of Home Affairs

Annexure

1. The proceedings of general Assam Rifles Courts where any of the sentences specified under column I below, is passed, will be reserved for confirmation by the authority specified opposite under column II below:-

I	II
(i) Death Sentences.	Central Government
(ii) All sentences passed on officers.	DGAR

2. In the event of finding of not guilty by a general Assam Rifles Court, in all cases of officers, powers to confirm or non confirm the proceedings will be with the DGAR.

Warrant for convening and confirming petty Assam Rifles Courts under
the Assam Rifles Act, 2006

To

The (Deputy Inspector-General) Assam Rifles

Whereas I have power to convene general Assam Rifles Courts under the AR Act, 2006, and whereas under that Act, any officer having power to convene general Assam Rifles Courts may, empower

any officer to convene a petty Assam Rifles Court for the trial under that Act of any person subject to AR Act under the command of such last mentioned officer and to confirm the findings and sentence thereof.

By virtue of the power vested in me under the said Act, I do hereby empower you, or the officer on whom your command may devolve during your absence, not under the rank of Commandant, from time to time, as occasion may require, to convene petty Assam Rifles Courts for the trial, in accordance with the said Act and the rules made thereunder, of any person under your command, who is subject to AR Act and is charged with any offence mentioned in the said Act, and is liable to be tried by a petty Assam Rifles Court.

And I do hereby further empower you, or the officer on whom your command may devolve during your absence, not under the rank of Commandant, to receive the proceedings of such courts, and the person tried by them, the powers created by the said Act in the confirming officer, in such manner as may be best for the good of the Force.

And for so doing, this shall be, as well to you as to all others whom it may concern, a sufficient warrant.

Given under my hand at _____ this _____ day of _____.

Signature of the Staff Officer

Signature of officer having power to
Convene general Assam Rifles Courts

PART - V

SPECIMEN CHARGES

No. 1

Assam Rifles Act
Section 21(a)

SHAMEFULLY ABANDONING A POST COMMITTED
TO HIS CHARGE,

in that he,

aton.....when in charge of post No.....in
Sector.....and attacked by the enemy, shamefully abandoned the
said post, without any attempt to resist the enemy.

No. 2

Assam Rifles Act
Section 21(b)

INTENTIONALLY USING MEANS TO INDUCE A
PERSON SUBJECT TO ASSAM RIFLES ACT TO ABSTAIN FROM
ACTING AGAINST THE ENEMY,

in that he,

aton.....when both he and No.....
Rank.....Name.....of his battalion were on duty at the forward
post No.....of his unit, under enemy fire, said to the said
No.....Rank.....Name.....

*" We are likely to be killed. Think of your wife and children.
Let us run away from the post and hide in the nallah nearby", or words
to that effect.

Note*— Insert actual words spoken or words to that effect.

No. 3

Assam Rifles Act
Section 21(c)

IN THE PRESENCE OF THE ENEMY MISBEHAVING
IN SUCH MANNER AS TO SHOW COWARDICE,

in that he,

aton....., when Rfnof....., one of the sentries at
the battalion quarter guard, had mortally wounded one sepoy of the said
guard and seriously wounded another and was firing his rifle in all
directions, showed cowardice by abandoning the said quarter guard and
hiding himself.

No. 4

Assam Rifles Act
Section 21(d)

**TREACHEROUSLY COMMUNICATING
INTELLIGENCE TO THE ENEMY,**

in that he,

aton.....with intent to assist the enemy, communicated with the enemy (specify enemy agency) by letter dated.....concerning the deployment of troops of B company of 3 AR battalion at

No. 5

Assam Rifles Act
Section 21(e)
read with Section
34 of Indian Penal
Code

ASSISTING THE ENEMY WITH AMMUNITION,

in that they together,

while on active duty, at on, in pursuance of a common intention, sold.....rounds of .303 ball ammunition, the property of the Government, to the enemy, to wit,.....hostiles up in arms against the Union through two persons, namely.....and

No. 6

Assam Rifles Act
Section 21(g)

**IN TIME OF ACTION LEAVING HIS PICKET
WITHOUT LEAVE,**

in that he,

aton....., in time of action, between 2000 hrs and 2200 hrs, being on duty at picket....., left the said picket without leave.

No. 7

Assam Rifles Act
Section 21(g)

**IN TIME OF ACTION LEAVING HIS POST, WITHOUT
LEAVE,**

in that he,

at field, on, when Second-in-Command.....company....., while his company was in contact with and under fire of the enemy in the area of, left his post without leave from about 0900hrs till about 2000 hrs the same day.

No. 8

Assam Rifles Act
Section 21(j)

**WHEN A SENTRY, IN TIME OF WAR, SLEEPING
UPON HIS POST,**

in that he,

aton.....between.....andhrs when sentry, in time of war on No.....(post of magazine guard) was found sleeping.

No. 9

Assam Rifles Act
Section 23 (a)

FORCING A SENTRY,

in that he,

when on active duty, at, on.....after being warned by No.....Rank.....Name.....of.....regiment, a sentry on post No.....not to pass, passed the said sentry.

No. 10

Assam Rifles Act
Section 23 (b)

**BREAKING INTO A HOUSE IN SEARCH OF
PLUNDER,**

in that he,

when on active duty, at, on..... broke into the house of Shri
.....ofin search of plunder.

No. 11

Assam Rifles Act
Section 23 (c)

WHEN A SENTRY, SLEEPING UPON HIS POST,

in that he,

when on active duty, at.....on.....between
0200 and 0300 hrs when sentry on No.....post of.....guard, was
asleep.

No. 12

Assam Rifles Act
Section 23 (d)

**LEAVING HIS GUARD WITHOUT ORDERS FROM
HIS SUPERIOR OFFICER,**

in that he,

at.....when sentry of the Assam Rifles guard on.....between 0500
and 0600 hrs, quit the said guard without orders from his superior
officer.

No. 13

Assam Rifles Act
Section 23 (e)

**INTENTIONALLY OCCASIONING A FALSE ALARM
IN CAMP,**

in that he,

when on active duty, at camp.....on.....by intentionally exploding
two grenades 36 HE, caused a false alarm in the said camp.

No. 14

Assam Rifles Act
Section 24 (a)

**CONSPIRING WITH OTHER PERSONS TO CAUSE A
MUTINY IN THE ASSAM RIFLES,**

in that they together,

at.....on.....agreed together to cause a mutiny in
.....companybattalion to wit, to cause the said
company to refuse to march on the date to.....(place), to which place
the said company was under orders to march.

No. 15

Assam Rifles Act
Section 24 (b)

JOINING IN A MUTINY IN THE ASSAM RIFLES,

in that they together,

at....., on....., in company with a number of other
sepoys of thecompany,(unit), in a

mutinous spirit entered the premises of quarter guard for removal of kote keys from the battalion key box, fired a round from a rifle in the unit ground and shouted"....." or words to that effect.

No. 16

Assam Rifles Act
Section 24 (b)

JOINING IN A MUTINY IN THE ASSAM RIFLES,

in that they together,

at.....on the night....., when serving with....., in company with a number of other personnel of the said unit, left the unit in a mutinous spirit, with arms and ammunition belonging to the Government.

No. 17

Assam Rifles Act
Section 24 (c)

BEING PRESENT AT A MUTINY IN THE ASSAM RIFLES NOT USING HIS UTMOST ENDEAVOURS TO SUPPRESS THE SAME,

in that he,

at.....on..... being present when sepoy sepoy..... and other soldiers of the same battalion together refused to go on a route march when ordered to do so by the Company Commander, failed to use his utmost endeavours to suppress the said mutiny.

No. 18

First Charge
Assam Rifles Act
Section 25 (1)

DESERTING THE SERVICE,

in that he,

at.....on..... absented himself from the battalion until apprehended by the civil police, at, on.....

Second Charge
Assam Rifles Act
Section 39 (a)

COMMITTING THEFT IN RESPECT OF PROPERTY BELONGING TO THE GOVERNMENT,

in that he,

when absenting himself from his battalion at the place and on the day aforesaid, committed theft by dishonestly taking with him one rifle (give description) value..... and twenty rounds of .303 ball ammunition value....., the property belonging to the Government.

(Note 1.- As a rule, proof of the date and circumstances in which the period of absence terminated is necessary to enable the court to decide whether the absence constituted desertion or merely absence without leave. Occasionally however, these facts are not material, and proof of them cannot be obtained without inconvenience to the public service and great delay. In such cases, they need not be proved, and should, therefore, not be averred in the particulars of the charge.

Note 2- It is immaterial whether the rifle is the one issued to the accused or to a comrade. See IPC S-27 and illustration (d) to IPC.S. 378.)

Assam Rifles Act
Section 25(1)

No. 19

DESERTING THE SERVICE,

in that he,

at.....on....., deserted from the battalion.

(Note. - This form may be used when the date and circumstances of the termination of the absence are not material facts, and proof of them cannot be obtained without an unreasonable amount of delay or expense.)

Assam Rifles Act
Section 25(1)

No. 20

DESERTING THE SERVICE,

in that he,

at.....on....., having been placed under orders for active duty and having been granted leave of absence fromto..... to proceed to....., did not rejoin aton the expiry of the said leave but absented himself with intent to avoid such active duty.

(Note. - It will often be advisable to frame an alternate charge for without sufficient cause overstaying leave granted to him.)

Assam Rifles Act
Section 25(1)

No. 21

ATTEMPTING TO DESERT THE SERVICE,

in that he,

at.....on....., attempted to quit the lines of his battalion disguised as a woman, with the intention to desert the service.

Assam Rifles Act
Section 25(2)

No. 22

HARBOURING A PERSON SUBJECT TO THE
ASSAM RIFLES ACT KNOWING HIM TO BE A DESERTER,

in that he,

at.....on....., concealed in his house, No....., Rank....., Name....., Battalion whom he knew to be a deserter from the said.....Battalion.

Assam Rifles Act
Section 25(3)

No. 23

BEING COGNIZANT OF THE DESERTION OF A
PERSON SUBJECT TO THE ASSAM RIFLES ACT NOT GIVING
NOTICE FORTHWITH TO HIS OWN OR OTHER SUPERIOR
OFFICER,

in that he,

at.....on....., when cognizant of the desertion of No....., Rank....., name....., of the same unit, did not give notice thereof forthwith to his own or other superior officer.

Assam Rifles Act
Section 26(a)

No. 24

ABSENTING HIMSELF WITHOUT LEAVE,

in that he,

at.....absented himself without leave from the unit lines from
....., to

Assam Rifles Act
Section 26(b)

No. 25
WITHOUT SUFFICIENT CAUSE OVERSTAYING
LEAVE GRANTED TO HIM,

in that he,

at.....on.....,having been granted leave of absence
from.....to..... to proceed to....., failed without sufficient
cause, to rejoin at....., on....., on the expiry of the said leave.

Assam Rifles Act
Section 26(c)

No. 26
BEING ON LEAVE OF ABSENCE HAVING RECEIVED
INFORMATION FROM PROPER AUTHORITY THAT
BATTALION TO WHICH HE BELONGS HAS BEEN ORDERED
ON ACTIVE DUTY, FAILING WITHOUT SUFFICIENT CAUSE TO
REJOIN WITHOUT DELAY,

in that he,

on.....,while on leave of absence at....., having received
information fromthat thebattalion had been ordered on
active duty, failed, without sufficient cause, to rejoin the said battalion
without delay.

Assam Rifles Act
Section 26(d)

No. 27
WITHOUT SUFFICIENT CAUSE FAILING TO
APPEAR, AT THE TIME FIXED, AT THE PLACE APPOINTED
FOR DUTY,

in that he,

at.....on.....,failed without sufficient cause to appear athrs
at....., the place appointed for PT (Commandant's) parade.

Assam Rifles Act
Section 26(e)

No. 28
QUITTING THE LINE OF MARCH WITHOUT
LEAVE FROM HIS SUPERIOR OFFICER,

in that he,

at.....on.....,when on the line of march fromto....., fell
out without leave from the Officer Commanding his Company.

Assam Rifles Act
Section 27(a)

No. 29
USING CRIMINAL FORCE TO HIS SUPERIOR
OFFICER,

in that he,

at.....on.....,struck with a stick on the head of No.....,
Rank....., name.....of the same battalion.

Assam Rifles Act
Section 27(a)

No. 30
ASSAULTING HIS SUPERIOR OFFICER,

in that he,

while on active duty, at....., on....., when ordered by his superior
officer No....., Rank.....,Name..... of the same unit to report to him
athrs that day, picked up a stone and threatened to throw it at the
said.....

49/9 GE/08-26

Assam Rifles Act
Section 27(c)

No. 31

USING INSUBORDINATE LANGUAGE TO HIS
SUPERIOR OFFICER,

in that he

at....., on....., said to his superior officer, No....., Rank.....,
Name....., of the same unit, "You know only how to get drunk
everyday. You are good for nothing", or words to that effect.

Assam Rifles Act
Section 28(1)

No. 32

DISOBEYING IN SUCH MANNER AS TO SHOW
WILFUL DEFIANCE OF AUTHORITY, A LAWFUL COMMAND
GIVEN PERSONALLY BY HIS SUPERIOR OFFICER IN THE
EXECUTION OF HIS OFFICE,

in that he,

at....., on....., when ordered by No....., Rank....., Name....., the
guard commander to proceed to sentry post, said "I shall not go, do
what you feel like" and did not proceed to the sentry post from the
guard room.

Assam Rifles Act
Section 28(2)

No. 33

DISOBEYING A LAWFUL COMMAND GIVEN BY HIS
SUPERIOR OFFICER,

in that he,

at....., on....., when ordered by No....., Rank....., Name.....,
of the same Battalion to eat his food, did not do so.

Assam Rifles Act
Section 28(2)

No. 34

DISOBEYING A LAWFUL COMMAND GIVEN BY HIS
SUPERIOR OFFICER,

in that he,

at....., on....., when ordered by No....., Rank....., Name.....,
of the same battalion to fall in for PT parade, did not do so.

Assam Rifles Act
Section 29(b)

No. 35

USING CRIMINAL FORCE TO A PERSON IN
WHOSE CUSTODY HE WAS LAWFULLY PLACED,

in that he,

at....., on....., when placed by No..... Rank.....,
Name....., unit....., with custody of No... Rank*.....Name..... of the
same unit struck with his web belt, on the head, the said*.....

Assam Rifles Act
Section 29(b)

No. 36

USING CRIMINAL FORCE TO A PERSON IN
WHOSE CUSTODY HE WAS LAWFULLY PLACED,

in that he,

at....., on....., struck on the head Civil Police Constable
No....., Name..... of..... Police Station, in whose
custody he was lawfully placed.

Assam Rifles Act
Section 29(e)

No. 37
NEGLECTING TO OBEY BATTALION ORDERS,

in that he,

at....., on....., neglected to obey battalion daily order Part I
No....., dated by entering Meena Bezar which had been placed
out of bounds by the said order.

Assam Rifles Act
Section 29(f)

No.38
WHEN CALLED UPON REFUSING TO ASSIST THE
FORCE POLICE, IN THE EXECUTION OF HIS DUTY,
in that he,

at....., on....., when called upon by No....., Rank....., Name....., Assistant Force Police of HQ.....to assist him in
arresting No....., Rank....., Name.....unit, an offender,
refused to do so.

Assam Rifles Act
Section 31

No. 39
MAKING AT THE TIME OF ENROLMENT A WIL -
FULLY FALSE ANSWER TO A QUESTION SET FORTH IN THE
PRESCRIBED FORM OF EN -ROLMENT WHICH WAS PUT TO
HIM BY THE ENROLLING OFFICER BEFORE WHOM HE
APPEARED FOR THE PURPOSE OF BEING ENROLLED,

in that he,

at....., on....., when appeared before No.....
.....Rank.....Name....., an enrolling officer, for the purpose of
being enrolled for service in the Assam Rifles, to the question put to
him "Have you ever been convicted by a criminal court" answered
"No", whereas he well knew that he had been convicted by Chief
Judicial Magistrate, Imphal West on for committing an offence
under Sec ____ of IPC.

Assam Rifles Act
Section 32

No. 40
BEING AN OFFICER BEHAVING IN A MANNER
UNBECOMING HIS POSITION AND THE CHARACTER
EXPECTED OF HIM,

in that he,

at....., on....., when answering 'TACTICS' paper at promotion
examination Part 'Z' was improperly found reading a précis on the
subject "Mountains favour the defender" for the purpose of answering
question No.1

Assam Rifles Act
Section 32

No. 41
BEING AN OFFICER BEHAVING IN A MANNER
UNBECOMING HIS POSITION AND THE CHARACTER
EXPECTED OF HIM,

in that he,

at....., on....., in payment of his outstanding dues towards the
CSD(I) Canteen of his unit, gave to Capt... .., the Canteen Officer,
a cheque for Rs.....(Rupeesandonly) drawn on the State bank
of India....., which was dishonoured when presented, well knowing that
he did not have sufficient funds in the said bank to meet the said
cheque.

Assam Rifles Act
Section 33(a)

No. 42

DISGRACEFUL CONDUCT OF AN INDECENT
KIND,

in that he,

at....., on....., at about2330 hrs, with indecent intent got
into bed with No....., Rank....., Name....., of the same battalion.

Assam Rifles Act
Section 33(b)

No. 43

MALINGERING,

in that he,

at....., on....., falsely pretended to Capt....., Medical
Officer, that he (the accused) was suffering from a sprained ankle.

Assam Rifles Act
Section 33(b)

No. 44

MALINGERING,

in that he,

at....., on....., between.....andhrs, with the intention of
evading his duties as a member of the Quarter Guard counterfeited
dumbness.

Assam Rifles Act
Section 33(b)

No. 45

FEIGNING DISEASE IN HIMSELF,

in that he,

at....., on....., pretended to, Medical
Officer, that he was suffering violent pain in the head and down his
back, whereas he was not so suffering.

Assam Rifles Act
Section 33(b)

No. 46

INTENTIONALLY DELAYING HIS CURE,

in that he,

at....., on....., when under medical treatment for a wound in his
leg removed the bandages from the said wound with intent thereby to
delay his cure and did thereby delay his cure.

Assam Rifles Act
Section 33(c)

No. 47

VOLUNTARILY CAUSING HURT TO A PERSON
WITH INTENT TO RENDER THAT PERSON UNFIT FOR
SERVICE,

in that he,

at....., on....., at the request of No....., Rank....., Name....., cut
off the trigger finger of the saidwith intent to render him unfit for
service.

Assam Rifles Act
Section 34

No. 48

USING CRIMINAL FORCE TO A PERSON SUBJECT
TO THE ASSAM RIFLES ACT BEING HIS SUBORDINATE IN
RANK,

in that he,

at....., on....., when drilling a squad of Sepoys, struck
Sepoy.....of the same unit on the shoulder with a pacesstick.

Assam Rifles Act
Section 34

No. 49

ILL-TREATING A PERSON SUBJECT TO THE
ASSAM RIFLES ACT BEING HIS SUBORDINATE IN RANK,

in that he,

at....., on....., ill- treated No....., Rank..., Name....., of the same
unit, by making him stand in the sun between 10 a.m. and 3 p.m. and
not allowing him to drink water during the said period.

Assam Rifles Act
Section 35

No. 50

INTOXICATION,

in that he,

at....., on....., when on duty (specify duty) was intoxicated.

Assam Rifles Act
Section 36(a)

No. 51

WHEN IN COMMAND OF A GUARD WILFULLY
RELEASING WITHOUT PROPER AUTHORITY A
PERSON COMMITTED TO HIS CHARGE,

in that he,

at....., on....., when in command of the Quarter Guard of the
.....Battalion, wilfully released, without proper authority, No.....,
Rank....., Name....., unit....., who was confined in the said
Quarter Guard and committed to his charge.

No. 52

Assam Rifles Act
Section 36(b)

WITHOUT REASONABLE EXCUSE ALLOWING TO
ESCAPE A PERSON WHOM IT WAS HIS DUTY TO GUARD,

in that he,

at....., on....., when posted as sentry over No, Rank.....,
Name....., ofUnit, allowed the saidto escape without
reasonable excuse.

Assam Rifles Act
Section 37(a)

No. 53

UNNECESSARILY DETAINING A PERSON IN
CONFINEMENT WITHOUT BRINGING HIM TO TRIAL,

in that he,

at....., on....., when officiating Commandant..... Battalion
unnecessarily detained No....., Rank....., Name....., of the same Unit in
confinement from..... to..... without bringing the said to
trial.

Assam Rifles Act
Section 38

No. 54

WHEN IN LAWFUL CUSTODY ESCAPING,

in that he,

at....., on....., when under close arrest in the unit Quarter Guard escaped there from.

Assam Rifles Act
Section 39(a)

No. 55

COMMITTING THEFT OF PROPERTY BELONGING
TO THE GOVERNMENT,

in that he,

at....., on....., committed theft in respect of one rifle 7.62 SLR Registered No, value....., the property of the Government.

Assam Rifles Act
Section 39(a)

No. 56

COMMITTING THEFT OF PROPERTY BELONGING
TO A PERSON SUBJECT TO ASSAM RIFLES ACT,

in that he,

at....., on....., committed theft in respect of a watch, the property of No....., Rank....., Name....., of the same Battalion.

Assam Rifles Act
Section 39(b)

No. 57

DISHONESTLY MISAPPROPRIATING PROPERTY
BELONGING TO THE GOVERNMENT,

in that he,

at....., between.....and..... dishonestly misappropriated _____ rounds of 7.62 SLR ammunition, the property of the Government value..... which had been entrusted to his charge for the target practice of Company.

Assam Rifles Act
Section 39(c)

No. 58

COMMITTING CRIMINAL BREACH OF TRUST IN
RESPECT OF PROPERTY BELONGING TO THE
GOVERNMENT,

in that he,

at....., on....., dishonestly misappropriated a sum of Rs..... the property belonging to the Government, which was entrusted to him as OC Field Workshop.

First Charge
Assam Rifles Act
Section 39 (d)

No. 59

DISHONESTLY RECEIVING THE PROPERTY
BELONGING TO THE GOVERNMENT KNOWING
THAT THEFT HAD BEEN COMMITTED IN RESPECT OF THE
SAME BY A PERSON SUBJECT TO ASSAM RIFLES ACT,

in that he,

at....., on....., dishonestly received 2 jerricans of 70 MT, the property belonging to the Government, which he knew to have been stolen by No....., Rank....., Name....., of Unit.

Second Charge
Assam Rifles Act
Section 49
(Alternative to the
first charge)

**AN ACT PREJUDICIAL TO GOOD ORDER AND
DISCIPLINE OF THE FORCE,**

in that he,

at....., on....., was in unauthorized possession of 2 jerricans of 70 MT,
the property belonging to the Government

No. 60

Assam Rifles Act
Section 39(e)

**WILFULLY DESTROYING PROPERTY OF THE
GOVERNMENT ENTRUSTED TO HIM,**

in that he,

at....., on....., wilfully destroyed one prismatic compass
valued....., the property of the Government, which had been entrusted
to him.

No. 61

Assam Rifles Act
Section 39(f)

**SUCH AN OFFENCE AS IS MENTIONED IN
CLAUSE (f) OF SECTION 39 OF THE ASSAM RIFLES ACT, WITH
INTENT TO DEFRAUD,**

in that he,

at....., on....., with intent to defraud, obtained from Shri....., a
shopkeeper, three packets of Gold Flake Cigarettes valued at Rs..... by
falsely pretending that he, the accused, was an orderly to Capt. of
...unit, and that he had been sent by the said Capt..... for the said
cigarettes.

No. 62

Assam Rifles Act
Section 39(f)

**SUCH AN OFFENCE AS IS MENTIONED IN
CLAUSE (f) OF SECTION 39 OF THE ASSAM RIFLES ACT, WITH
INTENT TO CAUSE WRONG-FUL LOSS TO A PERSON,**

in that he,

at....., on....., with intent to cause wrongful loss to
No.....Rank*....., Name....., debited the said*in the
acquittance roll for Rs.....ofCoy.....Battalion, with a deduction
of Rs.....on account of clothing, which deduction he did not credit to
the said*clothing account.

No. 63

Assam Rifles Act
Section 39(f)

**SUCH AN OFFENCE AS IS MENTIONED IN
CLAUSE (f) OF SECTION 39 OF THE ASSAM RIFLES ACT, WITH
INTENT TO CAUSE WRONG-FUL GAIN TO A PERSON,**

in that he,

at....., on....., while being the Detachment Clerk of 'B' and 'C'
Coys of his unit, with intent to cause wrongful gain to himself, altered
the entries of payment in the Acquittance Roll Serial Nofor April
20-- against his name from figure Rs.3000/- (Rupees three thousand
only) to figure Rs.2000/- (Rupees two thousand only).

Assam Rifles Act
Section 40(a)

No. 64

COMMITTING EXTORTION,

in that he,

at....., on....., by threatening to make a false report to the Officer Commanding their Coy to the effect that No....., Rank....., Name....., and No....., Rank....., Name....., had committed an unnatural offence together, extorted Rs.....from each of the saidpersons.

Assam Rifles Act
Section 40 (b)

No. 65

EXTRACTING WITHOUT PROPER AUTHORITY
MONEY FROM A PERSON,

in that he,

at....., on....., extracted, without proper authority Rs.....from No.....Rank....., Name..... of the same unit.

Assam Rifles Act
Section 41(a)

No. 66

MAKING AWAY WITH CLOTHING, THE PROPERTY
OF THE GOVERNMENT ISSUED TO HIM FOR HIS USE,

in that he,

at....., on....., sold his coat combat (Value Rs.....) property of the Government, issued to him for his use, to Shri.....for Rupees.....

Assam Rifles Act
Section 41(b)

No. 67

LOSING BY NEGLECT IDENTITY CARD, THE
PROPERTY OF THE GOVERNMENT ISSUED TO HIM FOR HIS
USE,

in that he,

at....., on....., lost by neglect Identity Card No....., the property of the Government, issued to him for his use.

Assam Rifles Act
Section 41(b)

No. 68

LOSING BY NEGLECT IDENTITY CARD THE
PROPERTY OF THE GOVERNMENT ISSUED TO HIM FOR HIS
USE,

in that he,

at....., on....., was deficient of Identity Card No....., the property of the Government, issued to him for his use.

(Note:- Ordinarily proof of the date and circumstances of the loss of the property is necessary. Occasionally, proof of them cannot be obtained. In such cases the particulars of the charge need to aver that the accused was deficient of the property in question on a specific date.)

Assam Rifles Act
Section 42(a)

No. 69

WITHOUT REASONABLE EXCUSE DESTROYING
AMMUNITION, THE PROPERTY OF THE GOVERNMENT
ENTRUSTED TO HIM,

in that he,

at....., on....., when i/c of the ammunition dump, without reasonable excuse, destroyed 1000 rounds of 7.62 SLR ammunition, the property of the Government entrusted to him.

Assam Rifles Act
Section 43(a)

No. 70

MAKING FALSE ACCUSATION AGAINST A PERSON SUBJECT TO THE ASSAM RIFLES ACT KNOWING SUCH ACCUSATION TO BE FALSE,

in that he,

at....., on....., when appearing before Commandant A....B.... Commanding the ...Battalion to answer for an offence, used language to the following effect, that is to say, "Assistant Commandant.... the Coy Commander takes no interest in his work and is entirely in the hands of the Platoon Commanders, who, in their turn, take bribes all round and allow no one without a bribe to approach the Assistant Commandant Sahib", well knowing the said statement to be false.

Assam Rifles Act
Section 43(b)

No. 71

IN MAKING A COMPLAINT UNDER SECTION 16 OF THE ASSAM RIFLES ACT, MAKING A STATEMENT AFFECTING THE CHARACTER OF A PERSON SUBJECT TO THE SAID ACT KNOWING SUCH STATEMENT TO BE FALSE.

in that he,

at....., on....., in a complaint under Section 16 of the Assam Rifles Act addressed to the Central Government, made the following statement "The Commandant is indulging in all sorts of malpractices in spending the money received by the unit out of the Annual Training Grant," well knowing the said statement to be false.

Assam Rifles Act
Section 44 (a)

No. 72

IN A CERTIFICATE SIGNED BY HIM KNOWINGLY MAKING A FALSE STATEMENT.

in that he,

at....., on....., in a certificate signed by him in the TA/DA claim for his temporary duty from his unit to for the duration fromto, stated that he was not provided with free messing at the outstation well knowing the said statement to be false.

Assam Rifles Act
Section 44(c)

No. 73

KNOWINGLY AND WITH INTENT TO DEFRAUD DESTROYING A DOCUMENT WHICH IT WAS HIS DUTY TO PRESERVE,

in that he,

at....., on....., when accounts officer of his unit, knowingly and with intent to defraud destroyed the cash book pertaining to the Regimental Accounts of the unit, a document which it was his duty to preserve.

Assam Rifles Act
Section 44(d)

No. 74

WHERE IT WAS HIS OFFICIAL DUTY TO MAKE A DECLARATION RESPECTING A MATTER, KNOWINGLY MAKING A FALSE DECLARATION,

in that he,

at....., on....., when being the custodian of classified documents of his unit, rendered a quarterly certificate that he checked and found correct all the said documents, well knowing that a secret document No.....had been lost by him.

Assam Rifles Act
Section 44(e)

No. 75

OBTAINING FOR A PERSON A PENSION BY
MAKING A FALSE STATEMENT WHICH HE KNEW TO BE
FALSE,

in that he,

at....., on....., when examined by Deputy Commandant AB
...of ...Unit who was investigating a claim to family pension preferred
by Shri C, inhabitant of, stated that he knew the said Shri C to be
the father of late Rfn.....ofBattalion well knowing such statement
to be false, and consequent to which a family pension of Rs.....p.m.
was sanctioned to the said Shri C.

Assam Rifles Act
Section 45(a)

No. 76

WHEN SIGNING A DOCUMENT RELATING TO
SUPPLIES, FRAUDULENTLY LEAVING IN BLANK A
MATERIAL PART FOR WHICH HIS SIGNATURE IS A
VOUCHER,

in that he,

at....., on....., when Officer Commanding 4 MGAR.....and
when signing the Receipt of articles supplied by contractor for the
month of, fraudulently left in blank the columns wherein the total
quantity of fresh rations received from the contractor were to be shown.

Assam Rifles Act
Section 46(c)

No. 77

REFUSING TO PRODUCE A DOCUMENT IN HIS
CONTROL LEGALLY REQUIRED BY AN ASSAM RIFLES
COURT TO BE PRODUCED BY HIM,

in that he,

at....., on....., when a witness, refused to produce a letter
dated.....in his control written to him by No...Rank...Name..., ...unit,
when legally required by the Summary Assam Rifles Court trying the
said.....to be produced by him (accused).

Assam Rifles Act
Section 46(e)

No. 78

CONTEMPT OF COURT BY USING INSULTING
LANGUAGE,

in that he,

at....., on....., when being tried by a General Assam Rifles
Court, said in a loud tone "It is no use my making any defence, the
Court has been told by the convening officer to convict me and of
course they will" or words to that effect.

Assam Rifles Act
Section 47

No. 79

HAVING BEEN DULY AFFIRMED BEFORE AN
ASSAM RIFLES COURT, MAKING A FALSE STATEMENT
WHICH HE KNEW TO BE FALSE,

in that he,

at....., on....., when examined as a witness before a Petty
Assam Rifles Court stated on solemn affirmation that Rfa.....,
unit, the person charged before the said Court was in his (the witness's)
company in the lines atbetween 0200 hrs and 0500 hrs on,
which statement was, as he well knew, false.

Assam Rifles Act
Section 48

No. 80

HAVING RECEIVED THE PAY OF A PERSON SUBJECT TO THE ASSAM RIFLES ACT, UNLAWFULLY REFUSING TO PAY THE SAME WHEN DUE,

in that he,

at....., on....., having received Rs.....as an advance of pay for the month ofin respect of No....., Rank....., Name.....of the same unit, unlawfully refused to pay the same to the said on.....

Assam Rifles Act
Section 49

No. 81

AN ACT PREJUDICIAL TO GOOD ORDER AND DISCIPLINE OF THE FORCE,

in that he,

at....., on....., improperly wrote and sent to his Commandant No....., Rank....., Name....., an anonymous letter in which he made use of the following words ".....".

Assam Rifles Act
Section 49

No. 82

AN ACT PREJUDICIAL TO GOOD ORDER AND DISCIPLINE OF THE FORCE,

in that he,

at....., on....., so negligently drove vehicle No. _____ 3 X Ton, the property of the Government, as to cause the said vehicle to be damaged to the amount of Rs. _____.

Assam Rifles Act
Section 49

No. 83

AN ACT PREJUDICIAL TO GOOD ORDER AND DISCIPLINE OF THE FORCE,

in that he,

at....., on....., while concerned with the care of public money, so negligently performed his duties as to be unable to account for Rs. _____ part of the said money.

Assam Rifles Act
Section 49

No. 84

AN OMISSION PREJUDICIAL TO GOOD ORDER AND DISCIPLINE OF THE FORCE,

in that he,

at....., on....., so negligently handled a rifle as to cause it to be discharged and thereby injuring No. _____, Rank _____, Name _____, of the same Unit.

Assam Rifles Act
Section 49

No. 85

AN ACT PREJUDICIAL TO GOOD ORDER AND DISCIPLINE OF THE FORCE,

in that he,

at....., on....., when appearing at part Z promotion examination for paper II-Tactics, was in improper possession of a précis on Tactics.

Assam Rifles Act
Section 50 (b)

No. 86

BY DEFILING A PLACE OF WORSHIP INTENTION-
ALLY WOUNDING THE RELIGIOUS FEELINGS OF A PERSON,

in that he,

at....., on....., entered the Mandir at _____ village with his boots on, and spat around, thereby intentionally wounding the religious feelings of the persons of the said village.

Assam Rifles Act
Section 50 (c)

No. 87

ATTEMPTING TO COMMIT SUICIDE AND IN SUCH
ATTEMPT DOING AN ACT TOWARDS THE COMMISSION OF
THE SAME,

in that he,

at....., on....., attempted to commit suicide by drinking a bottle of TIK-20.

Assam Rifles Act
Section 50 (e)

No. 88

OBTAINING FOR HIMSELF A GRATIFICATION AS A
REWARD FOR PROCURING LEAVE OF ABSENCE FOR A
PERSON IN THE SERVICE,

in that he,

at....., on....., while performing the duties of CHM of 'A Coy', obtained for himself Rs.500/- from No. _____, Rank _____, Name* _____ of his Coy, a gratification, as a reward for having procured leave of absence for the said* _____ from _____ to _____.

Assam Rifles Act
Section 50 (e)

No. 89

ATTEMPTING TO OBTAIN FOR HIMSELF A GRATIFICATION
AS A MOTIVE FOR PROCURING THE ENROLMENT OF A
PERSON,

in that he,

at....., on....., while working as a clerk in the recruitment rally of Assam Rifles, attempted to obtain Rs.2000/-, a gratification, as a motive for procuring the enrolment of Shri A B, by demanding the said sum from the said Shri AB,

Assam Rifles Act
Section 50 (f)

No. 90

COMMITTING AN OFFENCE AGAINST THE
PROPERTY OF A RESIDENT IN THE COUNTRY IN WHICH HE
WAS SERVING,

in that he,

at....., on....., maliciously damaged a motor car belonging to _____ of _____, a resident in _____ by thrusting a knife into one of the tyres.

Assam Rifles Act
Section 51

No. 91

ATTEMPTING TO INCITE A MUTINY IN THE FORCE
AND IN SUCH ATTEMPT DOING AN ACT TOWARDS THE
COMMISSION OF THE SAME,

in that he,

at....., on....., attempted to incite the under officers and men of his Company to combine together and refuse to eat their rations next day and to demand from No._____, Rank _____, Name _____, commanding the said unit that No._____, Rank _____, Name _____, be removed from his employment as _____ i/c of ration issue, and to this end addressed the Company personnel in the following words "_____" (set out the language used).

Assam Rifles Act
Section 52

No. 92

ABETMENT OF AN OFFENCE SPECIFIED IN SECTION 27
OF THE ASSAM RIFLES ACT, IN CONSEQUENCE OF WHICH
ABETMENT SUCH OFFENCE WAS COMMITTED,

in that he,

at....., on....., abetted by instigating No._____, Rank _____, Name _____, of the same Unit to strike Nb Sub... of the same Unit, in consequence of which the said _____ struck the said subordinate officer on the head with a stick.

Assam Rifles Act
Section 53

No. 93

ABETMENT OF AN OFFENCE PUNISHABLE WITH
DEATH UNDER SECTION 25 OF THE ASSAM RIFLES ACT, IN
CONSEQUENCE OF WHICH ABETMENT SUCH OFFENCE WAS
NOT COMMITTED,

in that he,

at....., on....., when on active duty, instigated No._____, Rank _____, Name* _____, of the same Unit to desert the service which offence was not committed by the said* _____.

Assam Rifles Act
Section 54

No. 94

ABETMENT OF AN OFFENCE SPECIFIED IN SECTION
39 OF THE ASSAM RIFLES ACT, AND PUNISHABLE WITH
IMPRISONMENT IN CONSEQUENCE OF WHICH ABETMENT,
SUCH OFFENCE WAS NOT COMMITTED,

in that he,

at....., on....., instigated No._____, Rank _____, Name _____, who was working as a batmen to No._____, Rank _____, Name* _____, of the same unit to commit theft of the Transistor belonging to the said* _____, which offence was not committed by the said Rifleman.

Assam Rifles Act
Section 55

No. 95

COMMITTING A CIVIL OFFENCE, THAT IS TO SAY,
CAUSING DEATH BY A RASH OR NEGLIGENT ACT NOT
AMOUNTING TO CULPABLE HOMICIDE PUNISHABLE UNDER
SECTION 304-A OF THE INDIAN PENAL CODE,

in that he,

at....., on....., by rashly or negligently driving vehicle No._____ caused the death of Shri _____, a civilian.

No. 96

Assam Rifles Act
Section 55

COMMITTING A CIVIL OFFENCE, THAT IS TO SAY,
MURDER, PUNISHABLE UNDER SECTION 302 OF THE INDIAN
PENAL CODE,

in that he,
at....., on....., by causing the death of No.____, Rank
____, Name _____ of his unit committed murder.

Assam Rifles Act
Section 55

No. 97
COMMITTING A CIVIL OFFENCE, THAT IS TO SAY,
RIOTING, PUNISHABLE UNDER SECTION 147 OF THE INDIAN
PENAL CODE,

in that he,
at....., on....., was a member of an unlawful assembly, which,
in prosecution of the common object of such assembly to use criminal
force to the Civil Police, beat the Civil Police with lathis, thereby
committing the offence of rioting.

Assam Rifles Act
Section 55

No. 98
COMMITTING A CIVIL OFFENCE, THAT IS TO SAY,
ATTEMPT TO MURDER, PUNISHABLE UNDER SECTION 307 OF
THE INDIAN PENAL CODE,

in that he,
at....., on....., fired two shots from a rifle at No.____,
Rank____, Name*____, of the same unit with intent to murder him
and thereby wounded the said* _____ in the right ear and left thigh.

Assam Rifles Act
Section 55

No. 99
COMMITTING A CIVIL OFFENCE, THAT IS TO SAY,
VOLUNTARILY CAUSING GRIEVOUS HURT, PUNISHABLE
UNDER SECTION 325 OF THE INDIAN PENAL CODE,

in that he,
at....., on....., voluntarily caused grievous hurt to No.____,
Rank____, Name _____, of the same unit by fracturing his left arm
with an iron rod.

Assam Rifles Act
Section 55

No. 100
COMMITTING A CIVIL OFFENCE, THAT IS TO SAY,
THEFT, PUNISHABLE UNDER SECTION 379 OF THE INDIAN
PENAL CODE,

in that he,
at....., on....., committed theft of a tin of ghee, of value of
Rs. _____ from the shop of Shri _____ in the Sadar Bazar, the property
of the said Shri _____.

Assam Rifles Act
Section 55

No. 101
COMMITTING A CIVIL OFFENCE, THAT IS TO SAY,
USING CRIMINAL FORCE TO A WOMAN WITH INTENT TO
OUTRAGE HER MODESTY, PUNISHABLE UNDER SECTION 354
OF THE INDIAN PENAL CODE,

in that he,
at....., on....., used criminal force to Smt. _____ wife of
Shri _____, by putting his right hand on her thigh intending
thereby to outrage her modesty.